चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 12 मार्च–18 मार्च 2012 | मूल्य 5 रुपये

बार गर्ल्स बनीं आतंकियों का हथियार

पेज-3

कांग्रेस का मिशन गुजरात और मीडिया का खेल

पेज-4

काटजू का बयान और नीतीश सरकार

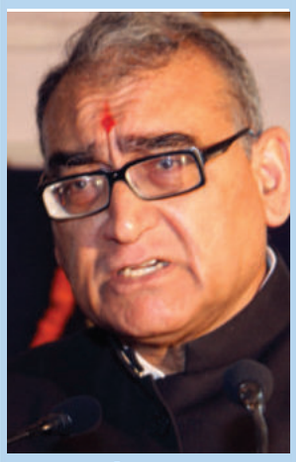

पेज-5

साई की महिमा

पेज-12

बजट-2012

देश पर गंभीर आर्थिक संकट

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सरकार चलाने का यह अजीबोग़रीब तरीक़ा है. पहले एक समस्या को जन्म दो, उसे पाल-पोस कर बड़ा करो और उसे बढ़ने दो. फिर मीडिया के ज़रिए उसके ख़तरे के बारे में लोगों को बताओ, चिंता जताओ, फिर हाथ खड़े कर दो कि इससे निपटने के लिए कड़े फ़ैसले लेने होंगे, क़ानून बदलना होगा. ऐसी रणनीति का फ़ायदा यह हो जाता है कि सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती. जन विरोधी एवं ग़रीब विरोधी नीतियों और क़ानूनों को लागू करने के लिए सरकार हमेशा इसी रणनीति का इस्तेमाल करती है. इसी तरह राजनीतिक दल और अधिकारी देश की जनता को मूर्ख बनाने में सफल हो जाते हैं और लोगों को सरकार की नीति जायज़ और सही लगने लगती है.

मनीष कुमार

सोलह मार्च को वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी बजट पेश करेंगे. पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद पेश किए जा रहे इस बजट की रूपरेखा पर हाल में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के घर पर एक मीटिंग हुई. दो घंटे के बाद मीडिया को सिर्फ़ इतना बताया गया कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाएगा, लेकिन इस मीटिंग के बाद जितने भी नेता मुखर्जी के घर से बाहर निकल रहे थे, उनके चेहरे से पता चल रहा था कि आगे क्या होने वाला है. किसी ने मीडिया से बात नहीं की.

लोकसभा चुनाव से पहले का यह शायद आख़िरी बजट है, जिसे प्रणव दा पेश कर रहे हैं. फ़िलहाल कांग्रेस के सामने कोई चुनाव नहीं है, इसलिए लोक लुभावन बजट पेश करने का दबाव वित्त मंत्री पर नहीं है. इसलिए सरकार मनचाहा काम करेगी. इसमें कोई शक नहीं है कि इस बजट पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलूवालिया के साथ ही उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के समर्थक अर्थशास्त्रियों की छाप होगी. यह बजट कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीति का आईना होगा. इससे पता चलेगा कि जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एवं इंदिरा गांधी की आर्थिक नीति और वर्तमान कांग्रेस की आर्थिक नीति में कोई फ़र्क़ है या नहीं. यह समझना इसलिए ज़रूरी है कि मनमोहन सिंह की सरकार जबसे दिल्ली की गद्दी पर क़ाबिज हुई है, तबसे ग़रीबों, किसानों, मज़दूरों एवं वनवासियों के साथ सिर्फ़ छलावा किया गया है और सारे फ़ायदे उद्योगपतियों और कॉरपोरेट घरानों को दिए गए हैं. जितनी भी योजनाएं बनती हैं, उनका फ़ायदा सिर्फ़ चंद लोगों को होता है. सरकार की यह नियति बन गई है कि ग़रीबों को सब्सिडी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते, लेकिन वह बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को अरबों-खरबों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए तत्पर रहती है.

केंद्र सरकार का यह बजट ऐसे समय पर आ रहा है, जब सरकार की साख दांव पर लगी है. पिछले कुछ समय से महंगाई की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया और सरकार ने हाथ खड़े कर दिए. प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की तरफ़ से गैर ज़िम्मेदार बयान दिए गए. यह कहा गया कि हमारे पास महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है. जनता में एक तरफ़ नाराज़गी है तो दूसरी तरफ़ देश के मज़दूर आंदोलन कर रहे हैं. हाल में हुए देशव्यापी बंद में कांग्रेस और भाजपा के मज़दूर संगठनों ने भी हिस्सा लिया. सरकार चलाने वालों को यह समझना पड़ेगा कि आम जनता के साथ-साथ उनके अपने कार्यकर्ता और संगठन के लोग भी सरकार की नीतियों से ख़ुश नहीं हैं. इसके अलावा इस बजट की पृष्ठभूमि गंभीर आर्थिक संकट है. देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार लगातार घटती जा रही है. सरकार की नीतियां एक के बाद एक फ़ेल हो रही हैं. केंद्र सरकार ने फ़रवरी 2011 में बजट पेश करने से पहले यह दावा किया था कि वह ऐसी नीतियों पर काम कर रही है, जिनसे देश की आर्थिक स्थिति ख़ासी मज़बूत हो जाएगी. सरकार ने दावा किया था कि वह 2011-12 में 9 प्रतिशत विकास दर हासिल कर लेगी. कुछ समय बीतते ही सरकार को समझ में आ गया कि 9 प्रतिशत विकास दर मुमकिन नहीं है तो उसने इस टारगेट को घटाकर 8.4 प्रतिशत कर दिया. आज देश की आर्थिक स्थिति का हाल यह है कि सरकार ने ख़ुद ही मान लिया कि 2011-12 में देश की जीडीपी विकास दर 8.4 प्रतिशत से घटकर 6.9 प्रतिशत रहेगी. यह पिछले तीन सालों में सबसे कम है. सरकार के मुताबिक़ ऐसा उत्पादन, कृषि और खनन में आई गिरावट की वजह से है. यूपीए की दूसरी पारी के पहले दो सालों में विकास दर 8.4 प्रतिशत थी. सरकार का जो भी अनुमान हो, हक़ीक़त यह है कि 6.9 प्रतिशत विकास दर को भी पाना मुश्किल है, क्योंकि थर्ड क्वॉर्टर के आंकड़े आ गए हैं और उनके मुताबिक़, जीडीपी विकास दर 6.1 प्रतिशत है. सरकार के मुताबिक़, सारे क्षेत्रों में गिरावट का माहौल है, उत्पादन की स्थिति एक साल में धरातल में पहुंच गई है. पिछले साल यह 7.6 प्रतिशत की गति से बढ़ रहा था, जो इस साल घट कर महज़ 3.9 प्रतिशत पर पहुंच गया है. कृषि की हालत भी बहुत ख़राब है. पिछले साल कृषि विकास दर 7 प्रतिशत थी, जो 2011-12 में 2.5 प्रतिशत पर पहुंच गई है. खनन की स्थिति दयनीय हो गई है. 2010-11 में खनन की विकास दर 5 प्रतिशत थी, लेकिन 2011-12 में यह -2.2 प्रतिशत पर पहुंच गई. विनिर्माण की हालत भी ख़स्ता है. इसकी विकास दर 4.8 प्रतिशत है, जबकि पिछले साल यह क्षेत्र 8 प्रतिशत की दर से विकास कर रहा था.

यह बजट ऐसे समय पर आ रहा है, जब सरकार की साख दांव पर लगी है. पिछले कुछ समय से महंगाई की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया और सरकार ने हाथ खड़े कर दिए. प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की तरफ़ से गैर ज़िम्मेदार बयान दिए गए. यह कहा गया कि हमारे पास महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है.

मनमोहन सिंह ने देश की आर्थिक नीति और उसके दर्शन को ही बदल दिया. भारत में सरकारी योजनाओं के ज़रिए सामाजिक विकास और समानता हासिल करने का उद्देश्य पीछे छोड़ दिया गया. 1991 में ऐसी नीति की नींव रखी गई, जिसका असर हर तरफ़ नज़र आ रहा है. अमीर पहले से ज़्यादा अमीर और ग़रीब पहले से ज़्यादा ग़रीब हो गए.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

संगठन का मानना है कि जिन बाबुओं के नाम इस घोटाले में आए हैं, उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है.

दिल्ली का बाबू

भरे जाने लगे ख़ाली पद

Prasar Bharati Board

सरकार भले ही देर से जागी, लेकिन अब लगता है कि विभिन्न मंत्रालयों में ख़ाली पड़े कई पदों पर नियुक्ति बहुत जल्द की जाएगी. इसके लिए सरकार ने शुरुआत कर दी है. जवाहर सरकार को प्रसार भारती का सीईओ बनाया जाना इस दिशा में उठाया गया क़दम माना जा सकता है. ग़ौरतलब है कि बहुत दिनों से प्रसार भारती के लिए स्थायी सीईओ की नियुक्ति लंबित थी और यह पद ख़ाली पड़ा था. सूत्रों का कहना है कि सूचना–तकनीक विभाग के सचिव के लिए खोज जारी है और दूरसंचार सचिव आर चंद्रशेखर, जो सूचना–तकनीक सचिव का काम भी संभाल रहे थे, को इस अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है. सरकार नियुक्ति में बहुत सावधानी बरत रही है, क्योंकि 2–जी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को वह भूल नहीं पाई है. इसी तरह पी के मिश्रा को कार्मिक सचिव तो बना दिया गया है, लेकिन अभी तक वह स्टील सचिव का काम भी देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक स्टील मंत्रालय ने उनकी जगह किसी को नियुक्त नहीं किया है. हालांकि अभी भी बहुत सारे पद ख़ाली पड़े हैं, लेकिन उम्मीद बरक़रार है.

बाबुओं की चिंता

ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी बाबू को सचिव के पद के लिए विचार किए बिना सेवानिवृत्ति की सूची में शामिल कर लिया गया हो. 1978 बैच के नागालैंड कैडर के अधिकारी वी एन गौर पहले अधिकारी हैं, जिन्हें इस तरह का संदेहास्पद सम्मान दिया जाने वाला है. गौर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण के सीईओ हैं, जो कि अतिरिक्त सचिव के समकक्ष पद है. स्वाभाविक है कि यह मामला वरिष्ठ बाबुओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनके साथ भी इसी तरह की घटना न घट जाए.

सूचना आयोग और बाबू

आरटीआई कार्यकर्ताओं की सरकार से हमेशा यह शिकायत रही है कि वह पूर्व अधिकारियों को केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) और राज्य सूचना आयुक्त (एसआईसी) नियुक्त करती रही है. उनका कहना है कि पूर्व अधिकारियों का एक तरह से इन पदों पर क़ब्ज़ा हो गया है. यह एक तरह से इस बात का संकेत है कि सरकार अपने पसंदीदा अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने पास रखना चाहती है, ताकि उसका उल्लू सीधा होता रहे. अभी जिन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हुई है, उससे तो यही लगता है कि सरकार आरटीआई कार्यकर्ताओं की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही है. सरकार ने अभी केंद्रीय सूचना आयुक्त के लिए जिन नामों की घोषणा की है, वे अधिकारी ही हैं. इस बार पूर्व आईबी प्रमुख राजीव माथुर और पूर्व पर्यावरण सचिव विजय शर्मा का नाम केंद्रीय सूचना आयुक्त के लिए घोषित किया गया है.

दिलीप चेरियन

बाबू संगठन और केरल सरकार

केरल आईएएस अधिकारी संगठन सरकार से ख़फ़ा है, क्योंकि कुछ वरिष्ठ बाबुओं को भूमि आवंटन मामले में आरोपी बनाया गया है. संगठन का मानना है कि जिन बाबुओं के नाम इस घोटाले में आए हैं, उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है. इसलिए आईएएस अधिकारी संगठन ने केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी से इसकी शिकायत की है और इस तरह की कार्रवाइयों के प्रति विरोध भी जताया है. जिन अधिकारियों के नाम भूमि आवंटन घोटाले में आए हैं, उनमें पूर्व मुख्य सचिव शीला थॉमस, पूर्व भूमि आयुक्त के आर मुरलीधरन, दो पूर्व जिलाधिकारी आनंद सिंह और कृष्णन कुट्टी शामिल हैं. अब यह तो न्यायालय तय करेगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस मामले के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे बाबुओं की बेचैनी बढ़ गई है.

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

मदान एएस और नीरज जेएस बने

1981 बैच के आईएएस अधिकारी विजय शंकर मदान को भारत सरकार के अंतर्गत अतिरिक्त सचिव का दर्जा दिया गया है. वह इससे पहले संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर रहे थे. इसी प्रकार 1992 बैच के आईएएस अधिकारी नीरज मित्तल को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया जाना है. मित्तल अभी इसी मंत्रालय में निदेशक के पद पर काम कर रहे हैं. वह डी एन नरसिम्हा राजू का स्थान लेंगे.

कमलकांत बने डीएफए

2000 बैच के आईएसएस अधिकारी कमलकांत नाथ को गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीआरपीएफ गुवाहाटी का उप वित्तीय सलाहकार (डीएफए) बनाया गया है. वह कंपनी मामलों के मंत्रालय में उप सचिव के पद पर काम कर रहे थे.

अमरेंद्र दूबे जनजातीय कार्य मंत्रालय पहुंचे

1982 बैच के आईएएस अधिकारी अमरेंद्र कुमार दूबे को जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह बचित्तर सिंह की जगह लेंगे, जिन्होंने इस मंत्रालय में अपना विस्तारित कार्यकाल पूरा कर लिया है. अमरेंद्र पंचायती राज मंत्रालय में जेएस थे.

अशोक सिंघवी शहरी विकास मंत्रालय में

1983 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. अशोक सिंघवी को शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह एम एम कुट्टी की जगह लेंगे, जिन्हें होम कैडर भेजा जा रहा है.

देश पर गंभीर आर्थिक संकट

पृष्ठ एक का शेष

अब सवाल यह है कि भारत की आर्थिक स्थिति यहां तक कैसे पहुंची, इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, क्या सिर्फ़ आंकड़े जारी करके सरकार की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? समझने वाली बात यह है कि सरकार ऐसी नीतियों को क्यों लागू करती है, जिनका असर उल्टा होता है. एक कठिन स्थिति से निकलने के लिए सरकार फ़ैसले लेती है और जब उसका असर सामने आने लगता है तो परेशानी पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है. क्या हमारे पास ऐसे अर्थशास्त्री नहीं हैं, जो ख़स्ताहाल अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकें. मंदी के दौर में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, तब भारत पर उसका असर नहीं दिखा. जब भाजपा की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और देश पर आर्थिक पाबंदियां लगीं, तब भी भारत पर उसका असर नहीं दिखा. जब भी स्टॉक एक्सचेंज में भूचाल आता है तो हमें बताया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था का आधार मज़बूत है. वैसे भी देश पर कोई विपदा नहीं आई. सूखा भी नहीं पड़ा. कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाए. फिर लगातार तीन सालों से हमारी अर्थव्यवस्था क्यों धरातल की ओर अग्रसर है. ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या यह जानबूझ कर किया जा रहा है.

सरकार देश को पूरी तरह से एक मुक्त बाज़ार में तब्दील करने का फ़ैसला कर चुकी है. यही वजह है कि वह एक ऐसा माहौल तैयार करने में लगी है, जहां वह कह सके कि बिना कड़े फ़ैसले के अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना नामुमकिन होगा. वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने जब 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई, तब भी वैसा ही माहौल था, जैसा आज है. वार्षिक विकास दर अस्सी के दशक में 3.5 प्रतिशत थी. सरकारी कंपनियों को लगातार नुक़सान हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का विकास नहीं हुआ और लाइसेंस राज ने उद्योगों को बढ़ने का मौक़ा नहीं दिया. साथ ही पूरी अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसी थी. राजीव गांधी के शासनकाल से ही देश की अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब होने लगी थी, लेकिन इसका उपाय नहीं ढूंढा गया. सरकार चलाने वाले मंत्रियों एवं अर्थशास्त्रियों को यह पता था कि अगर इसका उपाय नहीं किया गया तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी. इसके बावजूद वित्त मंत्रालय में बैठे लोग इसे टालते रहे. जानबूझ कर अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने दिया गया. ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि देश को सोना गिरवी रखने की ज़रूरत पड़ गई. उस वक़्त मनमोहन सिंह तत्कालीन सरकार के आर्थिक मामलों के सलाहकार थे. हालांकि इस पर जमकर राजनीति हुई, लेकिन हक़ीक़त यह है कि ऐसी नौबत किसी एक सरकार की वजह से नहीं आई, बल्कि यह 1991 से पहले की नीतियों का नतीजा था. हक़ीक़त यह है कि सरकार चलाने वाले लोग समस्या का समाधान निकालने के बजाय उसे टालते रहे. अगर 80 के दशक में सरकारी कंपनियों की हालत बेहतर कर दी गई होती, उन्हें चलाने वालों की ज़िम्मेदारी तय कर दी गई होती तो शायद आज उन्हें बेचने की नौबत नहीं आती. देश की निजी कंपनियों और पूंजी को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनतीं तो आज हमें विदेशी पूंजी पर निर्भर नहीं होना पड़ता. आज सरकार जो बेहतरीन सड़कें बना रही है, एयरपोर्ट्स बना रही है, ये सारे काम 80 के दशक में भी हो सकते थे, लेकिन सरकार ने इसकी ज़रूरत नहीं समझी. नतीजा यह हुआ कि 1991 में सरकार की ग़लतियां ही सरकार की दलील बन गईं, सरकार की नाकामी सरकार का तर्क बन गई. न किसी को ज़िम्मेदार ठहराया गया, न व्यवस्था में परिवर्तन किया गया और न कोई कोशिश हुई. सरकार ने हाथ खड़े कर दिए. नव उदारवादी व्यवस्था को अपनाना ही एकमात्र रास्ता बताकर उदारीकरण की नींव रख दी गई. इस तरह मनमोहन सिंह ने देश की आर्थिक नीति और उसके दर्शन को ही बदल दिया. भारत में सरकारी योजनाओं के ज़रिए सामाजिक विकास और समानता हासिल करने का उद्देश्य पीछे छोड़ दिया गया. 1991 में ऐसी नीति की नींव रखी गई, जिसका असर हर तरफ़ नज़र आ रहा है. अमीर पहले से ज़्यादा अमीर और ग़रीब पहले से ज़्यादा ग़रीब हो गए.

अब बजट पेश किया जा रहा है. उससे पहले माहौल तैयार किया जा रहा है. आज किसी के मन में कोई शक नहीं है कि देश की आर्थिक विकास दर धीमी है. मीडिया में कहा और लिखा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की तस्वीर ख़राब और चिंताजनक है. चिंताजनक इसलिए, क्योंकि निकट भविष्य में उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती. अब इसका तर्क यह दिया जाएगा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति ख़राब इसलिए है, क्योंकि निवेश दर में कोई तेज़ी नहीं आई है. विकास दर के डूबने के लिए वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता और सुस्त बाहरी मांग को ज़िम्मेदार बताया जाएगा. लेकिन इस पर सवाल कौन उठाएगा कि यह तो पिछले तीन सालों से चल रहा है, फिर सरकार ने क्या किया. आर्थिक मामलों के जानकार यह चेतावनी कई दिनों से दे रहे हैं कि सरकार की सुस्ती और रिज़र्व

बैंक की कोताही विकास को रोक रही है. सरकार आंकड़ों को दुरुस्त रखने के लिए समय–समय पर क़दम उठाती रही है.

एक उदाहरण है कोयले का. खनन क्षेत्र में लगातार गिरावट आ रही है. कई महीनों से अख़बारों में कोयले को लेकर बहुत हंगामा मचा है. देश में बिजली की कमी है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पावर प्लांट के लिए कोल इंडिया को कोयला आयात करने को कहा. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक़, वर्ष 2012–13 में 70 मिलियन टन कोयले का आयात करने का फ़ैसला किया गया है. दूसरी तरफ उद्योग जगत सरकार पर यह दबाव डाल रहा है कि कोयला आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाए. अब सवाल यह है कि क्या देश में कोयले की कमी हो गई है. चौथी दुनिया की तहक़ीक़ात के मुताबिक़, यूपीए सरकार के दौरान कोयले की खानें सिर्फ 100 रुपये प्रति टन की खनिज रॉयल्टी के एवज़ में बांट दी गईं. ऐसा तब किया गया, जब कोयले का बाज़ार मूल्य 1800 से 2000 रुपये प्रति टन के ऊपर था. संसद में इस बात को लेकर कुछ सांसदों ने हंगामा भी किया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला. 1993 से 2003 तक 40 ब्लॉक बांटे गए थे, जिनमें से अब तक सिर्फ़ 24 ने उत्पादन शुरू किया है. तो बाक़ी 16 कंपनियों के लाइसेंस ख़ारिज क्यों नहीं किए गए? 2004 में 4 ब्लॉक बांटे गए थे, जिनमें आज तक उत्पादन शुरू नहीं हो पाया. 2005 में 22 ब्लॉक आवंटित किए गए, जिनमें से आज तक केवल 2 ब्लॉकों में ही उत्पादन शुरू हो पाया है. इसी तरह 2006 में 52, 2007 में 51, 2008 में 22, 2009 में 16 और 2010 में एक ब्लॉक का आवंटन हुआ, लेकिन 18 जनवरी, 2011 तक की रिपोर्ट के अनुसार, कोई भी ब्लॉक उत्पादन शुरू होने की अवस्था में नहीं है. 1993 से लेकर 2010 तक कोयले के 208 ब्लॉक बांटे गए, जो कि 49.07 बिलियन टन कोयला था. इनमें से 113 ब्लॉक 184 निजी कंपनियों को दिए गए, जो कि 21.69 बिलियन टन कोयला था. अगर बाज़ार मूल्य पर इसका आकलन किया जाए तो 2500 रुपये प्रति टन के हिसाब से इस कोयले का मूल्य 5,382,830.50 करोड़ रुपये होता है. अगर इसमें से 1250 रुपये प्रति टन काट दिया जाए, यह मानकर कि 850 रुपये उत्पादन की क़ीमत है और 400 रुपये मुनाफ़ा, तो भी देश को लगभग 26 लाख करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ. यह आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है और शायद दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होने का गौरव भी इसे ही मिलेगा. शिबू सोरेन के जेल जाने के बाद जब कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के अधीन था, तब सबसे अधिक यानी कोयले के 63 ब्लॉक बांटे गए. इन चार सालों में लगभग 175 ब्लॉक आनन–फ़ानन में पूंजीपतियों और दलालों को मुफ्त में दे दिए गए. लगभग 21.69 बिलियन टन कोयले के उत्पादन क्षमता वाली खदानें निजी क्षेत्र के दलालों और पूंजीपतियों को मुफ्त दे दी गईं. देश में कोयला खदानों की लूट हो रही है, कंपनियां उन्हें आवंटित कराकर चुपचाप बैठ गई हैं और सरकार कह रही है कि देश में कोयले की कमी है. सरकार कोयले की कमी का नाटक क्यों कर रही है. सरकार कोयले की कमी का झांसा देकर विदेशी कंपनियों और देश के उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, ताकि कम दामों में विदेशों से कोयला भी ख़रीदा जा सके, निजी कंपनियों को फ़ायदा भी पहुंच सके और सरकारी आंकड़ा भी दुरुस्त रहे. जो हाल कोयले का है, वही हाल दूसरे खनिजों और उद्योगों का है. अगर जांच हो तो पता चलेगा कि हर क्षेत्र में सरकार की कोताही और भ्रष्टाचार की वजह से देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है.

सरकार को देश के ग़रीबों, मज़दूरों और किसानों से ज़्यादा उद्योगपतियों की चिंता है. यही वजह है कि सरकारी नीतियों का सीधा फ़ायदा चुने हुए उद्योगपतियों को होता है. हाल में जितने भी घोटाले उजागर हुए हैं, उनमें उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है. सरकार देश में ऐसा माहौल तैयार कर चुकी है, जिससे वह यह दलील दे सके कि उदारीकरण और निजीकरण में तेज़ी लाए बिना अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं लाया जा सकता है. सरकार अब हर क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश का फ़ैसला कर चुकी है. शिक्षा से लेकर खुदरा बाज़ार तक को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया जाएगा. उदारीकरण के 20 सालों में देश काफ़ी कठिन दौर से गुज़रा है. नक्सलियों का प्रभाव 60 जिलों से बढ़कर 260 जिलों तक फैल गया है. किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं. हाल में हुआ देशव्यापी बंद यह बताता है कि मज़दूर भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. मध्य वर्ग की नाराज़गी उनसे भी ज़्यादा है. युवाओं का भविष्य अंधकारमय है. देश में भ्रष्टाचार को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं. व्यवस्था परिवर्तन की मांग ज़ोर पकड़ रही है. जो जहां है, वहीं सरकारी तंत्र से नाराज़ है. ऐसे में अगर बजट में आम लोगों को राहत नहीं मिलती है तो उनका गुस्सा भड़क सकता है. सरकार अगर विदेशी कंपनियों को कृषि, उद्योग, खुदरा बाज़ार एवं शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में प्रवेश की छूट देती है तो यह मान लेना चाहिए कि देश के प्रजातंत्र पर संकट गहरा जाएगा.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 04 अंक 01
दिल्ली, 12 मार्च–18 मार्च 2012
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)
सी–20, ट्रांस यमुना, एनएच–2, आगरा
फोन : 0526–4064901, 9837082462

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर–440012
फोन नं : 0712–2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

यहां एक रात रुकने और खाने-पीने के छह लाख रुपये वसूले जाते थे, जिसमें ग्राहक को कॉलगर्ल के साथ शराब, खाने और डांस की सुविधा मुहैया कराई जाती थी.

बार गर्ल्स बनीं आतंकियों का हथियार

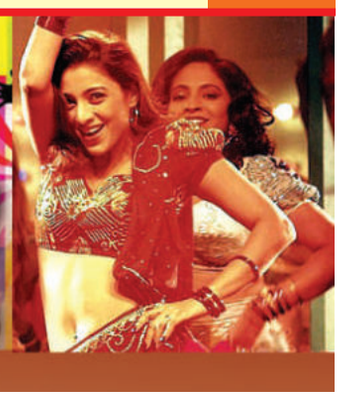

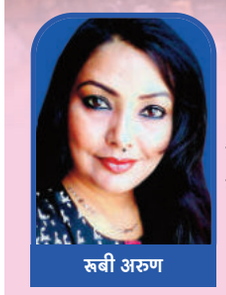

रूबी अरुण

भारत के ख़िलाफ़ रची गई है अब तक की सबसे ख़ौफ़नाक साज़िश. आतंकवादियों ने इस बार भारत पर हमले के लिए तैयार की है महिला ब्रिगेड. इस महिला ब्रिगेड में मुंबई और पाकिस्तान में काम करने वाली बार गर्ल्स शामिल हैं. भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसी के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि दुबई में बैठे दाऊद और उसके गुर्गे मुंबई और पाकिस्तान की बार गर्ल्स को डांस करने के नाम पर दुबई बुलाकर उन्हें आतंकी वारदातें अंजाम देने की ज़बरदस्त ट्रेनिंग दे रहे हैं. इतना ही नहीं, पाकिस्तान में भी 21 महिलाओं की एक टीम तैयार की जा चुकी है, जो मौक़ा मिलते ही भारत में घुसकर हमला करने की फिराक में है. आई बी को इस ख़तरनाक साज़िश की जानकारी तब मिली, जब मुंबई पुलिस ने जे बी नगर के अंधेरी कुर्ला रोड स्थित एक होटल सन एंड शील पर छापा मारा. इस होटल से गिरफ्तार बार डांसर्स और उनके मालिक से हुई गहन पूछताछ के बाद पुलिस को जो जानकारी मिली, वह दंग कर देने वाली थी. पता चला कि इस होटल में बार और डिस्कोथेक के नाम पर सेक्स रैकेट चलता है और यहां काम करने वाली लड़कियां दुबई, पाकिस्तान, मॉरिशस, बैंकॉक और थाईलैंड तक भेजी जाती हैं. ये लड़कियां भारत में आतंक फैलाने के लिए ज़िम्मेदार संगठनों के लिए न सिर्फ़ जासूस का काम करती हैं, बल्कि हवाला और मटका जैसे धंधों के लिए बड़ी मात्रा में पैसे इधर से उधर करने का भी ज़रिया बनती हैं. इस नए आतंकी गिरोह में शामिल लड़कियां अपने खातों में विदेशों से जमा पैसों को दर्जनों वीजा कार्ड्स के ज़रिए एटीएम से निकालती हैं.

आई बी के मुताबिक़, ये लड़कियां ग्रुप बनाकर किसी सुनसान से एटीएम पर जाती हैं. फिर वहां के गार्ड को कुछ पैसे देकर अपने साथ मिला लेती हैं और फिर दर्जनों एटीएम के मार्फ़त वे लाखों रुपये की निकासी कर लेती हैं. बहरहाल, पुलिसिया तफ्तीश में होटल सन एन शील के सभी ग्राहकों के गहरे ताल्लुक खाड़ी देशों से निकले. यहां एक रात रुकने और खाने-पीने के छह लाख रुपये वसूले जाते थे, जिसमें ग्राहक को कॉलगर्ल के साथ शराब, खाने और डांस की सुविधा मुहैया कराई जाती थी. होटल के सुरक्षा इंतज़ामात ऐसे कि ख़ुफ़िया एजेंसियों ने भी दांतों तले उंगलियां दबा लीं. मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर राकेश मारिया ने बताया कि रात के गुमनाम अंधेरों में चलने वाले इस होटल के इर्द-गिर्द ढाबे और रोज़मर्रा की चीज़ों की दुकानें हैं. इमारत की तीसरी मंजिल पर एक रेस्टोरेंट है. पूरे दिन यहां सामान्य कारोबार होता और जैसे ही रात होती और दूसरी दुकानों पर ताले लगते, यहां की रौनक पूरे शबाब पर आ जाती. सुबह के छह बजे तक इस होटल का धंधा चलता रहता, फिर सड़कों पर चहलपहल बढ़ते ही रेस्टोरेंट अपने मामूली रंग-ढंग में तब्दील हो जाता.

इस होटल के हरेक कमरे की क़ीमत किसी भी सेवन स्टार होटल से ज़्यादा तो थी ही, अपने काले धंधे और ग्राहकों के अनैतिक काम को पुलिस या किसी भी अजनबी की नज़र से बचाने की खातिर अत्याधुनिक तकनीक की व्यवस्था की गई थी. यह होटल इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे से लैस है, जिसका दरवाज़ा जानी-पहचानी आहट या उसकी मेमोरी में फीड किए गए निशान को पहचान कर ही खुलता था. किसी भी ख़तरे की आशंका से ज़रा से सिग्नल पर सक्रिय हो जाने वाली लिफ्ट, मैट्रेस के नीचे छुपाकर रखे गए अत्याधुनिक हथियार, किसी इमरजेंसी में दीवार तोड़ने के लिए रखे गए हैंडग्रेनेड, वॉयस आईडेंटिफिकेशन से खुलने वाले होटल के कमरे वग़ैरह जैसे सुरक्षा उपाय किसी ख़ुफ़िया एजेंसी के तौर तरीक़ों को भी मात दे देंगे. होटल में एक ऐसा इमरजेंसी रूम भी था, जो डांसर्स के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था और जिसकी फर्श में लिफ्ट लगी थी, जो किसी भी ख़तरे की स्थिति में बग़ैर होटल का मेन डोर इस्तेमाल किए लड़कियों को सीधे इमारत की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचा देती थी. बिल्डिंग एंट्रेंस पर इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा था, जिसे दबाते ही डांस बार में ख़तरे का सिग्नल चला जाता था. ग्राउंड फ्लोर पर 12 धुरंधर सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती थी, जिनका काम संदिग्ध विजिटर्स को रोकना और अपने कस्टमर्स से एक लाख रुपये कैश एंट्रेंस फीस वसूलना था.

राकेश मारिया बताते हैं कि पुलिस का छापा पड़ने पर कस्टमर्स और कॉलगर्ल्स को बचाने के लिए इस होटल में जितना मज़बूत इमरजेंसी प्लान था, उतना हिंदी फिल्मों में ही देखने को मिलता है, असल में नहीं. ख़ुफ़िया एजेंसियों से मिली सूचना के आधार पर जब इस होटल में पूरे प्लान और एहतियात के साथ चारों ओर नाकेबंदी करके छापेमारी की गई, तब 45 लोगों और 6 कॉलगर्ल्स को गिरफ्तार किया गया, जिनमें होटल मालिक भी शामिल है. होटल मालिक लालजी सिंह उर्फ विनोद सिंह की इंटरपोल को लंबे वक़्त से तलाश थी. इस होटल के मालिक के धंधे खाड़ी देशों के साथ-साथ मॉरिशस, थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया और सिंगापुर आदि में फैले हुए हैं. आई बी को यह ख़बर मिली थी कि इस होटल में डांस और कॉलगर्ल्स का काम करने वाली लड़कियों की मार्फ़त मालिक विनोद सिंह हवाला का कारोबार तो करता ही है, दुबई में बैठे आतंक के आकाओं को उन लड़कियों का पूरा ग्रुप भी मुहैया कराता है, जो पैसों की खातिर भारत के ख़िलाफ़ किसी भी हद तक जा सकती हैं. इसके अलावा यहां से इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी शाहरुख़ उर्फ यासीन अहमद के एक गुर्गे की भी गिरफ्तारी हुई, जिसकी निशानदेही पर हवाला के ज़रिए दस लाख रुपये यासीन अहमद को सौंपने के आरोप में गाजियाबाद से कंवर नयन वजीरचंद पथरेजा नामक हवाला कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया. गाजियाबाद में रहने वाला कंवर पथरेजा चांदनी चौक में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता है. महाराष्ट्र एटीएस की जानकारी के अनुसार, कंवर पथरेजा द्वारा यासीन को सौंपी गई रकम का प्रयोग मुंबई धमाकों को अंजाम देने में किया गया था. आई बी को मिले सबूत के मुताबिक़, भारत पर हमला करने की यह साज़िश बेहद पुख्ता तरीक़े से बनाई जा चुकी है. इस हमले को अंजाम देने की खातिर प्रतिबंधित संगठनों ने नए-नए नामों से अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवा लिए हैं. ये तमाम खाते बार गर्ल्स के नाम से खुलवाए गए हैं और ये खाते न सिर्फ़ भारत, बल्कि पाकिस्तान में भी खुलवाए गए हैं. पाकिस्तान के गुप्तचर विभाग ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि उन खातों में देश और विदेश से रक़म का स्थानांतरण हो रहा है. ये वे प्रतिबंधित संगठन हैं, जो पिछले काफ़ी समय से सुरक्षाबलों की कार्रवाई की वजह से कमज़ोर हो गए थे. इनमें से कुछ ऐसे भी संगठन हैं, जो ताज़ा चरमपंथी कार्रवाइयों में लिप्त रहे हैं और अब कल्याणकारी कामों में व्यस्त हैं. रकम के स्थानांतरण की वजह से ये प्रतिबंधित संगठन फिर से सक्रिय हो रहे हैं. गृह मंत्रालय के मुताबिक़, सात प्रतिबंधित संगठनों ने बैंकों में बार गर्ल्स के नाम से खाते खुलवाए हैं. इन संगठनों में जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-ए इस्लामी, मिल्लत-ए-इस्लामिया पाकिस्तान, ग़ाज़ी फ़ोर्स, हिज़बुत्तहरीर, जमीयत-उल-फ़ुरक़ान और ख़ैरुन निशा इंटरनेशनल ट्रस्ट शामिल हैं. पाकिस्तानी सरकार ने भी ऐसे लगभग 24 संगठनों के बैंक खातों पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिनमें लश्करे तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, सिपाह साहेबा पाकिस्तान और लश्करे झंगवी शामिल हैं.

ख़ुफ़िया एजेंसियों की रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की गई है कि इन संगठनों के लोगों ने अपने और दूसरे लोगों के नामों से देशी और विदेशी मुद्रा में बैंक खाते खुलवा कर उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. इनमें कुछ ऐसी बार बालाएं भी शामिल हैं, जो पहले से ही दाऊद के गिरोह के लिए पैसा वसूली और बैंक खातों के संचालन का काम करती रही हैं. हालांकि गृहमंत्री पी चिदंबरम की दलील है कि आतंकी संगठनों से संबंधित या शक के दायरे में आए इन खातों को पहले ही बंद किया जा चुका है और इन पर पैनी नज़र रखी जा रही है. हैरानी की बात यह है कि सरकार की सतर्कता के बावजूद नए संदिग्ध खाते खोले जा रहे हैं और उनमें विदेशी धन की आमदरफ्त भी जारी है. इन बैंक खातों में आ रही बेतहाशा रकम की वजह से प्रतिबंधित संगठन एक बार फिर एकजुट होकर सक्रिय हो रहे हैं. हालांकि संघीय जांच एजेंसी ने उन बैंक खातों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है, जिनकी ख़ुफ़िया एजेंसियों की रिपोर्ट में निशानदेही की गई है. ख़ासकर मुंबई के ग्रांट रोड, चरनी रोड, कालबादेवी, ओपरा हाउस और विरार में स्थित बैंकों पर ख़ुफ़िया विभाग की पैनी नज़र है. पहले भी महाराष्ट्र एटीएस ने इन्हीं इलाक़ों में चलने वाले अग्रणी बैंकों पर छापेमारी कर पैंसठ सौ करोड़ के हवाला कारोबार का भंडाफोड़ किया है. बहरहाल, सारी चौकसी और घेरेबंदी के बावजूद आतंकी संगठन हिंदुस्तान की सरज़मीं पर दहशत फैलाने के लिए रोज नए तरीक़े तो ईजाद कर ही रहे हैं, अब यह बार गर्ल्स का नया जाल भी ख़ुफ़िया एजेंसियों और पुलिस के लिए पहेली साबित हो रहा है.

ruby@chauthiduniya.com

"मेरा बचत खाता
मेरी पसंद के साथ."

आज ही खोलें और ढेरों लाभ उठायें*

• एस एम एस अलर्ट • 25000 रुपये तक के बाहरी चेकों का तुरंत भुगतान
• आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से निधि अंतरण • दैनिक राशि के आधार पर ब्याज देय

सेविंग बैंक अकाउण्ट
- परिचालन में आसानी कोई छुपी लागत नहीं
- शून्य बैलेन्स सुविधा
- नामांकन के लिए प्रावधान

सुपर सेविंग बैंक अकाउण्ट
- निःशुल्क आटो / रिवर्स स्वीप
- ब्याज का तिमाही भुगतान
- सामान्य बचत खाते की तुलना में अधिक प्रतिफल

बड़ौदा सेलरी एडवांटेज सेविंग अकाउण्ट
- 1 लाख रुपये तक ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ – वेतन खातों में
- बचत बैंक के अनुसार जमा राशि पर ब्याज
- खाते में न्यूनतम बैलेंस जरूरी नहीं

*शर्तें लागू

इंटरनेट बैंकिंग | मोबाइल बैंकिंग | एटीएम बैंकिंग | किसी भी शाखा से बैंकिंग

BARODA next
STATE-OF-THE-ART. STRAIGHT FROM THE HEART.
कांटैक्ट सेंटर – 1800 22 33 44
1800 102 44 55
www.bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

Brand Equity MOST TRUSTED BRANDS 2011 – BOI IS THE MOST TRUSTED SERVICE BRAND NO. 1 AMONG ALL NATIONALISED BANKS AS PER ET/NielsenSurvey 2011

बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमापूँजी

अपने वेतन से अधिकतम
प्रतिफल प्राप्त करने का बहुत ही बढ़िया अवसर

BOI Salary Plus

मुफ्त 24 डीडी — वर्ष में अधिकतम ₹ 50,000/- प्रत्येक के 24 डीडी/पीएसआई मुफ्त
मुफ्त 100 पन्ने — प्रति वर्ष मुफ्त में 100 चेक पन्ने
मुफ्त बीमा — ₹ 2 लाख तक का दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर
शून्य शेष राशि — कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं
कोई एएमसी नहीं डीमेट खाता — प्रथम वित्तीय वर्ष हेतु कोई एएमसी नहीं
50% की छूट — आवास ऋण और ऑटो ऋण के लिए प्रोसेसिंग फीस पर

*शर्तें लागू

अन्तर्निहित* ओवरड्राफ्ट सुविधा | मुफ्त एनईएफटी/आरटीजीएस नेट बैंकिंग के माध्यम से | मुफ्त मोबाइल बैंकिंग (आईएमपीएस) मुफ्त इन्टरनेट बैंकिंग | मुफ्त उपयोगिता बिलों का भुगतान

अन्य मुख्य विशेषताएं
- आवास ऋण एवं ऑटोफिन (वाहन ऋण) पर न्यूनतम बेस रेट के अध्यधीन 0.25% प्रतिवर्ष के समकक्ष ब्याज दर की दर में रियायत.
- सभी कर्मचारियों को मुफ्त एटीएम सह इन्टरनेशनल डेबिट कार्ड और उनको मुफ्त में प्लेटिनियम डेबिट कार्ड जिनका निवल वेतन (नेट सेलरी) ₹25000/- और इससे अधिक है अथवा जिनका अपने वेतन खाते में औसत तिमाही शेष (एक्यूबी) न्यूनतम ₹1 लाख है।
- सभी कर्मचारियों को मुफ्त गोल्ड क्रेडिट कार्ड और उन कर्मचारियों को मुफ्त गोल्ड इन्टरनेशनल क्रेडिट कार्ड जिनका निवल वेतन (नेट सेलरी) ₹25000/- और इससे अधिक है.
- भारत में इन्टरनेशनल डेबिट कार्ड के लिए 5 संव्यवहार प्रतिमाह (आरबीआई के निर्देशानुसार) तक किसी भी एटीएम में मुफ्त पहुँच (एक्सेस) तथा अन्य एटीएमों पर डेबिट कार्ड के प्रयोग के लिए प्लेटिनियम डेबिट कार्ड हेतु शून्य प्रभार (निल चार्जिज).

अधिक जानकारी के लिए www.bankofindia.co.in पर जाएं अथवा 022-40919191 पर संपर्क करें.

दिल्ली में बुनकरों ने इतनी बड़ी संख्या में पहुंच कर आवाज़ उठाने का प्रयास ज़रूर किया. न्याय के लिए गुहार अगर राजघाट से लगाई जाए तो उसके मायने कुछ और होते हैं, लेकिन उन मायनों को समझना ज़रूरी है.

कांग्रेस का मिशन गुजरात और मीडिया का खेल

डॉ. कमर तबरेज़

उत्तर प्रदेश में छठे और सातवें चरण का मतदान बाक़ी था, तभी नेशनल मीडिया से जुड़े पत्रकारों एवं संवाददाताओं ने एक तरह से जैसे गुजरात पर हल्ला बोल दिया. बहाना बनाया गया कि गुजरात दंगों के दस वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए देश को इस दंगे की सही तस्वीर दिखानी है, दंगा पीड़ितों के दु:ख-दर्द को पूरे देश के साथ बांटना है. लेकिन क्या इसका सच्चाई से भी कुछ लेना-देना था? शायद नहीं, क्योंकि पहले भी गुजरात दंगों के साल पूरे होते रहे हैं. अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को दंगा पीड़ितों के प्रति अपनी हमदर्दी दिखानी ही थी तो उन्हें ऐसा हर साल करना चाहिए था. मीडिया की तरफ़ से ऐसा पांच साल या आठ साल पूरा होने पर क्यों नहीं किया गया, आख़िर दस साल ही पूरा होना उसके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? अगर हम गुजरात पर मीडिया के इस धावे को उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़कर देखें तो बात पूरी तरह साफ़ हो जाती है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के छठे और सातवें चरण के मतदान में बीते 28 फरवरी और 3 मार्च को जिन-जिन क्षेत्रों में वोट डाले गए, वे मुस्लिम बाहुल्य इलाक़े थे, जैसे सहारनपुर, देवबंद, रामपुर, शामली, मुज़फ्फरनगर, खतौली, किठोर, मेरठ, बुलंद शहर, अलीगढ़, नजीबाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत एवं लखीमपुर आदि. ये वे इलाक़े हैं, जहां के मुसलमान इतने बेवकूफ भी नहीं हैं, जितना राजनीतिक दल उन्हें समझते हैं. यहां के मुसलमान शिक्षित हैं, सियासी सूझ-बूझ रखते हैं. उनकी इसी राजनीतिक चेतना ने उन सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दीं, जो उनके वोटों पर अपना पूरा हक़ जमाने की कोशिश कर रही थीं.

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो जैसे मुस्लिम वोटों का स्वयं को अकेला ठेकेदार समझ लिया था, लेकिन मुसलमानों की गहरी ख़ामोशी ने उन्हें भी बेचैन कर दिया. इन दोनों पार्टियों ने जब यह देखा कि मुसलमानों को रिझाने के लिए किए गए वायदों का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और वे इसे एक धोखा समझने लगे हैं तो इन पार्टियों ने दूसरे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए. गुजरात में देश के लगभग सभी न्यूज़ चैनलों के एडिटरों और रिपोर्टरों का इकट्ठा होना कांग्रेस की तरफ़ से इन्हीं मुसलमानों को अपने पाले में करने की चाल का एक हिस्सा था. पिछले अनुभव हमें बताते हैं कि कांग्रेस ने अधिकतर मुसलमानों को डरा-धमका कर उनका वोट हासिल करने की कोशिश की. पहले जो सांप्रदायिक दंगे होते थे, वे भी वोट बैंक की इसी गंदी साज़िश का एक हिस्सा हुआ करते थे. बाद में जब देश के बहुसंख्यक समुदाय को इस बात का एहसास हुआ कि राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकते हैं, तो उन्होंने भी ऐसी पार्टियों की गंदी चाल में फंसने से स्वयं को बचाना शुरू कर दिया. आज अगर देश में ऐसे दंगे नहीं होते तो इसका श्रेय देश की हिंदू बिरादरी को भी जाता है. ऐसे में कांग्रेस, भाजपा या किसी भी दूसरी पार्टी के बहकावे में आकर अगर इस देश का मीडिया अवाम के पुराने जख्मों को कुरेदने या सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिशों में लगा हुआ है तो हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है.

क्या आज राजदीप सरदेसाई से यह सवाल नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने 2002 में गोधरा में मारे गए लोगों के शव दिखाकर गुजरात दंगे की आग में घी डालने का काम क्यों किया था. अपने इस कारनामे से अगर वह भी फसाद को भड़काने में शरीक थे तो फिर आज गुजरात जाकर दंगा पीड़ितों के साथ आंसू बहाते क्यों दिखाई दे रहे हैं. ऐसे ही सवाल दूसरे न्यूज़ चैनलों के एडिटरों से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आज मीडिया अपना गौरव खोता जा रहा है. वह भी सियासी बाज़ीगरों के हाथों का खिलौना बनने लगा है. शायद इसीलिए पीसीआई के चेयरमैन मार्कंडेय काटजू ने इलेट्रॉनिक मीडिया के लिए सेल्फ रेगुलेशन की बात कही थी, जिसका सबसे अधिक विरोध राजदीप सरदेसाई ने किया था. पैसा कमाने के चक्कर में न्यूज़ चैनलों के एडिटर सरकारों के हाथ की कठपुतली बनते जा रहे हैं. वे उन चीजों को नहीं दिखाते, जिनका संबंध मुल्क की आम जनता से होता है, बल्कि वे केवल उन्हीं चीजों को फोकस करते हैं, जिनसे सियासी दलों की आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं. वे आम लोगों पर होने वाले पुलिसिया अत्याचार या पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार को नहीं दिखाते हैं, बल्कि पुलिस द्वारा बोले गए झूठ का ही प्रचार करते रहते हैं. उन्होंने कभी पुलिस से पलट कर यह सवाल नहीं किया कि उसकी कहानी में सच्चाई कितनी है. अगर मीडिया अपनी सही भूमिका निभा रहा होता तो उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान टीवी चैनलों पर जनता की समस्याएं देखने-समझने को मिलतीं. यह देखने को मिलता कि पिछली सरकार ने कितने अच्छे काम किए हैं और कितने ग़लत. यह देखने को मिलता कि कहां-कहां सड़कें टूटी हुई हैं, कहां पर पुल बनाने की ज़रूरत है, कहां पर सूखे का मसला अब तक हल नहीं हो पाया है, बिजली-पानी का इंतज़ाम कितना है, कितने लोगों को सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुंचा है और कौन लोग अभी भी विकास की इन धाराओं से वंचित हैं. सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश का मीडिया राजनीतिज्ञों को इन समस्याओं का समाधान बताता, अपने पैनल डिस्कशन में विशेषज्ञों को बुलाकर इन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता और फिर जनता को बताता कि नेताओं को इन मुद्दों पर कैसे घेरना है, लेकिन लगभग महीने भर चलने वाले चुनाव में ऐसा कहीं नहीं देखा गया.

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं. दिसंबर तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव कराए जाने की उम्मीद है. कांग्रेस ने बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी काफी धूल फांकी. राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए रात-दिन एक कर दिया, लेकिन उनकी मेहनत का कोई अच्छा फल उन्हें नहीं मिला. अब उनकी नज़र गुजरात पर है, इसलिए मीडिया को वहां पहले से कांग्रेस के लिए माहौल बनाने की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है. कांग्रेस राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहती है. इसलिए उनकी मां सोनिया गांधी भी बेटे के राजनीतिक प्रशिक्षण में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं. यह एक अच्छी सोच है. हम सभी चाहते हैं कि आगे जब भी कोई प्रधानमंत्री बने तो उसे मुल्क के करोड़ों ग़रीबों और मज़दूरों के बारे में सही जानकारी हो. वह जनता की समस्याओं से वाक़िफ़ हो, ताकि संसद में जब कोई नया क़ानून बनाया जाए तो वह उसमें इन ग़रीब मज़दूर-किसानों का भी ख्याल रखे, उन्हें अनदेखा न करे, जैसा कि वर्तमान यूपीए सरकार कर रही है.

Tabrez@chauthiduniya.com

झीनी-झीनी बीनी नहीं, फटी चदरिया

बुनकर! सिर्फ़ एक पेशा नहीं, बल्कि प्रतीक भारतीयता का, मिट्टी की सोंधी महक का. स्वतंत्रता सेनानियों ने करघा के आसरे क्रांति का ख्वाब देखा और स्वतंत्रता प्राप्ति की तरफ़ अग्रसर हुए. स्वतंत्र तो हम हुए, परंतु करघा दम तोड़ता गया. कपास से कपड़े तक के सफर में करघे पर ज़िंदगियां दम तोड़ती नज़र आती हैं. सिलसिला बदस्तूर जारी है. विकास और आधुनिकता की अंधी दौड़ के चलते हमने करघा, बुनकरों और खादी को लगभग बिसार दिया है. शायद यही वजह थी कि पिछले दिनों दिल्ली की गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा कस्तूरबा गांधी के 68वें निर्वाण दिवस के मौक़े पर आयोजित करघा यज्ञ के दौरान मंच से संबोधित करती महिला को वहां उपस्थित लोगों से अपील करनी पड़ी कि वे अपने स्थानों पर बैठे रहें और चर्चा को ध्यान से सुनें.

विषय था, बुनकरों के समक्ष चुनौतियां और समाधान. वहां खाली पड़ी कुर्सियां बता रही थीं कि आधुनिकता के फेर में हम परंपराओं को भूल गए हैं, अपनी संस्कृति से मुंह मोड़ कर उस ग्लोबल कल्चर की तरफ़ बढ़ गए हैं, जहां स्मार्ट वर्क की कसौटी पर मेहनती हाथों को सदैव मात खानी पड़ती है. खादी को महंगा बताकर नज़रअंदाज करना आदत है हमारी, लेकिन जब नज़र चाइनीज कपड़ों पर जाती है तो फैशन के इस दौर में पैसा कोई महत्व नहीं रखता. दरअसल, जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो जवाबी कार्रवाई के तौर पर कुछ संस्थाएं अतीत की तरफ़ लौटती हैं और याद दिलाती हैं हमारा गौरवशाली इतिहास, जिसे हम अकस्मात भूलते जा रहे हैं. यादों को ताज़ा करने के लिए जब पहुंचते हैं ऐसे मंचों पर, तो ज़्यादा झेल नहीं पाते. इसीलिए मंच से आवाज़ आती है, बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए, हम अपनी संस्कृति और लाखों बुनकरों का दर्द बयां कर रहे हैं.

गांधी जी ने कहा था कि उत्पादन आम लोगों द्वारा किया जाए, जिससे समाज के पिछड़े लोग भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें. 25 लाख हैंडलूम देश भर में हैं, जिनमें 40 से 50 लाख लोग दो वक़्त की रोटी का जुगाड़ करने की जद्दोजहद में अपना पूरा दिन सूत, रेशम और चरखे के बीच बिता देते हैं. वे छोड़ देना चाहते हैं इस काम को, लेकिन सांस्कृतिक और परिवेशिक मजबूरियों के साए में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन तो सुनहरी सुबह आएगी. चरखा घूमने के साथ दिनचर्या शुरू होती है और सूरज ढलने तक चरखा ही हाथ में रहता है. अनुमान के अनुसार, हथकरघा उद्योग से जुड़े 60 फ़ीसदी लोग ग़रीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के अंतर्गत आते हैं. बड़े जोर-शोर से प्रचार किया जाता है कि खादी हमारी धरोहर है, संस्कृति है, परंतु अगर किसी संस्कृति और धरोहर को संजोने में बहुसंख्यक वर्ग बर्बाद हो जाए तो ऐसी संस्कृति-धरोहर के पतन में समय नहीं लगता है. बुनकर समाज समस्याओं का एक पूरा पहाड़ लिए खड़ा है. वह चाहे सूत या धागे की अनुपलब्धता का मामला हो या मूलभूत संसाधनों की कमी का, बुनकरों को हर तरफ अनगिनत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. क़र्ज़ के तले दबे बुनकर दिन भर की मेहनत के बाद इतना ही कमा पाते हैं कि वे केवल दो वक़्त की रोटी खा सकें. क़र्ज़ अदायगी और सामाजिक कर्मकांडों का पालन भी ज़रूरी है. स्रोत एक है, परंतु ज़िम्मेदारियां अनेक हैं. रोशनी के अभाव में डिजाइन का फेर बुनकरों की कई दिनों की मेहनत पर पानी फेर सकता है. सबसे बड़ी चिंता खादी और हथकरघे से बने अन्य उत्पादों के प्रति लोगों का मोह भंग होना है. दिल्ली में जुटे इन 600 बुनकरों में किन्हीं चार को चुन लीजिए और उनके दिल का हाल जानिए. सबकी समस्या एक सी नज़र आती है. बिहार के रक्सौल की किशोरी देवी 1700 से 1800 रुपये महीना कमा पाती हैं. उनके पति भी यही काम करते हैं यानी हद से हद 4000 रुपये महीना. हरियाणा के कुरूक्षेत्र ज़िले के लियाकत अपना दर्द बयां करते-करते सिसकने लगते हैं. वह कहते हैं, दिल्ली आए हैं, ताकि अपनी आवाज़ और मजबूरियां नेताओं एवं कथित समाजसेवकों को नज़दीक से सुना सकें. पावरलूम ने हैंडलूम पर आधिपत्य जमा लिया है. यह कहें कि मशीनों की ग्रीस के आगे बुनकरों का पसीना कोई अहमियत नहीं रखता. हैंडलूम से बनने वाले उत्पाद पावरलूम की अपेक्षा अधिक समय में तैयार होते हैं. उद्योगपतियों की तिजोरियों में तो धन इकट्ठा होता जा रहा है, मगर बुनकर शाम की रोटी के लिए धागों में उलझा हुआ है. करोड़ों के राहत पैकेजों के सहारे बुनकरों की स्थिति मज़बूत करने के बारे में विचार किया जाता है, लेकिन यह भी ग़ौरतलब है कि बुनकर राजनीतिक बिसात पर मोहरों की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं. पैकेज के पैसों और सुविधाओं का सही आवंटन न होना समस्या को गंभीर बना रहा है. बजट में 3000 करोड़ और कुछ महीनों पहले क़रीब सवा 6 हज़ार करोड़ रुपये के राहत पैकेजों की घोषणा ने बुनकरों की आंखों में रोशनी तो जगाई, मगर अब वह अंधेरे में बदलती जा रही है, क्योंकि उक्त पैकेज अभी तक सिर्फ़ काग़ज़ी साबित हुए हैं. वाराणसी में हाल में बुनकरों की सही संख्या जानने के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ, मगर वह भी चुनाव आचार संहिता के कारण काग़ज़ों में दबा रह गया. बुनकरों में मुसलमानों की अच्छी-खासी संख्या है, जिन्हें राजनीतिक पार्टियां नज़रअंदाज नहीं कर सकतीं. इसलिए बुनकरों के विकास की बात उठती तो है, मगर राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए. ज़मीनी स्तर पर बुनकरों की स्थिति में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता. बुनकरों के पास अपने उत्पाद बेचने के लिए कोई बाज़ार न होना भी बड़ी समस्या है. बुनकर अपना उत्पाद साहूकारों को बेचते हैं और औने-पौने दाम पाते हैं, मगर साहूकार उस उत्पाद के सहारे चांदी काटता है. बुनकरों के लिए मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सरकारी प्रयासों को बट्टा लग रहा है, वहीं पैकेजों का सही वितरण न होने के कारण भ्रष्टाचार में भी बढ़ोत्तरी हो रही है.

ख़ैर दिल्ली में बुनकरों ने इतनी बड़ी संख्या में पहुंच कर आवाज़ उठाने का प्रयास ज़रूर किया. न्याय के लिए गुहार अगर राजघाट से लगाई जाए तो उसके मायने कुछ और होते हैं, लेकिन उन मायनों को समझना ज़रूरी है. राहत और पैकेज दोनों शब्दों के मायने अलग-अलग हैं. 2007 में 25 हज़ार भूमिहीन श्रमिकों का जत्था राजघाट पहुंचा था. उनकी मांग थी कि भूमि एवं आजीविका संबंधी विवादों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय भूमि प्राधिकरण, फास्ट ट्रैक अदालतों और सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत हो. उनके क़दम ताल ने उस समय संसद को हिला दिया था. सरकारी आश्वासन भी मिला था, परंतु वह दम तोड़ चुका है. अब फिर एक आग जली है, हल्ला बोल दिया गया है और हथियार गांधीवादी तरीक़ा है. देखते हैं, बुनकर आज़ादी पाता है या नहीं!

अमित कुमार
feedback@chauthiduniya.com

पंद्रह मिनट तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत कुलपति डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने प्राचार्य एवं छात्रों को समझ-बुझाकर किया. हालांकि इससे काटजू को एक बार फिर बोलने का मौक़ा मिल गया.

काटजू का बयान और नातीश सरकार

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाने के बाद बिहार में जंग छिड़ गई है. सत्ता पक्ष ख़ुद को बचाने में लगा है, वहीं विपक्ष सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने के प्रयास कर रहा है. काटजू ने भी कह दिया है कि वह किसी विवाद से डरने वाले नहीं हैं. अगर मीडिया की स्वतंत्रता के हनन के सबूत मिलेंगे तो कार्रवाई ज़रूर होगी. जस्टिस काटजू ने जो बात कही, वह चौथी दुनिया अप्रैल 2010 में ही छाप चुका है. आपका यह अख़बार बिहार का अकेला अखबार है, जो सरकार की गलतियों को लगातार उजागर करता रहा है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि सरकार की तरफ से न हमें कभी धमकाने की कोशिश हुई और न किसी ने तंग किया.

सरोज सिंह

मेरे ख़िलाफ़ लिखना मना है और सुशासन का सच, चौथी दुनिया में प्रकाशित इन दो आलेखों में जिस सच्चाई को सामने लाया गया था, वही बात मार्कण्डेय काटजू ने की. देश भर में बिहार के विकास की सच्चाई पर एक नई बहस छिड़ गई है. बिहार में सत्ता पक्ष के निशाने पर मार्कण्डेय काटजू हैं और विपक्ष के निशाने पर सत्ता पक्ष. चौथी दुनिया प्रमुखता के साथ यह बात प्रकाशित करता रहा है कि बिहार में प्रेस पर अघोषित पाबंदी है. मीडिया में वही ख़बर प्रकाशित-प्रसारित हो रही है, जिसे प्रकाशित-प्रसारित कराने की मंशा राज्य सरकार रखती है. चौथी दुनिया प्रदेश एवं देश को बता चुका है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में नीतीश सरकार द्वारा विभिन्न समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और टीवी चैनलों को अट्ठाइस करोड़ पंद्रह लाख बानवे हज़ार एक सौ चौवन रुपये के विज्ञापन वितरित किए गए. वैसे सरकार द्वारा अख़बारों को विज्ञापन देना कोई नई बात नहीं है. इसका तो कानूनी प्रावधान है, लेकिन समस्या यह है कि अगर अख़बार के रिपोर्टर और संपादक इसके बदले में सरकार के सूचना विभाग की तरह काम करने लग जाएं तो दोष किसका है. जस्टिस काटजू प्रेस काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्हें प्रेस की कारगुजारियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है. उन्हें तो ऐसे अख़बारों पर नज़र रखनी चाहिए, जो बिना किसी के कहे सरकार के चारण बन जाते हैं. चौथी दुनिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार की नीतियों एवं गलतियों को लगातार उजागर करता रहा है. इसमें भी कोई शक नहीं है कि आपका यह अखबार बिहार का अकेला अखबार है, जिसने पत्रकारिता का धर्म निभाया और सरकार की नीतियां हों या बिहार के मुद्दे, यह हमेशा एक आलोचक की भूमिका में रहा है, लेकिन जिस अंदाज में जस्टिस काटजू ने बिहार सरकार की आलोचना की, वह भी सच से दूर है.

अब काटजू ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि बिहार में प्रेस स्वतंत्र नहीं है. अगर किसी पत्रकार ने सरकार, मंत्री या अधिकारी के ख़िलाफ़ कोई ख़बर लिख दी तो उसे नौकरी से निकलवा दिया जाता है. पत्रकार अगर रसूख वाला है तो उसे स्थानांतरित करा दिया जाता है. कामकाज की चर्चा करते-करते काटजू नीतीश सरकार की तुलना लालू-राबड़ी के शासनकाल से कर बैठे. उन्होंने कहा कि लालू-राबड़ी के शासनकाल में लापरवाह और भ्रष्ट पदाधिकारी मीडिया की नज़रों से बच नहीं पाते थे. समझने वाली बात यह है कि अगर किसी संवाददाता पर कार्रवाई होती है तो इसके लिए दोषी कौन है. सरकार तो किसी संवाददाता को हटा नहीं सकती है, इसलिए जस्टिस काटजू को ऐसे संपादकों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो किसी सही रिपोर्ट के लिए संवाददाताओं का स्थानांतरण कर देते हैं.

पटना विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में काटजू द्वारा नीतीश सरकार के कामकाज पर की गई टिप्पणी सत्ता पक्ष को इतनी नागवार गुजरी कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उन्हें राजनीति में आने की चुनौती दे दी. मोदी ने कहा कि काटजू को विवादास्पद बयान देने की आदत पड़ गई है. बिहार में मीडिया पूरी तरह स्वतंत्र है या नहीं, यह तो पत्रकार ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन लालू राज की तुलना वर्तमान सरकार से करना किसी भी स्थिति में सही नहीं है. नीतीश कुमार ने भी मीडिया पर किसी तरह की सेंसरशिप की बात ख़ारिज कर दी. काटजू सत्ता पक्ष के नेताओं से इस कदर खीज गए कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें विवाद की चिंता नहीं है. बिहार में अगर मीडिया की स्वतंत्रता हनन के सबूत मिलेंगे तो निश्चित कार्रवाई होगी. प्रेस की स्वतंत्रता संविधान प्रदत्त है, उसे बाधित करने वाले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते.

बिहार में कई दिनों बाद कोई मामला राजनीतिक तौर पर इतना चर्चित हुआ है. टीवी में काटजू के बयान को क्या दिखाया गया, बिहार के राजनीतिज्ञों ने बयानों की झड़ी लगा दी. राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार में प्रेस की आज़ादी छिन गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ जारी बयान डस्टबिन में डाल दिए जाते हैं. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, सांसद राम कृपाल यादव, अशोक सिंह, प्रवक्ता रामानुज प्रसाद, महासचिव एजाज अहमद एवं रणधीर यादव ने कहा कि राज्य सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए मसले को दफनाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है. लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार में मीडिया पर नीतीश सरकार के दबाव को काटजू ने सामने लाकर रख दिया. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रभात कुमार सिंह, डॉक्टर विनोद शर्मा, एच के वर्मा एवं मोतीलाल शर्मा ने न्यायमूर्ति काटजू के बयान को बहुत संवेदनशील और गंभीर बताते हुए इसकी जांच कराने की मांग की. पूर्व एमएलसी पी के सिन्हा का मानना है कि नीतीश कुमार तानाशाह की तरह राज्य चला रहे हैं. ऐसे में प्रेस के स्वतंत्र रहने का सवाल ही कहां पैदा होता है. पूर्व एमएलसी प्रेम कुमार मणि मानते हैं कि केवल प्रेस ही नहीं, यहां तो लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करने की भी छूट नहीं है. भाकपा (माले) के राज्य सचिव नंदकिशोर प्रसाद ने कहा कि नीतीश सरकार ने सरकारी विज्ञापनों के बारे में एक ग़ज़ब नीति बनाकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता पर विपरीत प्रभाव डाला है. सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि काटजू के बयान से स्पष्ट है कि नीतीश सरकार जो चाहती है, वही बातें मीडिया द्वारा जनता के बीच पहुंचाई जाती हैं.

दूसरी तरफ़ जदयू सांसद शिवानंद तिवारी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कटाजू मीडिया में बने रहने की कला में निपुण हो गए हैं. अदालत में वह अपराधियों को लैंपपोस्ट से लटकाने संबंधी बयान देकर सुर्ख़ियों में रहते थे. बहरहाल, इस गंभीर मसले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है.

राजनीति का नहीं, यह चिंतन का विषय है

न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू ने कोई नई बात नहीं कही है. यह सभी को मालूम है कि बिहार सरकार ने अखबारों, पत्रिकाओं एवं टीवी चैनलों पर विज्ञापनों की बरसात करके उनके मुंह पर ताला लगा दिया है. मीडिया ने अपने मान-सम्मान, महत्व और गरिमा की बलि खुद चढ़ाई है, सरकारी प्रलोभनों के जाल में फंसकर. अगर मीडिया चाहे तो कोई भी सरकार उस पर बेजा दबाव नहीं बना सकती. मीडिया चाहे तो जन सरोकारों से जुड़ी खबरों को हर कीमत पर सबके सामने ला सकता है, आत्मबल होना चाहिए सरकारी खैरात ठुकराने और जनहित में सरकार से भिड़ जाने का. प्रत्यक्ष उदाहरण है चौथी दुनिया, जिसने मेरे खिलाफ लिखना मना है और सुशासन का सच जैसी कवर स्टोरियां प्रकाशित कीं, डंके की चोट पर. बिहार में चौथी दुनिया का नाम किसी के लिए अनजाना नहीं है. उक्त कवर स्टोरियों का एक-एक शब्द बिहार की अव्यवस्था पर हथौड़े जैसा था, बावजूद इसके न तो राज्य सरकार की ओर से कोई ऐतराज जताया गया, न कोई शिकायत की गई और न कोई धमकी दी गई.

दरअसल, राज्य में मीडिया संस्थानों के संचालक-संपादक अपने मालिकानों के हितों के पोषण के लिए इतने हैरान-परेशान हैं कि वे जनता के प्रति अपने कर्तव्य जानबूझ कर भूल गए हैं. मीडियाकर्मियों को सरकारी सुख-सुविधा-संरक्षण इस कदर भाने लगे हैं कि उन्हें यह याद नहीं रहा कि उनका असल धर्म क्या है, वे पत्रकार आखिर क्यों कहलाते हैं? जब आप खुद दरबारी, चारण, भांड बनने में अपनी शान समझने लगेंगे तो भला व्यवस्था को क्या परेशानी? वह तो चाहेगी ही कि कोई उसकी कमियों-खामियों की तरफ भूलकर भी न देखे और देख भी ले तो बोले नहीं, किसी अन्य की जानकारी में न आए. कुसूर तो आपका है कि आपने व्यवस्था द्वारा बिछाए गए जाल में फंसना हंसते-हंसते स्वीकार कर लिया. सरकारी खैरात के प्रति परहेज नहीं बरता. जब आप नियम विरुद्ध विज्ञापनों की मलाई खाएंगे तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे कैसे? बिका हुआ सही, लेकिन जमीर भी कोई चीज है! होना तो यह चाहिए कि बतौर प्रेस काउंसिल के मुखिया, न्यायमूर्ति काटजू कोई ऐसी व्यवस्था लागू करें, आचार संहिता बनाएं कि मीडिया किसी भी तरह के दबाव में आने से बचे, प्रलोभनों से बचे, जन सरोकारों की खबरों को दाबने से बचे, सरकारी प्रवक्ता बनने से बचे. सच को सच कहे, झूठ बोलने से बचे. मीडिया की स्वतंत्रता एक गंभीर विषय है, इस पर किसी भी पक्ष द्वारा राजनीति की कोशिश नहीं होनी चाहिए. मीडिया पर अगर सरकार का दबाव है, राजनीतिज्ञों का दबाव है, अपराधियों-माफियाओं का दबाव है या किसी और तरह का दबाव है तो उसके मूल में जाने की जरूरत है, वजह खोजने की जरूरत है और फिर उसके निराकरण की जरूरत है. यह मंचों पर खीझने, चीखने-चिल्लाने का विषय नहीं है, बल्कि चिंतन-मंथन का विषय है.

जस्टिस काटजू की धमकी

बिहार में मीडिया स्वतंत्र है या नहीं, यह गंभीर बहस का विषय है, लेकिन पटना के सीनेट हॉल में जन सिद्धांत विज्ञान, जनतंत्र, जीविका और जनता की एकता विषयक सेमिनार के दौरान भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू के बयान से पटना कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लालकेश्वर सिंह भी नाराज़ दिखे. जब जस्टिस काटजू ने कहा कि बिहार में मीडिया पर सेंसर लगा है. काउंसिल की तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा इसकी जांच कराई जाएगी. लालू सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार ने बेहतर क़ानून व्यवस्था क़ायम की है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि लालू प्रसाद के शासनकाल में मीडिया को जितनी स्वतंत्रता थी, उतनी इस सरकार में नहीं है. इतना सुनते ही पटना कॉलेज के प्राचार्य लालकेश्वर सिंह ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया. उन्होंने काटजू पर आरोप लगाया कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी के कहने पर ऐसा बोल रहे हैं. पंद्रह मिनट तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत कुलपति डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने प्राचार्य एवं छात्रों को समझा-बुझाकर किया. हालांकि इससे काटजू को एक बार फिर बोलने का मौक़ा मिल गया. उन्होंने कहा कि इस हंगामे से साबित हो गया कि प्रेस को सरकार के ख़िलाफ़ बोलने या लिखने की इजाज़त नहीं है. प्रेस काउंसिल की धारा-19 में भी मीडिया की आज़ादी पर रोक लगाना क़ानूनन अपराध माना गया है. बिहार में पत्रकारों की क्या हालत है, वह इस हंगामे से प्रमाणित हो गया. काटजू ने लगभग चेताने वाले अंदाज़ में कहा कि महाराष्ट्र में 10 वर्षों के अंदर 800 पत्रकारों पर हमले होने की शिकायत मिलने के बाद वहां के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कारण स्पष्ट करने को कहा गया है.

feedback@chauthiduniya.com

यूपीए सरकार के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में बनाए गए मंत्री समूह (जीओएम) ने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन का समर्थन किया है. उसने भी राजनीतिक चंदे को भ्रष्टाचार का एक प्रमुख स्त्रोत बताया है.

कंपनी बिल-2011

राजनीतिक दलों का दोहरा रवैया

संसद में क़ानून और न्याय मंत्री सलमान ख़ुर्शीद ने भी कहा था कि भ्रष्टाचार को कम करने में स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की अहम भूमिका हो सकती है. यही नहीं, यूथ कांग्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए चुनाव में स्टेट फंडिंग की बात की थी, लेकिन इस बिल में सोनिया गांधी की अपील को भी शामिल नहीं किया गया है. कुछ ऐसा ही विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

14 दिसंबर, 2011 को लोकसभा में एक घटना घटी. डॉ. वीरप्पा मोइली ने दोपहर के बाद कंपनी बिल–2011 लोकसभा में पेश किया. इस बिल में राजनीतिक दलों को कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले धन का प्रावधान है. इस बिल के पेश होने के एक घंटे के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी बोलने के लिए खड़े हुए. उन्होंने कहा कि काला धन प्रमुख तौर पर हमारे चुनाव में मिलने वाले चंदे से जुड़ा हुआ है और इस चुनावी चंदे के स्वरूप में परिवर्तन करके काले धन की समस्या पर बहुत हद तक क़ाबू पाया जा सकता है. यह यूपीए सरकार की दोहरी नीति को उद्घाटित करता है. एक तरफ़ सरकार यह कहती है कि चुनाव में चंदा इकट्ठा करने की प्रक्रिया के कारण काले धन का प्रवाह बढ़ता है, तो दूसरी तरफ़ कंपनी बिल में ऐसा प्रावधान किया जाता है, जिसके कारण कंपनियां अधिक धन राजनीतिक दलों को दे सकें. इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि अब कोई भी ग़ैर सरकारी कंपनी अपने पिछले तीन वित्तीय वर्ष की कुल औसत बचत का 7.5 फ़ीसदी धन राजनीतिक दल या राजनीतिक गतिविधियों में शामिल किसी व्यक्ति को राजनीतिक उद्देश्य के लिए दे सकती हैं. इससे पहले के कंपनी एक्ट 1956 में यह राशि पांच फ़ीसदी तक सीमित की गई थी. सरकार का तर्क है कि वर्तमान समय में राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ रही है जिससे अधिक धन चंदे के रूप में देने की आवश्यकता महसूस होने लगी है. कंपनियां भी अपनी बचत के पांच फ़ीसदी से अधिक धन को चंदे के तौर पर राजनीतिक दलों को देना चाहती हैं. सरकार का यह तर्क कितना उचित है, इसे बताने की ज़रूरत यहां पर नहीं है. एक तरफ़ सरकार को ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए कंपनियां तैयार बैठी हैं, तो दूसरी तरफ़ कंपनियों के सामाजिक उत्तरदायित्व को लेकर उनमें इस बात का संशय है कि कंपनियां अपनी बचत का दो फ़ीसदी हिस्सा भी सामाजिक कार्यों में ख़र्च नहीं कर पाती हैं. सरकार ने कॉर्पोरेट सोशल रिसपोंस्बलिटी (सीएसआर) के तहत यह तय किया है कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का दो फ़ीसदी धन सामाजिक कार्यों में ख़र्च करेगी. इस बिल में जिन सामाजिक कार्यों के बारे में बताया गया है, उनमें भुखमरी और ग़रीबी निवारण, शिक्षा को बढ़ावा देना, लिंग भेद को कम करना तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, एचआईवी तथा मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए काम करना, रोज़गार को बढ़ावा देने वाली व्यवसायिक गुणवत्ता बढ़ाने वाली संस्थाओं का निर्माण करना, पर्यावरणीय समस्याओं को कम करना तथा पर्यावरणीय सुरक्षा को बरक़रार रखना, सामाजिक व्यवसायिक प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री राहत कोष में धन देना या सामाजिक उद्देश्यों से बनाया गया कोई फंड या अनुसूचित जाति–जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक या महिलाओं के विकास के लिए बनाए गए कोष तथा अन्य गतिविधियां जिनका उल्लेख किया गया हो, को शामिल किया गया है. लेकिन कंपनियां इन कार्यों में अपना धन ख़र्च करना नहीं चाहती हैं, लेकिन ये कंपनियां राजनीतिक दलों को ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देना चाहती हैं. आख़िरकार इसका कारण क्या हो सकता है.

राजनीतिक दलों से ये कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहती हैं. अगर वे किसी राजनीतिक दल को चंदा देती हैं तो फिर इस बात की उम्मीद ज़रूर रखेंगी कि जितना धन वे चंदे के तौर पर दे रही हैं, उससे अधिक फ़ायदा चुनाव के बाद इन दलों से उठा सकें. कंपनियां कोई सामाजिक काम तो कर नहीं रही हैं. अगर वे व्यवसाय फ़ायदे के लिए करती हैं तो फिर अपना पैसा उन्हीं क्षेत्रों में ख़र्च करेंगी, जिनसे उन्हें लाभ हो. अगर कोई कंपनी अपना फ़ायदा बढ़ाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाती है तो बिना किसी स्वार्थ के वह अपने इस लाभ का एक बड़ा हिस्सा किसी को क्यों देगी, जबकि देना कोई आवश्यक नहीं है.

ज़ाहिर है, राजनीतिक दलों से ये कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहती हैं. अगर वे किसी राजनीतिक दल को चंदा देती हैं तो फिर इस बात की उम्मीद ज़रूर रखेंगी कि जितना धन वे चंदे के तौर पर दे रही हैं, उससे अधिक फ़ायदा चुनाव के बाद इन दलों से उठा सकें. कंपनियां कोई सामाजिक काम तो कर नहीं रही हैं. अगर वे व्यवसाय फ़ायदे के लिए करती हैं तो फिर अपना पैसा उन्हीं क्षेत्रों में ख़र्च करेंगी, जिनसे उन्हें लाभ हो. अगर कोई कंपनी अपना फ़ायदा बढ़ाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाती है तो बिना किसी स्वार्थ के वह अपने इस लाभ का एक बड़ा हिस्सा किसी को क्यों देगी, जबकि देना कोई आवश्यक नहीं है. इस तरह के चंदे के लिए उस पर दबाव तो बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई क़ानून तो है नहीं कि कंपनियों को राजनीतिक काम करने वाले लोगों को या राजनीतिक दलों को चंदा देना मजबूरी है. कंपनियां इन्हीं राजनीतिक दलों को चंदा देकर तरह-तरह के ग़ैर क़ानूनी काम करती हैं. भोपाल गैस त्रासदी को उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है. इसके पीड़ितों को अभी तक इंसाफ़ नहीं मिला है. आख़िरकार जब यह त्रासदी हुई थी, तो इसके बाद सरकार सोई हुई क्यों रही. इसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि इन कंपनियों से सभी राजनीतिक दलों को काफ़ी धन चंदे के रूप में प्राप्त होता है. इसी तरह के अन्य कई काम कंपनियां सरकार से कराती हैं, जिनमें नियम–क़ानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं. चाहे पर्यावरण के मुद्दे को दरकिनार कर किसी कंपनी को काम करने का ठेका देना हो या फिर दूसरी तरह की सुविधाएं प्राप्त करना.

ऐसा नहीं है कि कंपनी बिल–2011 में राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे के प्रावधान के संबंध में केवल यूपीए सरकार का रुख़ ही विरोधाभासी है. भारतीय जनता पार्टी का रुख़ भी उसी तरह का है. दोनों की कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है. सभी राजनीतिक दल एक तरफ़ तो चुनाव में चंदे को ग़लत क़रार देते हैं, तो दूसरी तरफ़ कॉर्पोरेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का इस बिल में समर्थन करते नज़र आते हैं. यूपीए सरकार की बात करें तो एक तरफ़ तो वह चुनाव में चंदे को राजनीति के लिए ख़तरनाक मानते हैं तो दूसरी तरफ़ कंपनी बिल लाते हैं, जिसमें चंदे की रक़म बढ़ाई जाती है. यूपीए सरकार के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में बनाए गए मंत्री समूह (जीओएम) ने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन का समर्थन किया है. उसने भी राजनीतिक चंदे को भ्रष्टाचार का एक प्रमुख स्त्रोत बताया है. इस जीओएम ने क़ानून मंत्रालय को भी इसके लिए कहा था. क़ानून मंत्रालय ने भी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन का समर्थन किया है. संसद में क़ानून और न्याय मंत्री सलमान ख़ुर्शीद ने भी कहा था कि भ्रष्टाचार को कम करने में स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की अहम भूमिका हो सकती है. यही नहीं यूथ कांग्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए चुनाव में स्टेट फंडिंग की बात की थी, लेकिन इस बिल में सोनिया गांधी की इस अपील को भी शामिल नहीं किया गया है. कुछ ऐसा ही विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है. भाजपा नेता यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में संसदीय समिति ने भी कंपनी बिल के इस प्रावधान का कोई विरोध नहीं किया है, बल्कि इसके पक्ष में ही सिफ़ारिश की है. इस समिति ने जो सिफ़ारिश की है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह कॉर्पोरेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करता है. इसका समर्थन करने से पहले यशवंत सिन्हा शायद भूल गए थे कि वह उस जीओएम के सदस्य थे, जो इंद्रजीत गुप्ता समिति की स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन संबंधी सिफ़ारिश पर विचार करने के लिए बनाया गया था. इस जीओएम की अध्यक्षता लालकृष्ण आडवाणी कर रहे थे. इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के बारे में अपनी रिपोर्ट 14 जनवरी, 1999 को सरकार को सौंपी थी. इसमें इस बात की भी सिफ़ारिश की गई थी कि राजीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले लोगों को सरकार धन नक़दी के रूप में न देकर चुनाव में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों के रूप में दे. 15 जनवरी, 2011 को इंदौर के प्रेस क्लब में पत्रकारों की एक सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के प्रावधान की अपील की थी. इस सभा में भारत के उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मौजूद थे. इस तरह से देखा जाए तो राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का जो प्रावधान इस बिल में किया गया है, उस पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का विचार विरोधाभासी है. एक तरफ़ दोनों दलों के नेता चुनावी चंदे को भ्रष्टाचार और काले धन का साधन मानते हैं, तो दूसरी तरफ़ इस बिल के माध्यम से कंपनियों से अधिक चंदा उगाहने का जुगाड़ कर रहे हैं. उनके इस दोहरे रवैये से तो यही कहा जा सकता है कि कंपनी बिल का मक़सद सरकार और व्यवसायिक घराने के बीच के गठबंधन को और अधिक मज़बूत करना है. अगर इन कंपनियों को राजनीतिक दलों को चंदा देना है और राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए धन चाहिए. ऐसे में राजनीतिक दलों को धन के लिए दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए. स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन को मंज़ूरी देनी चाहिए तथा कंपनियां जो अपने मुनाफ़े का एक हिस्सा राजनीतिक चंदे के रूप में देना चाहती हैं, उसके लिए एक फंड बनाया जाना चाहिए. इस फंड में जो धन इकट्ठा होगा, उसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों या चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को राज्य की तरफ़ से चुनाव में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों के रूप में देना चाहिए. इससे राजनीतिक दलों को चंदा भी मिल जाएगा और कंपनियों को इस बात का पता भी नहीं लगेगा कि उसने किस राजनीतिक दल को चंदा दिया, जिससे वह अपने चंदे के बदले किसी राजनीतिक दल से फ़ायदा न उठा सके. अभी यह बिल पास होना बाक़ी है, लेकिन अगर यह इसी तरह पास हो जाता है तो इस बिल को राजनीति और व्यवसाय के गठबंधन के रूप में देखा जा सकता है.

गोपाल कृष्ण
feedback@chauthiduniya.com

ऊर्जा दक्षता और भारत का भवन निर्माण क्षेत्र

वर्ष 2008 में पहली बार ऐसा हुआ कि विश्व की शहरी आबादी ग्रामीण आबादी से अधिक हो गई. यह प्रवृत्ति पिछले कुछ दशकों में साफ़ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई देने लगी है. प्रक्षेपणों से पता चलता है कि 21वीं सदी के अंत तक विश्व की 80 प्रतिशत आबादी शहरों (जो धरती की सतह का 0.05 प्रतिशत भाग घेरते हैं) में रह रही होगी. दैत्याकार रूप में विशालकाय होते हुए इस शहरी दानव ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी प्राकृतिक इको सिस्टम के लिए अनूठी चुनौतियों के साथ-साथ कई अवसर भी जुटा दिए हैं. परिणामस्वरूप नीति निर्माताओं को नए सिरे से भू-संसाधनों के नियोजन से लेकर व्यापक पारिस्थितिकीय एवं ऊर्जा संबंधी निहितार्थों जैसे विविध विषयों पर विचार करना होगा. ये चुनौतियां हैं, प्रदूषण में कमी लाना, जैव विविधता बढ़ाना, ऊर्जा की सबसे अधिक खपत के समय उसकी मांग एवं लागत का प्रबंधन, ऊष्मा दबाव संबंधी स्वास्थ्य के निहितार्थ, जल और पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति.

त्वरित शहरीकरण से इमारतों के निर्माण की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि होने के कारण अधिकाधिक अवसर भी पैदा हो रहे हैं. यह मांग अभी से भारत में बिजली की कुल खपत की 30 प्रतिशत आंकी गई है. बढ़ते विकास के अनुरूप ही देश के भवन निर्माण क्षेत्र में 2005 से 2050 तक पांच गुना वृद्धि की संभावना है. भारत एक ऐसे अनूठे दोराहे पर खड़ा है, जहां 2030 में विद्यमान रहने वाले दो तिहाई व्यवसायिक और गगनचुंबी आवासीय ढांचे अभी बनने बाक़ी हैं. इमारतों में ऊर्जा दक्षता को सुनिश्चित करते हुए अगले दस वर्षों में जो इमारतें निर्माण की प्रक्रिया में होंगी, वे अगले अनेक दशकों के लिए ऊर्जा और लागत पर होने वाली बचत सुरक्षित रखने के लिए एकल अवसर प्रदान कर रही होंगी. दक्षता पूर्वक निर्माण का महत्व उन तमाम व्यक्तिगत बचतों से कहीं अधिक निर्णायक है, जिनसे मकान मालिक और उनके अंतिम उपयोगकर्ता लाभांवित होते हैं. 2010-11 और 2016-17 के बीच भारत की कुल ऊर्जा संबंधी आवश्यकता 6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ने का अनुमान किया गया, ताकि 9 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षित दर का समर्थन किया जा सके, परंतु सर्वाधिक खपत के दौरान होने वाली कमी और ऊर्जा के आयात पर निर्भरता तथा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा के मूल्य की अस्थिरता के कारण असहाय बने रहने की चुनौतियों का सामना करना होगा. इसके अलावा भारत ग्रीन हाउस की गैसों के उत्सर्जन के क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बनने जा रहा है. इन सभी चुनौतियों को दैत्याकार रूप में बढ़ते भवन निर्माण क्षेत्र की ऊर्जा निगलने वाली प्रकृति को समझते हुए और देश के दीर्घकालीन विकास के नियोजन में ऊर्जा दक्षता को केंद्रीय भाव बनाकर पूरा किया जा सकता है.

वर्तमान नीतिगत परिवेश

वर्तमान नीतिगत परिवेश की शुरुआत से ही ऊर्जा दक्षता का संवर्धन और राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर उसका कार्यान्वयन इसकी सफलता के मुख्य निर्धारक तत्व होंगे. भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (2008) में भवन निर्माण के दक्षता संबंधी उपायों को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए आवश्यक माना गया है. हाल में अनेक राष्ट्रीय मिशनों में भवन निर्माण की दक्षता बढ़ाने पर जोर देने की कवायद शुरू कर दी गई है, जैसे राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन एवं राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन. यह देखना अभी बाक़ी है कि इन प्रयासों के गंभीर कार्यान्वयन से राष्ट्रीय नीति का परिदृश्य कैसे उभरता है. प्रस्थान बिंदु के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि इसका तंत्र बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ताकि गुणवत्ता की अपेक्षा और आग्रह बरक़रार रहे. इसे सुगम बनाने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 2007 में ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण कोड (ईसीबीसी) की शुरुआत की थी. ईसीबीसी ने 100 के डब्ल्यू/120 केवीए के कनेक्टेड लोड के साथ ऊर्जा दक्ष डिज़ाइन और भवनों के निर्माण के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं तय की हैं, जिनमें ऐन्वलप, लाइटिंग, हीटिंग, एयर कंडीशनिंग और विद्युत प्रणाली शामिल है. कोड के अलावा स्वतंत्र दर निर्धारण अर्थात रेटिंग का मानक होना भी आवश्यक है. इस समय इसका प्रबंधन दो निजी भवन निर्माण दर निर्धारण अर्थात रेटिंग प्रणालियों द्वारा किया जा रहा है, ऊर्जा एवं पर्यावरणीय डिज़ाइन का नेतृत्व (एलईईडी) और समन्वित पर्यावास मूल्यांकन के लिए हरित दर निर्धारण (जीआरआईएचए). दोनों को ही ईसीबीसी की अपेक्षाओं में शामिल किया गया है.

ऊर्जा दक्षता की चुनौतियां

इन आरंभिक नीतिगत नियमों के बावजूद व्यापक स्तर पर दक्षता अपनाने में बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं. महत्वपूर्ण चुनौतियों को तीन बड़े भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, सूचना एवं जागरूकता, आर्थिक और संरचनात्मक बाधाएं. ईसीबीसी इस समय स्वैच्छिक है, जिसके कारण अपटेक धीमा रहा है और प्रगति के लिए उसे बाज़ार पर निर्भर रहना पड़ता है, परंतु ऊर्जा दक्षता से होने वाले आर्थिक और अन्य लाभों के बारे में अर्थव्यवस्था संबंधी जानकारी और जागरूकता का अभाव रहा है. अनिवार्य नीतियों के अभाव में दक्षता के संबंध में निवेश करने का निर्णय विकासकर्ताओं, इमारतों के मालिकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं के हाथ में रहा है. इनकी पहुंच दक्षता से होने वाले तमाम लाभों से संबंधित विश्वसनीय सूचनाओं तक नहीं होती. दक्षता संबंधी प्रौद्योगिकियों की अधिक अग्रिम लागत भी होती है, जिनकी वजह से निवेशक अल्पावधि के आर्थिक लाभ पाने के इच्छुक नहीं होते. चूंकि अधिक अपफ्रंट लागत पर लाभ के संबंध में सूचना पाने का कोई सही स्रोत नहीं होता, इसलिए रियल इस्टेट के विकासकर्ता दक्षता के लिए अतिरिक्त बजट शामिल करने के इच्छुक नहीं होते. कारोबारी मामले की जानकारी के अभाव में वित्तीय संस्थाएं उन आकर्षक उत्पादों (यानी दक्षता के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज़) की पेशकश करने से अब तक हिचकती रही हैं, जिन्हें पहली अधिक लागत के बोझ को कम करते हुए निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है. एक बाधा यह है कि जब इमारतों के मालिक ख़र्च करते हैं तो ऊर्जा के कम बिल का लाभ उसकी खपत के बिल का भुगतान करने वाले किराएदार को मिलता है. संरचना की दृष्टि से दक्ष तकनीकी विशेषज्ञता और ऊर्जा दक्षता वाले उत्पादों के विक्रेताओं की कमी के कारण ऊर्जा दक्षता की अर्थव्यवस्था के लिए अपेक्षित योग्य कार्यबल भी विकसित नहीं हो पाया है.

अवसर और सिफ़ारिशें

बाधाओं के निराकरण एवं भवन निर्माण संबंधी बाज़ार के कायाकल्प के लिए सार्वजनिक और निजी स्तर पर निर्णय करने वाले लोगों द्वारा क़दम उठाया जाना अपेक्षित है. ईसीबीसी को अनिवार्य बनाकर ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी नई इमारतों के निर्माण के लिए ऊर्जा के उपयोग के न्यूनतम स्तर पर दक्षता का पालन किया जाए. जहां एक ओर राष्ट्रीय स्तर पर यह कोड अभी भी स्वैच्छिक है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान, उड़ीसा, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं और पश्चिम बंगाल ने 2012 तक अनिवार्य कोड के लिए योजनाएं घोषित करके कम मांग वाले इस अवसर को मान्यता प्रदान कर दी है, लेकिन इन प्रयासों की सफलता तभी मानी जाएगी, जब कोड का अनुपालन सुनिश्चित हो जाएगा. इसे सक्षम बनाने और अपनी विशिष्ट जलवायु की स्थितियों के अनुरूप ईसीबीसी के स्थानीय अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राज्य सरकारें अनुपालन हेतु लाभप्रद परिवेश तैयार कर सकती हैं. वे क्षेत्र की विनियमावली में कोड को शामिल कर सकती हैं, तीसरी पार्टी के सत्यापन के लिए तंत्र विकसित कर सकती हैं और कोड संबंधी तकनीकियों के लिए नगर निगम के अधिकारियों, वास्तुविदों एवं इंजीनियरों को प्रशिक्षित कर सकती हैं. निगरानी और कार्यान्वयन के स्थान पर ढांचा बनाना समुदाय द्वारा दक्ष निर्माण के सफल अपटेक के लिए महत्वपूर्ण है.

इसके समानांतर निजी क्षेत्र भी बाज़ार के नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. भवन निर्माण की मांग के चालकों के रूप में रियल इस्टेट के विकासकर्ताओं का भी अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली दक्षता संबंधी प्रणालियों पर खासा प्रभाव रहता है. चूंकि इस वर्ग के पास दक्ष निर्माण पर होने वाले निवेश के लिए अंतिम वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार रहता है, इसलिए उन अवसरों को दर्शाने की भारी संभावनाएं मौजूद रहती हैं, जो लागत संबंधी बचत, पुनर्भुगतान की अल्पावधि, बढ़े हुए प्रीमियम और कब्ज़े की दरों के ज़रिए भवन निर्माण को आकर्षित करने वाले कारोबारी मामलों से पैदा होती हैं. भूमि के मालिकों एवं किराएदारों के बीच दक्षता संबंधी निवेश की लागत और लाभ से जुड़े हरित पट्टों के संचालन से वित्तीय बाधाएं दूर करने में मदद मिल सकती है. वित्तीय संस्थाओं में ऊर्जा दक्षता की सेवाएं भी उत्पादों के अपने पोर्टफोलियो में शामिल की जा सकती हैं और दक्ष भवन निर्माण के बाज़ार को फैलाने के महत्वपूर्ण अप्रयुक्त अवसरों से लाभ उठाया जा सकता है.

कम कार्बन के भवन निर्माण क्षेत्र की ओर संक्रमण से नई सेवाओं एवं प्रौद्योगिकियों के लिए बाज़ार में तेज़ी आ सकती है और इसके लिए निर्माण की नई लहर की मांग के अनुरूप दक्ष कार्यबल की आवश्यकता होगी. जैसे-जैसे ईसीबीसी के अनुपालन में कड़ाई बढ़ती जाएगी, व्यवसायिक तौर पर उन तमाम मान्यता प्राप्त अन्य पक्षीय सत्यापकों की मांग बढ़ती जाएगी, जो इस क्षेत्र में होने वाली बचत को माप सकेंगे और उन्हें सत्यापित कर सकेंगे. इस भावी मांग को पूरा करने के लिए नए और वर्तमान दोनों ही प्रकार के कार्यबल के स्थान पर ऊर्जा दक्ष पाठ्यक्रम आवश्यक हो जाएगा. इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एवं व्यवसायिक शिक्षा संस्थान ऊर्जा सिमुलेशन और भवन निर्माण प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर सकेंगे और स्वतंत्र लेखा-परीक्षा संगठनों के साथ मिलकर काम कर सकेंगे, जो ईसीबीसी के अनुपालन का सत्यापन करेंगे. इस कुशल हरित कार्यबल के प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद का इस्तेमाल (2022 तक 500 मिलियन कुशल जन बल तैयार करने के लक्ष्य के साथ) एक मंच के रूप में किया जा सकता है. 2035 तक भारत की व्यवसायिक ऊर्जा खपत दोगुनी होने का अनुमान किया गया है. ऊर्जा दक्षता बढ़ती मांग एवं उससे संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे तेज़, सबसे साफ़ और सबसे सस्ते अवसर प्रदान करती है. जब सार्वजनिक एवं निजी, दोनों ही क्षेत्रों में जागरूकता और कार्रवाई में तेज़ी आ रही है तो हमारा ध्यान तत्काल ही इस अदृश्य संसाधन को समझने और इसका उपयोग करने पर केंद्रित हो जाना चाहिए. नीतियों, प्रोत्साहनों एवं संरचनात्मक समर्थन के सही संयोजन से एक ऐसा दक्ष वातावरण निर्मित किया जा सकता है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए भारत को आर्थिक और पर्यावरण विकास से संबंधित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिशा में सक्षम बना सकेगा.

त्वरित शहरीकरण से इमारतों के निर्माण की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि होने के कारण अधिकाधिक अवसर भी पैदा हो रहे हैं. यह मांग अभी से भारत में बिजली की कुल खपत की 30 प्रतिशत आंकी गई है. बढ़ते विकास के अनुरूप ही देश के भवन निर्माण क्षेत्र में 2005 से 2050 तक पांच गुना वृद्धि की संभावना है. भारत एक ऐसे अनूठे दोराहे पर खड़ा है, जहां 2030 में विद्यमान रहने वाले दो तिहाई व्यवसायिक और गगनचुंबी आवासीय ढांचे अभी बनने बाक़ी हैं.

राधिका खोसला
feedback@chauthiduniya.com

(लेखिका प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद, न्यूयॉर्क में वेल्च फैलो हैं.)

कई ऐसे धंधे भी हैं, जहां सब साथ-साथ काम करते हैं, तो भी उनमें संघ या संगठन नहीं हो सकता. उदाहरण के लिए किसी फिल्म कंपनी के कलाकारों को ले लीजिए.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

ट्रेड यूनियन की आवश्यकता और इतिवृत्त

किस तरह मज़दूर पूंजीवादी उद्योगपतियों का मुक़ाबला कर सका, इसका इतिवृत्त है. यह ज़ाहिर था कि कोई स्त्री या पुरुष, जो काम करता हो, नौकरी करता हो, अकेले जाकर मालिक के साथ न बहस कर सकता है, न मुक़ाबला. मालिकों का नपा-तुला यही जवाब होता है कि अगर इस मज़दूरी और स्थिति में तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे भाई दूसरे सैकड़ों करने वाले तैयार हैं. यह उत्तर लगभग सभी श्रमिकों के, अकेले बात करने पर, मुंह पर ताला लगा देता था. इसलिए मालिकों के सामने मज़दूरों की अपनी फरियाद का कुछ असर हो, उसकी कुछ सुनवाई हो, इसके लिए आवश्यक था कि किसी प्रकार का संगठन हो, क्योंकि एकता की आवाज़ ही मालिकों पर असर कर सकती है.

सब तरह के मज़दूरों के लिए किसी तरह से भी एकता का संगठन कर सकना संभव ही नहीं था. उदाहरण स्वरूप घरेलू नौकरों को ही लीजिए, एक घर में झाड़ू-बुहारी, पानी भरना, कपड़े धोना इत्यादि काम करता है. रसोइया या रसोइन रसोई बनाती है. सब क़रीब-क़रीब अपने-अपने दायरे में सीमित हैं. वे अकेले काम करते हैं. कहीं भी समुदाय या झुंडों में काम नहीं करते. एक-दूसरे से मिलने या विचार-विमर्श करने के मौक़े भी उन्हें कदाचित ही मिलते हैं. ऐसे श्रमिकों का संघ या संगठन होना नितांत मुश्किल है. या लीजिए खेतों में काम करने वाले मज़दूरों को, वहां भी अलग-अलग खेतों में जुताई-बुआई, बटाई-छंटाई इत्यादि अनेक कामों में सैकड़ों मज़दूर काम करते हैं, पर उनका आपस में मिलना और विचार-विमर्श कर सकना शक्य ही नहीं है. अतएव उनमें भी किसी प्रकार का संघ स्थापित होना मुश्किल है. अगर संघ क़ायम कर भी लिया जाए तो उसे सुसंगठित रख सकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वे एक-दूसरे से इतनी दूर-दूर रहते हैं कि उनका मिलना ही नहीं होता. ऐसी ही हालत इस तरह के सभी श्रमिकों की है. सिर्फ़ फैक्टरी, कारखाने, खानें, रेलवे, ट्राम, बसें इत्यादि कामों में श्रमिकों का संगठन हो सकता है. ऐसे मज़दूरों का संगठित स्वरूप चलता भी है.

कई ऐसे धंधे भी हैं, जहां सब साथ-साथ काम करते हैं, तो भी उनमें संघ या संगठन नहीं हो सकता. उदाहरण के लिए किसी फिल्म कंपनी के कलाकारों को ले लीजिए. एक प्रसिद्ध सिने तारिका को लाखों रुपये मिलते हैं, वहीं सैकड़ों दूसरी एक्सट्रा तारिकाओं को पेट भर खाने जितना भी वेतन नहीं मिलता. उनमें संगठन न हो सकने का कारण स्पष्ट है. समान कक्षा, समान शील, समान व्यवहार, समान श्रम वाले श्रमिकों का ही संगठन हो सकता है. जहां आमदनी में या सामाजिक

प्रतिष्ठा में एक-दूसरे में भयंकर अंतर हो, वहां वे आपस में संघ क़ायम कर ही नहीं सकते. फैक्टरी, कारखाने, रेलवे इत्यादि में काम करने वाले श्रमिकों का संघ क़ायम हो सकता है. मकान बनाने वाले राजमिस्त्री, गारा-चूना ढोने वाले, बढ़ई, लोहार इत्यादि श्रमिकों के भी संघ बनाने के प्रयत्न किए गए और आंशिक रूप से वे सफल भी हुए. कोई भी असहनीय दमन, जो मालिक लोग कर बैठते हैं, उसके विद्रोह स्वरूप ही तो संघ क़ायम होते हैं. एकबद्ध होकर श्रमिक लोग अपनी बात को अमुक दृष्टिकोण से देखने के लिए मालिकों को बाध्य कर सकते हैं. जब उनका ध्येय सिद्ध हो जाता है अथवा वे अपने ध्येय की प्राप्ति में असफल हो जाते हैं, तब वह संघ टूट जाता है. फिर जब कभी आपत्ति-विपत्ति आती है तो फिर उसी तरह संघ खड़ा होता है. इसके बाद उस संघ को अस्थायी रूप से क़ायम रखने के लिए वे कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं. नौकरी छूटने पर विपत्ति आती है, तब उस जमा की हुई पूंजी में से कुछ लेकर, कुछ समय तक योग क्षेम का काम चलाया जाता है. क्षणिक विद्रोह के लिए खड़े हुए संगठित श्रमिक संघ आगे चलकर स्थायी श्रमिक संघ बन गए. यही इतिहास है श्रमिक संघ का. ऐसे मजदूरों के संघ पूंजीवादियों के अनाधिकार हस्तक्षेपों को मिटाने के लिए क्या कर सकते हैं, यह सोचना है. जब एक श्रमिक संघ पूर्ण रूप से क़ायम हो जाता है, तब वे मालिक के सामने उसके मुंह पर कह सकते हैं कि हम अमुक मज़दूरी में काम नहीं करेंगे. यह जोखिम तो हमेशा रहता था कि तुम नहीं, तो तुम्हारे दूसरे भाई काम करेंगे. अब नहीं रहा.

अगर शहर के तमाम जुलाहे एक स्थायी संगठन बना लें तो मालिक के मज़दूरी कम करने पर कह सकते हैं कि हम इस कम मज़दूरी पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके गुजारे के लिए तो वह एकत्रित फंड उपलब्ध होगा ही. इस तरह इंकार कर देने से उनके मालिकों के उद्योग महीनों के लिए बंद हो जाएंगे. साथ ही संगठित मज़दूरों द्वारा हड़ताल कर देने पर इनके स्थान पर काम करने के लिए मालिकों को तत्काल मज़दूर नहीं मिल सकेंगे. एकाध आदमी को तो नौकरी से निकालने की धमकी दी जा सकती है और अकेले होने के कारण उसका डरना भी स्वाभाविक है, मगर तमाम मज़दूरों के काम छोड़ देने पर स्थिति संभालना किसी भी मालिक के लिए कठिन हो सकता है. इस तरह संगठित होकर, काम न करने का निश्चय करके मालिक को बाध्य करने की स्थिति को हड़ताल कहते हैं. मज़दूर लोग इस तरह से हड़ताल न केवल मज़दूरी कम करने के विरोध में ही करते हैं, बल्कि मज़दूरी बढ़ाने के लिए, काम के घंटे घटवाने के लिए या अन्य किसी भी हेतु से, जो वे मालिकों से करवाना चाहते हों, कर देते हैं. उनकी सफलता या विफलता बहुधा उस समय की व्यापारिक स्थिति पर ही निर्भर रहती है. अगर व्यापार की स्थिति सामान्य हो तो मालिक लोग मांग स्वीकार न करके कारखाने को बंद कर देते हैं. जब तक कि मज़दूरों का चंदे से इकट्ठा किया हुआ धन व्यय न हो जाए और बेकारी से भूखों मरने की नौबत न आ जाए, तब तक वे फैक्टरियां या कारखाने बंद ही रखते हैं. अंत में जब हड़तालियों को विवश होकर, हार स्वीकार कर, शरणागत होना पड़ता है, तब मालिक लोग अपनी शर्तों पर ही फैक्टरी या कारखाने चलाने को राजी होते हैं. लेकिन, अगर उस समय व्यापार में काफी उन्नति हो रही हो और कारखाने का एक दिन भी बंद रहना या उत्पादन न होना, मालिकों के मुनाफ़े में भारी फ़र्क़ डाल रहा हो तो वे येन-केन-प्रकारेण हड़तालियों की शर्तों के साथ समझौता करके कारखाने और फैक्टरियां चालू रखते हैं.

वे अपना हिसाब लगा लेते हैं कि मज़दूरों की मांगों को कबूल करने में उनको अपेक्षाकृत अच्छा लाभ है. समय निकलने के बाद मालिक लोग फिर अपने मौक़े की फिराक में रहते हैं. जब भी व्यापार की स्थिति मंदी या सामान्य होती है तो वे हिसाब लगा लेते हैं कि अगर फैक्टरी या कारखाना बंद रहे तो उनके लिए कोई विशेष फ़र्क़ नहीं पड़ेगा, ख़ास मुनाफ़े की हानि नहीं होगी या बहुत ही कम हानि होगी, तो वे मज़दूरी कम करने के लिए प्रयत्न करते हैं. मज़दूर न मानें तो वे तमाम कामों को बंद कर डालते हैं. ऐसी परिस्थितियों को मालिकों की हड़ताल या तालाबंदी कहा जाता है. व्यापार में जब भी उन्नति होती है तो मज़दूरों की हड़तालें हुआ करती हैं और अधिकतर वे सफल ही होती हैं. जब-जब व्यापार में मंदी आती है, तब-तब तालेबंदियां होती हैं और वे भी अधिकतर सफल ही होती हैं. व्यापार की स्थिति बदलती रहती है. प्रथम विश्व युद्ध के 5-7 वर्ष के बाद काफी बड़ी व्यापारिक मंदी आई और फलस्वरूप इतनी ज़्यादा बेकारी और दरिद्रता बढ़ी, जिसका असर बाद में कई वर्षों तक देश को भुगतना पड़ा. द्वितीय महायुद्ध के समय और उसके बाद जोर-शोर से व्यापार में तेजी आई. फलस्वरूप काफी ज़्यादा मजदूरी बढ़ी. मज़दूरों के सब आंदोलन सफल रहे. ये हड़ताल या तालेबंदियां एक तरह का वर्ग संघर्ष हैं.

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

शिक्षा के अधिकार से ग़रीब क्यों वंचित हैं

ख़बर आई है कि बिहार सरकार संत विनोबा भावे का भूदान आंदोलन एक बार फिर शुरू करने जा रही है. फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि विनोबा भावे द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन भूमिहीन किसानों को ज़मीन दिलाने के लिए था, वहीं बिहार सरकार का आंदोलन स्कूलों को ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए होगा. इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार लोगों से विद्यालयों के लिए ज़मीन मांगेगी. दरअसल, राज्य सरकार द्वारा 15 हज़ार नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, परंतु ज़मीन उपलब्ध न होने के कारण इस योजना में रुकावट आ रही है. हालांकि कुछ विद्यालयों के लिए ज़मीने मिल चुकी हैं, जिन पर भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में नवसृजित विद्यालय भूमि न होने के कारण भवन हीन हैं अथवा अस्थायी रूप से संचालित किए जा रहे हैं. इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने जनता से सहयोग मांगने का फ़ैसला किया है. इस समय देश में यदि कोई राज्य आश्चर्य रूप से प्रगति कर रहा है, तो वह बिहार है. आंकड़े बताते हैं कि कभी बीमारू और पिछड़ा राज्य कहलाने वाला बिहार अब गुजरात के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा विकास करने वाला राज्य बन गया है. राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ है. निवेश के अधिक से अधिक अवसर खुले हैं. अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ बिहार सरकार शिक्षा पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, बावजूद इसके प्राथमिक शिक्षा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है. जबकि इसे संपूर्ण शिक्षा की जड़ कहा जाता है. शिक्षकों की कमी का सबसे ज़्यादा प्रभाव यहां के प्राथमिक विद्यालयों पर ही पड़ता है.

दरभंगा को बिहार का ऐतिहासिक शहर होने का गौरव प्राप्त है. यह राज्य के एक प्रमुख शिक्षण केंद्र के रूप में विख्यात रहा है. इसके बावजूद यहां प्राथमिक शिक्षा की लचर व्यवस्था दीपक तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है. यहां के कुशेश्वर स्थान ब्लॉक अंतर्गत बर्रा पंचायत के वार्ड नंबर पांच में बने अस्थायी स्कूल का निरीक्षण करने पर कई ऐसी जानकारियां उजागर हुईं, जो स्कूली शिक्षा को बढ़ावा

देने के सरकारी दावे की पोल खोलती हैं. भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मिलने और फंड उपलब्ध होने के बावजूद यह स्कूल अस्थायी तौर पर चलाया जा रहा है, क्योंकि ज़मीन नहीं मिल पा रही है. गांव के अधिकतर लोगों के पास सीमित मात्रा में भूमि है, जो उनकी रोजी-रोटी का एकमात्र साधन है. ऐसे में वे ज़मीन देने में असमर्थ हैं. अस्थायी स्कूल होने के कारण शिक्षण कार्य लगभग ठप्प है. गांव वालों के अनुसार, अधिकतर शिक्षक नदारद रहते हैं. वहीं शिक्षकों का तर्क है कि वे प्रशिक्षण पर हैं, इसलिए स्कूल में समय नहीं दे पा रहे हैं. यह बात समझ से परे है कि आख़िर सरकार ने ऐसा कौन सा प्रशिक्षण शुरू किया है, जो शिक्षकों को उनके वास्तविक कार्यों से अलग करता है. बच्चों को स्कूल तक लाने वाली महत्वाकांक्षी योजना मिड डे मील का यहां कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जब शिक्षक आएंगे नहीं, तो बच्चों को मिड डे मील कहां से मिलेगा. बच्चों के अनुसार, मिड डे मील न मिलने के पीछे शिक्षकों का तर्क है कि उन्हें यह उपलब्ध नहीं कराया जाता.

इन तमाम बातों से अलग ब्लॉक अधिकारी ने सफाई दी कि सभी शिक्षक समय पर स्कूल आते हैं और मिड डे मील भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी रिपोर्ट उसके पास मौजूद है. यह हाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, बल्कि राज्य में ऐसे कई स्कूल हैं, जो जमीन न होने के कारण अस्थायी रूप से चल रहे हैं और भवन बनने की बाट जोह रहे हैं. प्रश्न यह उठता है कि आख़िर शिक्षा हासिल करना ग़रीबों का हक़ है या नहीं? यदि पिछड़े इलाक़ों के लोग अपनी ज़मीन देने में असमर्थ हैं तो क्या इसकी सज़ा उनके बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित होकर भुगतनी पड़ेगी. यदि सरकार भवन निर्माण के लिए फंड उपलब्ध करा सकती है तो ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए वह कोई ठोस नीति क्यों नहीं बना सकती? उच्च शिक्षा को अधिक से अधिक मज़बूत बनाने के लिए कई स्तरों पर विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं. नए तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है, ऑनलाइन परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और छात्रों को कम क़ीमत पर लैपटॉप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि सारा आकाश उनकी मुट्ठी में हो, परंतु प्राथमिक शिक्षा की बदहाली पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता है? शिक्षा इंसान को उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराती है. केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार क़ानून इस दिशा में एक ऐतिहासिक क़दम है, परंतु केवल क़ानून बना देने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो जाता. (चरखा)

सलमान अब्दुस समद
feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

कन्या भ्रूण हत्या के गुनाहगार

देश में कन्या भ्रूण हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. कहने को तो बड़े शहरों से लेकर छोटे क़स्बों एवं गांवों तक में जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कूड़े-कर्कट के ढेर में कन्या भ्रूण मिल जाते हैं. अफसोस की बात यह है कि ख़ुद को शिक्षित एवं सुसंस्कृत कहने वाला तबक़ा ही कन्या भ्रूण हत्या जैसे गुनाह में शामिल है. शहरों में ऐसे लोगों की कमी नहीं, जो कन्या भ्रूण हत्या पर औरों को नसीहतें देते हैं, लेकिन ख़ुद उनके परिवारों में अजन्मी बच्चियों की हत्या की जा रही है. अगर लोग अपने परिवार, ख़ानदान और परिचितों को कन्या भ्रूण हत्या से रोक सकें तो बेशक इस बुराई पर काफ़ी हद तक क़ाबू पाया जा सकता है.

-रफ़त जहां, *नांदेड़, महाराष्ट्र.*

आज़ादी को क़ायम रखेंगे

टीम अन्ना के सदस्य केजरीवाल का यह कहना कि अपराधियों, कॉरपोरेट माफ़िया एवं भ्रष्ट लोगों ने संसद और विधानसभा को बंधक बना लिया है, उचित नहीं है. यह सच है कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, जिन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी संसद और विधानसभा को ही कठघरे में खड़ा कर दिया जाए. यदि संसदीय लोकतंत्र खराब है तो क्या केजरीवाल के दिमाग़ में कोई दूसरा मॉडल है? तानाशाही, सैन्य शासन या एक पार्टी का शासन? बेशक लोकतंत्र से बेहतर और कोई मॉडल नहीं है. एक लंबे संघर्ष के बाद देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली है और हमें इसे क़ायम रखना है किसी भी क़ीमत पर.

-सनव्वर ख़ान, *हिसार, हरियाणा.*

पिछड़ेपन का दंश

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले का डुवार्स क्षेत्र आदिवासी बहुल है. चाय बाग़ानों को स्थापित करने के लिए अंग्रेज इन आदिवासियों को यहां लेकर आए थे. अंग्रेज तो चले गए, लेकिन यह क्षेत्र आज भी पिछड़ेपन की गुलामी में जकड़ा हुआ है. विडंबना यह है कि यहां विद्यालय कम और शराब के अड्डे ज़्यादा हैं. रोज़ाना 90 रुपये कमाने वाले ये मज़दूर शराब के कारण आर्थिक और नैतिक पतन की ओर जा रहे हैं. सरकारी प्रकल्पों से वंचित इन ग़रीबों का दर्द अगर आपके अख़बार द्वारा देश के समक्ष आता है तो मैं सदा आपका आभारी रहूंगा.

विनीत, *जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल.*

अमेरिका की साज़िश

अपने परमाणु कार्यक्रम से चर्चित ईरान ने अमेरिकी विमान वाहक पोत को फ़ारस की खाड़ी से दूर रहने की चेतावनी दी है. ईरान का कहना है कि अमेरिका अपनी जर्जर अर्थव्यवस्था से अमेरिकी जनता का ध्यान हटाने के लिए खाड़ी में परमाणु कार्यक्रम की आड़ में ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है, जबकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की देखरेख में ऊर्जा ज़रूरतों एवं शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जा रहा है. भारत को भी चाहिए कि वह अपनी ऊर्जा एवं गैस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस लाइन को चालू करे, जो अमेरिकी दबाव के कारण लंबित है.

-नित्यानंद सिंह, *धनबाद, झारखंड.*

जातिवाद हावी

आज भी पूरी राजनीति केवल जातिवाद पर केंद्रित है. हालत यह है कि जातिवाद में भी अनुसूचित जातियों के बीच वर्ग भेद खुलकर सामने आ गया. हर दल ने येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतने के लिए साम-दाम-दंड-भेद की नीति अपनाई. सभी दलों ने प्रत्याशियों का चयन जातिवाद के आधार पर ही किया है. खींचतान भी हिंदू-मुस्लिम और अगड़े-पिछड़े पर हो रही है.

-तेजवानी गिरधर, *अजमेर, राजस्थान.*

अख़बार अच्छा लगा

चौथी दुनिया पहली बार पढ़ा. आलेखों के विषयों, कवरेज एवं सामाजिक सरोकारों के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व के बोध ने मन को अभिभूत कर दिया. राष्ट्रीय जनजागरण के इस पवित्र कार्य के लिए अख़बार की संपादकीय टीम का आभार एवं हार्दिक शुभकामनाएं.

-श्रीप्रकाश शर्मा, *समस्तीपुर, बिहार.*

अंत में

दूसरे का दिल दुखाना,
बात यह अच्छी नहीं
हमेशा खिलखिलाना,
बात यह अच्छी नहीं,
थैंक्स कहते लोग अक्सर,
ग़मज़दा सूरत लिए
हंस के सॉरी बोल जाना,
बात यह अच्छी नहीं,
हंस के चुप होते सभी,
जब ग़लतियां ख़ुद ही करें
दूसरे पे तिलमिलाना,
बात यह अच्छी नहीं,
सीख देते हैं सुमन जब
दूसरों को वक़्त पर
और अपने से बहाना,
बात यह अच्छी नहीं,

-श्यामल सुमन, *झारखंड.*

राजकमल प्रकाशन समूह
1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002
फोन 011-23274463, 23288769, फैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com
शाखा : अशोक राजपथ, पटना-800006 फोन 0612-2672280
पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-211001 फोन 0532-3293838, 2427274

लेखन विधा सम्मान 2011
'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जानेवाली 700 रुपए की किताबें

देश के जाने-माने पत्रकार एवं 'चौथी दुनिया' के सम्पादक संतोष भारतीय के संपादन में प्रकाशित 'दलित अल्पसंख्यक सशक्तीकरण' के वैश्विक प्रयासों का तथ्यात्मक दस्तावेज। यह पुस्तक प्रमाणित करती है कि दुनिया भर के गरीब, दबे-कुचले और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग समूहबद्ध होकर यदि शक्तिसम्पन्न होने का संकल्प लें तो वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव सामने आएंगे।

मूल्य ₹ 1000 पृ. : 448 राजकमल प्रकाशन प्रा.लि.

राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी
हेल्पलाइन : 09311196029

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएँ इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11,
नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

गुर्नार मीर्डेल एवं उनकी पत्नी अल्वा मीर्डेल का नाम भारत में जाना-पहचाना है. वे अर्थशास्त्री हैं और वेलफेयर स्टेट फिलॉस्फी के बड़े चिंतकों में से एक हैं.

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

कॉरपोरेट सेक्टर अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी को समझे

बीती 27 फरवरी को बंगलुरू में ईटीवी उर्दू और ईटीवी कन्नड़ ने एक सेमिनार किया, जिसका विषय था–फ्यूचर ऑफ कॉरपोरेट्स इन इंडिया. मुख्य वक्ता कंपनी मामलों के केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली थे और मुख्य अतिथि थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा. सेमिनार में जाफर शरीफ, एम वी राजशेखर एवं जमीर पाशा भी शामिल थे, जो कर्नाटक की बड़ी हस्तियां हैं. वीरप्पा मोइली एवं मुख्यमंत्री सदानंद के भाषण सुनकर कई सारे सवाल मन में उठे. एक सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर को अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी का कोई एहसास है और अगर नहीं है तो क्यों? ज़िंदगी का हर क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है, हर जगह काम करने वाले महत्वपूर्ण होते हैं, पर हिंदुस्तान का कॉरपोरेट सेक्टर ज़िंदगी की सच्चाई को कितना देखना और समझना चाहता है, यह एक सवालिया निशान है. इसलिए, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर जितने भी काम करता है, सामाजिक ज़िम्मेदारी निभाने के नाम पर, वे सारे के सारे कॉस्मेटिक होते हैं यानी दिखावे के होते हैं. कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर बुनियादी समस्याओं से जुड़े सवालों को अपना विषय नहीं बनाता. सेमिनार में जब वीरप्पा मोइली ने कहा कि 1992 के बाद हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है और यहां लोगों के पास क्या-क्या नहीं है तो सुनकर लगा कि कॉरपोरेट अफेयर्स का मिनिस्टर बोल रहा है, लेकिन भारत सरकार का ज़िम्मेदार मंत्री नहीं बोल रहा है.

वीरप्पा मोइली को क्यों याद नहीं आया कि 1992 में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो उन्होंने भाषण दिया था कि हम उदार आर्थिक नीतियां इसलिए ला रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान में अगले 20 सालों में बिजली की कमी न रहे, सड़कें बन जाएं, लोगों को नौकरियां मिल जाएं, बेरोज़गारी ख़त्म हो. लोकसभा में दिया गया उनका वह भाषण पढ़ने लायक़ है. वीरप्पा मोइली केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी रहे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे. उन्हें ज़रूर इस भाषण की याद होगी. 20 साल बीत गए. जिस साल वे 20 साल पूरे हुए, वह 2010 था यानी दो साल पहले. क्या 2010 में कांग्रेस पार्टी या केंद्र सरकार ने अपने उस वादे का विश्लेषण किया कि हमने जो कहा था, उनमें क्या-क्या काम पूरे हुए और क्या-क्या नहीं. यह विश्लेषण न करना बताता है कि हिंदुस्तान का कॉरपोरेट सेक्टर ज़िम्मेदारी से भाग रहा है. जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे 2004 में, उस समय देश में नक्सलवाद से प्रभावित ज़िलों की संख्या 60 या 70 थी. आज जब हम इन पंक्तियों को लिख रहे हैं तो 260 से ज़्यादा ज़िले नक्सलवाद की चपेट में हैं. अगर एक लाइन का विश्लेषण करें और ईमानदारी से करें तो हम कह सकते हैं कि 1992 में शुरू हुआ उदारीकरण 25 प्रतिशत लोगों तक जाकर रुक गया. 35 से 40 प्रतिशत लोग तो उदारीकरण से सौ फ़ीसदी वंचित रहे, उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं हुआ. अब बचा बीच का तबका, 20 प्रतिशत लोग इस आशा में ऊपर देख रहे हैं कि शायद हमारे पास भी कुछ आए, पर दरअसल महज़ 25 से 30 प्रतिशत लोगों के लिए उदारीकरण का तोहफ़ा आया है. उस तोहफ़े ने देश में असमानता को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है. शायद इसीलिए ज़िले के ज़िले नक्सलवाद के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं.

अगर हम अर्थशास्त्रियों की बात करें, जब देश आज़ाद हुआ तो उन अर्थशास्त्रियों ने, जो अंग्रेजों के समय के अर्थशास्त्री थे, उस समय हिंदुस्तान की विकास दर ढाई प्रतिशत बताई थी और अब विकास दर कभी 8 प्रतिशत होती है तो कभी 6 प्रतिशत. ये आंकड़े बताते हैं कि लोगों के पास इस तथाकथित विकास का फ़ायदा नहीं पहुंचा. इसीलिए अगर राजनीतिज्ञ अपना रोल भूल जाएं तो कॉरपोरेट सेक्टर को अपना रोल याद करना चाहिए. जो वे लोगों से कमाते हैं हिंदुस्तान में, उनकी वह आय दिन दूनी-रात चौगुनी बढ़ रही है. उन्हें अपनी उस आय का एक हिस्सा हिंदुस्तान के लोगों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के ऊपर ज़रूर ख़र्च करना चाहिए. ये दो क्षेत्र ऐसे हैं, जहां की पूरी ज़िम्मेदारी कॉरपोरेट सेक्टर ले सकता है. समस्या इस बात की है कि जहां-जहां कॉरपोरेट सेक्टर शिक्षा एवं स्वास्थ्य में घुसा, वहां-वहां उसने स्कूलों और अस्पतालों का व्यवसायीकरण कर दिया. वहां स्कूल इतने महंगे हो गए हैं कि आम आदमी तो छोड़िए, अपर मिडिल क्लास को वहां बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत महसूस हो रही है. अस्पताल खुलते हैं और खुलते ही वे 20 गुने महंगे होते हैं.

अगर मैं कॉरपोरेट सेक्टर की ज़िम्मेदारी की बात कहता हूं तो उसका सीधा मतलब है कि वे हिंदुस्तान के ग़रीब आदमी को शिक्षा दें और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें. उसकी बीमारी का इलाज हो और वह इलाज कुनैन की गोली से न हो, सेरिडॉन से न हो, वह इलाज सचमुच ऐसा होना चाहिए, जैसा बड़े अस्पताल में होता है. मेडिकली एक्सीलेंस देहात में कैसे पहुंचे, इसके बारे में अगर कॉरपोरेट सेक्टर संवेदनशील नहीं होता है तो थोड़े दिनों के बाद बहुत सारे बड़े घरानों को हिंदुस्तान में अपने मूवमेंट के बारे में सावधान रहना पड़ेगा. नई पीढ़ी के लड़के, जो अपनी मां का पसीना देख रहे हैं, उसका परिश्रम देख रहे हैं, अपने घर में होती मौतों को देख रहे हैं, अपनी जवान बहन को इसलिए घर बैठा देख रहे हैं क्योंकि दहेज का पैसा नहीं है, वे लड़के अगर अपने छोटे भाइयों या अपने से बड़े लोगों का इलाज भी होते हुए नहीं देखेंगे और दूसरी तरफ़ आलीशान स्कूल एवं अस्पताल देखेंगे, तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं उनके मन में विद्रोह की आग न पैदा हो जाए. हिंदुस्तान का कॉरपोरेट सेक्टर कम दूरी की बात सोचता है. उसे लगता है कि इस तरह के जो लीडर पैदा हों या जो इस तरह की आवाज़ उठाएं, उन्हीं को ख़रीद लो तो आवाज़ बंद हो जाएगी. ऐसा नहीं होता. अब हिंदुस्तान में स्वाभाविक नेता या स्वाभाविक नेतृत्व वहीं विकसित होगा, जहां पर परेशानी है और परेशानी लगभग पूरे हिंदुस्तान में है. सरकार अपनी ज़िम्मेदारी आंशिक रूप से निर्वाह कर रही है. जो बचा हुआ हिस्सा है, उसमें कॉरपोरेट सेक्टर को अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी तत्काल समझनी चाहिए.

सेमिनार में मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा ने उनके राज्य में क्या-क्या हो रहा है, उसका एक लंबा बखान किया. उसके ऊपर ध्यान न दें तो भी चल जाएगा. लेकिन, वीरप्पा मोइली ने अपने भाषण में कुछ बिंदुओं की ओर इशारा किया. एक, उन्होंने कहा कि जब हमने उदारीकरण किया, तब हमें कुछ और क़ानून बनाने चाहिए थे, ताकि उदारीकरण को लोग हाईजैक न कर लें. दूसरा, उन्होंने कहा कि हालांकि हमारा भविष्य सुरक्षित है और कॉरपोरेट का भी. इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में कॉरपोरेट सेक्टर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. जिस चीज को वीरप्पा मोइली ने होशियारी से कहा, वह होशियारी से कहने वाली चीज नहीं है, उसे सफाई से कहने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी नीति ऐसी नहीं बन रही है, जो ग़रीबों को सीधे फ़ायदा पहुंचाए. वे नीतियां बन रही हैं, जो हिंदुस्तान के अपर मिडिल क्लास, ख़ासकर कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाएं. यही पूरी कॉरपोरेट नीति का उद्देश्य है. वीरप्पा मोइली बहुत ही संवेदनशील इंसान हैं, लेखक हैं, लेकिन अगर वह लेखक हैं, संवेदनशील हैं तो एक पार्टी के दायरे में भी बंधे हुए हैं. यह सवाल सिर्फ़ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य का है.

क्या भारतीय जनता पार्टी इस ज़िम्मेदारी को समझती है, क्या समाजवादी पार्टी इस ज़िम्मेदारी को समझती है? वामपंथी समझते भी हैं तो वे कुछ करने की स्थिति में नहीं होते. वे जिस राज्य में थे, वहां उन्होंने कॉरपोरेट्स को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया कि जनता उनसे दूर भाग गई. इसलिए अगर हम पोज़िटिव थिंकिंग करें तो हमें वीरप्पा मोइली से यह कहना चाहिए कि आपको इसमें आगे बढ़कर पहल करनी होगी. अगर आप यह समझते हैं कि हिंदुस्तान का कॉरपोरेट सेक्टर ग्रामीण अंचलों की तरफ़ नहीं जा रहा है तो उसमें थोड़ी सी समझ और जोड़ने की ज़रूरत है. वह यह कि कॉरपोरेट सेक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जा रहा है, उल्टे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा पैसा डाल रहा है और जहां ज़मीन है, वहां शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर ज़मीन घेरने का काम कर रहा है. इस चीज से कॉरपोरेट सेक्टर को बचना चाहिए और इसमें वीरप्पा मोइली का बहुत बड़ा रोल है. वह अगर कॉरपोरेट सेक्टर के सामने साफ-साफ दिशा रखें कि सामाजिक ज़िम्मेदारी का मतलब क्या होता है. अगर वह इस चीज को डिफाइन करेंगे तो शायद दबाव और शर्म में कुछ अच्छे काम हो जाएं. चूंकि यह सेमिनार टेलीविज़न पर आते हैं, इसलिए आम आदमी भी इन्हें देखकर कि कौन कितना सही बोल रहा है और कौन कितना नाटक कर रहा है, उसे पहचान लेते हैं. यह पहचान फिर आम आदमी की आशा को निराशा में बदलती है. निराशा ख़तरनाक स्थिति होती है, क्योंकि फ्रस्टेशन और होपलेसनेस आदमी को विध्वंस की तरफ़ मोड़ती है.

हम इस देश के रहने वाले हैं, हम यह नहीं चाहते कि इस देश में विध्वंस हो. इसलिए हम बार-बार यह अनुरोध करते हैं उन सबसे, जो इस राजनीतिक व्यवस्था को चलाने में भागीदार हैं या ज़िम्मेदार हैं, कृपा करके देश के आम आदमी की तकलीफों को जानिए और समझिए. बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं है कि मैं नहीं, मेरा बेटा समझेगा. हो सकता है, आपके बेटों को वे स्थितियां न मिलें, जो आपको मिली हैं. उन्हें वह जय-जयकार न मिले, जो आपको मिली है. उन्हें वे फूल न मिलें, जो आपको मिले हैं. अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शांति रहे और आपका परिवार भी ख़ुशहाल रहे तो आज आपको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी. कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों के सामने स्थिति इससे भी ज़्यादा भयावह होने वाली है. अगर वे अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी नहीं समझते हैं तो फिर अपनी अच्छी गाड़ी पर लिपस्टिक, पाउडर और परफ्यूम के साथ घूमना उनके लिए ख़तरा बन जाएगा, क्योंकि उस परफ्यूम की महक को सूंघते हुए पसीने से सराबोर ग़रीब आदमी जब उनकी तरफ़ लपकेगा तो उनके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा. इसलिए अभी वक़्त है, ख़ासकर सियासत में बैठे हुए लोग, कॉरपोरेट सेक्टर को चलाने वाले लोग और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ा मीडिया इस ज़िम्मेदारी को समझें और एक-दूसरे को सलाह दें कि हम सब आम लोगों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें, उनकी समस्याओं को जानें और अपने मन के दरवाज़े खोलें.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

हमारे क़ानून, उनके क़ानून

मेरे पास इटली निवासी एक दोस्त का फोन आया. वह पत्रकार हैं, भारत से संबंधित समाचार देखती हैं और कई बार भारत आ चुकी हैं. उन्होंने कहा कि भारत में इटली का इतना विरोध क्यों होता है. इन सबके बाद इस बात पर सोचना चाहिए कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में जो भारतीय मछुआरों की हत्या हुई, वह अन्य सभी विवादों से भिन्न क्यों है. मेरा अनुमान है, चूंकि इटली एक यूरोपीय देश है और जब भी कोई ऐसी हिंसात्मक घटना घटती है, जिसमें किसी भारतीय की जान जाती है, तो हम उपनिवेशवाद के दौर को याद करने लगते हैं. मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस घटना के बाद सोनिया गांधी के इटेलियन होने के मुद्दे को तूल नहीं दिया गया. अगर भारत का कैथोलिक चर्च ख़ुद को इस मुद्दे से दूर रखे तो अच्छा होगा, क्योंकि यह कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है. देखा जाए तो यह तथ्य अप्रासंगिक है कि बैटिकन इटली में है. जहां तक भारत का संबंध है तो यह एक स्पष्ट मुद्दा है. इटली के दो नौसेना अधिकारियों मस्सीमिलानो लटोरे एवं सल्वाटोर गिरोन ने केरल के दो मछुआरों की हत्या कर दी. दोनों अधिकारियों का कहना था कि उन्हें लगा कि ये लोग समुद्री लुटेरे हैं, जिसके कारण उन्होंने नाव पर गोली चलाई और मछुआरों की मौत हो गई. यह हो सकता है कि तकनीकी रूप से वह क्षेत्र यूएन कन्वेंशन ऑफ दी लॉ ऑफ डीसी द्वारा परिभाषित देश की समुद्री सीमा से बाहर हो. अगर बाहर न भी हो तो वह उसके काफी नज़दीक तो ज़रूर था.

कहा जा सकता है कि यह भारतीय पोत था और भारतीय क़ानून के अनुसार यह भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इटली सरकार अंतरराष्ट्रीय क़ानून की बात कर रही है. उसका कहना है कि यह घटना सुदूर समुद्र में घटी है और जब तक अंतरराष्ट्रीय क़ानून ऐसा कहता है, तब तक इटली के क़ानून ही लागू होने चाहिए. वह चाहती है कि उसके अधिकारी उसे सौंप दिए जाएं और उन पर मुक़दमा इटली की अदालत में ही चले. अब प्रश्न यह उठता है कि यहां कौन सा क़ानून लागू होना चाहिए. भारत का, इटली का या फिर अंतरराष्ट्रीय कानून. कुछ भारतीयों को इस पर संदेह है कि उनका उत्तर क्या होगा. चूंकि यह घटना यूएनक्लोस (यूएन कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ डीसी) द्वारा परिभाषित समुद्री क्षेत्र के भीतर घटी है, इसलिए यह मामला काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा. अब ऐसी ही एक दूसरी घटना पर नज़र डालते हैं. नार्वे सरकार ने भारतीय मूल के अनुरूप भट्टाचार्य एवं सागरिका के बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लिया और उसके कानून के अनुसार जब तक उक्त बच्चे बालिग नहीं हो जाते, उन्हें सरकार की कस्टडी में ही रखा जाएगा. भारत ने नार्वे सरकार के इस क़ानून को ग़लत माना और कहा कि वह भारतीय संस्कृति एवं भारतीयों की संवेदना की उपेक्षा कर रही है. ग़ौरतलब है कि यह घटना नार्वे की है और वहां उसी का क़ानून लागू होता है. अगर देखा जाए तो स्कैंडिनेवियाई देश एक मज़बूत वेलफेयर स्टेट हैं और वहां की सरकारें अपने नागरिकों के पारिवारिक मामलों में भी हस्तक्षेप करती हैं. इन देशों में पिछले सत्तर सालों से इस तरह की व्यवस्था का विकास हो रहा है.

गुर्नार मीर्डेल एवं उनकी पत्नी अल्वा मीर्डेल का नाम भारत में जाना-पहचाना है. वे अर्थशास्त्री हैं और वेलफेयर स्टेट फिलॉस्फी के बड़े चिंतकों में से एक हैं. मनोविज्ञान एवं बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित उनके कई शोध प्रकाशित हो चुके हैं. उनका कहना है कि परिवार को बच्चों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए. अगर परिवार अपने बच्चों का पालन-पोषण सही तरीक़े से नहीं करता है तो उन बच्चों को सही तरीक़े से रखने की ज़िम्मेदारी देश की है. इस तरह देखा जाए तो नार्वे के क़ानून के अनुसार, अगर वहां रहने वाले लोग अपने बच्चों को ठीक से नहीं रखते हैं तो सरकार उन बच्चों को अपनी कस्टडी में ले सकती है और माता-पिता के पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है. सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है. हालांकि इस तरह के सिद्धांत को न तो यूरोप के अन्य देशों में बहुत अधिक समर्थन मिला है और न एंग्लो-सैक्शन लोगों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन स्कैंडिनेवियन देशों में इस सिद्धांत को समर्थन मिला है. हालांकि यह मानना जरा मुश्किल है कि नार्वे की सरकार के पास इस बात के क्या सबूत थे कि जिन बच्चों को उसने अपनी कस्टडी में लिया, उन्हें किस तरह उपेक्षित किया गया था. स्कैंडिनेवियन देशों में दूसरी संस्कृतियों के साथ कुछ मेलजोल हुआ है, लेकिन अभी भी जितना यूके, फ्रांस या जर्मनी में दूसरी संस्कृतियों को अपनाया गया है, उतना नहीं अपनाया गया. बच्चों के अधिकार के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं. भारत और नार्वे में बच्चों के अधिकार के संबंध में जो विवाद है, वह दोनों की संस्कृतियों में भिन्नता के कारण उत्पन्न हुआ है. इसी तरह इटली के मामले को देखें तो यहां विवाद घरेलू क़ानून और अंतरराष्ट्रीय क़ानून में अंतर के कारण उत्पन्न हुआ है. जहां तक अंतरराष्ट्रीय क़ानून का सवाल है तो मेरा अनुभव यही रहा है कि अगर आप स्पष्ट समाधान चाहते हैं तो यह बहुत ही मुश्किल है. इसका पता मुझे 2003 के इराक युद्ध पर चर्चा के दौरान चला था. उस समय भी अंतरराष्ट्रीय क़ानून की धज्जियां उड़ा दी गई थीं. इस तरह के विवाद के कारण न्याय प्रभावित होता है. भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में अगर घरेलू क़ानून लागू किए जाते हैं तो इटली के अधिकारियों पर केरल की अदालत में मुक़दमा चलाया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो नार्वे में उन बच्चों का क्या होगा, अगर वहां की सरकार उन पर अपने घरेलू क़ानून लागू करती है.

गुर्नार मीर्डेल एवं उनकी पत्नी अल्वा मीर्डेल का नाम भारत में जाना-पहचाना है. वे अर्थशास्त्री हैं और वेलफेयर स्टेट फिलॉस्फी के बड़े चिंतकों में से एक हैं. मनोविज्ञान एवं बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित उनके कई शोध प्रकाशित हो चुके हैं. उनका कहना है कि परिवार को बच्चों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए. अगर परिवार अपने बच्चों का पालन-पोषण सही तरीक़े से नहीं करता है तो उन बच्चों को सही तरीक़े से रखने की ज़िम्मेदारी देश की है.

feedback@chauthiduniya.com

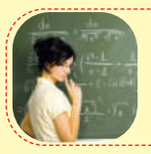

शिकागो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अभिभावकों एवं बच्चों की 53 जोड़ियों को अपने अध्ययन में शामिल किया.

सूचना का अधिकार – चौथी दुनिया की पहल

अपनी पंचायत का लेखा-जोखा मांगें

स्वराज, लोक स्वराज या गांधी का हिंद स्वराज आख़िर क्या है? गांधी जी का सपना था कि देश का विकास पंचायती राज संस्था के ज़रिए हो. पंचायती राज को इतना मज़बूत बनाया जाए कि लोग ख़ुद अपना विकास कर सकें. आगे चलकर स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के नाम पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू भी की गई. ज़िला स्तर पर ज़िला परिषद, खंड स्तर पर एक इकाई और सबसे नीचे के स्तर पर ग्राम पंचायत की अवधारणा लागू हो गई. इसके साथ ग्रामसभा नामक भी एक संस्था बनाई गई. ग्रामसभा एक स्थायी संस्था के रूप में काम करती है, जिसमें पंचायत के सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं. एक पंचायत में विकास कार्यों के लिए प्रति वर्ष लाखों रुपये आते हैं. इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं भी आती हैं. ग्रामसभा की संकल्पना इसलिए की गई थी, ताकि पंचायत के किसी भी विकास कार्य में गांव के लोगों की सीधी भागीदारी हो, विकास कार्य की कोई भी रूपरेखा उनकी सहमति से बने, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा. आज देश की किसी भी पंचायत में ग्रामसभा की हालत ठीक नहीं है. ग्रामसभा की बैठक महज़ खानापूर्ति के लिए की जाती है. किसी भी विकास योजना में ग्रामीणों से न तो कोई सलाह ली जाती है और न ग्रामसभा की बैठक में उस पर चर्चा की जाती है. पंचायती राज व्यवस्था के असफल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह भी यही है, लेकिन सूचना अधिकार क़ानून आने से अब सरपंच अपनी मर्जी नहीं चला सकते. बशर्ते, आप सरपंच और पंचायत से सवाल पूछना शुरू करें. ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर आपको लगता है कि सरपंच और अन्य अधिकारी मिलकर इन पैसों और योजनाओं में घोटाले कर रहे हैं, तो आप केवल सूचना अधिकार क़ानून के तहत एक आवेदन डाल दें. आप अपने आवेदन में किसी एक खास वर्ष में आपकी पंचायत के लिए कितने रुपये आवंटित हुए, किस कार्य के लिए आवंटन हुआ, वह कार्य किस एजेंसी द्वारा कराया गया, कितना भुगतान हुआ आदि जानकारियां और भुगतान की रसीद की मांग कर सकते हैं. इसके अलावा आप कराए गए कार्यों का निरीक्षण करने की भी मांग कर सकते हैं. इसके साथ ही आप केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं. मसलन, इंदिरा आवास योजना के तहत आपके गांव में किन–किन लोगों को आवास आवंटित हुए. ज़ाहिर है, जब आप उक्त सवाल पूछेंगे, तो भ्रष्ट सरपंचों एवं अधिकारियों पर एक तरह का दबाव बनेगा. यह काम आप चाहें तो कई लोगों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं. जैसे अलग–अलग मामलों या किसी एक ही मामले में कई लोग मिलकर आवेदन डालें. इसका असर यह होता है कि चाहकर भी कोई दबंग सरपंच या अधिकारी आप पर दबाव नहीं डाल पाएगा या आपको धमकी नहीं दे पाएगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(ग्राम पंचायत के खर्च का विवरण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
..................ग्राम पंचायत के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:–
1. वर्ष............के मध्य........ग्राम पंचायत को किन–किन मदों/योजनाओं के तहत कितनी राशि आवंटित की गई? आवंटन का वर्षवार ब्यौरा दें.
2. उपरोक्त ग्राम पंचायत द्वारा इस दौरान कराए गए सभी कार्यों से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें:–
(क) कार्य का नाम.....
(ख) कार्य का संक्षिप्त विवरण.....
(ग) कार्य के लिए स्वीकृत राशि......
(घ) कार्य स्वीकृत होने की तिथि......
(च) कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम......
(छ) कार्य शुरू होने की तिथि........
(ज) कार्य समाप्त होने की तिथि/चालू कार्य की स्थिति......
(झ) कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया......
(ट) कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है.......
(ठ) कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति.........
(ड) कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया.....

इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएं. उन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं पद बताएं, जिन्होंने कार्य का निरीक्षण किया और भुगतान की स्वीकृति दी. कार्य के वर्क ऑर्डर रजिस्टर एवं लेबर रजिस्टर/मस्टर रोल की प्रति उपलब्ध कराएं.

3. उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष........के दौरान कार्यों/योजनाओं पर होने वाले खर्चों की जानकारी निम्न विवरणों के साथ दें:–
(क) कार्य का नाम, जिसके लिए खर्च किया गया.....
(ख) कार्य का संक्षिप्त विवरण.....
(ग) कार्य के लिए स्वीकृत राशि......
(घ) कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम......
(च) कार्य शुरू होने की तिथि........
(छ) कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति.........
(ज) कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया? इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएं.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.......रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर..........है.
यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.
भवदीय
नाम..................
पता..................
फोन नंबर.............
संलग्नक..........
(यदि कुछ हो तो)

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
आप तेजी से बहुत ज़्यादा कार्यों को करने की चेष्टा करेंगे. कोई नया कार्य प्रारंभ करने की योजना बनाएंगे. ऐश्वर्य की वस्तु ख़रीदेंगे. कोई पारिवारिक शुभ कार्य संपन्न होने के संकेत हैं. भाग–दौड़ रहेगी. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. नौकरीपेशा और व्यापारी वर्ग दोनों ख़ुश रहेंगे. विद्यार्थी ध्यान से पढ़ाई करेंगे.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
आप ज़्यादा विश्वास में कोई निर्णय न लें और न अधिक आत्मविश्वास बढ़ाएं. अस्थि विकार का ध्यान रखें. अगर सिर दर्द होता हो तो धूप में अचानक न निकलें. आर्थिक दृष्टि से यह समय अच्छा रहेगा. व्यापारी अच्छा व्यवसाय करेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए मिला–जुला समय रहेगा. जीवन साथी से आपके संबंध मधुर होंगे.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
आपकी योजना में बदलाव लाने वाला सप्ताह है. सफलता थोड़ी मेहनत के बाद प्राप्त होगी. व्यापारी ख़ुश रहेंगे. किसी बुज़ुर्ग का स्वास्थ्य चिंता का कारण बनेगा. पारिवारिक वैमनस्यता बढ़ेगी. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को उन्नति के समाचार मिलेंगे. विद्यार्थियों की एकाग्रता थोड़ी भंग होगी, मेडिटेशन की ज़रूरत है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
पहले से की जा रही मेहनत अब सफलता के रूप में रंग दिखाएगी. विलासिता की वस्तु ख़रीदने से ख़र्च बढ़ेगा. आप उत्साहित रहेंगे और उमंग के साथ काम करेंगे. कार्य विस्तार की योजना भी बना सकते हैं. रक्तचाप और मधुमेह की बीमारी वाले लोग सावधान रहें. आर्थिक दृष्टि से अच्छा समय है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
आप अत्यधिक मेहनत करेंगे. आपके सपने पूरे होने वाले हैं. यह सप्ताह आर्थिक रूप से अच्छा साबित होगा. संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान दें. यात्रा आपको आर्थिक लाभ देगी. राजनीतिक लोग थोड़ा संभल कर कोई निर्णय लें. विद्यार्थी पढ़ाई अच्छी करेंगे. युवा अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
कोई नई संपत्ति ख़रीदने की सोचेंगे, लेकिन संबंधित दस्तावेज़ों को अच्छी तरह परख लें. किसी परिवारीजन की अस्वस्थता की ख़बर मिल सकती है. नौकरीपेशा लोग थोड़ा उतार–चढ़ाव देखेंगे. व्यवसायी अच्छा व्यवसाय करेंगे. युवा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखेंगे. विद्यार्थियों की एकाग्रता कम हो सकती है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
किसी काम के लिए जिद न करें, अन्यथा नुक़सान हो सकता है. मित्रों एवं सहकर्मियों से मधुर संबंध बनाकर चलें, अन्यथा वे आपके विरोधी हो जाएंगे. नौकरीपेशा लोग शुभ समाचार पाने के लिए तैयार रहें. व्यवसायी वर्ग थोड़ा उतार–चढ़ाव देखेंगे. कोई पारिवारिक शुभ कार्य संपन्न हो सकता है. विद्यार्थी अध्ययन पर ध्यान देंगे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, अन्यथा नुक़सान होगा. पारिवारिक आदर्श की भिन्नता की वजह से अपनी अभिव्यक्ति दबाकर रखें. भाई–बहनों से सामंजस्य बनाकर चलें. आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे, कोई पुराना बकाया मिल सकता है. अधिकारी आपसे ख़ुश रहेंगे. विद्यार्थी अपनी एकाग्रता में उतार–चढ़ाव देखेंगे.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
प्रोन्नति की ख़बर मिलने की प्रबल संभावना है. संबंधों में धन का मामला बीच में न आने दें. पित्त–गुर्दे से संबंधित रोगी चिकित्सक से मिलने की योजना ज़रूर बनाएं. धैर्य बनाए रखें, सफलता ज़रूर मिलेगी. आर्थिक रूप से मशक्कत का समय है. विद्यार्थियों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
वाहन सावधानी से चलाएं और विवादों से बचें. यात्रा आपकी सफलता की वजह बनेगी. इस सप्ताह नीले वस्त्रों का प्रयोग करने से सफलता ज़्यादा आसान हो जाएगी. युवा उत्साहित रहेंगे. नौकरीपेशा और व्यापारी, दोनों वर्ग ख़ुश रहेंगे. परिवार के लिए शुभ समय. विद्यार्थी अपनी एकाग्रता खोएंगे.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
सबकी बात सुनने के बाद भी निर्णय स्वयं लें. किसी से अपने जीवन का रहस्य न बताएं. वाहन ख़रीदने की योजना बना सकते हैं. गर्म भोजन के सेवन से बचें. पानी सावधानी से पिएं. सफलता से बहुत उत्साहित न हों. आर्थिक रूप से मिला–जुला समय. विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
संयम से काम लें. जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें. धार्मिक स्थलों के भ्रमण की योजना बन सकती है. पारिवारिक माहौल सौहार्द्रपूर्ण रहेगा. मित्रों एवं सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. व्यय पर नियंत्रण रखें, अन्यथा तनाव महसूस करेंगे. विद्यार्थी और युवा उत्साहित रहेंगे.

feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

गणित कैसे मज़बूत होगी

बच्चों को पढ़ाई में बेहतर करने के लिए माता–पिता पता नहीं क्या–क्या करते हैं. अगर बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो वे बहुत ख़ुश होते हैं. वैसे अभिभावकों को बच्चों को पहेलियां हल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. हो सके तो बच्चों को रोज़ाना पहेलियां सुलझाने के लिए कहना चाहिए. एक अध्ययन के अनुसार, पहेलियां हल करने से बच्चों का गणितीय कौशल बेहतर होता है. शिकागो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अभिभावकों एवं बच्चों की 53 जोड़ियों को अपने अध्ययन में शामिल किया. उन्होंने पता लगाया कि 2 से 4 साल के वे बच्चे, जो पहेलियों से खेलते थे, उनमें स्थानिक कौशल का बेहतर विकास हुआ और वे तर्कों के माध्यम से गणितीय सवालों को आसानी से हल कर सकते थे. अध्ययन में शोधकर्ताओं ने अभिभावकों से अपने बच्चों के साथ वैसे ही बातचीत करने के लिए कहा, जैसा वे आम तौर पर करते थे. इसमें शामिल आधे बच्चों ने कम से कम एक बार पहेलियां हल की थीं. पाया गया कि पहेलियां सुलझाने से बच्चों में गणित, विज्ञान और तकनीकी कौशल बेहतर होता है. साथ ही यह बच्चों की समझ और ज्ञान का महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है. शोधकर्ताओं की टीम के प्रमुख ने कहा कि इस अध्ययन से पता चलता है कि 2 से 4 साल की उम्र के वे बच्चे, जो पहेलियां हल करते थे, 2 साल बाद उनका निरीक्षण करने पर उनमें गणित के प्रति बेहतर समझ देखने को मिली.

वज़न कम करें

आजकल मोटापा एक बहुत बड़ी चिंता है. जिसे देखो, वही मोटापे से परेशान है. मोटापे की बढ़ती समस्या को देखते हुए कई कंपनियां अपने कर्मचारियों की सेहत के प्रति काफी सजग हो गई हैं. शंघाई की एक आई टी कंपनी ने अपने यहां कार्यरत पेशेवरों को सुझाव दिया है कि वे प्रतिदिन ऑफिस में अपने कार्यस्थल पर कम से कम आधे घंटे खड़े होकर काम करें. ऐसा दिन भर में दो बार करना है. कंपनी के मुताबिक़, हर महीने जिस कर्मचारी का वज़न सबसे ज़्यादा घटेगा, उसे विजेता घोषित किया जाएगा. प्रतिस्पर्धा जीतने वाले के लिए आकर्षक ईनाम की व्यवस्था की गई है. इस क़दम के पीछे कंपनी का मकसद कर्मचारियों को स्वस्थ रखकर उत्पादकता में वृद्धि और ऑफिस में आधुनिक माहौल तैयार करना है.

अजीबोग़रीब शौक़

वैसे तो हर किसी के अपने शौक होते हैं. जो उन्हें अच्छा लगता है, वे वही करते हैं. आज की बदलती हुई दुनिया में अजूबों की कोई कमी नहीं है. लंदन की एक महिला के अनूठे शौक ने लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है. इस महिला को अलग–अलग किस्म के काग़ज़ खाने का अद्भुत शौक है. यह महिला हमेशा अपने बैग में काग़ज़ के छोटे–छोटे टुकड़े रखती है. वह इन्हें नियमित अंतराल के बाद खाती रहती है. उसके मुताबिक़, अपने शौक को पूरा करने के लिए वह हमेशा काग़ज़ एकत्र करती रहती है, ताकि व्यस्त रहने या बाज़ार में ख़रीददारी के दौरान भी वह उन्हें लुत्फ उठाते हुए खा सके. उसका कहना है कि हर काग़ज़ का अपना एक विशेष स्वाद होता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रथम दृष्टया इसे यमन की जनता की जीत कहा जा सकता है, लेकिन क्या वास्तविक तौर पर इसे क्रांति की सफलता कहना उचित होगा? सालेह की सरकार में हादी उप राष्ट्रपति रहे हैं.

यमन

सालेह का जाना ही काफ़ी नहीं है

राजीव कुमार

अली अब्दुल्ला सालेह ने उप राष्ट्रपति रहे अब्दरब्बो मंसूर हादी को औपचारिक तौर पर सत्ता सौंप दी. सालेह के ख़िलाफ़ पिछले साल से ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है. यमन में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. अरब के कई देशों एवं अमेरिका ने सालेह को सत्ता छोड़ने की सलाह दी थी. सालेह पर हमला भी हो चुका है, जिसमें वह घायल हो गए थे. वह अमेरिका से अपना इलाज कराकर वापस लौटे हैं. अमेरिका से वापस लौटने के बाद उन्होंने सत्ता हस्तांतरित करने का फ़ैसला लिया. स्पष्ट है कि अमेरिका में वह केवल अपना इलाज नहीं करा रहे थे, बल्कि इस बात पर भी चर्चा कर रहे थे कि उनका राष्ट्रपति पद पर बने रहना अब संभव है या नहीं. ज़ाहिर है, अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया होगा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनका राष्ट्रपति बने रहना सही नहीं है, क्योंकि विद्रोह धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है. उम्मीद तो यही जताई जा सकती है कि हादी को राष्ट्रपति बनाने का फ़ैसला भी अमेरिका के इशारे पर लिया गया. कहने के लिए तो हादी के पक्ष में 99 फ़ीसदी वोट पड़े, लेकिन इसे चुनाव तो नहीं कहा जा सकता है. हादी राष्ट्रपति पद के एकमात्र प्रत्याशी थे यानी उन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति बनाया गया.

प्रथम दृष्टया इसे यमन की जनता की जीत कहा जा सकता है, लेकिन क्या वास्तविक तौर पर इसे क्रांति की सफलता कहना उचित होगा? सालेह की सरकार में हादी उप राष्ट्रपति रहे हैं. वह सालेह के नज़दीकी लोगों में से एक हैं. सालेह ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया है. फिर इसे क्रांति की जीत कैसे कहा जा सकता है. क्रांति तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए की जाती है. यमन में जिन लोगों ने सालेह का विरोध किया था, उनका मतलब केवल सालेह को हटाए जाने से नहीं रहा है. सालेह के विरोध का मतलब उस व्यवस्था का विरोध था, जिसका नेतृत्व वह कर रहे थे. तैंतीस सालों के शासन में उन्होंने यमन के साथ जो किया, लोगों ने उसका विरोध करने के लिए प्रदर्शन किए. इसलिए नहीं कि सालेह अपना उत्तराधिकारी चुनकर चले जाएं, जो उनकी नीतियों को कार्यान्वित करता रहे. यमन की जनता भी इस सत्ता हस्तांतरण को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है. जब हादी शपथ ले रहे थे तो यमन की जनता प्रदर्शन कर रही थी. उसका कहना था कि अमेरिकी राजदूत जेरल्ड फीशर को देश से बाहर निकाला जाए. जनता अपने आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप के ख़िलाफ़ है. वह इस बात से वाक़िफ़ है कि सालेह का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है.

सालेह ने अमेरिका से वापस आने के बाद ही राष्ट्रपति पद त्यागने का निर्णय लिया. उन्होंने ख़ुद हादी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और एक छद्म चुनाव कराकर यह साबित करने की कोशिश की कि हादी को जनता का समर्थन प्राप्त है, जबकि बहुत सारे लोगों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया. यमन की राजधानी सना में सालेह का विरोध कर रहे लोग भी वहां से जाने के पक्ष में नहीं हैं. वे व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं. उनका कहना है कि सत्ता का इस तरह से हस्तांतरण निवर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन की गारंटी नहीं देता है. यमन में भ्रष्टाचार चरम पर है. यह सही है कि इस भ्रष्टाचार का मुखिया चला गया, लेकिन उनके सिपहसालार तो अभी भी अपने पदों पर बने हुए हैं. हादी को राष्ट्रपति बनाया गया है, लेकिन जब तक सालेह के समर्थक और रिश्तेदार फौज में ऊंचे पदों पर बने रहेंगे, तब तक यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह शासन सही तरीक़े से चला पाएंगे. सत्ता हस्तांतरण के बाद सना के चेंज स्क्वायर पर डटे युवाओं से पत्रकारों ने बात की तो उनका कहना था कि इसे उनकी जीत की शुरुआत कहा जा सकता है, पूरी जीत नहीं. पूरी जीत तो तब कही जाएगी, जबकि यमन में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो. छात्र ओसामा सुल्तान का कहना था कि महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हादी सेना के साथ क्या करते हैं. अगर उन्होंने सेना में परिवर्तन नहीं किया तो फिर उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है.

हालांकि हादी को अरब लीग और अमेरिका से समर्थन मिल रहा है. उन्होंने अरब लीग के जनरल सेक्रेटरी नबी-अल अरबी से मुलाकात की, जो उन्हें बधाई देने के लिए यमन आए हुए थे. यूरोपीय संघ ने भी हादी को बधाई दी. बगदाद में होने वाली अरब सम्मिट में शामिल होने के लिए यमन के राष्ट्रपति हादी को आमंत्रित किया गया है. देखा जाए तो हादी को वैश्विक समर्थन मिल रहा है, लेकिन अभी हादी को अपने देश की जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह उसकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. अगर वह स्वामिभक्ति के बदले देशभक्ति को ज़्यादा तवज्जो देंगे, तभी वह देश की जनता को विश्वास में ले सकेंगे. जनता व्यवस्था में परिवर्तन की इच्छा रखती है. लोग सालेह से परेशान थे, क्योंकि वह तानाशाह थे. उन्होंने अपने सगे संबंधियों को उच्च पदों पर बैठा रखा था. भ्रष्टाचार देश को खोखला करता जा रहा था, युवा वर्ग परेशान था, लेकिन यमन के लोगों को मौक़ा नहीं मिल रहा था कि वे सालेह के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल सकें, लेकिन जैसे ही अरब के अन्य देशों में तानाशाही के ख़िलाफ़ विद्रोह भड़का, यमन की जनता को भी संबल मिल गया. उसने भी सालेह की तानाशाही का विरोध करना शुरू कर दिया. सालेह को अमेरिका का समर्थन हासिल था, इसलिए वह ज़्यादा दिनों तक विद्रोहियों को उलझाए रखने में सफल रहे, लेकिन जब सालेह और उनके आका को लगा कि बिना सत्ता हस्तांतरण के इसे रोका नहीं जा सकता तो उन्होंने एक चाल चल दी और अपने उप राष्ट्रपति को सत्ता सौंपकर अपनी परोक्ष सत्ता बनाए रखने की साजिश की. अब गेंद हादी के हाथों में है. अगर वह सालेह के हाथों की कठपुतली बने रहे और अमेरिका के इशारों पर काम करते रहे तो फिर यमन में शांति क़ायम नहीं हो सकेगी. अगर हादी अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो उन्हें सेना के नेतृत्व में परिवर्तन करके निष्पक्ष चुनाव कराने होंगे और इसके लिए उन्हें ख़ुद को सालेह की गिरफ्त से आज़ादी पानी होगी. देखना यह है कि सालेह अपनी चाल में कामयाब होते हैं या हादी अपना भविष्य सुरक्षित कर पाते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

अफ़ग़ानिस्तान

शांति बहाली का यह तरीक़ा ठीक नहीं

अफ़ग़ानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए तालिबान से बातचीत की कोशिश की जा रही है. अमेरिका अपने स्तर पर तालिबानियों से वार्ता करने की बात कह रहा है तो अफ़ग़ानिस्तान अपने स्तर पर. तालिबान ने कतर में अपना कार्यालय खोलने की बात कही है. अमेरिका कतर में ही तालिबानियों से बातचीत करेगा. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रज़ा गिलानी ने कतर की यात्रा की. वैसे तो कहा गया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की यह यात्रा कतर से व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए की जा रही है, लेकिन इसमें तालिबान-अमेरिका वार्ता की बात न हो, ऐसा कहना मुश्किल होगा. तालिबान के पाकिस्तानी संपर्कों के कारण अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर उसका सहयोग करे. पाकिस्तान भी खुलकर यह नहीं कह सकता कि वह तालिबान-अमेरिका वार्ता और शांतिपूर्ण समाधान के लिए कोशिश नहीं करेगा. चूंकि अभी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं. इसलिए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका को पूरा सहयोग नहीं दे रहा है. हालांकि अमेरिका ने तालिबान से बातचीत करने की सूचना पाकिस्तान को दी है और इस वार्ता को सफल बनाने के लिए सहयोग की भी अपील की है. दूसरी तरफ़ अफ़ग़ानिस्तान सरकार देश में शांति क़ायम करने के लिए तालिबान से वार्ता करने की कोशिश कर रही है. तालिबान-अफ़ग़ान वार्ता में सऊदी अरब मध्यस्थता कर रहा है. अफ़ग़ानिस्तान भी चाहता है कि तालिबान के साथ उसकी वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका हो, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान को अलग-थलग रखकर तालिबान के साथ उसकी वार्ता सफल नहीं हो सकती. अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने पाकिस्तान सरकार से इस वार्ता में सहयोग की अपील की है. इसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री गिलानी ने अफ़ग़ानिस्तान में संघर्ष कर रहे तालिबान से अपील की कि वह अफ़ग़ानिस्तान के साथ बातचीत करे. ग़ौरतलब है कि जब हामिद करजई ने तालिबान से शांति वार्ता की बात कही थी तो उसने ऐसा करने से इंकार कर दिया था. वह करजई सरकार को मान्यता देने के पक्ष में नहीं था. उसका कहना था कि वह केवल अमेरिका या अफ़ग़ानिस्तान के अन्य सहयोगी देशों के साथ ही बातचीत करेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सऊदी अरब की मध्यस्थता में यह वार्ता होगी, जिसमें पाकिस्तान का भी सहयोग अफ़ग़ानिस्तान को मिलेगा.

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह अफ़ग़ानिस्तान में शांति बहाल हो जाएगी, क्या अमेरिका अफ़ग़ानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए ही तालिबान से वार्ता करना चाहता है, अगर मुद्दा अफ़ग़ानिस्तान में शांति बहाली का है तो अमेरिका ने तालिबान के साथ वार्ता में अफ़ग़ानिस्तान को शामिल करना ज़रूरी क्यों नहीं समझा, कतर और अमेरिका अपने स्तर पर तालिबान से वार्ता करने को तैयार क्यों हो गए? अफ़ग़ानिस्तान ने तो कतर से अपना राजदूत भी बुला लिया था. हालांकि बाद में कतर ने अपनी भूल सुधारने की कोशिश की और एक प्रतिनिधिमंडल अफ़ग़ानिस्तान भेजा, ताकि दोनों देशों के बीच की ग़लतफ़हमियां दूर की जा सकें, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है. क्या वह वास्तव में तालिबान के साथ वार्ता केवल अपने सैनिकों को तालिबानी गिरफ्त से मुक्त कराने के लिए कर रहा है. अफ़ग़ानिस्तान में भी यही बात उठ रही है. अगर अमेरिका अफ़ग़ानिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सेना के जाने के पहले वहां शांति बहाल करना चाहता है तो फिर उसे अफ़ग़ानिस्तान सरकार को वार्ता में शामिल करना चाहिए. आख़िरकार अमेरिका के जाने के बाद स्थितियों से निपटना तो अफ़ग़ानिस्तान सरकार को है. अफ़ग़ानिस्तान अपने स्तर से प्रयास करे और अमेरिका अपने स्तर से, यह तो कोई बात नहीं हुई. पाकिस्तान के लिए भी यह निर्णय करना मुश्किल होगा कि वह किसके साथ सहयोग करे. अगर यही वार्ता अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और तालिबान को एक मंच पर लाकर की जाए तो इस बात की उम्मीद अधिक है कि अफ़ग़ानिस्तान में शांति बहाल हो जाए. अगर सभी अपनी डफली-अपना राग अलापते रहे तो फिर समस्या का समाधान होना मुश्किल है.

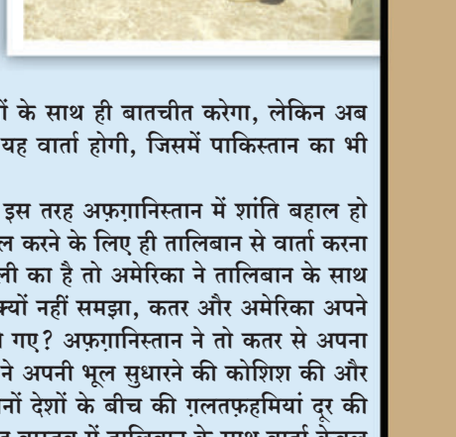

राजीव कुमार
feedback@chauthiduniya.com

मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के मुईनुद्दीन, श्रीनगर के एम जी बुक सेंटर के शब्बीर अहमद और किताबी दुनिया के इक़बाल का कहना है कि उर्दू अदब ख़ासकर शायरी की किताबें ज़्यादा बिक रही हैं.

साईं नाम जप लेना

कष्टों को मिटाना हो, दुःख दूर भगाना हो
तो साई नाम जप लेना....साई नाम जप लेना
हां, साई नाम जप लेना....

संतों ने कहा है, महंतों ने कहा है,
साई की महिमा तो सबसे जुदा है,
तुम्हें शिरडी जाना हो, साई दर्शन पाना हो,
तो साई नाम जप लेना....

बाबा का भंडारा जो कोई भी कराए,
सुख-संपत्ति उसके घर में आ जाए,
फरियाद लगाना हो, बुझे दीप जलाना हो,
तो साई नाम जप लेना....

बाबा के दर से कोई खाली नहीं जाता,
रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता,
तुझे बिगड़ी बनाना हो, किस्मत चमकाना हो,
तो साई नाम जप लेना....

मैंने ओढ़ लिया है चोला

मैंने ओढ़ लिया है, चोला देखो साई नाम का,
यह दुनिया है जंजाल, न तेरे-मेरे काम का,
मैंने ओढ़ लिया है, चोला देखो साई नाम का,

बाबा के दीवानों पर कष्ट कभी नहीं आता है,
यह ऐसा दर है, जहां से खाली कोई नहीं जाता है,
मैंने आज ही खाता खोला, देखो साई नाम का.

शिरडी में साई तूने सबको कैसा करिश्मा दिखाया है,
राम, रहीम, शिव और यीशू, तुझमें सबकी छाया है,
मेरा मन है अब तो डोला, देखो साई नाम का.

साई शरण में आके प्राणी, काहे को घबराता है,
साई तो है सबका बाबा, तेरा भी उनसे नाता है,
मैंने मन में अमृत घोला, देखो साई नाम का.

असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे प्रयास नहीं किए गए.
स्व. मालती कपूर

मां होने के कारण नारी का स्थान भगवान से भी ऊंचा है.
प्रेमचंद

आरती श्री शिरडी के साईबाबा की

आरती श्री साई गुरूवर की, परमानंद सदा सुरवर की
जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख, शोक, संकट, भयहारी
शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया
कितने भक्त चरण पर आए, वे सुख शांति चिरतंन पाए
भाव धरे मन में जैसा, पावत अनुभव वो ही वैसा
गुरू की लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को
साई नाम सदा जा गावे, सो फल जग में शाश्वत पावे
गुरूबारसर करि पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा
राम, कृष्ण, हनुमान रूप में, दे दर्शन जानत जो मन में
विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन से इच्छित फल पाते
जय बोलो साई बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरू की
साईदास आरती को गावे, घर में बसि सुख मंगल पावे.

नारायण सिंह कोरी
feedback@chauthiduniya.com

विश्व पुस्तक मेले में किताबों की बहार

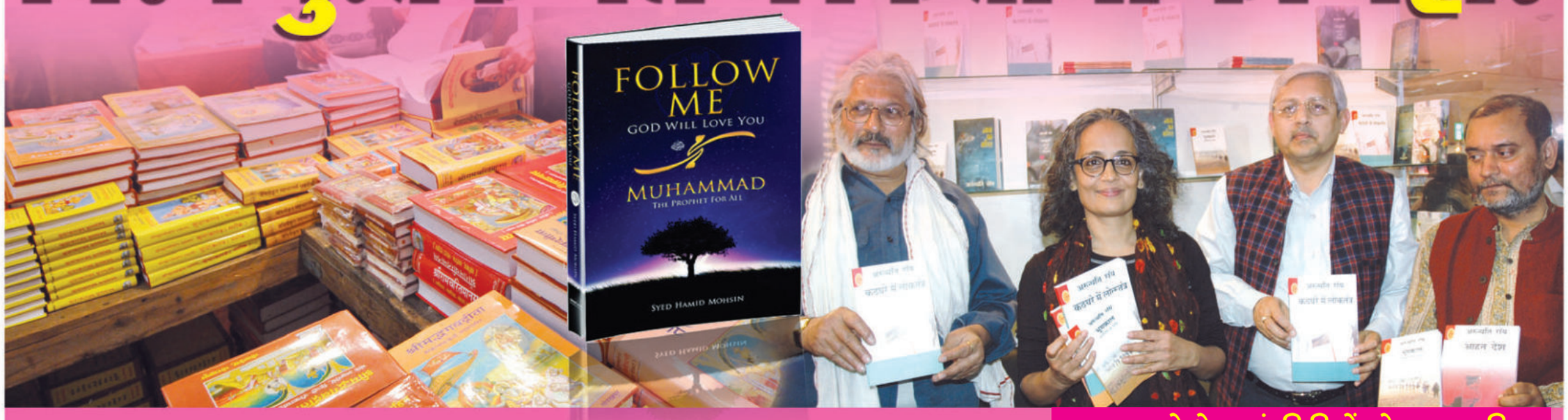

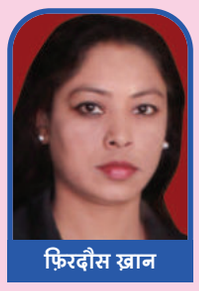

फ़िरदौस ख़ान

पुस्तक प्रेमी विश्व पुस्तक मेले का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. दिल्ली के प्रगति मैदान में बीती 25 फरवरी से 4 मार्च तक चले विश्व पुस्तक मेले का इस बार भी देश भर से आए पुस्तक प्रेमियों ने जमकर लुत्फ उठाया. किसी स्टॉल पर किताबों का लोकार्पण हो रहा था तो किसी स्टॉल पर लोग अपने प्रिय लेखक से गुफ्तगू कर रहे थे. प्रगति मैदान में बाहर पलाश के फूल दहक रहे थे तो अंदर किताबों की बहार थी. मेले का उद्घाटन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने किया. इस मौक़े पर उन्होंने कहा कि मेले की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार इसे हर साल आयोजित करने की योजना बना रही है. उन्होंने इस आयोजन को अफ्रीका-एशिया क्षेत्र में पुस्तकों से संबंधित प्रमुख आयोजनों में से एक बताया. फ़िलहाल यह मेला दो साल में एक बार लगता है. भारत अंग्रेजी किताबों का तीसरा सबसे बड़ा प्रकाशक देश है.

राजकमल प्रकाशन समूह के स्टॉल पर प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय की हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों, कठघरे में लोकतंत्र, भूमकाल: कॉमरेडों के साथ, आहत देश का विमोचन किया गया. इस मौक़े पर अरुंधति रॉय पाठकों से रू-ब-रू हुईं और पाठकों ने उनसे उनकी रचनाधर्मिता के बारे में चर्चा की. ग़ौरतलब है कि अरुंधति रॉय की उक्त पुस्तकें आदिवासियों और उनके संघर्षों से जुड़े कॉमरेडों के साथ बिताए हुए समय और उन कारणों पर रोशनी डालती हैं, जिनके चलते वह शोषित समाज के साथ जुड़कर व्यवस्था के विरुद्ध संघर्षरत हैं. द गॉड ऑफ स्माल थिंग्स (हिंदी में अनुवाद-मामूली चीज़ों का देवता) के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है. राजकमल प्रकाशन के मीडिया प्रभारी एवं राष्ट्रव्यापी पुस्तक प्रसार अभियान के संयोजक मुकेश कुमार ने बताया कि सबसे ज़्यादा बिकने एवं रॉयल्टी पाने वाली शीर्ष अट्ठारह महिला साहित्यत्कार दिल्ली के पुस्तक प्रेमियों के बीच सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं. इनमें सबसे शीर्ष पर हैं शिवानी, मन्नू भंडारी दूसरे, कृष्णा सोबती तीसरे, मैत्रेयी पुष्पा चौथे, महाश्वेता देवी पांचवें, मृणाल पांडेय छठे, महुआ माझी सातवें, ममता कालिया आठवें, चंद्रकांता नौवें एवं गीतांजलीश्री दसवें स्थान पर हैं. मेले में उर्दू के स्टॉल भी पुस्तक प्रेमियों को आकर्षित कर रहे थे. इस्लामी किताब घर के निदेशक एवं लेखक ताहा नसीम ने कहा कि यह देखकर ख़ुशी हो रही है कि उर्दू के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है. उर्दू को मुसलमानों की भाषा प्रचारित कर देने से इसका काफ़ी नुक़सान हुआ, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ रहा है. उनके स्टॉल पर आने वाले ग़ैर मुस्लिम लोग ऐसी किताब की मांग करते हैं, जिससे वे जल्द से जल्द उर्दू सीख सकें. उर्दू सीखने की किताब ख़रीदने वाले अनुराग का कहना है कि उर्दू में ग़ज़ब का आकर्षण है. यह भाषा व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है. इसलिए वह उर्दू सीखना चाहते हैं. उन्हें शायरी पढ़ने का भी बेहद शौक़ है. उर्दू सीख लेने के बाद वह उर्दू साहित्य को पढ़ पाएंगे. मक़तबा दारूल उलूम देवबंद के स्टॉल पर इस्लामी किताबों की बहार थी. यहां उर्दू के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में भी किताबें थीं. मोहम्मद फ़ैज़ान ने बताया कि उनके यहां आने वालों में ग़ैर मुसलमानों की भी तादाद काफ़ी है. इनमें ज़्यादातर छात्र हैं, जो इस्लाम को जानना और समझना चाहते हैं. मेले में क़ौमी काउंसिल बराए-ए-फरोग़-ए-उर्दू ज़बान सहित देश भर के उर्दू प्रकाशकों के स्टॉल थे, जहां इस्लामी, साहित्य, इतिहास एवं अन्य विषयों के नामी-गिरामी लेखकों की किताबें सजी थीं. मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के मुईनुद्दीन, श्रीनगर के एम जी बुक सेंटर के शब्बीर अहमद और किताबी दुनिया के इक़बाल का कहना है कि उर्दू अदब ख़ासकर शायरी की किताबें ज़्यादा बिक रही हैं. इसके अलावा उर्दू सिखाने वाली किताबों, उर्दू-हिंदी शब्दकोष और इस्लाम से संबंधित किताबों की ख़ासी मांग है. बरखा कहती हैं कि वह इस्लाम के दर्शन के बारे में जानना चाहती हैं, ख़ासकर महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर इस्लाम के नज़रिये को समझने की ख्वाहिशमंद हैं. बीए तृतीय वर्ष की छात्रा फ़ौज़िया परवीन बताती हैं कि वह ऐसी किताब चाहती थीं, जिससे अंग्रेजी व्याकरण आसानी से समझ में आ जाए और वह अंग्रेजी बोलना सीख सकें. उन्हें यहां ऐसी कई किताबें मिल गईं, जो उनके लिए बेहद उपयोगी हैं. उनकी छोटी बहन तस्मिया परवीन ने अरब की कहानियों और लोककथाओं की कई किताबें लीं. राजकुमारी ने पाक कला से संबंधित किताबें ख़रीदीं. वह कहती हैं कि हाल में उनका विवाह हुआ है और वह नए-नए व्यंजन बनाकर अपने परिवार के लोगों का मन मोह लेना चाहती हैं. पढ़ाई और नौकरी के बीच कभी इतना समय नहीं मिला कि वह यह सब सीख पातीं, लेकिन अब तो सीखना ही पड़ेगा. पंजाबी के चार प्रकाशनों ने अपने स्टॉल लगाए थे. आर सी पब्लिशर्स के रंजीत सिंह बताते हैं कि यह देखकर अच्छा लग रहा है कि लोग पंजाबी के स्टॉल तलाशते हुए यहां आ रहे हैं. ज़्यादातर पंजाबी लोग ही गुरुमुखी की किताबें ख़रीद रहे हैं. पंजाबी के प्रसिद्ध लेखकों अमृता प्रीतम, बलराज साहनी, जसवंत सिंह कंवल, शिवकुमार बटावली, प्रो. किशन सिंह, करतार सिंह दुग्गल, मोहन सिंह, नरेंद्र पाल सिंह, महिंदर सिंह सरना और डॉ. जसवंत गिल आदि की किताबों की ख़ासी मांग है. दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी माध्यमिक कार्यान्वयन निदेशालय के स्टॉल पर शोधार्थियों और छात्रों के उपयोग की किताबें थीं. उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से आए अवनीश कुमार ने बताया कि वह आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और यहां किताबें ख़रीदने आए हैं. इस स्टॉल पर वाजिब दाम में उपयोगी किताबें मिल जाती हैं. ग़ौरतलब है कि नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस 20वें मेले में 1300 प्रकाशकों ने शिरकत की. इसके साथ ही 30 विदेशी प्रकाशक भी इस मेले में शामिल हुए, जिनमें सऊदी अरब, हांगकांग, मलेशिया, जापान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जर्मनी, यूएई, चीन, तुर्की, दक्षिण कोरिया, स्पेन, बेलारूस, फ्रांस, ईरान, थाईलैंड, इजराइल और यूके शामिल हैं. इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को और विश्व बैंक आदि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. पुस्तक मेला सुबह ग्यारह बजे से रात के आठ बजे तक चला. इस साल बच्चों के लिए 10 रुपये और वयस्कों के लिए 20 रुपये का टिकट रखा गया था.

firdaus@chauthiduniya.com

राजकमल ने श्रेष्ठ पांडुलिपियों को पुरस्कृत किया

राजकमल प्रकाशन ने अपने 63वें स्थापना दिवस के मौक़े पर बीती 28 फरवरी को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में तीसरा और चौथा राजकमल प्रकाशन कृति सम्मान प्रदान किया. तीसरा पांडुलिपि कृति सम्मान मैला आंचल-फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार लेखिका महुआ माजी की पांडुलिपि मरंग गोड़ा नील कंठ हुआ को और चौथा सम्मान लोकायत-देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय पुरस्कार अमरेंद्र किशोर की पांडुलिपि बादलों के रंग हवाओं के संग को दिया गया. वरिष्ठ आलोचक डॉ. नामवर सिंह, प्रतिष्ठित लेखिका कृष्णा सोबती एवं गीतकार-पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने सम्मान स्वरूप महुआ माजी और अमरेंद्र किशोर को एक-एक लाख रुपये की नक़द राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया. महुआ माजी और अमरेंद्र किशोर को पुस्तक पर रॉयल्टी भी दी जाएगी. सम्मान समारोह का आयोजन लोदी रोड स्थित इंडिया इंटरनेशनल में किया गया. समारोह में देश के जाने-माने साहित्यकारों ने शिरकत की. इस साल से राजकमल प्रकाशन ने हिंदी में सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के मक़सद से सृजनात्मक गद्य सम्मान देने की परंपरा शुरू की है. पहला राजकमल सृजनात्मक गद्य सम्मान (शांति कुमारी वाजपेयी की याद में) आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक व्योमकेश दरवेश:आचार्य हजारी प्रसाद का पुण्य स्मरण को दिया गया. पुरस्कार स्वरूप एक लाख रुपये की नक़द राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया. इससे पहले बीती 26 फरवरी को उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सुप्रतिष्ठित ग़ज़लकार एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर की हिंदी में प्रकाशित किताब लावा का लोकार्पण किया. इंडिया हेबिटेट सेंटर के स्टेर ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में अंसारी ने लावा शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि जावेद अख्तर की ग़ज़लें और नज्में लावा शब्द के अर्थों पर पूरी तरह मुकम्मल उतरती हैं.

धार्मिक किताबें छाईं

विश्व पुस्तक मेले के पहले दिन बंगलौर के प्रसिद्ध सलाम सेंटर के चेयरमैन सैयद हामिद मोहसिन की पैग़ंबर-ए-इस्लाम पर अंग्रेजी किताब फॉलो मी गॉड विल लव यू के हिंदी संस्करण मोहम्मद से वफ़ा-मोहम्मद सबके लिए का लोकार्पण विख्यात आलिमेदीन एवं क़ुरआन के हिंदी अनुवादक मौलाना मोहम्मद फ़ारूक़ ख़ां ने किया. इस मौक़े पर उन्होंने कहा कि मोहम्मद किसी विशेष धर्म, संप्रदाय, समय और क्षेत्र के नहीं, बल्कि सबके थे. उन्होंने कहा कि यही कारण है कि उनकी आदर्श जीवनी और शिक्षाओं को धर्म एवं संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं. सैयद हामिद मोहसिन ने बताया कि उनका सेंटर ग़ैर मुस्लिमों से एक फॉर्म भरवा कर उन्हें यह किताब मुफ्त दे रहा है, जबकि मुसलमानों से इसके लिए 150 रुपये लिए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि चार साल पहले सलाम सेंटर ने इस किताब का वितरण शुरू किया था और अब तक क़रीब डेढ़ लाख किताबें बांटी जा चुकी हैं. ये किताबें छह भाषाओं में हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी शामिल है. क़ुरआन की हिंदी और अंग्रेजी प्रतियां वितरित करने के पीछे उनका मक़सद इसके प्रति ग़ैर मुस्लिमों की भ्रांतियां दूर करना है. मेले में गीता प्रेस, रामकृष्ण मिशन, गायत्री परिवार, राधास्वामी ब्यास जैसे धार्मिक संगठनों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर भी ख़ासी भीड़ थी. यहां हिंदू धर्म एवं वेदों पर आधारित किताबों के अलावा अन्य धर्मों से संबंधित किताबें भी थीं.

साहिर ने फिल्मी दुनिया में भी अपनी शायरी का कमाल दिखाया. उनके गीतों और नज़्मों का जादू सिर चढ़कर बोलता था. उनका नाम जिस फिल्म से जुड़ जाता था, उसमें वह सर्वोपरि होते थे.

अनंत विजय

पत्रकार की नज़र में आंदोलन

काफी लंबे समय के बाद भारतीय समाज में एक ऐसा आंदोलन देखने को मिला, जिसके समर्थन में जनता स्वत:स्फूर्त तरीक़े से सामने आई. जनता के समर्थन से होने वाले इस आंदोलन ने सरकार की नींद उड़ा दी. अगर हम भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर नज़र डालते हैं तो जय प्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के बाद यह पहला बड़ा आंदोलन था, जिसे देशव्यापी जनसमर्थन मिला. हम बात कर रहे हैं लोकपाल की मांग को लेकर किए गए अन्ना हजारे के आंदोलन की. लंबे समय से प्रिंट और टेलीविज़न पत्रकारिता कर रहे युवा संपादक आशुतोष की नई किताब आई है–अन्ना, थर्टीन डेज दैट अवेकंड इंडिया. जैसा कि किताब के नाम से ही स्पष्ट है कि यह किताब अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को केंद्र में रखकर लिखी गई है. आशुतोष अपनी किताब में तक़रीबन साल भर से भी कम के बेहद छोटे से कालखंड को उठाते हैं और उसमें घट रही घटनाओं को सूक्ष्मता से परखते हुए अपने राजनीतिक विवेक के आधार पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में टिप्पणियां करते चलते हैं. किताब की शुरुआत बेहद दिलचस्प और रोमांचक तरीक़े से होती है. रामलीला मैदान में अपने सफल अनशन के बाद अन्ना मेदांता अस्पताल में इलाज करा रहे होते हैं. अचानक एजेंसी पर ख़बर आती है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. जबकि कुछ घंटे पहले ही अन्ना के डॉक्टरों ने ऐलान किया था कि उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में चार से पांच दिन लगेंगे. अचानक आई इस ख़बर के बाद संपादक की उत्तेजना और टेलीविज़न चैनल के न्यूज़ रूम में काम कर रहे पत्रकारों के उत्साह से लबरेज माहौल से यह किताब शुरू होती है. जिस तरह से ख़बर आगे बढ़ती है, उसी तरह से रोमांच अपने चरम पर पहुंचता है. इसमें एक ख़बर को लेकर संपादक की बेचैनी और उसके सही साबित होने का संतोष भी लक्षित किया जा सकता है.

आशुतोष ने अपनी इस किताब में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ शुरू हुई मुहिम को शुरुआत से लेकर अन्ना के मुंबई के असफल अनशन तक को समेटा है. अन्ना और उनके आंदोलन पर लिखी गई इस किताब को आशुतोष ने बीस अध्यायों में बांटकर उसके विभिन्न पहलुओं को उद्घाटित किया है.

एक संपादक के तौर पर आशुतोष उस वक़्त चिंतित और खिन्न दिखाई पड़ते हैं, जब बाबा रामदेव की अगुवानी के लिए प्रणब मुखर्जी के एयरपोर्ट जाने की ख़बर आती है. आशुतोष के मुताबिक़, जिस समय यह ख़बर आई, उस समय वह एडिटर्स गिल्ड की बैठक में प्रणब मुखर्जी के साथ मौजूद थे. दफ्तर से जब यह पूछते हुए फोन आता है कि क्या प्रणब मुखर्जी बाबा रामदेव की अगुवानी के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं तो उसके उत्तर में वह कहते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग़ ख़राब हो गया है. तुम यह सोच भी कैसे सकते हो कि प्रणब मुखर्जी रामदेव को रिसीव करने जाएंगे. रामदेव कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं हैं. इसके बाद जब यह ख़बर सही साबित होती है तो आशुतोष इसे सरकार के संत्रास के तौर पर देखते हैं और इसके राजनीतिक मायने और आगे की राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव पर अपनी चिंता जताते हैं. दरअसल, आशुतोष अन्ना के दिल्ली के आंदोलनों के चश्मदीद गवाह रहे हैं, चाहे वह जंतर–मंतर का अनशन हो या राजघाट का अनशन या फिर रामलीला मैदान का ऐतिहासिक अनशन, जिसने सरकार को घुटने पर आने को मजबूर कर दिया था. अन्ना के आंदोलन के दौरान जिस तरह से देश भर में उन्हें जनसमर्थन मिलता है, उसके सामाजिक कारणों की भी लेखक ने पड़ताल की है. दरअसल, इस किताब में आशुतोष ने लोकपाल के लिए आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, उसके अंदर की कहानी को भी सामने रखा है. आशुतोष की यह किताब पढ़ने के बाद एक बात साफ तौर पर उभर कर सामने आती है कि अन्ना आंदोलन के दौरान उनके अंदर का रिपोर्टर बेहद सक्रिय था. संपादक के अंदर का वह रिपोर्टर एक साथ टीम अन्ना और सरकार के अपने सूत्रों से जानकारियां ले रहा था. अपने सूत्रों से मिल रही जानकारियों से वह न सिर्फ़ अपने प्रतियोगियों को पीछे छोड़ रहा था, बल्कि दर्शकों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को भी बख़ूबी निभाकर संतोष का अनुभव कर रहा था. अन्ना हजारे को जब उनके सहयोगियों अरविंद केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली के मयूर विहार से हिरासत में लिया गया था, उस वक़्त अरविंद के एसएमएस लगातार उनके पास आ रहे थे, जो अन्ना की पल–पल की गतिविधियों की जानकारी दे रहे थे. इसी तरह रामलीला मैदान में अनशन के दौरान भी उनके पास ख़बरें पहले आ रही थीं.

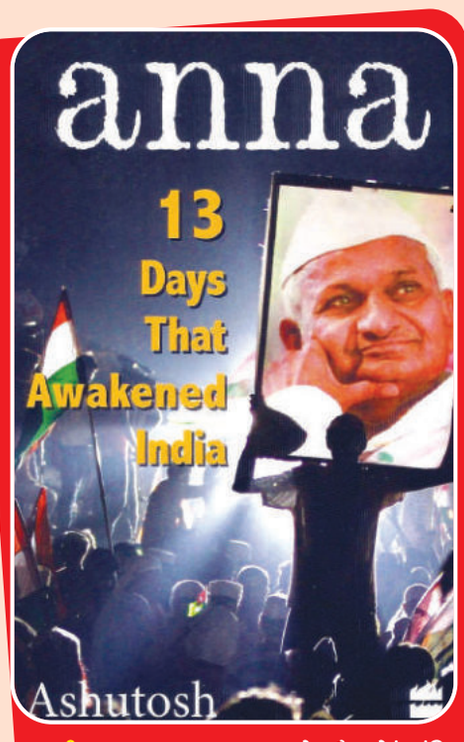

समीक्ष्य पुस्तक : अन्ना, 13 डेज दैट अवेकंड इंडिया
लेखक : आशुतोष
प्रकाशक : हॉर्पर कॉलिंस, नोएडा, उत्तर प्रदेश.
मूल्य : 199 रुपये

अपनी इस किताब में आशुतोष ने अन्ना के आंदोलन से ठीक तरीक़े से न निबट पाने के लिए ग़ैर राजनीतिक मंत्रियों को ज़िम्मेदार माना है. उनके मुताबिक़, यह एक राजनीतिक आंदोलन था, जिससे राजनीतिक रूप से ही निबटा जा सकता था. आशुतोष के मुताबिक़, दो ग़ैर राजनीतिक वकील मंत्रियों ने इस पूरे मामले को मिसहैंडिल किया. ज़ाहिर तौर पर उनका इशारा चिदंबरम और कपिल सिब्बल की ओर है. लेखक का मानना है कि जिस तरह से अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निबटने की सरकार ने रणनीति बनाई, वह ग़ैर राजनीतिक मंत्रियों की नाकामी और आंदोलन को समझ न पाने का नमूना है. आशुतोष लोकपाल आंदोलन के दौरान देश से सोनिया गांधी की अनुपस्थिति को भी उसी मिसहैंडलिंग से जोड़कर देखते हैं. ग़ौरतलब है कि उसी दौर में सोनिया गांधी अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए अमेरिका में थीं. आशुतोष अन्ना के आंदोलन में संघ की भागीदारी पर बेबाकी से कलम चलाते हैं और कई संदर्भों एवं लोगों की बातों को आधार बनाकर अपनी बात कहते हैं.

इस किताब की ख़ूबसूरती इस बात में है कि इसमें अन्ना के आंदोलन के सामने और पर्दे के पीछे के तथ्यों एवं गतिविधियों का प्रामाणिक दस्तावेजीकरण किया गया है. लेकिन जब भी, जहां भी लेखक को लगता है, वह अन्ना और उनकी टीम की आलोचना से भी नहीं हिचकते हैं. जब इमाम बुखारी के बयान के दबाव में अनशन स्थल पर रोजा खुलवाने जैसा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो आशुतोष उसे सस्ते राजनीतिक हथकंडे के तौर पर देखते हैं और कड़ी टिप्पणी करते हैं. अन्ना आंदोलन के विरोध में लेख लिखकर या फिर महत्वहीन चीजों के आधार पर आंदोलन की लानत मलामत करने वालों को भी लेखक बख्शता नहीं है. किताब के अंत में एपिलॉग में आशुतोष ने मुंबई में अन्ना के आंदोलन के असफल होने की वजहें भी गिनाई हैं. इस किताब का प्राक्कथन मशहूर समाजवादी चिंतक आशीष नंदी और इंट्रोडक्शन योगेंद्र यादव ने लिखा है. योगेंद्र यादव इस किताब को इस आंदोलन के इतिहास का रफ ड्राफ्ट कहते हैं.

पिछले दिनों कई संपादकों की किताबें आईं, जिनमें आउटलुक के प्रधान संपादक विनोद मेहता की लखनऊ ब्वॉय और एस निहाल सिंह की इंक इन माई वेंस अ लाइफ इन जर्नलिज्म प्रमुख हैं. ये दोनों किताबें कमोबेश उनकी आत्मकथाएं हैं, जिनमें उनके दौर की राजनीतिक गतिविधियों का संक्षिप्त दस्तावेजीकरण है. हालांकि विनोद मेहता और एस निहाल सिंह की किताबों की तुलना आशुतोष की किताब– अन्ना, थर्टीन डेज दैट अवेकंड इंडिया से नहीं की जा सकती है. विनोद मेहता और निहाल सिंह की किताबों में लंबे कालखंड की राजनीतिक घटनाएं लेखक के हवाले से सामने आती हैं, वहीं आशुतोष चंद महीनों के एक ही राजनीतिक आंदोलन पर अपनी लेखनी चलाते हैं. अगर हम समग्रता में देखें तो इस किताब में अन्ना के आंदोलन को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा और परखा गया है. लेखक ने बेहद श्रमपूर्वक उस आंदोलन से जुड़ी हर छोटी–बड़ी घटना को अपनी किताब में समेटा है. अन्ना के आंदोलन को जानने और समझने के लिए यह एक ज़रूरी किताब है, जिससे भविष्य के शोधार्थियों को काफी मदद मिलेगी.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

साहिर लुधियानवी हर पल के शायर थे

बीती आठ मार्च को साहिर लुधियानवी का जन्मदिन था. उनके चाहने वालों ने इसे अपने–अपने तरीक़े से मनाकर उन्हें अपनी अक़ीदत के फूल पेश किए. जहां रेडियो पर उनके लिखे गाने दिन भर बजे, वहीं श्रोताओं ने भी उनके गानों की ख़ास तौर पर फ़रमाइश की. वैसे तो साहिर का असली नाम अब्दुल हयी साहिर था, लेकिन उन्होंने इसे बदल कर साहिर लुधियानवी रख लिया था. उनका जन्म 8 मार्च, 1921 में लुधियाना के एक जागीरदार घराने में हुआ था. उनके पिता बेहद अमीर थे. घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन माता–पिता के अलगाव के बाद वह अपनी मां के साथ रहे और इस दौरान उन्हें गुरबत में दिन गुज़ारने पड़े. उन्होंने लुधियाना के ख़ालसा हाईस्कूल से दसवीं की. गवर्नमेंट कॉलेज से 1939 में उन्हें निकाल दिया गया था. बाद में इसी कॉलेज में वह मुख्य अतिथि बनकर आए थे. यहां से संबंधित उनकी नज़्म बहुत मशहूर हुई:–

इस सर ज़मीन पे आज हम इक बार ही सही
दुनिया हमारे नाम से बेज़ार ही सही
लेकिन हम इन फ़िज़ाओं के पाले हुए तो हैं
गर यहां नहीं तो यहां से निकाले हुए तो हैं

1943 में वह लाहौर आ गए और उसी साल उन्होंने अपना पहला कविता संग्रह तल्ख़ियां शाया कराया, जो बेहद लोकप्रिय हुआ और उनकी ख्याति दूर–दूर तक फैल गई. इसके बाद 1945 में वह प्रसिद्ध उर्दू पत्र अदब–ए–लतीफ़ और शाहकार लाहौर के संपादक बन गए. बाद में वह द्वैमासिक पत्रिका सवेरा के भी संपादक बने. इस पत्रिका में उनकी एक नज़्म को पाकिस्तान सरकार ने अपने ख़िलाफ़ बग़ावत मानते हुए उनके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया. 1949 में उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और दिल्ली आ गए. यहां उनका दिल नहीं लगा और वह मुंबई चले आए. वहां वह उर्दू पत्रिका शाहराह और प्रीतलड़ी के संपादक बने. इसी साल उन्होंने फिल्म आज़ादी की राह के लिए गीत लिखे. संगीतकार सचिन देव बर्मन की फिल्म नौजवान के गीत ठंडी हवाएं लहरा के आएं...ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई. इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने सचिन देव बर्मन के अलावा, एन दत्ता, शंकर जयकिशन और ख़य्याम जैसे संगीतकारों के साथ काम किया. साहिर एक रूमानी शायर थे. उन्होंने ज़िंदगी में कई बार मुहब्बत की, लेकिन उनका इश्क़ कभी परवान नहीं चढ़ पाया. वह अविवाहित रहे. कहा जाता है कि एक गायिका ने फिल्मों में काम पाने के लिए साहिर से नज़दीकियां बढ़ाईं और बाद में उनसे किनारा कर लिया. इसी दौर में साहिर ने एक ख़ूबसूरत नज़्म लिखी:–

चलो इक बार फिर से
अजनबी बन जाएं हम दोनों
चलो इक बार फिर से...
न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिलनवाज़ी की
न तुम मेरी तरफ़ देखो ग़लत अंदाज़ नज़रों से
न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से
न ज़ाहिर हो तुम्हारी कशमकश का राज़ नज़रों से
चलो इक बार फिर से...

साहिर ने फिल्मी दुनिया में भी अपनी शायरी का कमाल दिखाया. उनके गीतों और नज़्मों का जादू सिर चढ़कर बोलता था. उनका नाम जिस फिल्म से जुड़ जाता था, उसमें वह सर्वोपरि होते थे. वह किसी के सामने नहीं झुकते थे, चाहे वह लता मंगेशकर हों या फिर सचिन देव बर्मन. वह संगीतकार से ज़्यादा मेहनताना लेते थे और ताउम्र उन्होंने इसी शर्त पर फिल्मों में गीत लिखे. हर दिल अज़ीज़ इस शायर ने कभी घुटने नहीं टेके, न शायरी में और न सिनेमा में. उनकी आन–बान–शान किसी फिल्मी सितारे से कम न थी. उन्हें भी फिल्मी सितारों की तरह चमचमाती महंगी गाड़ियों का शौक़ था. अपनी फ़ितरत की वजह से वह आलोचनाओं का भी शिकार रहे. वह अपने गीत को समूची फिल्म कृति से भारी समझते थे और इस बात को वह डंके की चोट पर कहते भी थे. यश चोपड़ा की फिल्म कभी–कभी के गीतों को याद कीजिए. फिल्म की शुरुआत में ही साहिर के दो गीत रखे गए, जो बेहद लोकप्रिय हुए:–

कभी–कभी मेरे दिल में ख्याल आता है
कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए
तू अबसे पहले सितारों में बस रही थी कहीं
तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए...
.....

मैं पल दो पल का शायर हूं
पल दो पल मेरी जवानी है
पल दो पल मेरी हस्ती है
पल दो पल मेरी कहानी है...

साहिर सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी सिद्धांतवादी थे. वह लाहौर में साहिर साक़ी नामक एक मासिक उर्दू पत्रिका निकालते थे. पत्रिका घाटे में चल रही थी. साहिर की हमेशा यह कोशिश रहती थी कि कम ही क्यों न हो, लेकिन लेखक को उसका मेहनताना ज़रूर दिया जाए. एक बार वह ग़ज़लकार शमा लाहौरी को वक़्त पर पैसे नहीं भेज सके. शमा लाहौरी को पैसों की सख्त ज़रूरत थी. वह ठंड में कांपते हुए साहिर के घर पहुंच गए. साहिर ने उन्हें चाय बनाकर पिलाई. इसके बाद उन्होंने खूंटी पर टंगा अपना महंगा कोट उतारा और उन्हें सौंपते हुए कहा, मेरे भाई, बुरा न मानना, लेकिन इस बार नक़द के बदले जिंस में मेहनताना कुबूल कर लो. ऐसे थे साहिर. 25 अक्टूबर, 1980 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया, लेकिन अपनी शायरी की बदौलत वह गीतों में आज भी ज़िंदा हैं. उनकी महान रचनाओं ने उन्हें अमर कर दिया है. रहती दुनिया तक लोग उनके गीत गुनगुनाते रहेंगे.

फ़िरदौस ख़ान
firdus@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
भूमकाल
कॉमरेडों के साथ

लेखक
अरुंधति रॉय

प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन

मूल्य
95 रुपये

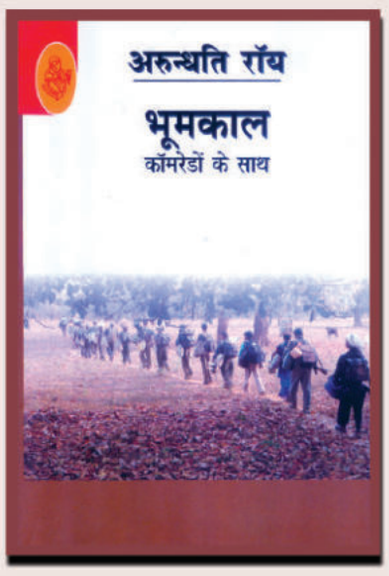

इस किताब में वर्ष 2010 में अरुंधति रॉय द्वारा जंगलों में आदिवासियों के साथ गुज़ारे लम्हों का विवरण है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

फोर्ड का दावा है कि नई ऑटोमेटिक फिएस्टा 16.81 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज प्रदान करेगी.

सोनी एनईएक्स-5 एन डिजिटल कैमरा

कैमरे की रेंज में सोनी अक्सर नए प्रयोग करता रहता है. अभी हाल में सोनी ने एनईक्स-7 सीरीज कैमरा लांच किया था. एनईएक्स-3 और एनईएक्स-7 के साथ उसने एनईएक्स-5 एन पेश किया था. अब सोनी ने डिजिटल कैमरे के बाज़ार में सेकेंड जेनरेशन सीरीज के तहत नया कैमरा लांच किया है. इसमें स्पोर्ट लुक के साथ एपीएस-सीएमओएस सेंसर दिया गया है. सोनी एनईएक्स-5 एन में कई खास फीचर्स हैं, जैसे 16.1 मेगा पिक्सल सीएमओएस का ऑप्टिकल सेंसर, 4912/3264 इमेज पिक्सल सपोर्ट 1920/1080 का वीडियो रेज्योलेशन, जो बेहतरीन वीडियो क्वालिटी देता है. इसमें 3.1 का ऑप्टिकल ज़ूम और 10.1 एक्स डिजिटल ज़ूम है, जिससे पिक्चर क्वालिटी ख़राब नहीं होती, चाहे कितनी भी दूर फोकस ऑब्जेक्ट हो. इसके द्वारा की गई कैप्चरिंग में एवीएचडीसी और एमपेग 4 वीडियो सपोर्ट करता है. 921600 डॉट एलसीडी टच स्क्रीन के साथ यह इस्तेमाल करने में आसान है. किसी भी डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इसे कंप्यूटर एवं लैपटॉप से कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एचडीएमआई पोर्ट दिया गया है. सोनी एनईएक्स-5 एन में कई इफेक्ट भी दिए गए हैं, जिनसे यूजर कैमरे में अपनी फोटो एडिट भी कर सकता है. बाज़ार में यह कैमरा 35,000 रुपये की अनुमानित क़ीमत पर उपलब्ध है.

होंडा की सीबीआर-250 आर

भारतीय ग्राहकों के बीच स्पोर्ट बाइकों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. वहीं वाहन निर्माता कंपनियां भी आएदिन अपने वाहनों में कुछ न कुछ फेरबदल करके उन्हें ग्राहकों के सामने पेश कर रही हैं. होंडा ने भी कुछ ऐसा ही किया है. होंडा ने इस बार भारतीय बाज़ार में अपनी लोकप्रिय स्पोर्ट बाइक सीबीआर-250 आर का नया ट्राई कलर वैरिएंट उतारा है. होंडा सीबीआर-250 आर का यह नया रूप है. विशेषकर तीन रंगों के साथ मिलकर तैयार नई होंडा सीबीआर-250 आर लोगों को बेहद पसंद आएगी. कंपनी ने अपनी यह बाइक बीते दिनों ऑटो एक्सपो में पेश की थी. इसमें प्रयुक्त पर्ल हेरोन ब्लू रंग सबसे ज़्यादा आकर्षक है, जो बाइक को स्पोर्टी लुक प्रदान करता है. कंपनी ने इसके फीचर्स और तकनीक आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया है. इसमें 250 सीसी के डीओएचसी इंजन का प्रयोग किया गया है, जो बाइक को शक्ति प्रदान करता है. भारतीय बाज़ार में सीबीआर-250 आर के इस नए मॉडल की क़ीमत 1.45 लाख रुपये तय की गई है. कंपनी को उम्मीद है कि सीबीआर-250 आर का यह नया रूप भारतीय ग्राहकों को बेहद पसंद आएगा.

वॉटरप्रूफ म्यूजिक हेडफोन

सुबह-सुबह जॉगिंग और एक्सरसाइज करने से न केवल तन स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी अच्छा रहता है. एक्सरसाइज करते समय अगर म्यूजिक भी हो तो बात कुछ और होती है. साधारण हेडफोन को पसीने की वजह से प्रयोग करना बेहद मुश्किल होता है. इसलिए एच2ओ नामक ऑडियो हेडफोन बनाने वाली कंपनी ने बाज़ार में नए फिट स्पोर्ट हेडफोन लांच किए हैं, जिन्हें खासकर एक्सरसाइज के उद्देश्य से बनाया गया है. इन पर पानी का कोई असर नहीं होता. इसके अलावा इनमें खास तरह की केबल का प्रयोग किया गया है, जो दौड़ते वक्त आपस में उलझती नहीं है. हेडफोन का साउंड भी आपको पसंद आएगा. अगर आप एच2ओ के नए वॉटरप्रूफ हेडफोन ख़रीदना चाहते हैं तो ये कंपनी की ऑनलाइन साइट पर 1,970 रुपये की अनुमानित क़ीमत में उपलब्ध हैं.

एचपी की मिनी नेटबुक

एचपी मिनी-1104 नेटबुक में 320 जीबी की हार्डडिस्क इनबिल्ड है, जो 5,400 राउंड की स्पीड से रन करती है.

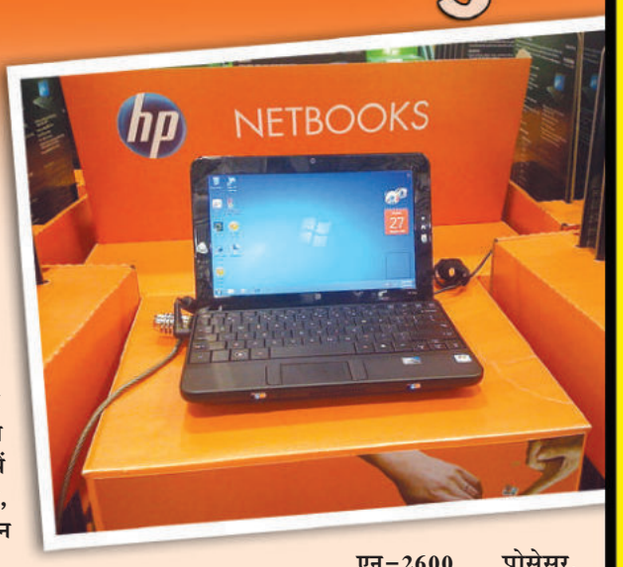

एचपी बाज़ार में एचपी ने 10.1 इंच की नई नेटबुक लांच की है. कंपनी के अनुसार, यह नेटबुक ख़ास तौर से स्टूडेंट्स और बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए पेश की गई है. एचपी मिनी-1104 नेटबुक में 320 जीबी की हार्डडिस्क इनबिल्ड है, जो 5,400 राउंड की स्पीड से रन करती है.

नेटबुक में मोशन सेंसर और एस्लरोमिटी के साथ प्रोटेक्टेट की-बोर्ड है. बाज़ार में 10.1 इंच स्क्रीन ऑप्शन में कई टैब भी हैं. एचपी-1104 मिनी में टैब के मुक़ाबले 1.6 गीगाहर्ट का ड्यूल कोर एटम प्रोसेसर दिया गया है, जो किसी भी टैबलेट से बेहतर परफॉर्मेंस देता है. इस मिनी नेटबुक की क़ीमत 25,000 रुपये है. इसमें विंडो-7 प्रोफेशनल दिया गया है. इंटल एटम एन-2600 प्रोसेसर, इंटल एनएम-10 एक्सप्रेस चिपसेट, 1.26 किलो भार, 2 जीबी 1333 मेगाहर्ट डीडीआर-3 एसडी रैम, एसओ डीआईएमएम, 320 जीबी हार्डडिस्क, 10.1 लिड बैकलाइट स्क्रीन और 1024/600 रेज्योलेशन सपोर्ट इसकी ख़ास ख़ूबियां हैं. इसमें थ्री यूएसबी पोर्ट के साथ कार्ड रीडर और फुलसाइज की-बोर्ड है. वाईफाई और ब्लूटूथ के साथ इसमें एक साल की वारंटी भी है.

बाथरूम में म्यूजिक का मज़ा

अगर आप बाथिंग सिंगर हैं और अपने मनपसंद गाने बाथरूम में केवल इसलिए नहीं सुनते कि आपकी डिवाइस पानी से कहीं ख़राब न हो जाए तो आपके लिए एक ख़ुशखबरी है कि बाज़ार में आईशॉवर नामक एक नई डिवाइस आ चुकी है, जिसमें आप अपने नहाने का जेल भी रख सकते हैं. शॉवर जेल के साथ इसमें एमपी-3 की सुविधा दी गई है. आई शॉवर के बैक साइड में एक हुक लगा हुआ है, जिसकी मदद से इसे बाथरूम में कहीं भी रखा जा सकता है. आईशॉवर में प्ले, स्टॉप, नेक्स्ट के अलावा वॉल्यूम कंट्रोल का बटन है. इसमें पॉवर के लिए ट्रिपल ए बैट्री के अलावा एसडी मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है. अगर आप संगीत प्रेमी हैं तो आपको यह ज़रूर पसंद आएगा.

फोर्ड का नया अवतार

भारतीय बाज़ार में एक से बढ़कर एक शानदार कारें पेश करने वाली अमेरिका की प्रमुख कार निर्माता कंपनी फोर्ड ने एक और धमाका किया है. इस बार फोर्ड ने भारतीय बाज़ार में अपनी लोकप्रिय सिडान कार फिएस्टा को एक नए रूप में पेश किया है. फोर्ड ने फिएस्टा का डूअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वैरिएंट उतारा है. जानकारी के अनुसार, भारतीय बाज़ार में इस नए वैरिएंट की शुरुआती क़ीमत लगभग 8.99 लाख रुपये तय की गई है. कंपनी ने अपनी नई फिएस्टा में 6-स्पीड गियर बॉक्स का प्रयोग किया है. इसमें बेहतरीन 1.5 लीटर टीआई-वीसीटी इंजन है. कंपनी ने इस बार गियर बॉक्स के मामले में बेहतर तकनीक का प्रयोग किया है. फोर्ड ने इस नए वैरिएंट में हल्के गियर बॉक्स का प्रयोग किया है, जिससे कार का वजन भी कम हुआ है, जो बेहतर माइलेज देने में पूरी तरह स्पोर्ट करता है. फोर्ड का दावा है कि नई ऑटोमेटिक फिएस्टा 16.81 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज प्रदान करेगी. ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अलावा डूअल क्लच तकनीक ने इस कार को और भी शानदार बना दिया है. भारी से भारी यातायात के बीच भी आपको क्लच को लेकर ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है. डूअल क्लच एवं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का योग आपको एक बेहद शानदार और आरामदेह राइड प्रदान करता है. फोर्ड की नई ऑटोमेटिक फिएस्टा केवल टाइटेनियम वैरिएंट में पेश की गई है, जो कि पेपरिका रेड कलर के साथ बाज़ार में उतारी गई है.

बोस ऑन ईयर ओई-2 स्टीरियो हेडफोन

हेडफोन के ईयर कप काफी चौड़े हैं, जो कानों में अच्छी तरह फिट बैठते हैं. डिजायनर ईयर हेडफोन में कम, ज़्यादा एवं मध्यम फ्रीक्वेंसी ऑप्शन दिए गए हैं, जिन्हें यूजर अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है.

बोस ने जेए-2 नामक हेडफोन बाज़ार में पेश किए हैं, जिन्हें ख़ास तौर से आईफोन के लिए डिजाइन किया गया है. इनमें ख़ास कुशन का प्रयोग किया गया है, जिससे देर तक म्यूजिक सुनने में कान दुखते नहीं हैं. इसके अलावा हेडफोन के ईयर कप काफी चौड़े हैं, जो कानों में अच्छी तरह फिट बैठते हैं. डिजायनर ईयर हेडफोन में कम, ज़्यादा एवं मध्यम फ्रीक्वेंसी ऑप्शन दिए गए हैं, जिन्हें यूजर अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है. वजन में हल्के ओई-2 हेडफोन देखने में कूल लुक प्रोवाइड करते हैं. ये हेडफोन बाज़ार में 7,385 रुपये की अनुमानित क़ीमत में उपलब्ध हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

बीपीएल पर फिक्सिंग का साया

संदेहास्पद गतिविधियों में लिप्त होने के कारण एक पाकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) पर मैच फिक्सिंग के बादल मंडराने लगे हैं. पाकिस्तान के साजिद ख़ान को मीरपुर में चटगांव किंग्स और बारिसाल बर्नर्स के बीच खेले गए मैच के दौरान खिलाड़ियों के क्षेत्र में जाने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया. रिपोर्टों में कहा गया है कि सुरक्षा अधिकारियों को साजिद के मोबाइल से चटगांव किंग्स की तरफ़ से खेल रहे एक खिलाड़ी का बैंक एकाउंट नंबर और ढाका ग्लैडिएटर्स के एक खिलाड़ी का ई-मेल पता मिला है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के सुरक्षा प्रमुख कर्नल (सेवानिवृत्त) मेसबाहुद्दीन सरनीबाट ने कहा कि चटगांव में खेले गए मैचों से वह साजिद की गतिविधियों पर ध्यान दे रहे थे. उन्होंने कहा कि उसकी गतिविधियां काफी संदेहास्पद पाई गईं. चटगांव फ्रेंचाइजी के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा कि साजिद को टूर्नामेंट के दौरान कुछ विदेशी खिलाड़ियों से बात करते हुए देखा गया था. अभी कुछ समय पहले ही ढाका ग्लैडियटर्स के कप्तान मशरफे मुर्तजा ने अपने फ्रेंचाइजी को बताया था कि उनके साथी क्रिकेटर ने उन्हें बीपीएल के दौरान संभावित स्पॉट फिक्सिंग को लेकर पेशकश की थी. बीसीबी ने इस आरोप की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की है.

हार के बावजूद सम्मान

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) की मानद आजीवन सदस्यता पाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. तेंदुलकर को यह सम्मान देते हुए न्यू साउथ वेल्स के प्रधानमंत्री बैरी ओफारेल ने कहा, सचिन अब तक के महानतम क्रिकेटरों में से एक हैं और हमारा दुनिया के सबसे शानदार क्रिकेट मैदानों में से एक की आजीवन सदस्यता से उनका सम्मान करना सही है. खेल भावना के लिए तेंदुलकर की सराहना करते हुए ओफारेल ने कहा, इस महान बल्लेबाज़ ने कहा था कि भारत के बाहर एससीजी उनका पसंदीदा मैदान है और अगर आप इस मैदान पर उनका रिकॉर्ड देखो तो उनका यह कहना हैरानी की बात नहीं है. टेस्ट मैचों में यहां उनका औसत 157 रनों का है. उन्होंने 2004 में यहां शानदार दोहरा शतक लगाया था. हमेशा से वह दर्शकों के पसंदीदा रहे हैं. सचिन को अधिकतर आस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ियों के बराबर समर्थन मिलता है. एसससीजी ट्रस्ट अध्यक्ष रोडनी कैवेलियर ने कहा कि एससीजी में क्रिकेट के प्रति तेंदुलकर के बेजोड़ योगदान के लिए उन्हें यह मानद सदस्यता दी गई है. इस मैदान पर तेंदुलकर ने पांच टेस्टों में 157 के औसत से 785 रन बनाए हैं, जबकि सात एक दिवसीय मैचों में उन्होंने 60.20 के औसत से 301 रन बटोरे.

रावत ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया

रेलवे के विकेट कीपर महेश रावत ने जामथा के वीसीए स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के ख़िलाफ़ सात कैच पकड़ कर लिस्ट ए मैचों में नया रिकॉर्ड बनाया. मध्य प्रदेश की टीम 48 रनों पर ढेर हो गई, जिसके बाद रेलवे ने नौ विकेट की आसान जीत दर्ज की. भारत-ए के पूर्व खिलाड़ी रावत ने चार कैच शैलेंद्र गहलोत की गेंद पर, जबकि दो कृष्णकांत उपाध्याय की गेंद पर लपके. उन्होंने अनुरीत सिंह की गेंद पर सातवां कैच लपक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया. रावत ने कहा, गेंद काफी सीम कर रही थी, मुझे कैच लपकने में कोई परेशानी नहीं हुई. राष्ट्रीय रिकॉर्ड के बारे में मुझे मैच के बाद पता चला.

गांगुली और द्रविड़ खेलेंगे

भारतीय क्रिकेट टीम के दो पूर्व कप्तानों, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को दुबई में 23 मार्च को होने वाले ट्वेंटी-20 टूर्नामेंट के लिए एमसीसी की टीम में शामिल किया गया है. इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मार्क राम प्रकाश को एमसीसी का कप्तान बनाया गया है. इस टूर्नामेंट में एमसीसी, इरहम, लंकशायर एवं ससेक्स की टीमें भाग लेंगी. बंगाल की तरफ़ से विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे गांगुली और आस्ट्रेलिया के दौरे के बाद फ़िलहाल विश्राम कर रहे द्रविड़ को आईपीएल के पांचवें सत्र से पहले इस मैच में अभ्यास का अच्छा मौक़ा मिलेगा. आईपीएल में गांगुली पुणे वारियर्स की ओर से, जबकि द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स की तरफ़ से खेलेंगे. राम प्रकाश टी-20 मैच के बाद 27 से 30 मार्च के बीच जायद स्टेडियम अबूधाबी में होने वाले चार दिवसीय प्रथम श्रेणी मैच में भी एमसीसी की अगुवाई करेंगे. यह मैच एमसीसी और काउंटी चैंपियन लंकशायर के बीच खेला जाएगा और इसमें नारंगी रंग की गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा.

सचिन के सलामी जोड़ीदार बनेंगे लेवी

ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर लोगों का ध्यान खींचने वाले दक्षिण अफ्रीकी सलामी बल्लेबाज़ रिचर्ड लेवी आगामी इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की तरफ़ से खेल सकते हैं. लेवी को पूर्व आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ एंड्रयू साइमंड्स की जगह लिया जा सकता है, जिन्होंने हाल में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया. यदि ऐसा होता है तो इस युवा बल्लेबाज़ को सचिन तेंदुलकर के साथ पारी का आगाज़ करते हुए देखा जा सकता है. बीती चार फरवरी को हुई नीलामी में किसी भी फ्रेंचाइजी ने लेवी को तरजीह नहीं दी. उनकी मूल क़ीमत 50 हज़ार डॉलर थी, लेकिन न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 51 गेंदों पर 117 रन बनाने के बाद कई टीमों ने उनमें दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी. पुणे वारियर्स भी उनमें से एक है. जब लग रहा था कि पुणे उनकी सेवाएं ले लेगा, तभी साइमंड्स के संन्यास लेने से मुंबई भी इस दौड़ में शामिल हो गया. ऐसे में यह 24 वर्षीय बल्लेबाज़ मुंबई का चयन कर सकता है.

भारतीय फुटबॉलर सेलिन का निधन

शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर, ओलंपियन एवं 1951 के एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के कप्तान सेलिन मन्ना का निधन हो गया. विश्वस्तरीय डिफेंडर मन्ना को इंग्लिश एफए ने 1953 में दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में शामिल किया था. 87 वर्षीय मन्ना पिछले एक साल से बीमार चल रहे थे. उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटी है. भारत के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडरों में शामिल प्रतिष्ठित कप्तान मन्ना ने 1948 के लंदन ओलंपिक में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया. वह 1952 के ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान और 1954 के एशियाई खेलों की टीम के सदस्य थे. उन्हें 1971 में पद्मश्री से नवाज़ा गया. मन्ना ने अपने करियर की शुरुआत हावड़ा यूनियन के साथ की, जो उस समय कलकत्ता फुटबॉल लीग का सेकेंड डिवीजन का क्लब था. अपनी ताक़तवर फ्री किक के लिए पहचान पाने वाले मन्ना कुछ सत्रों के बाद मोहन बागान के साथ जुड़ गए और फिर 1960 में अपने संन्यास तक यानी 19 वर्षों तक इसी क्लब की ओर से खेलते रहे. वह 1950 से लेकर 1955 तक मोहन बागान के कप्तान रहे. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2000 में उन्हें फुटबॉलर आफ द मिलेनियम चुना. 2001 में क्लब ने उन्हें मोहन बागान रत्न से नवाज़ा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

लाखों के नक़द ईनाम

मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में फ्रांस को 8-1 से हराकर ओलंपिक क्वालीफायर टूर्नामेंट जीतने के साथ ही लंदन ओलंपिक में खेलने का अधिकार हासिल करने वाली भारतीय हॉकी टीम पर ईनामों की बौछार शुरू हो गई. फाइनल मैच में पांच गोल करने वाले संदीप सिंह को हरियाणा सरकार 25 लाख रुपये देने का ऐलान किया है. अन्य मैचों में संदीप ने 11 गोल किए हैं, जिसके लिए उन्हें एक लाख रुपये प्रति गोल मिलेंगे. भारत ने आठ साल बाद ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है. टीम की इस उपलब्धि पर हॉकी इंडिया और प्रायोजक ललित होटल्स के अलावा मध्य प्रदेश ने खिलाड़ियों को एक-एक लाख रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की. हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कारों की घोषणा की. उन्होंने कहा कि फाइनल मैच में गोल करने वाले हरियाणा के प्रत्येक खिलाड़ी को प्रति गोल पांच लाख रुपये दिए जाएंगे. इसी तरह टूर्नामेंट के अन्य मैचों में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा किए गए प्रति गोल के लिए उन्हें एक लाख रुपये मिलेंगे. इसके अलावा हरियाणा के हर खिलाड़ी को 11-11 लाख रुपये मिलेंगे. हुड्डा ने भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ियों को ढाई-ढाई लाख रुपये देने की घोषणा की. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीम को बधाई देते हुए प्रत्येक खिलाड़ी को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि हॉकी के गौरव को पुन: स्थापित करने का पहला पड़ाव भारत ने पार कर लिया है. क्वालीफाइंग मुक़ाबले में मिली जीत से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है, इससे भारत का प्रदर्शन और ज़्यादा निखरेगा.

एक रिकॉर्ड टीम इंडिया के नाम

बेशक भारत सिडनी में हारकर सीरीज़ से बाहर होने की कगार पर खड़ा हो गया, लेकिन इस हार के बावजूद टीम इंडिया ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. भारत 800 एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. भारतीय क्रिकेट टीम ने त्रिकोणीय सीरीज में आस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच खेलकर यह नया मुक़ाम हासिल किया. भारत ने पहली बार 1974 में एक दिवसीय मैच खेला था. उसने अब तक जो 800 मैच खेले हैं, उनमें से 394 मैचों में उसे जीत मिली, जबकि 365 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा. छह मैच टाई छूटे, जबकि 35 मैचों का परिणाम नहीं निकला. सर्वाधिक एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले देशों की सूची में दूसरे नंबर पर आस्ट्रेलिया काबिज है. आस्ट्रेलिया ने अब तक 783 मैच खेले हैं, जिनमें उसने 486 मैचों में जीत दर्ज की. तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जिसने 765 मैचों में से 412 मैच जीते. सर्वाधिक एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले अन्य देशों में वेस्टइंडीज 665, श्रीलंका 654, न्यूजीलैंड 618, इंग्लैंड 576, दक्षिण अफ्रीका 468, जिम्बाब्वे 407, बांग्लादेश 258 और केन्या 146 आदि शामिल हैं.

पुणे को पांचवां विदेशी नहीं मिलेगा!

बेसहारा पुणे वारियर्स को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पांचवें सत्र के अंतिम एकादश में चार विदेशी खिलाड़ियों से ही संतोष करना पड़ सकता है. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, आईपीएल संचालन परिषद ने साफ तौर पर कहा कि पुणे वारियर्स की मांग तभी मानी जाएगी, जब बाक़ी फ्रेंचाइजी सैद्धांतिक तौर पर तैयार हों. फ़िलहाल दो फ्रेंचाइजी ने अपनी सहमति नहीं भेजी है, लिहाज़ा वारियर्स को चार विदेशी खिलाड़ियों से ही काम चलाना पड़ेगा. बोर्ड कुछ नहीं कर सकता. उन्होंने कहा, यदि वारियर्स आठ फ्रेंचाइजी से सहमति ले भी लेता है तो संचालन परिषद यह मामला कार्य समिति को सौंपेगी, जो इसे मंजूरी देगी. वारियर्स ने वेस्टइंडीज के हरफनमौला मर्लोन सैमुअल्स और रेलवे के तेज गेंदबाज़ कृष्णकांत उपाध्याय को टीम में शामिल किया है.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 12 मार्च-18 मार्च 2012

गोल में कनिष्क का किरदार एक ऐसे लड़के का है, जो बिल्कुल नहीं बोलता है. टीम में बिल्कुल चुप बैठा रहता है. वह पूरी फिल्म में एक-दो बार ही बोलता है.

बॉलीवुड का एक्शन कनेक्शन

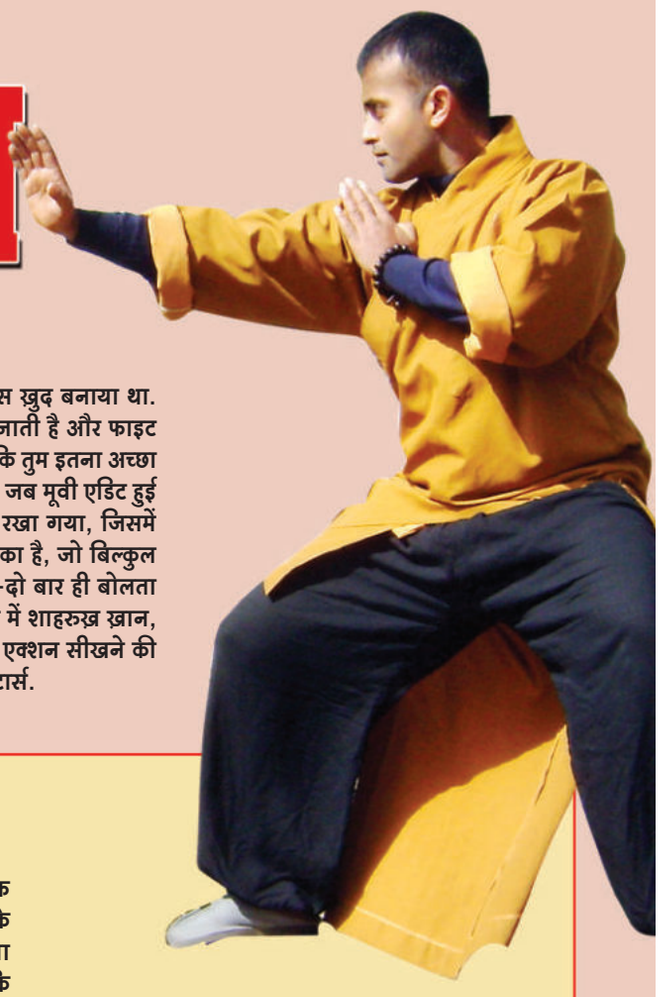

रीतिका सोनाली

फिल्म गोल का बिल्लो रानी गाना किसने नहीं सुना होगा. इस फिल्म की दो ख़ास बातें हैं, पहली फिल्म का गाना और दूसरी फिल्म का आख़िरी सीन जिसमें फुटबॉलर हवा में उछलकर गोल-गोल चक्कर खाते हुए गोल करके मैच जीत जाता है. आख़िरी गोल कर दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने वाला यह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि देश का पहला शाउलिन वॉरयर कनिष्क शर्मा है, जिन्होंने चीन के प्राचीन मठ शाउलिन जाकर इस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है. अब वह भारत लौटकर यहां मिलिट्री, आर्म्ड फोर्सेस, महिलाओं, एक्जीक्यूटिव्स, बच्चों और फिल्म स्टार्स को ट्रेनिंग देते हैं. फिल्म गोल में बिल्लो रानी गाने के बाद एक सीन है, जिसमें अंग्रेज शीशे में पत्थर मारते हैं और पाकीज और इंडियंस कहकर गालियां देते हैं, तब जॉन अब्राहम बाहर निकलते हैं, पहले उनकी फाइट होती है हैक्लर्स से, जिसमें जॉन को पंच लग जाता है और फिर कनिष्क पांच लोगों के साथ फाइट करते हैं. इसके लिए उन्होंने लंदन के पांच प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट को चुना था. उन्होंने इसका सिक्वेंस ख़ुद बनाया था. सीन में जब वह फाइट करके सबको मारते हैं तो मारने के बाद पूरी टीम आ जाती है और फाइट ख़त्म होने के बाद कोच यानी बोमन ईरानी कहते हैं कि छोटू तुमने बताया नहीं कि तुम इतना अच्छा कुंगफू करते हो, मैं चाहता हूं कि तुम इसका इस्तेमाल फुटबॉल में करो. हालांकि जब मूवी एडिट हुई तो यह एक्शन सिक्वेंस पूरा डिलीट कर दिया गया और सिर्फ़ वह एक गोल रखा गया, जिसमें कनिष्क उछलकर गोल करते हैं. गोल में कनिष्क का किरदार एक ऐसे लड़के का है, जो बिल्कुल नहीं बोलता है. टीम में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है. वह पूरी फिल्म में एक-दो बार ही बोलता है. इसके अलावा कनिष्क ने कई और स्टार्स को ट्रेनिंग दी है, जैसे फिल्म डॉन में शाहरुख़ ख़ान, प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल वग़ैरह-वग़ैरह. आइए जानते हैं कि जब बात एक्शन सीखने की आती है तो एक्शन कोरियोग्राफर कनिष्क शर्मा की नज़र में कैसे छात्र हैं ये स्टार्स.

शाहरुख़ ख़ान

फिल्म डॉन और इसके सिक्वल डॉन-2 ने शाहरुख़ ख़ान को लवर ब्वॉय से एक्शन हीरो बनाया है. अपने एक्शन के लिए शाहरुख़ ने न केवल ऐब्स बनाए हैं, बल्कि पसीना भी बहाया है. फिल्म डॉन के एक्शन कोरियोग्राफर कनिष्क शर्मा कहते हैं कि दिल्ली के दिलवाले शाहरुख़ ख़ान बहुत ही रफ एंड टफ हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उन्होंने हॉकी, फुटबॉल खेला है. फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह होने के बावजूद वह ज़मीन से जुड़े हैं, उन्हें धूल-मिट्टी से कोई परेशानी नहीं है. एक्शन ट्रेनिंग के लिए उन्हें ए सी जिम या हॉल नहीं चाहिए. डॉन की शूटिंग के वक़्त शाहरुख़ ख़ान के गर्दन का ऑपरेशन हुआ था तो वह पेनकिलर खाकर शूटिंग करते थे. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो कनिष्क उनसे नहीं करवा सकते थे. कनिष्क शाहरुख़ ख़ान के साथ ही 3-4 महीने तक डॉन की शूटिंग के दौरान रहे और इस बीच शाहरुख़ ख़ान ट्रेनिंग लेते रहे. शाहरुख़ ख़ान ने फिल्म के कई स्टंट ऑन द स्पॉट किए थे. कनिष्क कहते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा कॉम्पलीमेंट यही था कि जब एमटीवी पर शाहरुख़ ख़ान ने कनिष्क को थैंक्यू बोला और फिर पर्सनली कनिष्क को बुलाकर कहा कि मैं इतने साल से एक्शन कर रहा था तो लोग मुझसे कहते थे कि शाहरुख़ भाई आप एक्शन में सही नहीं लगते, आप लव स्टोरी करो. लेकिन जब तुमने मेरे लिए डॉन में कोरियोग्राफ किया तब से लोग मुझसे कहने लगे हैं कि शाहरुख़ भाई आप एक्शन में भी जमते हो. इस फिल्म के लिए शाहरुख़ ख़ान को कनिष्क ने जितकुंडो, शाउलिन दावांदा और क्लोज फाइटिंग, नाइन शेक्सन चेन सिखाया था. ये शाउलिन मार्शल आर्ट से लिए गए हैं, जो बहुत ही मुश्किल हैं.

बोमन ईरानी

फिल्म डॉन में मलेशिया के गेंटिंग हाइलैंड के रूफ टॉप पर जब बोमन ईरानी को शाहरुख़ ख़ान के साथ चाकू से ख़तरनाक फाइट करते हुए देखा होगा तब किसी के लिए भी यह मानना मुश्किल होगा कि उस वक़्त वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे. डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन धुन के पक्के बोमन ईरानी ने अपनी उसी हालत में फाइट सीन किया. कनिष्क बताते हैं कि मुझे बोमन ईरानी से एक्शन कराना था, लेकिन उनके घुटने में प्रोब्लम थी और डॉक्टर ने उन्हें चलने से मना कर दिया था. इलाज के दौरान बोमन ने मुझे हॉस्पिटल में बुलाया और कहा कि आप मेरे डॉक्टर से मिलो, ताकि फाइट सिखाने में किन बातों का ध्यान रखना है यह जान सको . डॉक्टर ने बोमन को किसी भी तरह की हेवी मूवमेंट करने से मना कर दिया. डॉक्टर ने कहा कि उनके मूवमेंट हैवी नहीं हो सकते और उन्हें खड़े-खड़े ही सीन करना पड़ेगा. यह मुश्किल था और चैलेंजिंग भी. लेकिन इसके बाद भी बोमन ईरानी ने डॉन के एक्शन को बख़ूबी किया. बोमन ने बेहतरीन तरीक़े से नाइफ मूवमेंट सीखा और परफॉर्म भी किया. यह नाइफ मूवमेंट आर्मी और मिलिट्री को दी जाने वाली ट्रेनिंग फिलिपिंस की पीकीडी टरसिया काली मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है. बोमन ईरानी के साथ कनिष्क ने गोल में भी काम किया है. वहीं कनिष्क ने यह पाया कि बोमन ईरानी बहुत ही फनी हैं. साथ ही वह दिल के बेहद साफ और ज़िंदादिल इंसान हैं.

प्रियंका चोपड़ा

कनिष्क की बेस्ट स्टूडेंट हैं प्रियंका चोपड़ा. फिल्म डॉन में प्रियंका की एंट्री ज़बरदस्त तरीक़े से दिखाई गई है. फिल्म में एक्शन सीन कर उन्होंने साबित कर दिया कि वह ब्यूटी और पावर दोनों का कॉम्बो हैं. फिल्म के एक्शन कोरियोग्राफर कनिष्क शर्मा बताते हैं कि उन्होंने प्रियंका को शाउलिन शिंगी सिखाया था. यह चाइनीज मार्शल आर्ट शाउलिन की एक सेल्फ डिफेंसिव तकनीक है. इसके साथ ही प्रियंका ने फिल्म का एक और मुश्किल सीन किया है, जिसमें वह ट्रेन के अंदर शाहरुख़ ख़ान पर चेन से हमला करती हैं. इसके लिए उन्होंने एक ख़ास तकनीक को सीखा. इसके लिए उन्होंने शाउलिन मार्शल आर्ट का बहुत ही डिफिकल्ट वेपन सीखा था जिसका नाम है, नाइन सेक्शन विद चेन. इसे सीखने में जहां एक आम स्टुडेंट को तीन महीने लगते हैं, वहीं प्रियंका चोपड़ा ने इसे केवल सात दिन में सीख लिया था. यह काफ़ी ख़तरनाक होता है, जिसके एजेज काफ़ी शार्प होते हैं. प्रियंका ने इसे सीखने के लिए ओरिजनल वेपेन का ही इस्तेमाल किया और फिल्म में भी ओरिजनल वेपेन का ही इस्तेमाल हुआ. इसके अलावा फिल्म में शाहरुख़ यानी डॉन से पहली मुलाक़ात में जंगली बिल्ली तेज़ी से चाकू चलाती हुई काफ़ी एग्रेसिव और पावरफुल लगती है. यह स्टंट उन्होंने सीखा शाउलिन नाइफ फाइट प्रोसेस से. पूरी फिल्म में कई जगह पर परफॉर्म किए मार्शल आर्ट की तकनीक के लिए प्रियंका चोपड़ा ने नाइन सेक्शन विद चेन के साथ शाउलिन सिंगी और चौआन, शाउलिन नाइफ और शाउलिन कुंफू सीखा था. कनिष्क ने प्रियंका चोपड़ा को रबड़ डॉल नाम दिया है, उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है कि वह किसी भी एंगल से मुड़ जाती हैं. निजी तौर पर प्रियंका न केवल एक बेहतरीन और फ्रेंडली इंसान हैं, बल्कि वह एक बहुत ही अच्छी सिंगर भी हैं.

अभिषेक बच्चन

अभिषेक बच्चन एक ऐसे स्टार हैं, जो अपने किरदार के साथ निजी जीवन में भी इंवॉल्व हो जाते हैं. कनिष्क बताते हैं कि उन्हें ऐसा स्टार पहले कभी नहीं मिला था. किसी स्टार ने मुझसे यह प्रश्न नहीं किया कि वह क्या सीख रहे हैं और क्या सीखेंगे. अभिषेक पहले ऐसे स्टार हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म के एक्शन कोरियोग्राफर कनिष्क को कहा कि वह उनके घर आएं और उन्हें पूरी तरह से बताएं कि फिल्म के एक्शन सींस के लिए उन्हें जो सीखना है, वह दरअसल है क्या. फ़रहान अख्तर की प्रोडक्शन फिल्म गेम में कनिष्क ने अभिषेक बच्चन को एक्शन सींस सिखाया है. इसके लिए उन्होंने मार्शल आर्ट पिकिडी टर्शिया काली सिखाया है. अभिषेक ने इस मार्शल आर्ट की पूरी थ्योरी जानने समझने के बाद ही ट्रेनिंग लेनी शुरू की.

अर्जुन रामपाल

कफ़ी फिट और स्ट्रांग मैन हैं अर्जुन रामपाल. फिल्म डॉन में एक पैर से असमर्थ दिखाए जाने के बावजूद उन्होंने जो ट्रेनिंग ली उसका रिजल्ट बेहतरीन दिया. अर्जुन रामपाल ने डॉन के फाइट सींस के लिए कनिष्क के साथ जमकर ट्रेनिंग ली. अर्जुन रामपाल को जो एक्शन सिक्वेंस दिया था, उसमें काफ़ी फास्ट फाइट मूवमेंट्स थे. यह मूवमेंट एक मार्शल आर्ट से लिया गया है. यह मार्शल आर्ट थाईलैंड का है, जिसे कनिष्क ने ही सिखाया है. इस मार्शल आर्ट का नाम है मोए थाय. यह हार्ड एक्शन फाइट के साथ काफ़ी जमता है. अर्जुन रामपाल इस फाइट को करते हुए जंचते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी अच्छी है. उन्हें इसीलिए हार्ड एक्शन दिया गया था. इस फिल्म में उनकी एक टांग नहीं थी तो इसकी जगह उन्हें थोड़ी सी स्टिक फाइट भी सिखाई गई थी, क्योंकि इसी स्टिक से वह फाइट स्टंट करते हैं. अर्जुन को इस पूरी फाइट को सीखने में 15-20 दिन तक ट्रेनिंग दी गई. फिल्म में उनके दूसरी फाइटिंग सींस के लिए उन्हें मॉडर्न बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग दी गई.

मिथुन चक्रवर्ती

कनिष्क ने मिथुन चक्रवर्ती को हसन रज़ा की एक बंगाली फिल्म में एक्शन सींस सिखाया है. कनिष्क कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि यह उनकी लाइफ की सबसे टफ फिल्म होगी, क्योंकि मिथुन दा को एक्शन सिखाना और वह भी तब जब उनकी उम्र भी दूसरे हीरो के मुक़ाबले ज़्यादा है. ऐसे में उन्हें 25 वेपेन से फाइट सिखानी थी, लेकिन एक आश्चर्य की तरह उन्होंने यह सब सीखा. शायद इसलिए वह मिथुन दा हैं. कनिष्क कहते हैं कि उन्होंने मिथुन दा को कोई ट्रेनिंग नहीं दी. दरअसल कनिष्क ने फिल्म में होने वाले स्टंट को केवल मिथुन दा के सामने करके दिखाया था, और फिर जैसे ही डायरेक्टर का कमांड आता है, मिथुन दा उसे ठीक वैसे ही कर देते हैं जैसे कनिष्क ने बताया होता है. इससे कनिष्क भी हतप्रभ रह जाते थे. मिथुन दा ही ऐसे कलाकार हैं, जो बिना किसी ट्रेनिंग के यह कर पाते हैं. केवल देखकर ही वह एक्शन सीन कर लेते हैं. अपने अनुभव से शॉट देने वाले इस इंसान का मेंटल लेवल कितना शानदार होगा यह कहने की बात नहीं है.

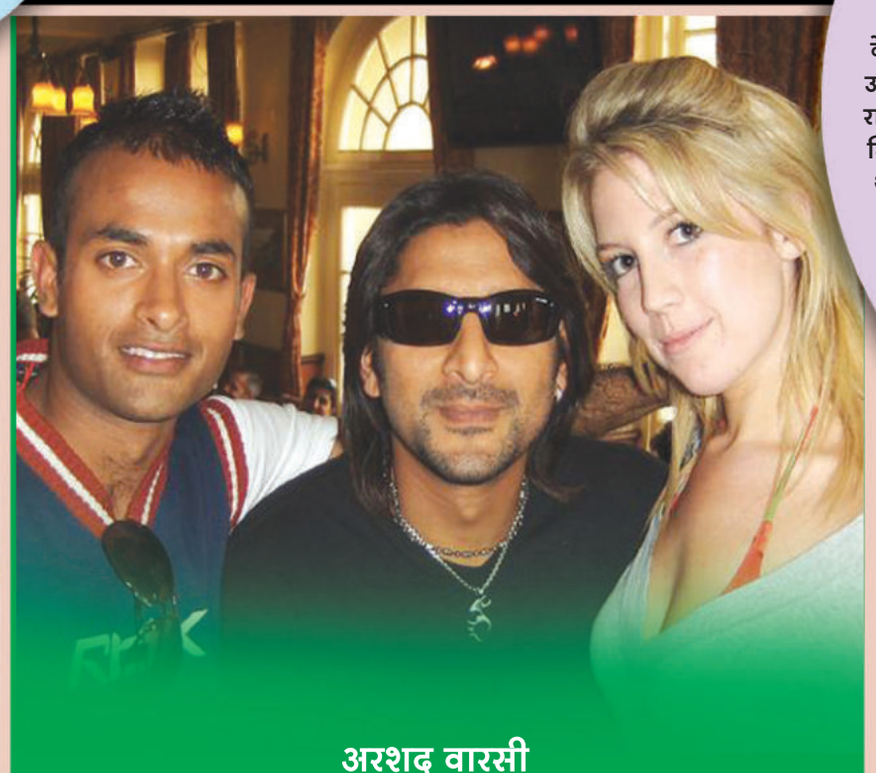

अरशद वारसी

बहुत कम ऐसे स्टार्स होते हैं, जो जैसे रील लाइफ में ख़ुद को प्रदर्शित करते हैं, ठीक वैसे ही वे रीयल लाइफ में भी हों. अरशद वारसी ऐसे ही इंसान हैं. अरशद के ज़्यादातर रोल्स कॉमेडी वाले ही रहे हैं, लेकिन यह जानना आश्चर्यजनक है कि अरशद रीयल लाइफ में भी हंसी मज़ाक़ करने वाले, ख़ुशमिज़ाज, ज़िंदादिल इंसान हैं. फिल्म गोल के दौरान कनिष्क शर्मा की मुलाक़ात अरशद वारसी से हुई. इस फिल्म में कनिष्क ने ख़ुद भी एक्टिंग की है और एक्टर्स को एक्शन सींस भी सिखाए हैं. इस दौरान उन्हें अरशद वारसी के व्यक्तित्व ने ख़ूब प्रभावित किया. फिल्म की ट्रेनिंग देने के दौरान ही कनिष्क ने उन्हें कॉमेडियन का ख़िताब दे दिया. कनिष्क कहते हैं कि अरशद वारसी उनसे बच्चों की तरह तायची सीखने की ज़िद करते थे. वह कहते थे तुझे मुझे तायची सिखानी पड़ेगी हर हालत में. किसी स्टार के मुंह से ऐसे सुनना ही काफ़ी अच्छा लगता है. अरशद बिल्कुल अमेजिंग इंसान हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन हैं, ऐसे कि अगर आप अरशद वारसी के साथ बैठेंगे तो हंसा-हंसा कर वह पागल कर देंगे.

फ़रहान अख्तर

फिल्म डॉन में एक्शन कोरियोग्राफ करते हुए कनिष्क शर्मा फिल्म मेकर फ़रहान अख्तर के दीवाने हो गए. वह कहते हैं कि फ़रहान अख्तर ज़मीन से जुड़े इंसान हैं. वह सामने वाले को इतना सहज कर देते हैं जैसे उनसे कोई पुराना रिश्ता हो, कनिष्क उन्हें भाई जैसा दोस्त मानते हैं. फ़रहान शायद बॉलीवुड की उन चुनिंदा नामी हस्तियों में से हैं, जो फोन पर कॉल मिस हो जाने पर कॉलबैक करते हैं. कनिष्क कहते हैं कि कभी भी हम फोन करते हैं तो वह हमेशा रिटर्न कॉल करते हैं, जबकि ज़्यादातर स्टार्स कभी रिप्लाई नहीं करते हैं. फ़रहान अख्तर डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे होते हैं तो काम ही करते हैं और काम नहीं कर रहे होते हैं तो वो फनिएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ हो जाते हैं.

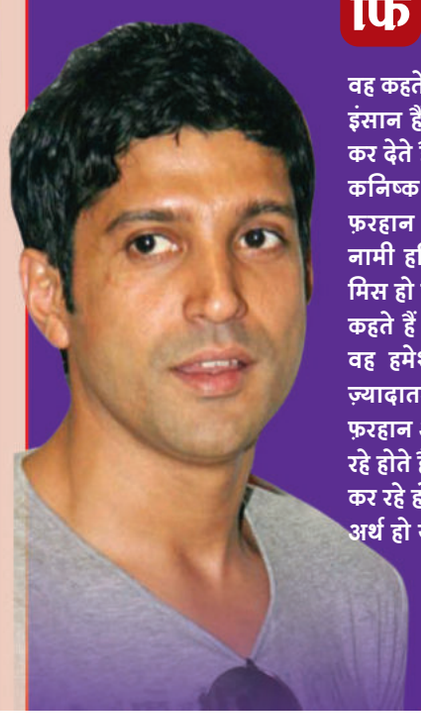

ritika@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 12 मार्च-18 मार्च 2012

www.chauthiduniya.com

कृपा शंकर पर राजकीय कृपा

विलासराव देशमुख के बाद राज्य के एक और कांग्रेसी नेता मुंबई अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह पर मुंबई उच्च न्यायालय ने अपना हथौड़ा चलाया है और उनकी बेहिसाब संपत्ति को ज़ब्त कर उनके व उनके परिवार के ख़िलाफ़ आर्थिक अपराध दाख़िल करने का निर्देश पुलिस को दिया. राज्य में भ्रष्टाचार की परत-दर-परत उधड़ रही है और हमारे नेता आत्ममुग्ध नज़र आ रहे हैं.

प्रवीण महाजन

महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षितिज में इन दिनों काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है, जिससे राजनीति को भी शर्मिंदगी ज़रूर महसूस होती होगी, पर राजनेताओं का शर्म से कोई नाता नहीं रहता है. आख़िर वे माननीयों की बिरादरी से आते हैं. चौथी दुनिया ने अपने 27 फरवरी से 4 मार्च के अंक में केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख पर इन माननीयों को शर्म नहीं आती शीर्षक से उनके मनमानी निर्णयों और कदाचार के विषय में लिखा. उसके पहले राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री छगन भुजबल पर मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट में लिप्त होने का मामला उजागर हुआ था. मगर अपने को सभी पाक साफ़ बताते रहे हैं. विलासराव देशमुख के बाद राज्य के एक और कांग्रेसी नेता मुंबई अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह पर मुंबई उच्च न्यायालय ने अपना हथौड़ा चलाया है और उनकी बेहिसाब संपत्ति को ज़ब्त कर उनके व उनके परिवार के ख़िलाफ़ आर्थिक अपराध दाख़िल करने का निर्देश पुलिस को दिया. राज्य में भ्रष्टाचार की परत-दर-परत उधड़ रही है और हमारे नेता आत्ममुग्ध नज़र आ रहे हैं. जब तक अदालती हथौड़ा नहीं पड़ता है तब तक उनका संरक्षण पार्टी संगठन सहित सरकार भी करती नज़र आती है. अब मनपा, चुनाव नतीजों के परिणाम की उलटबांसी कहा जाए या अदालती हथौड़े की मार का नतीजा कि कृपाशंकर को तुरंत मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा. अदालती हथौड़ा तो विलासराव देशमुख पर भी पड़ा है, जिन्हें फिल्म निर्माता सुभाष घई के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने और क़ानून का उल्लंघन करने का सीधे तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन उन पर अभी भी पार्टी आलाकमान की कृपादृष्टि बनी हुई और वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के नगीने बने हुए हैं. साधारण सी बात है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से रोज़ी-रोटी की तलाश में कृपाशंकर मुंबई आए थे. पहले तो उन्हें रोज़गार के लिए मुंबई में भटकना पड़ा. कृपाशंकर सिंह राजनीति में आने से पहले कुछ वर्षों तक एक दवा कंपनी में मशीन ऑपरेटर थे. उसके बाद उन्होंने आलू-प्याज़ की दुकान लगानी शुरू की. उसी दरम्यान उनका कुछ कांग्रेसी नेताओं से संपर्क हुआ और उन्होंने राजनीति का दामन थाम लिया. उसके बाद उनके क़दम तेज़ी से राजनीति में बढ़ते चले गए. राजनीति में पावर हासिल करने के बाद तो कृपाशंकर सिंह का जैसे विवादों से चोली-दामन सा साथ हो गया. उनकी शिक्षा-दीक्षा को लेकर भी विवाद रहा है. हालांकि कृपाशंकर सिंह के अनुसार वह बीएससी यानी स्नातक हैं, लेकिन जौनपुर स्थित जयहिंद इंटर कॉलेज जहां उन्होंने पढ़ाई की है, उसके रिकॉर्ड के अनुसार वह 12वीं फेल हैं. इसका ख़ुलासा भी मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता संजय तिवारी द्वारा सुचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर जौनपुर के जयहिंद इंटर कॉलेज के प्राचार्य ने स्कूल सर्टीफिकेट की कॉपी भेज कर सूचित किया कि वह 12वीं फेल हैं. इतना ही नहीं वर्ष 2004 और 2009 के विधानसभा चुनाव के दरम्यान कृपाशंकर सिंह ने जो एफीडेविट पेश किए थे, उसमें आयकर पैन कार्ड के नंबर भी अलग-अलग भरे थे. इतना ही नहीं उन्होंने अपनी पत्नी और अपने नाम की उत्तर प्रदेश स्थित संपत्तियों की जानकारी नहीं दी थी. इसका मतलब यही है कि कृपाशंकर सिंह का पूरा साम्राज्य ही झूठ की नींव पर खड़ा है.

अब सवाल यह उठता है कि एक आलू-प्याज़ की दुकान लगाने वाला, दवा कंपनी में कुछ हज़ार की मशीन ऑपरेटर की नौकरी करने वाला एकाएक करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? यहां तो लोग आलू-प्याज़ की दुकान लगाते-लगाते ज़िंदगी गुज़ार देते हैं, लेकिन एक अदद मकान तक नहीं बनवा पाते हैं. जैसे-जैसे जीवन की गाड़ी खींचते नज़र आते हैं, लेकिन कृपाशंकर सिंह तो एकदम से आसमान में ही पहुंच गए. उनका आर्थिक साम्राज्य महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैल गया. इसका राज़ क्या है? इस सवाल को लेकर लोगों की जिज्ञासा का जाग उठना स्वाभाविक है. दरअसल, वर्ष 2008 में कृपाशंकर सिंह के बेटे नरेंद्र सिंह की शादी झारखंड के राजनेता कमलेश सिंह की बेटी अंकिता के साथ हुई. उसके तुरंत बाद ही झारखंड में 4000 करोड़ रुपये के गोलमाल का मामला सामने आया, जिसमें वहां के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कौड़ा के साथ ही कृपाशंकर सिंह के समधी यानी नरेंद्र सिंह के ससुर कमलेश सिंह का नाम भी आया. इस मामले में कृपाशंकर सिंह का नाम भी सामने आया. यह भी पता चला कि उनकी पत्नी, पुत्रवधू और बेटे के बैंक खातों में करोड़ों रुपये का ट्रांसफर झारखंड से किया गया. इस बात के सामने आने के बाद से आरटीआई कार्यकर्ता संजय तिवारी ने उनकी बेनामी संपत्ति होने की शिकायत राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में की थी. मगर यहां कृपाशंकर सिंह को पूरा राजकीय संरक्षण प्राप्त होने से जांच में कुछ ख़ास प्रगति नहीं हो सकी. मामला जब न्यायालय में पहुंचा तो राज्य सरकार ने एसीबी की रिपोर्ट पेश कर दी. एसीबी की रिपोर्ट में कहा गया था कि कृपाशंकर सिंह के ख़िलाफ़ अपराध करने योग्य सबूत नहीं हैं. इस तरह तब उनको एसीबी की रिपोर्ट के आधार पर बेदाग़ बताकर छोड़ दिया गया. मगर बाद में एसीबी ने इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा न्यायालय में पेश की गई है, उसकी जानकारी के बिना ऐसा किया गया. इससे यह बात तो साफ़ हो जाती है कि पूरी सरकार कृपाशंकर सिंह को बचाने में लगी थी. उसके बाद वर्ष 2009 में जब 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले का ख़ुलासा हुआ तो इसके आरोपियों से भी कृपाशंकर सिंह व उनके बेटे नरेंद्र सिंह का संबंध होने की बात सामने आई. शाहिद बलवा के साथ बिजनेस पार्टनरशिप के तथ्य सामने आए. इसके बाद भी कृपाशंकर सिंह का कुछ नहीं बिगड़ा. इसका मुख्य कारण यह था कि कृपाशंकर सिंह कभी राज्य के गृह राज्यमंत्री की कुर्सी की शोभा बढ़ा चुके थे. उनकी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अच्छी पटती थी. इसलिए पुलिस भी उनके ख़िलाफ़ गंभीरता से जांच कर कार्रवाई नहीं कर सकी. इसलिए विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावड़े के इस दावे मे दम नज़र आता है कि अवैध संपत्ति की जांच में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह को बचाने में केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार व राज्य के गृहमंत्री आरआर पाटिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. प्रेस कांफ्रेंस में तावड़े ने कहा कि दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच में ढिलाई के लिए कृपाशंकर सिंह ने 19 साल बाद एकाएक शरद पवार और गृहमंत्री से मुलाक़ात की थी और उनसे दोषमुक्त करने का अनुरोध किया था. उसके बाद ही कृपा को बचाने की सरकारी कोशिशें तेज़ हो गईं और न्यायालय में एसीबी की रिपोर्ट को आधार बनाकर गृह मंत्रालय ने उनके ख़िलाफ़ सबूत न होने का हलफ़नामा दायर किया था. कृपाशंकर पर राजकीय कृपा होने के बाद भी आरटीआई कार्यकर्ता ने हार नहीं मानी और राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा इस मामले की एसीबी की गोपनीय जांच की रिपोर्ट न देने का हवाला देते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में गए. उच्च न्यायालय से अवैध बेहिसाबी संपत्ति अर्जित करने पर कृपाशंकर सिंह के ख़िलाफ़ एसीबी को आपराधिक मामला दर्ज करने और उसकी विशेष दल से जांच कराने का अनुरोध किया. सरकार ने पुनः कृपाशंकर सिंह को न्यायालय में बचाने के भरपूर प्रयास किए, पर एसीबी के यह कहने पर कि उसने उन्हें मामले में कोई छूट नहीं दी है, सुनवाई दरम्यान इन सारे तथ्यों के सामने आने पर मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह और न्यायाधीश रोशन दलवी की खंडपीठ ने कड़ा रुख़ अपनाते हुए पुलिस आयुक्त अरूप पटनायक को सीधे आदेश दिया कि पुलिस आयुक्त भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कृपाशंकर सिंह पर आपराधिक कदाचार के लिए सरकार से मुक़दमा चलाने की अनुमति प्राप्त करें. कृपाशंकर सहित उनके परिजनों (पत्नी, बेटे, पुत्रवधू समेत) की चल-अचल संपत्ति के बारे में दस्तावेज़ी साक्ष्य एकत्र करें. खंडपीठ ने यह भी कहा कि कृपाशंकर की अचल संपत्ति को ज़ब्त कर लिया जाएगा, लेकिन प्रतिवादियों के बैंक खातों के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आरोप है कि पैसा उड़ा दिया गया है. खंडपीठ ने उक्त आदेश पर रोक लगाने के लिए कृपाशंकर सिंह के वकील द्वारा पेश याचिका को तत्काल ख़ारिज कर दिया और पुलिस को अपने आदेश पर गंभीरता से अमल करने का आदेश है. उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के तत्काल बाद ही मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद से कृपाशंकर की छुट्टी कर दी गई. अदालत के गंभीर व सख्त रुख़ से ऐसा लगता है कि कृपाशंकर सिंह व उनके परिजन पूरी तरह क़ानून के घेरे में आ गए हैं. इसी के साथ उनकी मुश्किलों को दौर शुरू हो गया है. अब आरटीआई कार्यकर्ता संजय तिवारी को आशा है कि उनकी मेहनत रंग लाएगी और एक भ्रष्ट राजनेता के चेहरे को बेनक़ाब करने में कामयाबी मिलेगी. कृपाशंकर सिंह की संपत्तियों के संबंध में तिवारी का कहना है कि विधायक के रूप में कृपाशंकर सिंह को हर माह क़रीब 45 हज़ार रुपये मिलते हैं. उनके परिवार की इसके अलावा आय का अन्य कोई ज्ञात स्त्रोत नहीं है. इसलिए उनके द्वारा एकत्रित पूरी संपत्ति बेमानी है. अब देखना यह है कि राज्य सरकार कृपाशंकर सिंह पर मुक़दमा चलाने की अनुमति कब तक देती है? पुलिस आयुक्त कब तक उनके ख़िलाफ़ आय से अधिक बेहिसाबी संपत्ति एकत्र करने के दस्तावेज़ी सबूत जुटा पाते हैं? इस मामले से तो यह साफ़ हो गया है कि कृपाशंकर सिंह का भ्रष्टाचारियों से गहरा नाता है और उनका आर्थिक साम्राज्य पूरी तरह से ग़ैर क़ानूनी ढंग से एकत्रित करोड़ों रुपये के दम पर जुटाई गई है.

feedback@chauthiduniya.com

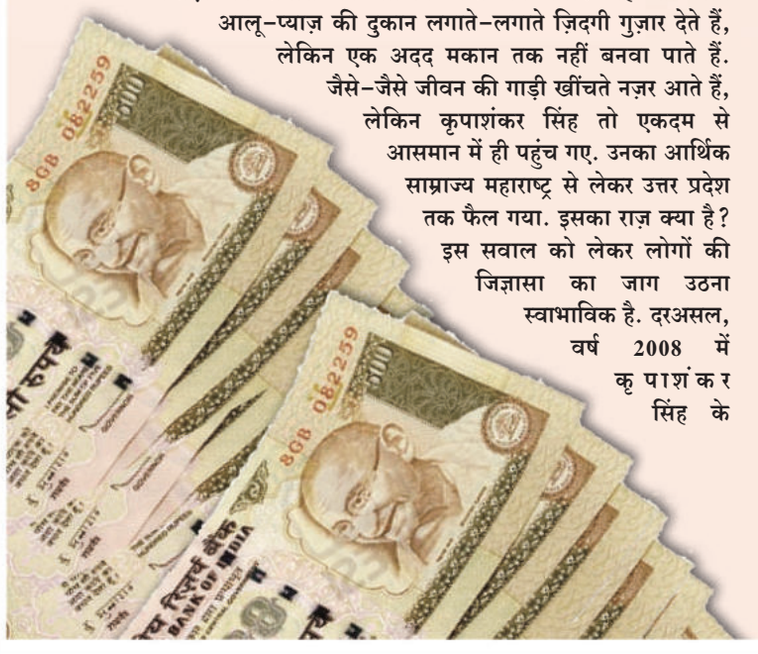

करोड़ों रुपये कहां गए

कृपाशंकर सिंह की पत्नी मालती देवी के बैंक खाते में वर्ष 2009 के मार्च से लेकर नवंबर तक यानी आठ माह की अवधि में 3 करोड़ 40 लाख रुपये का व्यवहार किया गया. इसी तरह उनके पुत्र नरेंद्र के बैंक खाते से दो साल में 60 करोड़ का लेन-देन का व्यवहार हुआ. कृपाशंकर की पुत्रवधू अंकिता के बैंक खाते से चार माह में 1 करोड़ 25 लाख और एक वर्ष में क़रीब 1 करोड़ 75 लाख का अलग से व्यवहार किया गया. इससे यह सवाल उठता है कि इनके खातों में एकदम रुपयों की इतनी बाढ़ आई कहां से और कहां गई? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि खातों से रक़म ग़ायब की जा चुकी है. इस बात का उल्लेख न्यायालयीन निर्देश में भी किया गया है.

कृपा शंकर के बेटे ने फिल्म व रियल इस्टेट कंपनियों में पैसा लगाया

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कौड़ा की करोड़ों की रक़म को कृपाशंकर सिंह के पुत्र नरेंद्र द्वारा फिल्मों में भी निवेश किए जाने की चर्चा है. चर्चा है कि उसने उड़ान नामक एक फिल्म बनाई थी. इसके अलावा उसके द्वारा रियल इस्टेट का व्यवसाय करने वाली कंपनियों को भी क़रीब 22 करोड़ रुपये बिना ब्याज़ के देने के तथ्य भी सामने आए हैं. बहरहाल, इस मामले में राज्य की एसीबी अब तक इसका जवाब न्यायालय को स्पष्ट रूप से नहीं दे पाई है.

भ्रष्ट कमाई से जुटाई गई संपत्ति

- पूर्वी बांद्रा में बांद्रा-कुर्ला संकुल के एचडीआईएल के आलीशान व्यापारी संकुल में 22 हज़ार 500 चौरस फुट का कार्यालय.
- पूर्वी बांद्रा-कुर्ला संकुल के ट्रेड-लिंक, वाधवा बिल्डिंग में 12 हज़ार चौरस फुट का कार्यालय
- पश्चिम बांद्रा में स्थित कार्टर रोड में 423 चौरस मीटर क्षेत्रफल का आलीशान तरंग बंगला.
- पश्चिम बांद्रा में ही माउंट मेरी मार्ग पर आलीशान इमारत में फ्लैट.
- विले पारले के पूर्व में स्थित वीर घाणेकर मार्ग पर जूपीटर बिल्डिंग में छठवीं एवं सातवीं मंज़िल पर 1355 चौरस फुट में निर्मित व 550 चौरस फुट का छत सहित फ्लैट.
- भांडुप के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर एचडीआईएल बिल्डिंग में दुकानें.
- सांताक्रूज टाऊन प्लानिंग स्कीम क्रमांक 4, सीटीएस 445, वांद्रे दांडा में 959 यार्ड का भूखंड.
- अंधेरी पूर्व में पवई में किंगस्टन बी में 401 क्रमांक की 700 चौरस फुट और 1006 क्रमांक का फ्लैट (मुख्यमंत्री के कोटे से हासिल किया हुआ).
- पश्चिम बांद्रा में टर्नर रोड में स्थित आलीशान इमारत अफेयर में 401 क्रमांक के 2000 चौरस फुट का फ्लैट.
- पवई स्थित हिरानंदानी गार्डन में स्थित भव्य व्यापारी संकुल में 38 व 39 क्रमांक के 930 चौरस फुट की दुकानें.
- कुर्ला स्थित हिरानंदानी गार्डन्स की अब्रोसिया बहुमंज़िली इमारत में 202 क्रमांक का फ्लैट.
- रत्नागिरी, वडापेठ में 250 एकड़ का भूखंड.
- उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में 8000 चौरस फुट का व्यावसायिक परिसर.
- पनवेल में 1100 चौरस फुट की दुकानें.
- कोंकण के राजापुर तहसील में भी कृपाशंकर का 100 एकड़ का बाग़ होने का भी पता चला है.

राज्य के हर ज़िले के लिए जल संकट से निपटने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई योजना नज़र नहीं आ रही है.

इन चुनावों के दौरान नक्सलियों ने अपने दबदबे वाले क्षेत्र के ग्रामवासियों से चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की थी.

महाराष्ट्र हलचल

अकोला में स्वास्थ्य के लिए पैदल चलो का संदेश देने वाली 11 किलोमीटर वॉकथॉन- 2012 स्पर्धा आयोजित की गई. इसमें हज़ारों की संख्या में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ने हिस्सा लिया.

यवतमाल ज़िले की वणी तहसील की निवली पंचायत समिति की ओर से प्रशिक बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान नाटक के ज़रिये स्वच्छता का महत्व समझाते हुए कलाकार.

नागपुर शहर में रोटरी क्लब ऑफ नागपुर और डॉ. आंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट व रिसर्च के संयुक्त तत्वावधान में पेट्रोल की बचत, प्रदूषण कम करने और स्वास्थ्य का संदेश देने वाली साइकिल रैली निकाली गई. रैली में बच्चों के साथ-साथ बुजुर्गों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

अमरावती में मधुसूदन जाजोदिया की स्मृति में अग्रसेन भवन में पति-पत्नी संयुक्त रक्तदान शिविर आयोजित किया गया. इस अवसर पर 57 दंपत्तियों ने रक्तदान किया.

अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल मिरज, मुंबई की ओर से आयोजित कत्थक नृत्य परीक्षा में चंद्रपुर के नादयोग कत्थक केंद्र की 26 में से 16 छात्राओं ने विशेष योग्यता और 10 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी हासिल की. सफल छात्राओं के साथ मार्गदर्शक.

पश्चिम नागपुर नागरिक संघ राम मंदिर रामनगर में शोभायात्रा कार्यालय के उद्घाटन समारोह में मंचासीन नागपुर विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. विलास सपकाल, विधि विशेषज्ञ आनंद परचुरे, संघ के अध्यक्ष बाबासाहब देशपांडे, उपाध्यक्ष प्रवीण महाजन व राजीव काळेले, सचिव चंद्रशेखर घुशे, शोभा यात्रा के संयोजक किशोर कोलवाडकर.

तुमसर-बावनथड़ी प्रकल्प को जल्द पूरा करने और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग को लेकर किसान गर्जना संगठन की ओर से भंडारा ज़िले में महापदयात्रा निकाली गई.

सोने के कारीगर मोहरे बने

बात सोने की हो और अकोला का नाम न आए, यह कैसे संभव है. विदर्भ और उसके आसपास सोने की चोरी कहीं भी हो, उसकी रिकवरी अकोला से होती है. ऐसे एक नहीं कई मामले हैं, जिनमें अकोला ज़िले के बाहर की पुलिस ने अकोला के सराफ़ा व्यापारियों को चोरी का सोना ख़रीदने के लिए पकड़ा. बाद में इन व्यापारियों ने अपनी एसोसिएशन के माध्यम से पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अब उसमें भी बात नहीं बनती देख इन व्यापारियों ने नई तरकीब खोजकर निकाली है. अब पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए सराफ़ा व्यापारी ख़ुद चोरी का सोना नहीं ख़रीदते, बल्कि बीच में सोने के गहने बनाने वाले कारीगरों को रखकर चोरी का सोना ख़रीदा जाता है. इस कारण पुलिस के माल की रिकवरी करने में पुलिस की परेशानियां बढ़ गई हैं.

चोरी के सोने की ख़रीदी-बिक्री के लिए अकोला सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है. विदर्भ में कहीं भी सोने की चोरी होने पर वहां की पुलिस का शक सबसे पहले अकोला की ओर जाता है. कई बार अन्य ज़िलों की पुलिस ने अकोला की अपराध शाखा के साथ मिलकर यहां के कई सराफ़ा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर चोरी का माल ज़ब्त किया है. पुलिस की कार्रवाइयां बढ़ने के बाद इससे बचने के लिए अकोला सराफ़ा व्यापारी अपनी एसोसिएशन के माध्यम से पुलिस पर दबाव बनाने लगे हैं. जब भी पुलिस किसी सराफ़ा व्यापारी के प्रतिष्ठान पर छापा मारने जाती है, एसोसिएशन के लोग आगे आकर उस कार्रवाई को रोक देते हैं. एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि कुछ व्यापारियों के कारण सभी सराफ़ा व्यापारियों को पुलिस बदनाम करती है [illegible] ख़ाली हाथ लौटना पड़ रहा है. [illegible] बार पुलिस दोषी सराफ़ा व्यापारी से चोरी का माल ज़ब्त कर लेती है. जानकारों के अनुसार कार्रवाई से बचने के लिए कुछ सराफ़ा व्यापारी अपराध शाखा के अधिकारियों को ख़ुश रखते हैं. [illegible] कारीगरों को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं. [illegible] 3 चोरियों का 125 ग्राम सोना पुलिस ने ज़ब्त किया था. इसमें से 75 ग्राम सोना चोरों ने इस कारीगर को बेचा था. सवाल यह है कि क्या एक कारीगर इतना अधिक सोना किसी चोर को मोटी रकम देकर ख़रीद सकता है?

चोरी के सोने की ख़रीदी-बिक्री के लिए अकोला सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है. विदर्भ में कहीं भी सोने की चोरी होने पर वहां की पुलिस का शक सबसे पहले अकोला की ओर जाता है. कई बार अन्य ज़िलों की पुलिस ने अकोला की अपराध शाखा के साथ मिलकर यहां के कई सराफ़ा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर चोरी का माल ज़ब्त किया है.

रोज़गार की मारामारी

सोने के भाव दिनोंदिन तेज़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके गहने बनाने वाले कारीगरों के हाल जैसे के तैसे हैं. बताया जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा यह कारीगरी का काम कई परिवार अधिक आमदनी नहीं होने से छोड़ चुके हैं. [illegible] इसी लाचारी का लाभ कुछ सराफ़ा व्यापारी उठा रहे हैं. चोरी के माल में होने वाले लाभ का कुछ हिस्सा देने की शर्त पर सराफ़ा व्यापारी कारीगरों के हाथों चोरी का माल ख़रीदवाते हैं. ऐसे में यदि पुलिस कार्रवाई होती भी है, तो कारीगर फंसता है, न कि व्यापारी. कारीगर किसी अन्य स्थान पर चोरों से माल ख़रीदता है और बाद में सराफ़ा व्यापारी को देता है. [illegible] इससे व्यापारी पुलिस कार्रवाई से साफ़ बच जाते हैं.

सोना पल भर में गल जाता है

चोरी का माल दुकान में आते ही उसे पल भर में गला दिया जाता है, ताकि कोई सबूत न बचे. व्यापारियों की इस रणनीति के कारण पुलिस को चोरी का माल ज़ब्त करने में दिक्क़तें आ रही हैं. अकोला की स्थानीय अपराध शाखा की ओर से ऐसे संदिग्ध कारीगरों की सूची भी बनाई गई है. [illegible] 75 ग्राम सोने के साथ एक कारीगर को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली [illegible]

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मेलघाट से बाघ ग़ायब

यदि आप इसे बुरी ख़बर मानते हैं, तो यह जान लें कि यह केवल बुरी ख़बर नहीं है, बल्कि ख़तरे की घंटी भी है. देश के मुख्य 10 व्याघ्र प्रकल्पों में शामिल महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले के मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में बाघ ग़ायब हैं. ये और कोई नहीं, बल्कि वन विभाग के अधिकारी ही कह रहे हैं. बीती 10 से 19 फरवरी के बीच हुई प्रगणना में एक भी बाघ नज़र नहीं आया है और न ही उनके पैरों के निशान अधिकारियों को मिले हैं. तो क्या हज़ारों एकड़ में फैला मेलघाट का जंगल बाघ विहीन हो गया है? फिर बाघों की सुरक्षा के लिए आए करोड़ों रुपये आख़िर कहां ख़र्च किए गए? वर्ष 2011 में हुई बाघों की प्रगणना के अनुसार देश में लगभग 1706 बाघ बचे हैं. इनमें से लगभग 250 बाघ विदर्भ में हैं. नागपुर से लगकर ताड़ोबा (160 किलोमीटर), बोर (90 किलोमीटर) और नवेगांव बांध व नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प (150 किलोमीटर) को मिलाकर लगभग 400 किलोमीटर क्षेत्र में व्याघ्र प्रकल्प है. पिछली बाघ गणना में बाघों की संख्या में वृद्धि होने की ख़बर आने के बाद केंद्र सरकार के पर्यावरण विभाग की ओर से नागपुर को बाघ राजधानी तक घोषित करने का मन बना लिया गया था, लेकिन अब नागपुर से लगे अमरावती ज़िले में स्थित मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में एक भी बाघ नहीं दिखने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है. उल्लेखनीय है कि 10 से 19 फरवरी के बीच 227 बीट की 454 ट्रांजिट लाइन पर सुबह 6 से 11 बजे तक वन अधिकारी तथा कर्मचारियों ने पैदल चलकर वन्यजीवों की प्रगणना की. उन्हें बारहसिंगा, बायसन, सियार, जंगली सुअर तो दिखे, लेकिन बाघ नज़र नहीं आया. कम से कम बाघ के पैरों के निशान मिलने की आस वन अधिकारियों को थी, लेकिन वह भी टूट गई. सवाल यह उठता है कि आख़िर यहां के बाघ गए कहां? क्या शिकारियों के हत्थे चढ़ गए? फिर बाघों की सुरक्षा में लगे वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आख़िर कर क्या रहे थे? देश में तेज़ी से बाघों की संख्या कम हो रही है. इसे देखते हुए उनकी सुरक्षा हेतु जगह-जगह व्याघ्र प्रकल्पों का निर्माण किया गया. वहां हर वर्ष सरकार करोड़ों रुपये ख़र्च करती है, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलना, चिंताजनक है.

अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बाघ के अंगों की क़ीमत

खाल	35 हज़ार से 50 हज़ार डॉलर (17 से 25 लाख रुपये)
आंखें	170 से 350 डॉलर (8500 से 18 हज़ार रुपये)
हड्डियों का चूरा	1459 डॉलर प्रति पौंड (72 हज़ार 950 रुपये)
पूरा बाघ	75 हज़ार डॉलर से आगे (37 से 40 लाख रुपये)

12 वर्षों में 467 बाघों का शिकार

देश में पिछले 12 वर्षों में 467 बाघों के शिकार के मामले सामने आए हैं. हालांकि वन विभाग ने कई शिकारियों को पकड़ा भी है, लेकिन जितने मामले सामने आए हैं, उससे कहीं अधिक मामलों की जानकारी वन विभाग को नहीं मिल पाई है. बाघों के शिकार के पीछे सबसे मज़बूत पहलू उसका आर्थिक गणित है. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बाघ की क़ीमत क़रीब 40 लाख रुपये तक है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 1997 में बाघों की संख्या लगभग 3508 थी, जो वर्ष 2008 में घटकर 1411 तक पहुंच गई. इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वर्ष 1997 से वर्ष 2008 के बीच कितने बड़े पैमाने पर बाघों की तस्करी की गई. जापान, थाइलैंड, अमेरिका, चीन में पौरुषत्व बढ़ाने के लिए बनने वाली दवाइयों के लिए बाघ के अलग-अलग अवयवों की काफ़ी मांग है. इसी के कारण बाघों का शिकार किया जाता है. बताया जाता है कि शिकारी जड़ी-बूटी खोजने के बहाने से ग्रामीणों से संपर्क करते हैं और उन्हें बाघ के शिकार के लिए उकसाते हैं. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में लाखों रुपये में बिकने वाले बाघ के शिकार के लिए ग्रामीणों को चंद हज़ार रुपये ही दिए जाते हैं. पकड़े जाने पर ग्रामीणों को ही सज़ा होती है, जबकि असल शिकारी पुलिस के हाथ नहीं लग पाते. तेज़ी से घट रहे बाघों की संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1993 में ही बाघ की ख़रीद-बिक्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ रही भारी मांग को देखते हुए इसके शिकार में बढ़ोत्तरी हुई. 4 वर्ष पूर्व बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कई क़दम उठाए. इसका नतीजा यह हुआ कि कई स्थानों पर बाघों की संख्या में अच्छी वृद्धि देखी गई. मध्य भारत में इसके नतीजे सबसे अधिक उत्साहवर्धक थे, लेकिन इस वर्ष मेलघाट में शुरू बाघ प्रगणना के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है. बाघ तो दूर उसके निशान तक कर्मचारियों को नहीं दिखे हैं. हालांकि प्रगणना का दूसरा चरण अभी शुरू है, जो 30 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान 400 कैमरों की मदद से प्रगणना की जा रही है, लेकिन पहले चरण के नतीजों ने पूरे वन विभाग को हिला कर रख दिया है.

कर्मचारी भूखे, हीरोइनों पर लाखों ख़र्च

एक ओर बाघों की सुरक्षा के नाम पर मशहूर फिल्म हीरोइनों को आगे कर बड़े-बड़े आयोजनों पर लाखों रुपये ख़र्च किए जा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर वन कर्मचारी भूखे पेट बाघ गणना में लगे हैं. पिछले दिनों वेद की ओर से नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में फ्रेंड्स ऑफ टाइगर कंट्री सेंट्रल इंडिया की स्थापना की गई. इसमें प्रमुख रूप से पूर्व मिस यूनिवर्स और फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता सेन को बुलाया था. इस कार्यक्रम पर ख़र्च हुए लाखों रुपये से बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए कितना फ़ायदा हुआ यह तो खुद सुष्मिता सेन भी नहीं बता सकतीं, लेकिन जो कर्मचारी दिन-रात बाघों की सुरक्षा में लगे हैं, उन्हें दो महीने से वेतन नहीं दिए जाने के ख़ुलासे ने इस पूरी योजना की ही पोल खोलकर रख दी है. नागपुर से नज़दीक मानसिंगदेव अभयारण्य के 35-40 कर्मचारियों को वन विभाग की ओर से दो महीने से वेतन नहीं दिया गया है. इस स्थिति में कैसे हम बाघों की सुरक्षा कर पाएंगे? व्याघ्र प्रकल्पों में फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों के सैकड़ों पद ख़ाली होने से अन्य कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया है. शिकारियों से निपटने के लिए आधुनिक सुविधाओं और हथियारों की मांग तो काफ़ी पुरानी है. यही कारण है कि शिकार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं.

इस वर्ष 12 बाघों की मौत

वर्ष 2011 में मध्य भारत में 62 बाघों की मौत हुई थी, जबकि वर्ष 2012 की शुरुआत में ही अब तक 12 बाघों की मौत हो गई है. इसमें से कितने बाघों की तस्करी की गई, यह बताना मुश्किल है. जनवरी 2003 में मेलघाट में एक बाघिन को करंट देकर मारा गया. उस समय उसके पेट में पांच शावक थे. चंद्रपुर ज़िले में पिछले दिनों गाड़ी की टक्कर से एक बाघ की मौत हो गई थी. एक वर्ष पूर्व अमरावती ज़िले में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया. वह इंटरनेट के माध्यम से बाघ की बिक्री पर करोड़ों रुपये का सौदा कर रहा था. यदि इसी तरह बाघों का शिकार होता रहा, तो बाघ केवल तस्वीरों में ही बच जाएंगे.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त समाचार

पिता ने पुत्री की हत्या की

राज्य के मुखिया पृथ्वीराज चव्हाण के गृह ज़िले सतारा में घरवालों की मर्ज़ी से विवाह न करने से नाराज़ पिता ने अपनी 25 वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी. ज़िले के औंध गांव निवासी है शंकर शिंदे. उनकी उच्च शिक्षित पुत्री आशा शिंदे अपनी मर्ज़ी से अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी. आशा के घरवाले उसकी शादी के लिए रिश्ते तलाश रहे थे और कई रिश्ते आए भी, पर उसे पसंद नहीं आए. उसके नज़दीकियों का कहना है कि आशा हमेशा अपने घरवालों से कहती थी कि वह अपनी पसंद की लड़के से शादी करेगी. इससे उसके पिता सहित सभी घरवाले नाराज़ रहते थे. उस पर दबाव डालते थे कि वह घरवालों की पसंद के समाज के ही किसी लड़के से शादी कर ले. इस बात को लेकर घर में कई बार कलह भी हो चुकी थी. कुछ दिनों पहले आशा की अपने पिता से शादी को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई. झगड़े के पश्चात आशा जब रात में अपने बिस्तर में जाकर सो गई तो उसके पिता शंकर शिंदे ने लोहे की रॉड से उस पर लगातार कई वार किए. गहरी नींद में हुए हमले से आशा चीख़ भी नहीं सकी और उसकी मौत हो गई. पुत्री की हत्या करने के बाद शंकर शिंदे थाने गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया. सुबह जब लोगों को इस घटना का पता चला तो पूरा गांव सन्न रह गया. अब इस मुद्दे को लेकर राज्य में बहस छिड़ गई है कि जाति के अहंकार पर पुत्रियों की हत्या करना क्या उचित है?

धर्मविहीन घोषित करने की मांग ठुकराई

जाति तोड़ो, समाज जोड़ो का अभियान कभी महाराष्ट्र के संतों न चलाया था, लेकिन किसी व्यक्ति ने ख़ुद को जातिविहीन, धर्मविहीन घोषित करने की मांग कभी किसी अदालत से अब तक नहीं की है. हां, धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर देश में ख़ूब बहस एवं फ़साद अवश्य हुए हैं. देश एवं महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति द्वारा ख़ुद को जाति एवं धर्मविहीन घोषित करने की मांग अदालत से करने का मामला सामने आया है. ठाणे निवासी एडवोकेट श्रीरंग बलवंत खांबेटे ने जन्म से कोंकणी हिंदू ब्राह्मण होने के बाद भी 20 जुलाई, 2009 को अदालत में अपील पेश कर ख़ुद को जातिविहीन एवं धर्मविहीन घोषित करने की मांग की थी. अपनी याचिका में खांबेटे ने कहा था कि वह जन्म से हिंदू ब्राह्मण हैं, लेकिन 40 साल के अध्ययन एवं अनुभव के बाद देश में तेज़ी से बढ़ रहे जातिवाद, धर्मवाद और उसके नाम पर होने वाली राजनीति, धार्मिक दंगल आदि से उनका मन ऊब गया है. जाति एवं धर्म का लेबल अनावश्यक होने पर भी उसके बिना जीना मुश्किल हो गया है. हाल में इस मामले में दीवानी अदालत के न्यायाधीश एसरस तोडणकर ने याचिका को ठुकराते हुए कहा कि हिंदू क़ानून खांबेटे का व्यक्तिगत क़ायदा नहीं है. साथ ही जातिविहीन एवं धर्मविहीन वह हैं, इसके लिए उन्होंने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है. मात्र खांबेटे द्वारा अदालत में व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं और उनके विचार के आधार पर यदि फ़ैसला दिया जाता है तो उनके मत को सभी पर जबरन लादना होगा. इसलिए न्यायालय उनकी याचिका को निरस्त करती है. मगर आज जिस तरह से जातिवाद और धर्म का ज़हर फैल रहा है या फैलाया जा रहा है, वह चिंता का विषय है. खांबेटे ने एक बार फिर जाति-धर्म की दीवार को तोड़कर मानव को जोड़ने का मुद्दा उठाकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारतीय समाज किस ओर जा रहा है?

अपंगों के प्रति प्रशासन असंवेदनशील

सरकार के ख़ज़ाने से करोड़ों रुपये राज्य के अपंग लोगों के हित में विविध योजनाओं के माध्यम से ख़र्च किए जाते हैं, मगर असंवेदशील प्रशासन के चलते राज्य के अपंगों को समय पर कोई राहत नहीं मिलती है. औरंगाबाद ज़िला परिषद के समाज कल्याण विभाग की मार्फ़त अपंगों को वितरित करने के लिए शासन द्वारा 126 तिपहिया साइकिलों के लिए निधि उपलब्ध कराई गई थीं. निधि से तिपहिया साइकिलें ख़रीदी तो गईं, पर अपंग व्यक्तियों को वितरित नहीं किया गया. इसके कारण रखे-रखे वह गोदाम में ही कबाड़ में तब्दील हो गईं. इसके लिए ज़िम्मेदार समाज कल्याण अधिकारी के ख़िलाफ़ बार-बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस संबंध में कांग्रेस अपंग विकास सेल के नगराध्यक्ष राजू देहाडे का कहना है कि समाज कल्याण अधिकारी से इन तिपहिया साइकिलों के वितरण के विषय में बार-बार पूछा गया, पर कोई जवाब नहीं मिला. जब हमने सवाल किया कि उक्त साइकिलें कब और कितनी ख़रीदी गईं? उनका वितरण अपंगों को कब किया जाएगा? तो हमेशा टाल-टोल जवाब दिया जाता रहा है. इससे यह संदेह होता है कि इन साइकिलों की ख़रीदी में अधिकारी स्तर पर घोटाला हुआ है. वर्तमान में उक्त साइकिलें कबाड़ में बदल गईं. जब हमने मोर्चा निकाला और ज़िला परिषद के सीईओ को निवेदन दिया, जिस पर उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी वंदना कोचुरे पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. लेकिन इस मामले से यह पता चलता है कि प्रशासन अपंगों के प्रति कितना असंवेदनशील है.

हुज़ूर, लापता बैल का पता लगाइए!

मुंबई उच्च न्यायालय में एक व्यक्ति ने याचिका दायर कर न्यायाधीश से मांग की कि उसके लापता बैल का पता लगवाया जाए, क्योंकि 30 हज़ार रुपये का बांड भरने के बाद भी उसका बैल नहीं मिल रहा है. इस पर उच्च न्यायालय ने याचिका का संज्ञान लेते हुए महानगर पालिका एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी कर संपूर्ण स्थिति अपने समक्ष रखने का निर्देश दिया है. याचिका में कहा गया है कि चार माह पहले लापता इस बैल को कुर्बानी के लिए मुंबई लाया गया था. मुंबई पहुंचने के बाद अचानक बैल लापता हो गया. उसके पांच दिन बाद किसी अजनबी व्यक्ति ने बैल के उपद्रव से परेशान होकर स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. इस पर पुलिस ने बैल को अपनी हिरासम में ले लिया और उसके मालिक को सूचित किया गया. मालिक के आने पर पुलिस ने बैल को मुंबई की गिरगांव की अदालत में पेश किया. इस पर महानगरीय दंडाधिकारी ने बैल मालिक को 30 हज़ार रुपये का बांड भरकर बैल को ले जाने को कहा. मालिक ने दंडाधिकारी के निर्देशानुसार बांड भर दिया. इसके बाद भी उसका बैल नहीं मिला. इस पर उस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जज से अनुरोध किया कि हुज़ूर, मेरे लापता बैल का पता लगवाइए.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ये क्या हो रहा है...

सभ्य समाज की करतूत

हम पढ़े-लिखे लोग उच्च शिक्षित, सभ्य होने का दावा करते हैं. नियम-क़ायदों की बातें करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सभ्य समाज की करतूतें मानवता को शर्मसार करती हैं. बहू-बेटियों की कृतघ्नता से हत्या की हर घटना के बाद यह सवाल हमारे सामने आकर झकझोरने लगता है कि हम कितने सभ्य-सुसंस्कृत हैं? हमें मिलने वाली शिक्षा ने हमें संस्कारों के किन आभूषणों से अलंकृत किया है? एक वकील पति द्वारा वकील पत्नी को ज़िंदा जलाकर उसकी हत्या करना, कैसी सभ्यता है? उपराजधानी नागपुर में घटित वकील पूर्णिमा बोरकर हत्याकांड उन सभी लोगों से यह सवाल करता है, जो उच्च शिक्षित, सभ्य और सुसंस्कृत होने का दावा करते हैं. उसका क्या दोष था कि उसके पति वकील राजेश बोरकर ने उसे ज़िंदा जला दिया? मगर यह कृतघ्न समाज क्या जवाब देगा, जब वह स्त्री-पुरुष में भेद करता हो और बेटियों की कोख में हत्या करने जैसा कुकृत्य करता हो. आख़िर समाज में हो क्या रहा है? वह किस दिशा की ओर जा रहा है? इस हत्याकांड के ख़ुलासे के बाद एक बार फिर यह समाज स्त्री-पुरुष में विभाजित दिखाई दिया. समझ में नहीं आता कि समाज सेवा का दम भरने वाले उपराजधानी के ख़ुद को समाज का कर्णधार बताने वाले संगठन एवं सोशल वर्कर किस खोल में घुस गए. राजनीतिक दल कहां सो गए, जो हमेशा अन्याय का विरोध करने को उतावले नज़र आते हैं. यहां तक क़ानून की 24 घंटे बातें करने वाले वकील संगठन ज़िला बार एसोसिएशन तक दोफाड़ नज़र आया. महिला वकील जहां पूर्णिमा बोरकर हत्याकांड का खुलकर विरोध कर रही थीं और हत्यारों को कठोर दंड देने की मांग कर रही थीं, वहीं पुरुष वकील चुप्पी साध कर अपने खोल में घुसे हुए थे, जबकि संगठन के चुनाव में महिला वकीलों को बहन-बहन कहकर उनसे हाथ जोड़कर वोट मांगते नहीं थकते थे. यह हाल तो हमारे क़ानून के जानकारों का है. वकील यदि क़ानून का सम्मान करते तो राजेश बोरकर अपनी पत्नी को ज़िंदा जलाने की हिमाक़त भी नहीं करते. ऐसा लगता है कि हमारे वकील क़ानून को अपनी रखैल समझते हैं और उससे कमाई करना ही सीख पाए हैं, लेकिन यह समस्या सिर्फ़ एक पेशे की नहीं है. यह समस्या संपूर्ण समाज की नैतिकता पर सवालिया निशान है. हम जितने अधिक शिक्षित एवं आधुनिक हो रहे हैं, उतने अधिक सामाजिक दायित्वों की अवहेलना करते नज़र आते हैं. ऐसा न पहली बार हो रहा है और न ससुरालियों द्वारा पूर्णिमा बोरकर की हत्या करना कोई पहली घटना है, लेकिन हर घटना को भुला देना, उससे कोई सबक़ न लेना और पुनः सुप्तावस्था में चले जाना, यह समाज की विडंबना है. जब ख़ुद पर आती है तो पीड़ा होती है, लेकिन जब दूसरों पर गुज़रती है तो मात्र घटना बनकर रह जाती है. यह स्थिति किसी भी समाज के लिए घातक एवं विनाशकारी ही सिद्ध होती है. इस तरह की घटनाओं का बार-बार होना समाज की दुर्बलता को दर्शाता है. भला यह कैसे हो सकता है कि घर में एक औरत आग की लपटों में घिरकर चीख़-चिल्ला रही हो और पति, देवर, सास, ससुर को पता न चले? पीड़ित महिला के कमरे में जो पानी रखा हो, वह आग बुझाने की बजाय और आग को भड़काए? पीड़िता के बाहर आने के सारे रास्ते बंद हों? उसे अपने घर की बालकनी से कूदकर पड़ोसी के पास जाना पड़े? ये सभी सवाल राजेश बोरकर सहित उनके सारे परिवार की असंवेदशीलता और क्रूरता का परिचय देते हैं. समाज के हर व्यक्ति को यह अपने आप से सवाल करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं क्या उनके सभ्य होने पर प्रश्नचिन्ह नहीं है? यदि समाज इससे शर्मसार है तो ऐसे क्रूरतम कृत्य करने वाले लोगों को उनकी करनी की सज़ा दिलाने के लिए पूरे समाज को आगे आना चाहिए, स्त्री-पुरुष और अपने-पराये के भेदभाव को भूलकर.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

भीषण जल संकट के मुहाने पर विदर्भ-मराठवाड़ा

विदर्भ-मराठवाड़ा फिर जल संकट के घेरे में है और इस संकट की घड़ी में यहां का आम आदमी एवं किसान अकेला है. महज़ एक महीना पहले वोट मांगने के लिए मतदाताओं के दर-दर पहुंचने वाले नेता अब नदारद हैं. अब स्थिति यह है कि लोगों को पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है. लोकतंत्र में राजा कहलाने वाला मतदाता चुनाव होते ही नौकर बन गया है और यह नौकर राह देख रहा है कि कोई उसके और उसके परिवार के गले की प्यास को बुझाए. वर्ष 2011 में राज्य में औसत से कम बारिश हुई. वहीं चार महीने अनियमित बारिश होने के कारण राज्य के सिंचाई प्रकल्प पूर्ण रूप से नहीं भर पाए थे. फरवरी 2012 के अंत तक राज्य के कुल 2436 प्रकल्पों में 18 हज़ार 269 दलघमी (50 प्रतिशत) पानी का संग्रह था. इसमें सबसे ख़राब स्थिति विदर्भ और मराठवाड़ा की है. विदर्भ के नागपुर विभाग के 366 प्रकल्पों में 2637 दलघमी (42 प्रतिशत) पानी ही बचा है. वहीं अमरावती विभाग के 359 प्रकल्पों में 1264 दलघमी (42 प्रतिशत) जल संग्रह है, जबकि वर्ष 2011 में फरवरी माह तक नागपुर विभाग के प्रकल्पों में 58 प्रतिशत और अमरावती विभाग में 64 प्रतिशत जल संग्रह था. यही कारण है कि वर्ष 2011 की गर्मियों में विदर्भ में जल संकट की भीषणता अधिक नहीं थी. यही स्थिति मराठवाड़ा की भी थी, किंतु अब स्थिति बिलकुल उलट है. मराठवाड़ा के 600 प्रकल्पों में 2778 दलघमी (41 प्रतिशत) पानी बचा है. अमरावती विभाग के प्रमुख प्रकल्पों में अमरावती ज़िले के उर्ध्व वर्धा प्रकल्प में 55 प्रतिशत, यवतमाल ज़िले के पुस प्रकल्प में 63 प्रतिशत, अरुणावती में 48 प्रतिशत, बेंबला में 33 प्रतिशत, अकोला ज़िले के काटेपूर्णा प्रकल्प में 34 प्रतिशत, बुलढाना ज़िले के वाण में 66 प्रतिशत, नलगंगा में 45 प्रतिशत और पेनटाकली प्रकल्प में केवल 30 प्रतिशत पानी का संग्रह है. जानकारों के अनुसार कई प्रकल्पों में तो इससे भी कम पानी का संग्रह है. मार्च महीने में धीरे-धीरे तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है. इसके कारण बड़े पैमाने में पानी का वाष्पीकरण होता है. ऐसे में विदर्भ और मराठवाड़ा के प्रकल्पों में तेज़ी से पानी का संग्रह घटेगा, जिसका सीधा असर यहां रहने वाले लोगों को होने वाली जलापूर्ति पर पड़ेगा. विदर्भ के अमरावती, अकोला, बुलढाना, चंद्रपुर और यवतमाल ज़िलों में खारे पानी और फ्लोराइड ग्रस्त इलाक़ों में जनवरी माह से ही लोगों को पानी की क़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है. कई स्थानों पर भूजल स्तर भी काफ़ी नीचे चला गया है और कुएं और बोरवेल सूख चुके हैं. ऐसे में अप्रैल और मई माह में यहां की स्थिति काफ़ी भयावह होने का अनुमान है.

भू जल स्तर नीचे जाने से कुएं और बोरवेल सूखे

योजनाएं बनीं, फिर भी पानी की क़िल्लत बरक़रार है. सबसे हैरत की बात यह है कि राज्य के हर ज़िले के लिए जल संकट से निपटने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई योजना नज़र नहीं आ रही है. विदर्भ के कई छोटे शहरों में सप्ताह में केवल 2 दिन जलापूर्ति की जा रही है. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में तो स्थिति और ख़राब है. कई किलोमीटर भटकने के बाद लोगों को प्यास बुझाने लायक़ पानी मिल पा रहा है. योजनाओं के अनुसार जिन गांवों में टैंकरों से जलापूर्ति की जानी थी, वहां टैंकर पहुंच ही नहीं रहे हैं. नागपुर, अमरावती, अकोला, यवतमाल के लोगों का कहना है कि उन्हें पानी ख़रीद कर पीना पड़ रहा है. प्रशासन की ओर से यदि टैंकर भेजे भी जा रहे हैं, तो भी टैंकर चालक द्वारा लोगों से पैसे वसूलने की जानकारी मिली है. ऐसे में पानी के लिए लोग परेशान हैं.

पशुधन बिकेगा

गर्मियों में मवेशियों की परेशानी सबसे अधिक बढ़ जाती है. गर्मियों में पानी की क़िल्लत के कारण मवेशियों को बेचने के मामलों में अचानक बढ़ोत्तरी होती है. इस दौरान व्यापारी काफ़ी कम दाम देकर मवेशियों को ख़रीदते हैं. गर्मियों में गांवों में कुएं, हैंडपंप, तालाब आदि सूख जाने के कारण पानी की क़िल्लत तो पैदा होती ही है, साथ में मवेशियों के लिए चारा भी उपलब्ध नहीं हो पाता. ऐसे में मजबूरन मवेशी पालक अपने मवेशियों को बेच देते हैं. विदर्भ के खारे पानी और फ्लोराइड पट्टे में ऐसे मामले ज़्यादा देखने को मिलते हैं. उनकी इस मजबूरी का लाभ व्यापारी उठाते हैं. हालांकि पानी और चारे की क़िल्लत से निपटने के लिए राज्य सरकार तहसील निहाय चारा डिपो शुरू करवाती है, लेकिन ये कहां खुलते हैं और किस-किस को इससे लाभ मिलता है, यह बताना काफ़ी मुश्किल है.

विभाग	प्रकल्पों की संख्या	जल संग्रह	प्रतिशत
अमरावती	359	1264 (दलघमी)	42 प्रतिशत
नागपुर	366	1637(दलघमी)	42 प्रतिशत
मराठवाड़ा	600	2778 (दलघमी)	41 प्रतिशत
नासिक	348	2190 (दलघमी)	47 प्रतिशत
पुणे	595	5645 (दलघमी)	52 प्र.श.
कोंकण	154	1012 (दलघमी)	63 प्रतिशत
अन्य बांध	14	3743 (दलघमी)	63 प्रतिशत

कोंकण की स्थिति बेहतर

राज्य के प्रकल्पों में पानी संग्रह के मामले में कोंकण विभाग की स्थिति बाक़ी विभागों से बेहतर है. यहां के 154 प्रकल्पों में कुल 63 प्रतिशत पानी का संग्रह है, लेकिन नासिक और पुणे में स्थिति ख़राब है. नासिक विभाग के 348 प्रकल्पों में केवल 47 प्रतिशत ही पानी बचा है. वहीं पुणे विभाग के 595 प्रकल्पों में 52 प्रतिशत जल संग्रह है. ऐसे में नासिक और पुणे विभाग में भी लोगों को पानी की क़िल्लत का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नक्सलियों के समक्ष नतमस्तक प्रशासन

राज्य सरकार क्या इतनी निष्क्रिय हो गई है कि वह नक्सलियों के आगे झुक जाए. विश्वास तो नहीं होता है, पर भारतीय लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है. एक ओर हमारे केंद्रीय गृहमंत्री घोषणा करते हैं कि नक्सलियों से सख्ती से निपटा जाएगा और इसके लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने गड़चिरोली ज़िले में माओवादियों के दबाव में प्रस्तावित इस्पात योजना को रोकने की घोषणा कर दी है. इस घोषणा से ज़िले में सुरक्षा एजेंसियों में नाराज़गी है. पिछले दिनों राज्य में महानगर पालिका के साथ ही ज़िला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव संपन्न हुए हैं. इन चुनावों के दौरान नक्सलियों ने अपने दबदबे वाले क्षेत्र के ग्रामवासियों से चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की थी. उनकी अपील न माने जाने पर अंजाम देख लेने की धमकी दी गई थी. नक्सल प्रभावित गड़चिरोली ज़िले में कुछ जगह तो प्रशासन ने भारी सुरक्षा का इंतज़ाम कर जैसे-तैसे चुनाव करा लिए, लेकिन कुछ जगहों पर नक्सलियों ने चुनाव पार्टी पर गोलीबारी भी की थी. चुनाव के पहले भामरागढ़ में एक राजनीतिक कार्यकर्ता की सरेआम हत्या कर दी गई थी. आदिवासियों ने मतदान में अपनी भागीदारी भी निभाई थी. यहां तक़रीबन 60-65 प्रतिशत मतदान हुआ था. मगर ज़िले के ही कोरची एवं भामरागढ़ तहसील के कुछ इलाक़ों में चुनाव का बहिष्कार किया गया.

ज़िले की कोरची एवं भामरागढ़ तहसीलें नक्सलियों का गढ़ मानी जाती हैं. इनमें से कोरची तहसील के निवासियों ने मांग की थी कि यदि सरकार और प्रशासन चाहता है हम चुनाव में हिस्सा लें तो उसको यहां प्रस्तावित इस्पात परियोजना को रद्द करना होगा. पहले तो शासन-प्रशासन यही हुंकार भरते रहे कि हम नक्सलियों के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, उनकी कोई मांग नहीं मानेंगे. मगर अब शासन-प्रशासन का रुख़ बदल चुका है. प्रशासन ने कोरची तहसील क्षेत्र में प्रस्तावित इस्पात परियोजना को रद्द करने की घोषणा की है. इस पर सुरक्षा एजेंसियों ने सख्त आपत्ति दर्ज कराई है. इसकी वजह यह है कि कोरची तहसील नक्सलियों का गढ़ है और प्रस्तावित इस्पात परियोजना की लीज रद्द करने की मांग करने का निर्णय वहां के नागरिकों ने नक्सलियों के दबाव में ही लिया था. इसका साफ़ मतलब है कि नक्सली अपनी मांग मनवाने के लिए नागरिकों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. यदि प्रशासन ने इस मांग को मान लिया है तो भविष्य में नक्सली अपनी और भी मांगें मनवाने के लिए किसी भी गांव को बंधक बनाकर वहां के निवासियों का उसी तरह उपयोग करेंगे जिस तरह से कोरची तहसील के निवासियों का इस्पात परियोजना को रद्द करने के लिए किया गया है. यह प्रशासन का ख़तरनाक क़दम है.

दूसरी ओर प्रशासन का नज़रिया यह है कि वह ये क़दम कोरची में ज़िला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए उठा रहे हैं. एक तरह से कोरची में लोकतंत्र को बचाने के लिए यह क़दम उठाया गया है. चूंकि पूरी कोरची तहसील के लोग प्रस्तावित इस्पात परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे थे, इसलिए प्रशासन ने उनकी मांग मानते हुए उक्त परियोजना को मंज़ूरी न देने की घोषणा की है. मगर प्रशासन के इस निर्णय पर ज़िला और तहसील प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है. फोन करने पर तुरंत काट दिया जाता है. लोगों का कहना है कि प्रशासन नक्सलियों की चाल में फंस गया है. यदि ज़िले की किसी परियोजना के भविष्य का निर्धारण नक्सली करेंगे तो उस ज़िले की विकास परियोजनाओं का क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है. इस फ़ैसले के बाद शासन-प्रशासन की स्थिति सांप-छछूंदर की तरह हो गई जो न निग़ली जा सकती है और न उगली जा सकती है. वहीं नक्सली अपना विस्तार अब शहरों की ओर अधिक कर रहे हैं. कुछ दिन पहले ख़ुफ़िया एजेंसियों के हवाले से सूचनाओं के आधार पर दिल्ली से ख़बर आई थी कि नक्सली अपने रेड कॉरिडोर में महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नागपुर, वर्धा और यवतमाल को भी शामिल करना चाहते हैं. नक्सली संगठनों ने यह फ़ैसला अपने शीर्ष नेता किसनजी के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद लिया था. महाराष्ट्र में गड़चिरोली और चंद्रपुर ज़िलों में नक्सली अधिक सक्रिय हैं. गोंदिया ज़िले में भी छत्तीसगढ़ से जुड़े गांवों में उनकी सक्रियता है, लेकिन अब वे मुंबई, पुणे, वर्धा, यवतमाल सहित उपराजधानी नागपुर में भी अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की कार्ययोजना पर काम कर रहे हैं. इन परिस्थितियों में कोरची तहसील में प्रस्तावित इस्पात योजना को नक्सलियों के दबाव में रद्द करना कहां तक उचित है? प्रशासन के इस निर्णय से नक्सलियों से मुक़ाबला कर रहे सुरक्षा एजेंसियों के जवानों का मनोबल भी गिरता है, क्योंकि वे अपनी जान जोखिम में डाल कर नक्सलियों का मुक़ाबला करते हैं. दूसरी ओर शासन-प्रशासन उनके बनाए दबाव को अप्रभावित कर देते हैं. फिर नक्सलियों को प्रशासन की कमज़ोरी पकड़ में आते ही वे अपनी रह मांग को मनवाने के लिए नागरिकों का उपयोग कर सकते हैं. सुरक्षा एजेंसियों की इस आशंका को नकारा नहीं जा सकता है.

ताड़ोबा को सशस्त्र अड्डा बनाने की कोशिश

एक ओर नक्सलियों के दबाव में प्रशासन कोरची तहसील में प्रस्तावित इस्पात परियोजना को रद्द करने की नीति अपना रहा है, वहीं ताड़ोबा को माओवादी नक्सली अपना नया सशस्त्र अड्डा बनाने की फ़िराक में हैं. इस बात का ख़ुलासा पिछले दिनों चंद्रपुर ज़िले की तहसील नागभीड़ से गिरफ्तार किए गए कुख्यात नक्सली कमांडर मारोती कुरवटकर से पूछताछ और ज़ब्त की गई सामग्री से हुआ है. हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ताड़ोबा की भौगोलिक स्थिति के लिहाज़ से कुरवटकर की बात पर विश्वास नहीं होता है. मगर कुरवटकर ने जिस तरह के बयान दिए, उससे ऐसा आभास होता है कि यहां नक्सली ताड़ोबा दलम के नाम से नया दल बनाकर सशस्त्र गतिविधियां संचालित करना चाहते थे. कुरवटकर के बयान पर नागपुर, बल्लारपुर आदि जगहों से भी लैपटॉप सति अन्य सामग्रियां ज़ब्त की गईं और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नोट छापने वाली पुरानी मशीनों का क्या किया जाता है? इसका सही-सटीक जवाब भारतीय रिजर्व बैंक ही दे सकता है.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

मतदाताओं ने नकेल कसी

चुनाव ख़त्म हो गए हैं. राज्य की सत्ताधारी आघाड़ी सरकार में शामिल दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोपों को भूलकर काम शुरू कर दिया है. अब सरकार को सोचना होगा कि गए वर्षभर में संभल नहीं पाए राज्य के बजट को आने वाले वित्तीय वर्ष में किस तरह संभाला जाए. वहीं भ्रष्टाचार से जन्मे कांग्रेस के मिस्टर क्लीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पिछले एक वर्ष में कई अवसर आने के बाद भी अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं. संयमी, सुसंस्कृत, शालीन आदि गुण होने के बाद भी वह अपने आसपास अच्छे लोग नहीं जोड़ पाए हैं. दिल्ली से मिलने वाले पूरे सहयोग के बावजूद नीतियों के अभाव, राजकीय सोच और अच्छे सलाहकारों की कमी के कारण महाराष्ट्र में अपना नेतृत्व स्थापित करने का इतना अच्छा अवसर होने के बाद भी चव्हाण बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं. हाल में हुए चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दमदार प्रदर्शन कर नंबर वन की दौड़ जीत ली है. हालांकि मुंबई और नागपुर, विदर्भ में मतदाताओं ने राकांपा पर ज़रूर लगाम लगाई है. वहीं पुणे में एक ही के हाथ में सत्ता नहीं दी है. मतदाताओं ने राकांपा को भी बता दिया है कि आयातित नेतृत्व के बल पर पार्टी को तेज़ी से नहीं बढ़ाया जा सकता. इन चुनावों में राज ठाकरे की मनसे को मतदाताओं ने काफ़ी अच्छा समर्थन दिया है, लेकिन बेलगाम होकर अपनी मर्ज़ी चलाई जा सके, यह स्थिति भी नहीं आने दी है. कम मतदान होने की चिल्ल-पों के बीच जो मतदान हुआ, उसमें मैनडेट का कितना विचार लोगों ने किया है, यह भी स्पष्ट हो गया है. हर ओर पैसा, शराब, दादागिरी, भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्ति होने के बावजूद मतदाताओं ने भी सही तरह से अपना राजनीतिक कर्तव्य पूरा किया है, जिसके कारण किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता को ऐसा जनाधार नहीं मिला कि वे अपनी मनमर्ज़ी चला सकें. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को नासिक, पुणे और मुंबई में मतदाताओं ने अच्छा समर्थन दिया है. हमें पूछे बग़ैर महापौर तय करना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर हम प्रस्थापित राजनीतिक पार्टियों को झुकाकर जैसा चाहे वैसा राजकीय इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की राज ठाकरे की सोच को मतदाताओं ने धूल में मिला दिया है. मनसे ने सीटें जीतीं, लेकिन उससे भाजपा को नहीं, बल्कि कांग्रेस-शिवसेना को नुक़सान हुआ है. हो सकता है कि भाजपा ने जो पहले से मनसे के साथ अंदरूनी गुप्त समझौता किया था, उससे वह अपनी प्रतिष्ठा संभालने में सफल रही. शिवसेना प्रमुख का तुरुप का इक्का साथ में होने के कारण महायुति सत्ता हासिल कर पाई है. वहीं आख़िरी समय में बालासाहब ठाकरे के लिए 100 क़दम पीछे आने की भावुक अपील के कारण राज ठाकरे भी फ़ायदे में रहे हैं. जिस स्थान पर मनसे के पिछले ढाई वर्ष में विधायक हैं, वहां भी केवल दादर छोड़ दिया जाए तो वे पूरी तरह पकड़ नहीं जमा पाए हैं. इंदू मिल मैदान का विवाद होने से दादर को अधिक महत्व मिला और मतदाताओं ने मनसे को अवसर दिया है.

महायुति में आकर रामदास आठवले ने 52 पत्तों में से केवल जोकर की भूमिका निभाई है. आठवले की पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया है. इसका अर्थ यह है कि भाजपा-सेना ने उन्हें साथ मिलाया, लेकिन मतदाताओं ने नहीं, यह कहा जा सकता है. मुंबई में 29 जगह मिलने के बाद भी आठवले अपनी पार्टी को स्थापित नहीं कर पाए. क्योंकि उन्होंने योग्य उम्मीदवारों का चयन न करके केवल पैसे देने वालों को टिकटें दीं. विधानसभा चुनाव पर नज़र रखकर यदि उन्होंने क़दम उठाए होते तो निश्चित ही परिस्थिति कुछ और होती. 2004 में उनकी पार्टी से आपराधिक प्रवृत्ति का पप्पू कलानी विधायक बना था. अब मुंबई में डीके राव का अपराधी भाई सुब्बाराव नगरसेवक बना है. गवली टोली के दो उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है. इन लोगों को साथ लेकर अब शिवसेना मुंबई में सत्ता स्थापित करेगी. राज ठाकरे को किंगफिशर कहने वाले रामदास आठवले की हालत वर्तमान में राजनीतिक कांटे में अटकी मछली की तरह हो गई है, लेकिन नासिक में वे अपने तीन नगरसेवकों के बल पर कांग्रेस-राकांपा और सेना का समर्थन लेकर अपना महापौर बनाने का प्रयास कर रहे हैं. यह उनकी चाणक्य नीति काफ़ी प्रभावित करने वाली है, लेकिन यदि उन्होंने इसी तरह की नीति चुनाव के पहले अपनाई होती, तो निश्चित ही वह अपना राजनीतिक महत्व स्थापित कर पाने में सफल रहते, परंतु ग़लत समय पर लालू स्टाइल में जोक सुनाकर, मिमिक्री कर और फ़ालतू की कविताएं कर लोगों को हंसाने के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया. लोग हंसे यानी हम हिट हो गए, जैसी समझ दिखाकर आठवले ने मतदान के पूर्व स्वयं का व्यक्तित्व जोकर जैसा बना लिया. इसके कारण मतदाताओं ने उन्हें अधिक गंभीरता से नहीं लिया. अब मुंबई, उल्हासनगर, ठाणे, नागपुर में महायुति और पिंपरी-चिंचवड़, सोलापुर, अमरावती, पुणे, अकोला में आघाड़ी का महापौर बनने जा रहा है, लेकिन इन स्थानों पर सभी पार्टियों को जोड़-तोड़ तो करनी पड़ ही रही है. अमरावती में पूर्व राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख को महत्व देना होगा. केवल पिंपरी में राकांपा और नागपुर में भाजपा की निर्विवाद सत्ता आएगी. नासिक में मनसे का महापौर नहीं बनने देने के लिए रामदास आठवले को आगे कर उद्धव ठाकरे अपना खेल, खेल रहे हैं. वहीं ठाणे में मनसे उनका महापौर नहीं बनने देने के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है. ऐसे में भाजपा की मदद से रिपाइं का साथ लेकर मनसे का महापौर नासिक में बनाना ही शिवसेना के पास सही पर्याय है. इसी फार्मूले के तहत ठाणे में सेना-भाजपा-रिपाइं-बसपा-निर्दलीय का महापौर बनते समय मनसे तटस्थ रहेगी, लेकिन क्या यह राजकीय होशियारी ठाकरे बंधु दिखाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है. पुणे में कलमाड़ी के कांग्रेस का साथ अजीत पवार को लेना होगा. ऐन चुनाव के समय कलमाड़ी को जेल से बाहर निकालकर पुणे में जीत हासिल करने का सपना कांग्रेस का टूट गया है. अब कांग्रेस और राकांपा को साथ आना ही होगा, तभी सोलापुर में भी उनका महापौर बन पाएगा. पूरे राज्य की राजकीय परिस्थिति को देखा जाए, तो कहा जा सकता है कि मतदाताओं ने जो जनादेश दिया है, उससे सभी नेताओं और पार्टियों पर ज़िम्मेदारी और राजनीतिक संयम बनाए रखने के लिए नकेल कसी है. मतदाता राजा समझदार है, इसलिए इस देश में लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है.

किशोर आपटे
feedback@chauthiduniya.com

नोट छापने वाली पुरानी मशीनें कहां गईं

राजेश नामदेव

देश में जाली नोटों का चलन उसी तरह बढ़ता जा रहा जिस तरह अनजाने में किसी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य पर मधुमेह जैसा रोग हमला कर देता है और उसे पता भी नहीं चलता है. जाली नोट चलाने की साज़िश दुश्मन देश जहां भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करने के लिए करते हैं, वहीं देश के अंदर के कुछ लोग जल्द से जल्द धनवान बनने के लिए करते हैं. मगर दोनों ही रूप में नुक़सान देश को होता है और उसका सबसे अधिक भार पड़ता है ग़रीब जनता पर. इसलिए बार-बार यह सवाल उठता है कि जाली नोटों की छपाई कहां होती है? इस सवाल पर गंभीरता से विचार करने में सबसे पहले भारत की नोट प्रिंटिग प्रेसों का नाम सामने आता है. इन पर पूरी तरह नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक का होता है. वहां जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, उससे यह नहीं लगता कि वहां से किसी का जाली नोटों के मामले में कोई लेना-देना होगा. समय के साथ महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास स्थित मौद्रिक प्रेसों की मशीनरी में बदलाव, नोटों के डिजाइन के सांचों में भी बदलाव किया जाता होगा. इस स्थिति में यह सवाल उठना लाज़िमी है कि फिर नोट छापने वाली पुरानी मशीनों का क्या किया जाता है? इसका सही-सटीक जवाब भारतीय रिजर्व बैंक ही दे सकता है, लेकिन जब उक्त सवाल उसके सामने दो बार रखा गया तो दोनों बार अलग-अलग जवाब मिले. इससे नोट छापने की पुरानी मशीनों का रहस्य गहरा गया है. हालांकि अब इस सारे मामले की ख़ुफ़िया विभाग ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन मशीनें कहां गईं? इसका जवाब न मिल पाना चिंता की बात है. पुरानी मशीनें कहां गईं? इस एक ही सवाल का उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक ने दो बार अलग-अलग दिया. यह सवाल किया था आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन रॉय ने. सूचना के अधिकार के तहत मनोरंजन रॉय ने 21 नवंबर, 2011 को रिजर्व बैंक के करेंसी प्रिंटिग विभाग से सवाल किया था कि वर्ष 1947 से अब तक नोट छापने वाली कितनी मशीनें बदली गईं अथवा उनकी मरम्मत की गई. इस आरटीआई के जवाब में नासिक स्थित करेंसी नोट प्रेस के मुख्य इंजीनियर वीएम ढाके ने बताया कि वर्ष 1947 के पश्चात अब तक केवल एक बार वर्ष 1998-99 के दरम्यान मॉडर्नाईजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्रिटिंग मशीनें बदली गई थीं. उसी आरटीआई के दूसरे सवाल के जवाब में कहा गया कि सरकार की प्रचलित प्रक्रिया के अंतर्गत उक्त प्रिंटिंग मशीनों को खुली निविदा के माध्यम से डिस्पोज यानी निपटारा किया गया.

मनोरंजन रॉय का इस पर कहना है कि वह रिजर्व बैंक से मिले जवाब से संतुष्ट नहीं हुए. इसलिए 12 दिसंबर, 2011 को एक और आरटीआई के माध्यम से पूछा कि नोट छापने वाली पुरानी मशीनों के निपटारे के लिए कितनी निविदाएं प्राप्त हुईं? साथ ही निविदा करने वाली कंपनी के नाम एवं पते की सूची मांगी. करेंसी सिक्योरिटी प्रेस, नासिक से निविदाओं की कॉपी की भी मांग की. दूसरी आरटीआई के जवाब में रॉय को बताया गया कि वर्ष 1998-99 में किसी भी प्रिंटिंग मशीन को नष्ट नहीं किया गया और न ही किसी फर्म को बेचा गया है. इस तरह एक ही सवाल के अलग-अलग जवाब मिलने से यह साफ़ पता चलता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी ज़रूर है. पहले पूछा गया तो कहा गया कि वर्ष 1998-99 में मॉडर्नाईजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत मशीनों को बदला गया. उनको निविदा मंगाकर नष्ट किया गया. दोबारा वही सवाल करने पर कहा गया कि उक्त वर्ष में किसी नोट छापने वाली मशीन को नहीं बदला गया और न ही कोई मशीन नष्ट नहीं की गई. इससे मामला और पेचीदा हो उठा और पुरानी मशीनों का रहस्य और गहरा गया. रिजर्व बैंक द्वारा दिए जवाबों से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. आख़िर करेंसी प्रेस की पुरानी मशीनों का क्या किया गया? वास्तव में उनको डिस्पोज किया गया या किसी को बेची गई? रॉय बताते हैं कि इस पहेली को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के ख़ुफ़िया विभाग को पत्र लिखकर सारे मामले की जांच करने की मांग की. आख़िर देश में बड़ी मात्रा में जाली नोट पकड़े जा रहे हैं. जाली नोटों के बढ़ते चलन से देश की अर्थव्यवस्था को ख़तरा पैदा हो गया है. इन स्थितियों में सरकारी प्रेस से निकलकर नोट छापने की पुरानी मशीनों का निजी हाथों में देना ग़ैर ज़िम्मेदराना ही होगा.

चूंकि मामला भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा है. इसलिए गृह मंत्रालय के ख़ुफ़िया विभाग ने आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन रॉय की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. इसके बावजूद सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता के ख़ज़ाने की सुरक्षा की व्यवस्था की देखरेख करने वाला भरतीय रिजर्व बैंक इस मामले में अब तक इतना लापरवाह क्यों रहा? उसे पुरानी मशीनों की वास्तविक स्थिति की जानकारी क्यों नहीं है? एक ही सवाल का जवाब अलग-अलग एक ज़िम्मेदार अधिकारी कैसे दे सकता है? उक्त सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं. लोगों को याद होगा महाराष्ट्र में घटित स्टांप घोटाला. जिनको याद नहीं वे भी अगर अपने दिमाग़ पर ज़ोर डालेंगे तो स्टांप घोटाले की याद आते ही इसको अंजाम देने वाले अब्दुल करीम तेलगी का चेहरा भी याद आ जाएगा. स्टांप घोटाले के मास्टर माइंड अब्दुल करीम तेलगी ने नासिक स्थित सरकार के नोट छापने वाले प्रेस से ही मशीनें ख़रीदी थीं. उसके बाद वह अरबों के स्टांप छाप कर ख़ुद तो मालामाल हो गया और कई नेताओं को भी उस धन से उपकृत किया था. उसने वर्ष 1997 में नासिक के सरकारी प्रेस के अधिकारियों से मिलीभगत करके पुरानी मशीनें ख़रीदी थीं. स्टांप घोटाला पूरे देश में काफ़ी दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा. इस घोटाले में महाराष्ट्र के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम भी सामने आए, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. मामले के सामने आते ही उन नेताओं ने तेलगी को पहचानने से इंकार कर दिया, जो उसकी पार्टी की कभी शान बढ़ाते थे. अब स्टांप घोटाले के आलोक में भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं. अब यदि पहली आरटीआई के सवालों के दिए गए जवाबों पर नज़र डाली जाए तो यह सवाल सामने आता है कि जब मशीनें वर्ष 1998 में बदली गईं और डिस्पोज की गईं तो 1997 में अब्दुल करीम तेलगी ने कैसे मशीनें ख़रीदीं? दूसरी आरटीआई के जवाब में यह बताया गया है कि वर्ष 1998-99 में कोई मशीन नहीं बदली गई और न ही किसी निजी फर्म को बेची गई. दोनों आरटीआई पर दिए गए जवाब भारतीय रिजर्व बैंक के प्रिंटिंग विभाग को कठघरे में खड़ा कर देते हैं. फिर तेलगी सरकारी प्रेस से पुरानी मशीनें कैसे नासिक से ले गया? स्टांप घोटाले से अभी पूरी तरह पर्दा नहीं उठा है. बार-बार यह आरोप लगता है कि अब्दुल करीम तेलगी ने जिन नेताओं के नाम ख़ुफ़िया एजेंसियों के सामने पूछताछ के समय लिए, उनको क्यों बचाया गया? इससे संशय और बढ़ जाता है कि मामले में बहुत कुछ काला है. भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो जाली नोटों का बढ़ता जंजाल एक दिन भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला कर देगा.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 12 मार्च-18 मार्च 2012

www.chauthiduniya.com

The Most Cost Effective Builder In India

www.vastu-vihar.com

वास्तु विहार®

एक विश्वस्तरीय टाउनशिप

AN ISO : 9001-2008 CERTIFIED COMPANY

हम बनाते हैं आपके सपनो का घर...!

7 लाख में घर

स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग सेन्टर, 24 घन्टे बिजली एवं जलापूर्ति

Multiple Option to choose your dreame shelter in any city...

पटना	- 07488538120/21/23, 0612-6450735	रांची	- 07488535220/21
मुज़फ्फरपुर	- 07488535211, 0621-6499030	आरा	- 07488535201
गया	- 07488535291/93, 0631-2221624	छपरा	- 07488535202
हाजीपुर	- 07488538151, 07488538139	कोलकाता, सिल्लीगुड़ी	- 09331339202
हजारीबाग	- 07488538192/93		
भागलपुर	- 07488535249/50	Coming Soon	
धनबाद	- 07488535261/62	राउरकेला भुवनेश्वर दरभंगा	

For details Enquiry Type SMS VASTUVIHAR and send it to 56677

Our on going projects

संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान

SANJEEVANI BUILDCON

3rd & 4th floor, GEL Church Complex, Main Road, Ranchi, Customer Care No. - 0651-2331429

Sanjeevani Dynasty-I
PLOT-13 LAC, DUPLEX-25 LAC
Near Ranchi College

Sanjeevani Dynasty-II
PLOT-10 LAC, DUPLEX-22 LAC
Booty More

Future City (BIT)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Future City (Namkom)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Future City (Pithoria)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Sanjeevani Mega Township
PLOT-3.5 LAC, BUNGLOW-09 LAC
Hazaribagh

चुनाव का इशारा

चुनाव की बात कर नीतीश कुमार ने एक बार फिर सबसे आगे निकल जाने की पहल कर दी. वह बार-बार कहते हैं कि जब मैं चुनाव प्रचार ख़त्म कर देता हूं तो हमारे विरोधी चुनाव प्रचार शुरू करते हैं, लेकिन इस बार बात केवल विपक्ष की नहीं है, मामला जदयू की सहयोगी पार्टी भाजपा का भी है.

सरोज सिंह

मौक़ा तो विधानसभा सत्र को लेकर जदयू विधायक दल की बैठक का था, पर इसमें लोकसभा के मध्यावधि चुनाव का राग अलाप कर नीतीश कुमार ने भविष्य की राजनीति के संकेत साफ़-साफ़ दे दिए. नीतीश कुमार को जानने वाले जानते हैं कि वह कभी हल्की बात नहीं करते और कभी-कभी इशारों ही इशारों में बड़ी बात कह देते हैं. विधायक दल की बैठक में उन्होंने अपने विधायकों का चुनाव के लिए कमर कस लेने का आह्वान किया और क्षेत्र में जाकर सरकार की उपलब्धियों को आंकड़ों के साथ बताने का निर्देश दिया है. नीतीश कुमार ने कहा कि मध्यावधि चुनाव तय है, आप लोग 2004 की तरह इंडिया शाइनिंग के भ्रम में न रहें.

दरअसल, चुनाव की बात कर नीतीश कुमार ने एक बार फिर सबसे आगे निकल जाने की पहल कर दी. वह बार-बार कहते हैं कि जब मैं चुनाव प्रचार ख़त्म कर देता हूं तो हमारे विरोधी चुनाव प्रचार शुरू करते हैं, लेकिन इस बार बात केवल विपक्ष की नहीं है, मामला जदयू की सहयोगी पार्टी भाजपा का भी है. हाल के दिनों में कई बार इस बात के संकेत मिले कि जदयू और भाजपा के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है. दूसरी पार्टियों के विधायकों ख़ासकर मुसलमान विधायकों एवं नेताओं को जदयू में शामिल कराकर नीतीश कुमार ने यह संदेश दिया कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी जदयू ही है. सूत्रों पर भरोसा करें तो ऑपरेशन लोजपा के बाद नीतीश एंड कंपनी का ऑपरेशन राजद एवं कांग्रेस अब अंतिम चरण में है. 15 से ज़्यादा राजद विधायकों को शामिल कराकर इनमें से अधिकांश को सत्ता का स्वाद चखाने की योजना है. नीतीश कुमार के विश्वस्त लोग पूरी गोपनीयता एवं सावधानी से इस ऑपरेशन को चला रहे हैं. राजद के एक बड़े नेता को राज्यसभा भेजने का भी प्लान है. अलग-अलग नेताओं से अलग-अलग लोग बात कर रहे हैं. विधानसभा सत्र में नीतीश तो बस इस संभावित जोड़-तोड़ के इशारे कर रहे हैं. बानगी देखिए, जब आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो इधर काहे बैठे हैं सदानंद बाबू. नीतीश कुमार के इतना कहते ही पूरा सदन ठहाके में डूब जाता है. राजद विधायक दल के नेता फ़रियाद करते हैं, जनता ने आपको इतना बड़ा जनादेश दिया है तो विपक्ष को बख्श दीजिए. नीतीश कुमार का जवाब, हम तोड़ने में नहीं जोड़ने में भरोसा करते हैं. हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं.

माना जा रहा है कि यह पूरी बिसात लोकसभा चुनाव को लेकर बिछाई जा रही है और भाजपा एवं जदयू इस खेल में एक दूसरे को शह और मात देने में जुटे हैं. जदयू के रणनीतिकार चाहते हैं कि पूरे देश में लगभग सौ सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए. यह तभी संभव है जब भाजपा के साथ इसका रिश्ता टूट जाए. बिहार की चालीस एवं झारखंड की 14 सीटों के अलावा बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली में जदयू अपना भाग्य आज़माना चाह रहा है. पार्टी की सोच है कि चालीस से पचास सीटें अगर हाथ लग जाएं तो फिर नीतीश कुमार को पीएम के तौर पर पेश कर मज़बूत दावा जताया जा सकता है. नीतीश एंड कंपनी इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि बिहार की 22 सीटों पर चुनाव लड़कर राष्ट्रीय राजनीति में मज़बूत दख़ल नहीं दी जा सकती है. लोजपा के बाद ऑपरेशन राजद एवं कांग्रेस सही अंजाम तक पहुंच गया तो बिहार की सरकार ठाठ से चलती रहेगी और सारा ध्यान राष्ट्रीय राजनीति में दिया जा सकता है. भाजपा से दूर हटने के लिए बस एक बहाने का इंतज़ार है, जिस दिन यह मिल गया जदयू एवं भाजपा की राहें अलग-अलग हो सकती हैं. दूसरी तरफ़ भाजपा भी बिहार में बन रहे नए राजनीतिक समीकरणों पर पैनी नज़र गड़ाए हुए है. भाजपा के एक बड़े नेता ने बताया कि पार्टी अभी वेटिंग मोड में है. भाजपा ख़ुद रिश्ता ख़त्म कर जदयू को राजनीतिक लाभ उठाने का मौक़ा नहीं देना चाहती है. राजद के साथ संभावित गठजोड़ पर इस भाजपा नेता का कहना था कि यह दो चीज़ों पर निर्भर करता है. पहला जब लालू प्रसाद को यह लग जाएगा कि नीतीश कुमार राजद को तोड़ ही देंगे और दूसरा यह कि लालू प्रसाद को यह अहसास हो जाएगा कि मुसलमान उनसे दूर जा रहे हैं. यही दो परिस्थितियां हैं, जिनमें भाजपा एवं राजद की सरकार बन सकती है और नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो सकते हैं. फ़िलहाल तो यह सब आगे की राजनीतिक परिस्थतियों पर निर्भर करता है. अगर नरेंद्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो जदयू को बैठे-बैठे बड़ा बहाना मिल जाएगा.

लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश लोकसभा के मध्यावधि चुनाव की बात अपने सांसदों को एकजुट रखने के लिए कर रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि ममता बनर्जी और शरद पवार के तेवर कांग्रेस की राह में कांटे भर रहे हैं. अगर इन दोनों ने समर्थन वापस ले लिया, तो हो सकता है कि जदयू के सांसदों को सत्ता का लोभ दिखाकर कांग्रेस तोड़ न ले. सभी जानते हैं कि कई दफ़ा इसकी कोशिश हो भी चुकी है. कांग्रेस अपनी सरकार बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. इसलिए नीतीश कुमार सांसदों को चुनाव का भय दिखाकर इन्हें अनुशासन में रहने का संदेश दे रहे हैं. वरना इतना खुलकर नीतीश कुमार कभी भी मध्यावधि चुनाव की बात नहीं करते और न ही विधानसभा में सदानंद सिंह एवं अब्दुल बारी सिद्दीक़ी से यह कहते कि मैं तोड़ने में नहीं, बल्कि जोड़ने में यक़ीन करता हूं. देखा जाए तो नीतीश कुमार ने मध्यावधि चुनाव का राग अलाप कर एक साथ अपने कई राजनीतिक हित साधने की कोशिश की है. इसे राज्यसभा एवं विधान परिषद चुनाव में दबाव से बचने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है. बहुत से वंचित रहे नेताओं को लोकसभा के टिकट का लॉलीपॉप पकड़ाया जा सकता है. कई बार दबाव कम करने की यह रणनीति कामयाब भी हुई है, लेकिन असली मसला भाजपा से दूरी बनाने का है, जिसे बहुत ही सलीक़े से अंजाम दिया जा रहा है. भाजपा भी इस ख़तरे को पहचान गई है और अंदरख़ाने अपनी तैयारी में है. बिहार की सत्ता का सर्वेसर्वा बनने की यह लड़ाई प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देगी और कई ऐसे नेता बहुत पीछे छूट जाएंगे, जो हमेशा हां और ना के बीच रहकर अपनी राजनीतिक गोटी सेंकने की फ़िराक़ में लगे रहते हैं.

जदयू के रणनीतिकार चाहते हैं कि पूरे देश में लगभग सौ सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए. यह तभी संभव है जब भाजपा के साथ इसका रिश्ता टूट जाए. बिहार की चालीस एवं झारखंड की 14 सीटों के अलावा बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली में जदयू अपना भाग्य आज़माना चाह रहा है. पार्टी की सोच है कि चालीस से पचास सीटें अगर हाथ लग जाएं तो फिर नीतीश कुमार को पीएम के तौर पर पेश कर मज़बूत दावा जताया जा सकता है. नीतीश एंड कंपनी इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि बिहार की 22 सीटों पर चुनाव लड़कर राष्ट्रीय राजनीति में मज़बूत दख़ल नहीं दी जा सकती है. लोजपा के बाद ऑपरेशन राजद एवं कांग्रेस सही अंजाम तक पहुंच गया तो बिहार की सरकार ठाठ से चलती रहेगी और सारा ध्यान राष्ट्रीय राजनीति में दिया जा सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

बोधिवृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी. इस वृक्ष की सूखी हुई पत्तियां भी विदेशों में अच्छी क़ीमत पर बिकती हैं.

मदरसे की नौ कट्ठा पांच धूर ज़मीन को हड़पने की नियत से केसरिया थाना में कांड संख्या 138/10 झूठा अपहरण का मुक़दमा दर्ज कराया गया.

महाबोधि मंदिर विवाद फिर गहराया

सुनील सौरभ

केंद्र एवं बिहार सरकार को उच्चतम न्यायालय का नोटिस मिलने के बाद बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है. इस मामले को लेकर पिछले दो दशक से कभी तेज़ तो कभी धीमे स्तर पर आंदोलन होता रहा है. बौद्ध तथा हिंदू संगठनों के नेता महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को लेकर बने एक्ट को बदलने की मांग पर आपस में टकराते भी रहे हैं. कई बार तो इस मामले को लेकर पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने वाले बोधगया में अशांति की भी स्थिति उत्पन्न हुई. वर्तमान में अधिवक्ता विनीता धांडा की जनहित याचिका जिसमें बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 की धारा तीन को चुनौती दी गई है, पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर एवं न्यायमूर्ति एसएस निज्जर की पीठ ने केंद्र एवं बिहार सरकार को चार हफ्ते का समय देकर महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति में हिंदुओं के बहुमत पर जवाब देने को कहा है. इसी आदेश के बाद तथागत की ज्ञान भूमि बोधगया में दोनों धर्मों के संगठनों के लोगों में सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर नज़र रखी जा रही है. जनहित याचिका में कहा गया है कि बोधगया टेंपल एक्ट 1949 की धारा तीन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है. इसके अनुसार बिहार सरकार द्वारा बोधगया मंदिर के प्रबंधन हेतु एक नौ सदस्यीय समिति के गठन का प्रावधान है तथा उक्त प्रावधान के तहत गया ज़िले के ज़िला पदाधिकारी इस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे, बशर्ते की वह हिंदू हों. इस समिति में चार हिंदू और चार बौद्ध सदस्य होते हैं. इन्हीं में से एक को सदस्य सचिव के रूप में मनोनीत किया जाता है. याचिका में कहा गया है कि इस प्रावधान से बौद्धों के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है, यह क़ानून संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 के विपरीत है. अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वहीं अनुच्छेद 26 हर व्यक्ति व समुदाय को अपने धार्मिक स्थल या संस्था के प्रबंधन का अधिकार देता है, जबकि बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति में एक्ट के अनुरूप पांच हिंदू हो जाते हैं. हालांकि इस एक्ट में परिवर्तन की मांग को लेकर 1990 के दशक में अंबेडकरवादी नव बौद्धों द्वारा अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर मुक्ति आंदोलन समिति बनाकर एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसका नेतृत्व जापानी मूल के भारतीय बौद्ध सुरई ससई कर रहे थे. इस आंदोलन में भदंत आनंद तथा प्रग्याशील के साथ–साथ मगध विश्वविद्यालय के चर्चित प्रोफेसर पीसी राय की भूमिका महत्वपूर्ण थी. तब बोधगया में पूरी तरह अशांति का माहौल उत्पन्न हो गया था.

बिहार सरकार द्वारा बोधगया मंदिर के प्रबंधन हेतु एक नौ सदस्यीय समिति के गठन का प्रावधान है तथा उक्त प्रावधान के तहत गया ज़िले के ज़िला पदाधिकारी इस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे, बशर्ते की वह हिंदू हों. इस समिति में चार हिंदू और चार बौद्ध सदस्य होते हैं. इन्हीं में से एक को सदस्य सचिव के रूप में मनोनीत किया जाता है. याचिका में कहा गया है कि इस प्रावधान से बौद्धों के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है, यह क़ानून संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 के विपरीत है. अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वहीं अनुच्छेद 26 हर व्यक्ति व समुदाय को अपने धार्मिक स्थल या संस्था के प्रबंधन का अधिकार देता है, जबकि बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति में एक्ट के अनुरूप पांच हिंदू हो जाते हैं.

तत्कालीन लालू राबड़ी की सरकार ने आंदोलन से जुड़े सुरई ससई, भदंत आनंद तथा प्रग्याशील को बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति का सदस्य मनोनीत कर दिया और प्रग्याशील को इस समिति का सदस्य सचिव बना दिया. इसके बाद यह आंदोलन थम गया, लेकिन इस समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने समिति के सभी बौद्ध एवं हिंदू सदस्यों को बदल दिया और कालीचरण सिंह यादव को समिति का सदस्य सचिव बनाया. यह समिति छह वर्षों तक कार्यरत रही और विवादों में भी रही, जिसमें सबसे बड़ा विवाद रहा बोधिवृक्ष की टहनी को काटकर विदेश में बेचने का. बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी. इस वृक्ष की सूखी हुई पत्तियां भी विदेशों में अच्छी क़ीमत पर बिकती हैं. हालांकि महाबोधि मंदिर परिसर में हिंदू देवी–देवताओं का भी मंदिर स्थापित है. इन मंदिरों का इतिहास भी अति प्राचीन है. इन मंदिरों को बोधगया स्थित आदि शंकराचार्य मठ के तत्कालीन महंत उद्धव गिरि ने सम्राट अशोक से आग्रह कर निर्माण करवाया था, जिसमें एक मंदिर में दो शिवलिंग, एक अन्य मंदिर में पांच पांडव तथा तीसरे मंदिर में अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा स्थापित है. इसी मंदिर के सामने चैतन्य गिरि की धूनी है.

इसके अलावा महाबोधि मंदिर परिसर में अनेक हिंदू देवी–देवताओं की प्राचीन प्रतिमाएं मुख्य स्थानों पर स्थापित हैं. सबसे बड़ी बात है कि महाबोधि मंदिर के गर्भ गृह में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के ठीक सामने एक शिवलिंग स्थापित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसे स्थापित कराया था. इसके लिए पुजारी भी सदियों से नियुक्त होते रहे हैं. वर्तमान पुजारी संजय कुमार मिश्र चौथी पीढ़ी के हैं. हालांकि जब तब इस मामले को लेकर बोधगया में हिंदू और बौद्ध धर्मों के कुछ संगठनों द्वारा टकराव की स्थिति पैदा कर दी जाती है. स्थानीय नागरिक इस मामले को बेवजह तूल दिए जाने के ख़िलाफ़ रहते हैं, क्योंकि विवाद बढ़ने से बोधगया में विदेशी पर्यटकों का आना कम हो जाता है और पर्यटन के व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ता है. बोधगया के लोग किसी भी रूप में शांति चाहते हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों और बौद्ध श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नोटिस दिए जाने के मामले पर बोधगया के लोग डरे–सहमे हैं कि कहीं फिर विवाद न हो जाए और उनका कारोबार भी चौपट हो जाए.

feedback@chauthiduniya.com

ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण रखें

डॉ. आईडी सिंह

मौजूदा दौर में हृदय रोगियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने से आमजन के साथ–साथ चिकित्सा महकमा भी ख़ासा चिंतित है. आख़िर यह रोग होता क्यों है और इसके बचाव के क्या उपाय हैं, इस बारे में कोसी प्रमंडल के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ आईडी सिंह ने चौथी दुनिया से ख़ास बातचीत की.

हृदय रोग क्या है और इसके कारण क्या हैं?

हृदय रोग अमूमन दो तरह के होते हैं. पहला तो पैदाइशी और दूसरा परिस्थितिजन्य. हृदय की बनावट, हृदय में छेद, हृदय से जुड़ी नली से ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं आना आदि पैदाइशी हृदय रोग माने जाते हैं, जबकि तनाव, अनिद्रा, रहन–सहन की ग़लत आदत, धूम्रपान, शराबख़ोरी आदि के कारण परिस्थितिजन्य रोग होना तय माना गया है.

रोग की पहचान कैसे संभव है?

छाती में हल्का–हल्का दर्द होने पर ही लोगों को चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए. सांस में तकलीफ़, दम फूलना, अधिक थकान का महसूस होना तथा बच्चों के जोड़ों में लगातार दर्द रहना इस बीमारी की प्रारंभिक पहचान है.

परहेज़ के तौर पर क्या करना चाहिए?

खानपान में परहेज़ रोगियों के लिए रामबाण माना गया है. नियमित व्यायाम के साथ तनाव से दूर रहना रोगियों के लिए अति आवश्यक है. शुगर तथा ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण पाते हुए कुशल चिकित्सकों से परामर्श लेते रहना आवश्यक है.

मनोज ठाकुर
feedback@chauthiduniya.com

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
ASRFEN-P Aceclofenac + paracetamol Serratiopeptidase Tab.
ECTALOPAM Escitalopram Oxalate & Clonazepam Tablets
SILIPLEX
ACOBA CAP/SYP/INJ
Carbo-XT Ferrous Ascorbate With Folic Acid Tab.
AREX Dextromethorphan,Guaiphenesine Ammonium Chloride Cough Syp.
MENSOSET Her Tonic With Ashoka 1800mg.
MUSTAL Levocetirizine Hydrochloride Montelukast Sodium Tab.

कब तक सच्चाई से भागेगी पुलिस

इंतेज़ारुल हक़

जब से प्राथमिकी दर्ज हुई है, तब से लेकर आज तक वरीय पुलिस पदाधिकारी दबी ज़बान से कहते हैं कि आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है. सच्चाई जानते हुए भी हम सच्चाई नहीं लिख सकते, क्योंकि हम पर भारी सरकारी दबाव है. इस केस की पैरवी भागलपुर के सांसद सैयद शाहनवाज़ हुसैन कर रहे हैं. आप लोग मदरसा और मस्जिद की ज़मीन उनके आदमी को दे दीजिए, केस उठा लीजिए तब तो ख़ैर है, नहीं तो इस सरकार में न्याय की लड़ाई लड़ने का ख़ामियाज़ा भुगतने को तैयार रहिए. यह दास्तां सरिया प्रखंड के लाला छपरा गांव के ग्रामीणों की है, जहां यह बयान मानवाधिकार सुरक्षा संघ ने दर्ज किया है. दर्ज बयान में ग्रामीणों ने बताया कि यहां स्थित मदरसा एवं मस्जिद की ज़मीन हड़पने की नीयत से अब्दुल मन्नान सैफ़ी एवं अब्दुल मजीद सहित बारह लोगों पर अपहरण का झूठा मुक़दमा किया गया है. मदरसे की नौ कट्ठा पांच धूर ज़मीन को हड़पने की नीयत से केसरिया थाना में कांड संख्या 138/10 झूठा अपहरण का मुक़दमा दर्ज कराया गया. गांव निवासी जमीलुद्दीन उर्फ़ खुदन के पुत्र आरिश इक़बाल के अपहरण का मामला बनाकर बारह लोगों पर मुक़दमा दर्ज कराया गया, जबकि वह अपने माता-पिता के साथ आसाम के नलियापुर में रह रहा है. अपनी बहन की शादी में 25 नवंबर, 2010 को वह अपने घर भी आया था और ग्रामीणों ने इसकी सूचना केस के आईओ को दी थी. आईओ भी इस शादी में शामिल थे, किंतु इस लड़के को बरामद करना मुनासिब नहीं समझा. ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक मोतिहारी को तीन मोबाइल नंबर 9939072978, 9801265655 पर 8 अक्टूबर, 2010 को प्रिंट आउट निकलवाने की मांग की, किंतु आज तक प्रिंट आउट नहीं निकाला गया. ये मोबाइल नंबर केस के अनुसंधानकर्ता के हैं. ग्रामीणों ने फिर पुलिस महानिदेशक पटना को तीन जनवरी को इसकी शिकायत की, किंतु इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. आख़िर में यह मामला अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ के पास जा पहुंचा, जहां टीम ने इस मामले की गहन जांच की. जांच टीम के समक्ष ग्रामीण अब्दुल मजीद, मोहम्मद अमानुल्लाह, मक़बूल अहमद, ध्रुव प्रसाद, प्रो. एन अली, मोहम्मद काज़िम, सनाउल्लाह, मोहम्मद निज़ामुद्दीन, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद वाहिद, विरेंद्र कुमार यादव, खुशबू महतो, रहमतुल्लाह, क्यामुल हक़, मोहम्मद मुर्तुज़ा, मोहम्मद क़ासिम, मोईन कुरैशी, मोहम्मद याक़ूब, मोहम्मद साबिर ख़ां, छोटेलाल साह, रामाश्रय महतो, संजय महतो, शंभू महतो, लालबाबू महतो, रामजी महतो, मोहम्मद मोहिबुल्लाह, मोहम्मद हफ़ीज़, राजेंद्र प्रसाद यादव, भोला महतो, अब्दुल हकीम, सतेंद्र महतो, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष रामाशरण प्रसाद यादव समेत एक सौ सोलह ग्रामीणों ने लिखित बयान में स्पष्ट किया कि इस मामले को लेकर गांव में अशांति पैदा हो गई है और बेगुनाहों पर ज़ुल्म ढहाया जा रहा है. इस मामले में बारह लोगों पर वारंट भी जारी किया गया है. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि 10 सितंबर, 2010 को इस मामले की पैरवी करने क़रीब पांच सौ लोग डीएसपी चकिया के पास पहुंचे थे और सभी ने अपहरण के मामलों को झूठा क़रार दिया था. यहां भी डीएसपी द्वारा इन ग्रामीणों की बातें नहीं सुनी गईं और गवाही को सिरे से ख़ारिज करते हुए सूचक के बड़े भाई एवं दो अन्य गवाहों की गवाही के आधार पर इस कांड को सत्य क़रार दिया गया. हद तो तब हो गई जब जांच प्रतिवेदन में डीएसपी ने आईओ का नाम सबीर ख़ां लिख दिया, जबकि इस कांड के आईओ श्याम बिहारी राम हैं. पुलिस अधीक्षक ने भी 3 नवंबर, 2011 को घटना स्थल का निरीक्षण किया, जहां ग्रामीणों ने आरिश इक़बाल के अपहरण का मामला झूठा क़रार दिया. एसपी ने ग्रामीणों के बयान दर्ज न कर चकिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की रिपोर्ट को सत्य क़रार देते हुए गिरफ्तारी का आदेश निर्गत कर दिया. बिहार में एक तरफ़ सरकार भले ही अल्पसंख्यक संस्थाओं एवं इससे जुड़ी संपत्तियों की रक्षा के लिए अनेक घोषणाएं कर रही है, किंतु केसरिया की इस घटना ने ज़िले के अल्पसंख्यक समाज को हिलाकर रख दिया है. आख़िर पुलिस अपहृत को बरामद करने में दिलचस्पी क्यों नहीं लेती, ग्रामीणों द्वारा दिए गए मोबाइल का प्रिंट आउट क्यों नहीं निकाला गया? ज़िले का मुस्लिम समाज अनेक तरह के सवाल खड़े कर रहा है. हालांकि इस मामले में ज़मीन ख़ाली कराने को लेकर न्यायालय में छह मुक़दमा विचाराधीन है. अगर आरिश इक़बाल का अपहरण हक़ीक़त में हुआ है तो अट्ठारह महीनों से पुलिस क्या कर रही है? आख़िर इसकी बरामदगी के लिए छापेमारी क्यों नहीं करती? अगर करती है तो सफलता क्यों नहीं मिलती? अनेक सवाल जन्म ले रहे हैं और जवाब किसी के पास नहीं हैं. आख़िर निर्दोष कब तक भागते फिरेंगे और अब उन्हें न्याय कहां मिलेगा? पुलिस दबाव में अपना कर्तव्य भूल जाएगी और निर्दोषों पर ज़ुल्म ढहाएगी. उधर, युवा जदयू के जिलाध्यक्ष मोहम्मद तमन्ना ने भी इस मामले की गहन जांच कराने की मांग सरकार से की है.

feedback@chauthiduniya.com

रंगों के पर्व होली के शुभअवसर पर जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।
निवेदक
मनोज कुमार
ग्राम पं. राज कुण्डी, गोगरी, खगड़िया

रंगों के पर्व होली के शुभअवसर पर जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।
निवेदक
मो0 आसिफ इकबाल
मुखिया प्रतिनिधि
ग्राम पं0 राज देवरी, परवत्ता, खगड़िया

रंगों के पर्व होली के शुभअवसर पर जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।
निवेदक
नरेश प्रसाद बादल
पूर्व प्रखण्ड प्रमुख चौथम
सह कॉंग्रेस प्रत्याशी परबत्ता विधानसभा
ग्राम पो0– धुतौली, मलपा, चौथम

रंगों के पर्व होली के शुभअवसर पर जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।
निवेदक
लतरू पटेल
युवा समाजसेवी सह पूर्व मुखिया
ग्राम पं0 राज ईटहरी, गोगरी, खगड़िया

जिले वासियों सहित प्रदेश वासियों को सुख समृद्धि, शान्ति एवं खुशहाली के पर्व होली की हार्दिक बधाई
निवेदक
विनय भारती
पशु चिकित्सक, प्रखंड पोठिया (किशनगंज)

नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार
आर एन सिंह प्रदेश अध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ
सूबे के आमलोगों एवं किसानों के सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना करता हूं।
राजेश खेतान
प्रदेश सचिव किसान प्रकोष्ठ

जिले वासियों सहित प्रदेश वासियों को सुख समृद्धि, शान्ति एवं खुशहाली के पर्व होली की हार्दिक बधाई।
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बिहार
सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री, बिहार
शशिभूषण प्रसाद
भाजपा जिलाध्यक्ष, खगड़िया
नीरज कुमार
जिला महामंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा, खगड़िया

महर्षि मेहीं कॉलेज ऑफ पॉलिटेकनिक एण्ड पारामेडिकल
हॉस्पीटल रोड, खगड़िया
(Courses Approved by UGC, AICTE, DEC, Ministry of HRD, Government of India)
Admission Open
POLYTECHNIC
Diploma in Mechanical, Civil, Electrical, Electronic & Communication & Computer Engineering
PARAMEDICAL
Master of Physiotherapy, Occupation Therapy, Medical Lab Technology, Radiation Technology, Optometry and Ophthalmic Technology.
Bachelor of Physiotherapy, Occupation Therapy, Medical Lab Technology, Radiation Technology, Optometry and Ophthalmic Technology.
P.G. Diploma in Drug Regulatory Affairs, Hospital Health Management, Geriatric Medicine, Maternal & Child Health.
Diploma in Medical Lab Technology, Ophthalmic Technology, Operation Theater Technology, ECG Technology, Radiography Technology.
APPLIED SCIENCE
M.Sc. Biotechnology, Microbiology, Biochemistry, Mathematics, Physics, Chemistry, B.Sc. Biotechnology, Microbiology, Biochemistry, Mathematics, Physics, Chemistry, General Sciences
Contact No.- 9431093027, 9852274380
Dr. H. Prasad
Director

Millia Institute of Technology
Rambagh, Purnea - 854301
Approved by AICTE, New Delhi Recognized by Sc. & Tech Deptt. Govt. of Bihar & Affiliated to B.N. mandal University Madhepura (Bihar)
ADMISSION NOTICE 2012 -13
B.TECH 1st Year (4 years degree course)
CSE, ECE
CE, EE, ME
MBA (Full time 2 years Course) Semester System
MCA (Full Time 3 years course) Semester System
Lateral Entry 2012 : (Admission in 2nd year B.Tech) CSE, ECE, ME, EE, CE
for Contact 06454-240433, 434 (O) 9431087906 (M) 9431088043 (M) 9431437563 (M)
Principal

ADMISSION NOTICE 2012-13
KISHANGANJ COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
भेरियाडांगी नियर रेश्मी फैक्ट्री एण्ड किशनगंज ब्लॉक,बहादुरगंज रोड, किशनगंज (बिहार) 855 107
APPROVED BY AICTE VIDE LETTER NO. NRO/2010-11/-1-16433411, DATED 08.09.2010 RECOGNISED BY SC. & TECH. DEPTT. GOVT. OF BIHAR & AFFILIATED TO BNMU MADHEPURA BIHAR
बी.टेक. (Ist year) 4 years Degree Course
योग्यता इन्टर पास in physics, Chemistry & Maths
(50% Seats from BCECE & 50% Management Quota)
Features Lab & Workshop Equipped with latest machines, Qualified & Expert Faculty, Reach Library with Internet Facility, Computer Center with Internet, Transport Facility

S.N.	Name of the Course	Intake	Duration
01	Mechanical Engineering	60	4 Years
02	Electrical Engineering	60	4 Years
03	Civil Engineering	60	4 Years
04	Computer Sc & Engineering	60	4 Years
05	Electronics & Comm. Engg	60	4 Years

Contact : 06456-222171, 222172 (O) 9334527151 (M) 8986071548 (M) Our Website : kcet.org.in
Principal

Millia Polytechnic Rambagh., Purnea - 854301
(Approved by AICTE New Delhi Recognised by Govt. of Bihar & Affiliated to The State Board of Technical Education, Patna
ADMISSION NOTICE : 2012-13
DIPLOMA ENGG Semester (3 years course)
Phone : 06454-294011 9431461337, 9431088043, 9631342533
Principal

Millia Fakhruddin Ali Ahmad
B.Ed. Teacher's Training College
Rambagh, Purnea, Bihar Ph : 06454-243447 (O)
Recognised by NCTE, Bhubneshwar, Vide Letter No. ERC/7-86 (1) 20/2008/1129 (1) dated : 23.05.2008 & Affiliated to B.N. Mandal University, Lalu Nagar, Madhepura
ADMISSION NOTICE - 2012 - 13
Contact No. : 9304253003, 9471851415
(Dr. Shampa Sinha) Principal

Millia Convent English School
Rikabganj, Bhagalpur (in front of Jaglal Intermediate School)
To be Affiliated from CBSE, New Delhi up to + 2 Level
(A unit of Millia Educational Trust, Purnea)
ADMISSION NOTICE : 2012 - 13
Last date of Submission of Form : 25.03.2012
Date of Admission Test : 26.03.2012 at 10.30 AM
Date of Result : 28.03.12
Admission Start : 30.03.12
(Sayed Shakeel Ahmad) Asst. Secretary 9931289308
Md. Abu Zilani 9708860094

Millia Convent English School
Rikabganj, Bhagalpur (in front of Jaglal Intermediate School)
To be Affiliated from CBSE, New Delhi up to + 2 Level
(A unit of Millia Educational Trust, Purnea)
WANTED
Applications are invited for the post of Principal/PGT/TGT in Maths, English, History, Commerce, Geography, Economics, Pol. Science, Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Urdu, Sanskrit, Hindi, Physical Education
(Sayed Shakeel Ahmad) Asst. Secretary 9931289308
Md. Abu Zilani 9708860094

ARARIA PUBLIC SCHOOL
(Affiliated to C.B.S.E,Delhi)
Wasiabad, Araria
Contact No. 9431205924, 9128944401,8051436426
Email Address aps_principal@yahoo.com
Admission Strictly on Merit Basis
Registration open for session 2012-13
From Classes I To IX
Entrance Test on 04 March & 18 March, 2012
Salient Features
1. TeachNext Smart Class room
2. Digital Language Lab
3. Career Guidance & Counseling
4. Students Ratio 1:30
5. Music Vocal & Instrumental
6. Excellent Board Results
7. Abundance Library Resources
8. Well Equipped Lab
10. Highly qualified & dedicated teachers
11. "Beware Health Care" Programme
• Audio-visual Aids
• Co-Education
• Located in the heart of city
• Conveyance Facility
• 25% seats is available in Class I as per RTE Act.

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
Authorised Study Centre of EIILM University. Code-CIIP/101683
Diploma/PG Diploma/Bachelor Degree/PG Degree in the following Subjects :
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE
1 YEAR GUARANTY
Contact : 9386595926, 9334115955

चल रहे धरने में भीड़ का उमड़ना भी इस बात का संकेत देने लगा है कि इस बार जनप्रतिनिधि या सरकारी हुक्मरान महज़ आश्वासन की चाशनी चटाकर लोगों को मना नहीं सकते.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

सांसद और विधायक का हुक़्क़ा–पानी बंद

खगड़ियावासी ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू होने से पहले किसी भी क़ीमत पर मानने को तैयार नहीं होंगे. दरअसल, खगड़िया शहर को दो भागों में विभाजित करने वाले पूर्वी रेलवे केबिन को पार करना स्थानीय लोगों के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के समान हो गया है. पूर्व मध्य रेल के बरौनी–कटिहार तथा समस्तीपुर–सहरसा रेलखंड पर दर्जनों गाड़ियों के प्रतिदिन चलने के कारण पूर्वी केबिन पर हमेशा दबाव बना रहता है.

ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से नाराज़ खगड़िया वासियों का गुस्सा अब धीरे–धीरे परवान चढ़ने लगा है. हालात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आक्रोशित लोगों ने निर्माण कार्य शुरू होने तक सांसद और विधायक के न केवल खगड़िया प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है, बल्कि हुक़्क़ा पानी बंद करने का भी ऐलान कर दिया है. लगातार चल रहे धरने में भीड़ का उमड़ना भी इस बात का संकेत देने लगा है कि इस बार जनप्रतिनिधि या सरकारी हुक्मरान महज़ आश्वासन की चाशनी चटाकर लोगों को मना नहीं सकते. क्योंकि इस बार हर हालत में खगड़ियावासी ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू होने से पहले किसी भी क़ीमत पर मानने को तैयार नहीं होंगे. दरअसल, खगड़िया शहर को दो भागों में विभाजित करने वाले पूर्वी रेलवे केबिन को पार करना स्थानीय लोगों के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के समान हो गया है.

पूर्व मध्य रेल के बरौनी–कटिहार तथा समस्तीपुर–सहरसा रेलखंड पर दर्जनों गाड़ियों के प्रतिदिन चलने के कारण पूर्वी केबिन पर हमेशा दबाव बना रहता है. ज़िला प्रशासन द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने की बाबत जवान तो तैनात किए गए हैं, लेकिन चवन्नी –अठन्नी वसूलने के आदी हो चुके जवानों का ट्रैफिक व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं दिखता है. नतीजतन इस दौरान कई घटनाएं हो चुकी हैं. आंदोलन का आगाज़ करने वाले प्रसिद्ध समाजसेवी सह युवा शक्ति के प्रदेश संरक्षक नागेंद्र सिंह त्यागी का कहना है कि शहर के पूर्वी भाग में लगभग सभी महत्वपूर्ण बाज़ार तथा पश्चिम दिशा में सदर अस्पताल, अनुमंडल कार्यालय, सामहरणालय, सिविल कोर्ट, कोसी कॉलेज, डीएभी, केंद्रीय विद्यालय, प्रखंड कार्यालय, जेल, दूरभाष केंद्र, सन्हौली पंचायत सहित दर्जनों सरकारी तथा निजी संस्थान हैं. इस तरह की स्थिति के कारण लोगों का इस पार से उस पार आना–जाना हमेशा लगा रहता है. बावजूद इसके जाम की समस्या के निदान के प्रति कोई गंभीर नहीं दिख रहा है. त्यागी के मुताबिक़, तत्कालीन रेलमंत्री रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव तथा नीतीश कुमार ने भी अपने–अपने कार्यकाल में पूर्वी केबिन पर ओवरब्रिज निर्माण किए जाने की घोषणा की थी. लेकिन इन बिहारी रेलमंत्रियों की बातें हवा हवाई साबित हुईं, जबकि पुल निर्माण कार्य की घोषणा 2008 में होने के बाद वर्ष 2009 में शिलान्यास किया गया. राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच 2010 में समझौता होने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा पुल निर्माण कार्य में सहयोग नहीं किया जाना लोगों की समझ से बाहर की बात है. रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के सदस्य सुभाष चंद्र जोशी का कहना है कि बीते दस वर्षों से वह लोग अनवरत संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की गई है. सार्थक पहल नहीं होने से नाराज़ होकर समाजसेवियों द्वारा तीन दिवसीय सत्याग्रह धरना दिया गया, लेकिन राजनीतिक रोटी सेंकने में दक्षता रखने वालों ने इस आंदोलन को भी राजनीतिक रंग दे दिया. दूसरी तरफ़ खगड़िया के जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव का कहना है कि पूर्वी केबि ढाला के समीप शीघ्र ही रेलवे ओवरब्रिज बनेगा. इसके बाबत रेलवे द्वारा अधिकृत कंपनी इरकॉन और राज्य सरकार के बीच पुल के मामले पर आपसी सहमति बन गई है. उन्होंने कहा कि पुल के नक्शे में परिवर्तन होने के कारण निर्माण कार्य की लागत बढ़ गई है. जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. बहरहाल, पुल के निर्माण कार्य की मांग को लेकर खगड़ियावासी जिस तरह आंदोलित हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर अब भी जनप्रतिनिधि नहीं चेते तो जनता के आक्रोश का ख़ामियाज़ा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा.

मनेंद्र कुमार
feedback@chauthiduniya.com

EARTH INFRASTRUCTURES LTD.
Innovation beyond Imagination
EARTH SAPPHIRE COURT
A green Workspace
Fully Furnished green offices spaces
EARTH SAPPHIRE COURT 12% ASSURED RETURN P.A. WITH BANK GUARANTEE
Walk-in & start playing
Available in 450 sq.ft. & 750 sq.ft. (approx.)
Actual sample office images
CONSTRUCTION IN FULL SWING
Site as on 31 January, 2012
Earth Infrastructures Ltd.
4th Floor Bhagwati Dwarika Arcade (Opp. Pandey Motors), Exhibition Road
Patna - 800001
TEL: +91-612-6500643, +91-612-3215709
Mob: +91-09266637081, 09266637082, 09266670292, 09266632054
Founder member Indian Green Building Council
Member of: CREDAI
earthinfra.com
FOR CORPORATE ENQUIRY +91- 09266637088
Disclaimer : Visual representation shown in the advertisement are purely conceptual. All plans, specifications etc are tentative and subject to variation & modification by the company or the competent authorities and the company does not bear any legal consequences for it.

आयुष नर्सिंग होम
न्यू कॉलोनी, नया बाजार, सहरसा (बिहार)
विशेषताएं
- प्रमंडल का पहला A/C कमरे वाला अस्पताल
- सहरसा मधेपुरा सुपौल जिले के विभिन्न अस्पतालों से पटना भागलपुर आदि के लिए रेफर मरीजों का ईलाज, ऑपरेशन एवं स्वस्थ्य होने की पुरी गारंटी
- 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध
- मुफ्त में बीपीएल रोगियों का इलाज/ऑपरेशन की सुविधा
- इंटरनेट के माध्यम से बड़े शहरों के प्रसिद्ध सर्जन (विशेषज्ञ) से मरीज के इलाज /ऑपरेशन पर मार्गदर्शन की सुविधा
- हर तरह के जांच, ऑपरेशन में आधुनिक तकनीकी का उपयोग
- साफ सुथरे माहौल में इलाज /ऑपरेशन की सुविधा

लक्ष्य
- अपना अत्याधुनिक ब्लड बैंक
- नई नई तकनीक के उपयोग की सुविधा
- ईलाज /ऑपरेशन में विशेषज्ञों की टीम को गरीब से गरीब रोगियों तक पहुंचाना

डॉ. अजय कुमार सिंह
एम.एस (जेनरल सर्जरी)
पूर्व वरीय रेजडेन्ट, बी.पी.के.आई.एच.एस. (धरान नेपाल)
फोन न.- 06478-222256 Email : newcolonyayush@rediffmail.com

इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च
हेल्थ इंस्टीच्युट रोड, बेउर, पटना-२
(बिहार सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार तथा आइ.ए.पी.से मान्यता प्राप्त)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबंधन प्राप्त
We Impart:-
POST GRADUAGE COURSES:
MPT Master of Physiotherapy
MOT Master of Occupational Therapy
MPO Master of Prosthetic & Orthotic
MASLP Master of Audiology & Speech Language Pathology
BPT Bachelor of Physiotherapy
BOT Bachelor of Occupational Therapy
BPO Bachelor of Prosthetic & Orthotic
BASLP Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology
BMRT Bachelor of Radio Imaging Technology
BMLT Bachelor of Medical Laboratory Technology
B.Ed. (Special Education)
B.Ophth. Bachelor of Ophthalmology
संस्थान द्वारा संचालित निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ
स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श
टीकाकरण
फिजियोथेरापी
अकुपेशनल थेरापी
स्पीच थेरापी
नेत्र जाँच
सभी प्रकार की विकलांगता पोलियो,लकवा,गठिया,हड्डी, जोड़ एवं नस से संबंधित सभी प्रकार के रोगों की जांच एवं उपचार
हकलाना, तुतलाना सहित गूंगे-बहरों की जाँच एवं उपचार हियरिंग-एड
मानसिक विकलांगता तथा मंद बुद्धिपता जाँच एवं उपचार
कृत्रिम हाथ,पैर,कैलीपर,पोलियो के जूते,वैशाखी, सर्वाइकल कॉलर, बेल्ट आदि का निर्माण एवं वितरण
लाचार विकलांगों को तिपहिया-साकिल तथा व्हीलचेयर
विकलांगों की शल्य चिकित्सा,सर्जिकल करेक्शन
रियायती दर पर पैथोलोजिकल जाँच,एक्स-रे, इ.सी.जी. तथा शल्य
1 Yr. ABRIDGED DEGREE For DPT & DOT
DIPLOMA COURSES:
DPT Diploma in Physiotherapy
DPO Diploma in Prosthetic & Orthotic
DMLT Diploma in Medical Lab. Tech
D-X-Ray Diploma in x-ray Technology.
DHM Diploma in Hospital Management
DOTA Diploma in Operation Theater Assistant
DECG Diploma in E.C.G.
certificate courses:
CMD Certificate in Medical Dressing
Foundation Course for Teachers in Disability
Form & Prospectus:- Available at the institute counter against payment of Rs. 300/-. Send a DD of Rs. 350/-only for postal delivery, in favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna-2
Eligibility:- For Post Graduate Courses- Degree in the same. 10+2 with science for Under Graduate & Diploma Courses. For B.Ed. Degree in any Subject.
Admission Going On...
डा.अनिल सुलभ निदेशक-प्रमुख
फोन न. : 0612-2253290, 2252999, फैक्स: 0612-2253290,email. iiher_beur@gmail.com, www.iiher.org

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 12 मार्च-18 मार्च 2012

www.chauthiduniya.com

मायावती का आपरेशन क्लीन फेल हुआ

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

अजय कुमार

बसपा के क़द्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी को तब तक कोई आंच नहीं आ सकती है, जब तक उन्हें मायावती का संरक्षण प्राप्त है. हालांकि चुनाव के दरम्यान मायावती ने कई मंत्रियों को सिफ़ारिश पत्र पाते ही दरबार से विदा कर दिया था. इनमें कई ऐसे घाघ मंत्री भी थे, जो जिताऊ साबित हो सकते थे. कई विभागों के मंत्री बने नसीमुद्दीन का क़द मायावती दरबार में ज्यों का त्यों बना रहा. बाबू सिंह कुशवाहा के जाने के बाद तो आबकारी मंत्री के दोनों हाथों में लड्डू आ गए. मायावती का इकलौता विश्वसनीय यह मंत्री आय से अधिक संपत्ति के मामले में अख़बारों की सुर्ख़ियों में छाया रहा. कई बार विभागों में धांधलियों को लेकर उंगलियां उठीं, लेकिन सब माफ़. विरोधी दलों ने नसीमुद्दीन के विरुद्ध काफ़ी हो हल्ला मचाया. इस बाबत लोकायुक्त के पास शिकायतें गईं. काफ़ी छानबीन के बाद लोकायुक्त ने मंत्री के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्य सरकार को अपनी सिफ़ारिश भेज भी दी. लेकिन मंत्री का सुरक्षा कवच बनीं मायावती ने लोकायुक्त की सिफ़ारिश पर अमल करने से साफ़ इंकार कर दिया.

लोकायुक्त को भेजे प्रत्युत्तर में शासन ने इस बात का उल्लेख किया है कि नसीमुद्दीन के विरुद्ध कार्रवाई विधिक रूप से संभव नहीं है. उनके विरुद्ध जो आरोप हैं, वे मंत्री द्वारा किए गए किसी कार्य अथवा निर्णय या प्रदान किए गए किसी अनुमोदन से संबंधित नहीं हैं. लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त द्वारा किसी लोकसेवक के विरुद्ध लगाए गए उन्हीं आरोपों के विषय में जांच या संस्तुति की जा सकती है, जिनमें ऐसे लोकसेवक द्वारा किया गया कोई कार्य अथवा उनके द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर की गई किसी कार्रवाई का बिंदू मौजूद हो. शासन स्तर से लोकायुक्त से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह अपने स्तर से परिवादी को अवगत करा दें कि लगे आरोपों जैसे एफ क्यू एजुकेशन सोसायटी का गठन, स्टांप शुल्क आदि की देयता के विषय में सुसंगत अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्रवाई करने अथवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु परिवादी स्वतंत्र है. सिद्दीक़ी के विरुद्ध लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत शिकायती पत्र में उनके संबंधियों द्वारा क्रय की गई भूमि के मूल्य एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एजुकेशन सोसायटी के गठन एवं सोसायटी द्वारा अर्जित की गई संपत्ति आदि के विषय में आरोप लगाए गए हैं. इस मामले में सुसंगत नियमों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के समक्ष परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है. पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि यदि किसी लोकसेवक के विरुद्ध ज्ञात आय के स्त्रोतों से अधिक संपत्ति का कोई आरोप है, तो इस पर कोई सम्मन देने के लिए लोकायुक्त सक्षम प्राधिकारी नहीं है. चूंकि सिद्दीक़ी के विरुद्ध लगे आरोप में मंत्री के रूप में उनके किसी कृत्य अथवा अनुमोदन के विषय में आपत्ति नहीं उठाई गई है. आरोप लोकायुक्त के विधिक क्षेत्राधिकारी की परिधि में नहीं आता. इसलिए लोकायुक्त द्वारा की गई जांच एवं संस्तुतियों पर कार्रवाई करने से असमंजसपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है. इस संदर्भ में शासन स्तर पर कार्रवाई करना संभव नहीं है. शासन ने लोकायुक्त से इस प्रकरण को समाप्त करने का भी अनुरोध किया है.

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी पर कार्रवाई से इंकार करने के बाद मायावती का असली चेहरा सामने आ गया है. उन्हें भय इस बात से है कि नसीमुद्दीन पर लगे आरोपों की सच्चाई यदि सामने आ गई तो इसके छींटे उनके दामन पर भी पड़ेंगे. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि नसीमुद्दीन के साथ ही मायावती की भूमिका की भी जांच कराई जानी चाहिए. रालोद नेता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि लोकायुक्त की सिफ़ारिश के बाद भी मायावती आख़िर नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच की सिफ़ारिश से पीछे क्यों हट गईं.

बहरहाल, कांग्रेस बसपा पर आक्रामक दिख रही है. कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल बीएल जोशी से मिलकर नसीमुद्दीन को मंत्रिमंडल से बर्ख़ास्त किए जाने की मांग की थी. राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि राज्य की बसपा सरकार के भ्रष्टाचार में सिद्दीक़ी की अहम भूमिका रही है और हक़ीक़त को सामने लाने के लिए पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए. वहीं लोकायुक्त सरकार के इस फ़ैसले से ख़ुश नहीं थे. उनका कहना था कि अभी उन्होंने शासन के जवाब का अध्ययन नहीं किया है. जवाब का परीक्षण करने के बाद वह कोई फ़ैसला करेंगे.

अगर वह शासन के निर्णय से संतुष्ट होंगे तो प्रकरण समाप्त कर देंगे, नहीं तो राज्यपाल को विशेष रिपोर्ट भेजेंगे. लोकायुक्त ने कहा कि वह यह भी देखेंगे कि बाक़ी मंत्रियों के मामलों में उनकी संस्तुतियों पर कार्रवाई सीएम ने किस आधार पर की और नसीमुद्दीन के मामले में कार्रवाई न करने के क्या आधार लिए गए. मालूम हो कि मायावती लोकायुक्त की सिफ़ारिश पर अब तक छह मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी हैं, जिनमें राजेश त्रिपाठी, अवधपाल सिंह यादव, रंगनाथ मिश्र, बादशाह सिंह, चंद्रदेव राम यादव एवं रतनलाल अहिरवार आदि शामिल हैं. लेकिन ये मंत्री शायद नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी जैसे विश्वासपात्र न थे और न चुनाव में वोटरों को खींचने में सक्षम थे. हां, राजेश त्रिपाठी और रंगनाथ मिश्र चुनाव लड़ने के लिए टिकट ज़रूर पा गए. इसके पीछे यह भी रहस्य हो सकता है कि लोकायुक्त का यह फ़ैसला चुनाव के ऐसे नाज़ुक मोड़ पर आया, जब बसपा को कांग्रेस और सपा से ज़बरदस्त चुनौती मिल रही थी. नसीमुद्दीन के सहारे ही बसपा ने कई दर्जन मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट बांटे थे. चुनावी मझधार में बसपा सुप्रीमो ऐसा जोखिम उठाने के मूड में नहीं थी. कहते हैं कि नसीमुद्दीन की हैसियत तब और ज़्यादा हो गई, जब एनआरएचएम में फंसे बसपा के क़द्दावर नेता बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री ने हटा दिया. कुशवाहा के जाने के बाद मायावती टीम को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी. कुशवाहा के जाने के बाद पार्टी का सारा दारोमदार नसीमुद्दीन के कंधे पर आ पड़ा. नसीमुद्दीन पार्टी संगठन का काम तो देख ही रहे हैं, साथ ही विधायकों के संपर्क में भी रहते हैं. वह बसपा के रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे हैं. मायावती की चुनावी सभाएं इस बात को बयान करती रही हैं कि उन्होंने लोकायुक्त की हर सिफ़ारिश पर मंत्रियों को बर्ख़ास्त किया और हटाया. लेकिन नसीमुद्दीन के बचाव को लेकर बसपा सुप्रीमो पर विरोधी दल अंगुलियां उठा रहे हैं. विरोधी दलों का कहना है कि बसपा में ऑपरेशन क्लीन चलाने वाली मुख्यमंत्री का ऑपरेशन क्लीन का अस्त क्या भोथरा पड़ गया है.

मायावती का इकलौता विश्वसनीय यह मंत्री आय से अधिक संपत्ति के मामले में अख़बारों की सुर्ख़ियों में छाया रहा. कई बार विभागों में धांधलियों को लेकर उंगलियां उठीं. लेकिन सब माफ़. विरोधी दलों ने भी मंत्री नसीमुद्दीन के विरुद्ध काफ़ी हो हल्ला मचाया.

आबकारी घोटाले में मंत्री शामिल

इलाहाबाद के विनय कुमार मिश्र ने नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी के जवाब पर अपना पक्ष लोकायुक्त को सौंप दिया. विनय मिश्रा का कहना है कि नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी ने अपने बचाव में मुलायम सिंह सरकार की आबकारी नीति को ढाल बनाया है. जिस प्रदेश की आबकारी नीति की सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही गई है, वह मुलायम सिंह यादव सरकार ने बनाई थी, जबकि जिस नीति के अंतर्गत ब्लू वाटर इंडस्ट्रीज को सहकारी चीनी मिल संघ के साथ शराब व्यवसाय में साझीदार बनाया गया, वह मायावती सरकार ने बनाई है. शिकायतकर्ता ने लिखा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी ने शिकायत के जवाब में जिसका ज़िक्र किया है, वह मुलायम सरकार के समय की नीति थी, जबकि उनकी शिकायत 13 मई, 2007 के बाद आबकारी महकमे में हुए घोटाले को लेकर है. विनय मिश्रा ने अपने जवाब में लिखा है कि मंत्री द्वारा संलग्नक के रूप में लगाए गए सहकारी चीनी मिल संघ के प्रबंध निदेशक के पत्र से यह सिद्ध हो रहा है कि बिना टेंडर के ब्लू वाटर को सहकारी चीनी मिल संघ का साझीदार बनाया गया. शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त से जल्द से जल्द कार्रवाई करने की प्रार्थना की है. लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा का कहना है कि नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी के जवाब और विनय मिश्र के प्रति उत्तर का परीक्षण करने के बाद वह निर्णय लेंगे.

feedback@chauthiduniya.com

एवोकैडो बटरफ्रूट नामक यह पौधा वर्ष 1950 में मैक्सिको से लाया गया था. यह पौधा सबसे पहले बागेश्वर और जौलीकोट नैनीताल में लगाया गया.

आगरा स्थित डीईआई के हिंदी विभाग द्वारा दो दिवसीय अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी में व्यक्त किए गए. संगोष्ठी का विषय था हिंदी मीडिया की सामाजिक उपादेयता-युवा पीढ़ी और रोज़गार.

एक नज़र

मायावती के शासन में दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि ख़ुद को दलितों का मसीहा बताने वाली बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के शासनकाल में दलितों पर ही सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख ने किसी का हाल तक नहीं पूछा. मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी शासन में मायावती के रूप में दलित मुख्यमंत्री के रहते हुए भी दलितों का कोई भला नहीं हुआ. मायावती के शासन में दलित महिलाओं तथा बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या-अपहरण की वारदातें होती रहीं, लेकिन मायावती ने किसी भी पीड़ित का हाल जानने कष्ट नहीं किया.

दिग्गी-श्रीप्रकाश, गांधी परिवार के प्यादे : शरद यादव

जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव ने पिछले दिनों अपने विवादास्पद बयानों को लेकर सुर्ख़ियों में रहे केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को नेहरू-गांधी परिवार का प्यादा क़रार दिया. यादव ने बदायूं में संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर केंद्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के हाल के बयान पर कहा कि दरअसल जायसवाल नेहरू-गांधी परिवार के प्यादे हैं और उसी ख़ानदान के रहम-ओ-करम के चलते वह मंत्री भी बने हैं. उन्होंने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को भी नेहरू-गांधी परिवार का प्यादा क़रार देते हुए कहा कि पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सिंह जब-तब मीडिया में किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ कोई भी बयान देते रहते हैं. टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य अरविंद केजरीवाल के सांसदों को चोर, लुटेरा ठहराने संबंधी बयान पर जदयू प्रमुख ने कहा कि केजरीवाल की बात वाजिब नहीं है. उन्होंने कहा कि बहुत से लोग आसमान पर पानी फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कामयाब नहीं होते. इसी तरह संसद भी सर्वोच्च विधायी संस्था है.

संजय सक्सेना
feedback@chauthidunya.com

ऐतिहासिक विरासत ख़तरे में

अयोध्या

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की नगरी अयोध्या के ऐतिहासिक कुंडों और सरोवरों का अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है. करोड़ों लोगों की आस्था-श्रद्धा से जुड़े इन धार्मिक स्थलों को बचाने एवं सजाने-संवारने वाला कोई नहीं रह गया. अब इन प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक धरोहरों की पहचान एवं महत्व इतिहास के पन्नों में ही दर्ज है. इस नगरी में प्राचीन कुंडों और सरोवरों की एक लंबी श्रृंखला है. साथ ही उनके जल का लाभ और महत्व भी है. जानकारी के अनुसार, यहां पर दंतधावन कुंड, हनुमान कुंड, गणेश कुंड, स्वर्णखानि कुंड, सीता कुंड, विद्या कुंड, निर्मली कुंड, वशिष्ठ कुंड, लक्ष्मण कुंड, धनंजय कुंड, वृहस्पति कुंड, उर्वशी कुंड, यज्ञ कुंड, खर्जू कुंड, अग्नि कुंड, मनु कुंड, सूर्य कुंड, महादुर्भस कुंड, सतरूपा कुंड, सरस्वती कुंड, दशरथ कुंड, वैतरणी कुंड, गिरिजा कुंड सहित क़रीब 40 कुंडों का नाम प्रकाश में आता है. इसके अलावा तीन सागरों, जिनमें सप्त सागर, क्षीर सागर एवं दुर्लभ सागर के साथ ही पांच सरोवर अद्भुत सरोवर, चंद्र सरोवर, दुर्लभ सरोवर, राम सरोवर एवं विदेह सरोवर का भी उल्लेख मिलता है. अगर अयोध्या के चौदह कोसी परिक्रमा क्षेत्र के बाहर की बात करें तो अयोध्या से बारह किलोमीटर की दूरी पर भरत कुंड तथा पंद्रह किलोमीटर पूरब विल्वहरि घाट पर दशरथ समाधि है.

इन कुछ कुंडों के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, अयोध्या से दर्शन नगर मार्ग पर राजा अयोध्या के पुत्र प्रताप की देन से एक कुंड का निर्माण सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ जिसका नाम खर्जू कुंड है इसे लोग खजुहा कुंड के नाम से जानते हैं. इस कुंड में रविवार या मंगलवार को स्नान कर चमरौंगे से निजात पा लेता है. हलकारा का पुरवा के निकट इस कुंड में आज भी लोग स्नान करते हैं. यह अब एक गड्ढे की शक्ल में ले रहा है और पूरे कुंड में जलकुंभी फैल चुकी है. जल भी स्वच्छ नहीं है. यहां सिर्फ़ कीचड़युक्त जल है. कहा जाता है कि कभी यह पक्का बड़ा कुंड था. छोटी देवकाली मंदिर के पश्चिम में राजा बेन का बनाया सप्त सागर है, जो अब कॉलोनी में तब्दील हो चुका है, बीच में थोड़ा सा जल है. पच्चीस बीघा के क्षेत्रफल में फैले इस पक्के सागर की विशेषता रही है कि जिधर से भी देखा जाता है, उधर से सप्तरंग में जलधारा दिखती है. जन्म से लेकर मुंडन, कथा, विवाह आदि मंगल कार्यों में इसमें से जल ले जाकर यहां के लोग कार्यक्रम का श्रीगणेश करते थे. यहां महिलाओं की आस्था विशेष रूप से रही है.

धीरे-धीरे यह सागर कई हिस्सों में मालिकों ने बेच डाला और इसे पाट कर अब लोग मकान बनाते जा रहे हैं. इस सागर में दर्जनों मकान बन चुके हैं और बनते जा रहे हैं. रामजन्म भूमि के निकट मुख्य मार्ग टेढ़ी बाज़ार चौराहे पर ऐतिहासिक वृहस्पति कुंड है, लेकिन अब यह कुंड कूड़ादान बन गया है. चारों तरफ़ अनधिकृत रूप से प्रशासन की अदूरदर्शिता के कारण दुकानें लोगों ने लगा लीं. कुंड में कूड़ा फेंका जाने लगा, यहां तक कि नगर पालिका परिषद के कर्मचारी भी कूड़ा डालने लगे. इस कुंड के बारे में यहां के बड़े-बुज़ुर्ग बताते हैं कि पहले इस कुंड में लोग स्नान करके पूजा अर्चना करते थे वृहस्पति व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए यह श्रद्धा का कुंड रहा. गुरु पूर्णिमा को यहां मेला लगता था. आज इस पावन कुंड का नामो-निशान मिट गया.

वहीं सरकारी ख़र्च से जीर्णोद्धार कराए कुंडों में प्रमुख रूप से दंतधावन कुंड, दशरथ कुंड, सूर्य कुंड, विभीषण कुंड, विद्या कुंड, वैतरणी कुंड एवं गिरिजा कुंड शामिल है. ये भी एक वर्ष बाद फिर जस की तस हालत में पहुंचते जा रहे हैं. इन धार्मिक पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण पर सरकार पैसा तो ख़र्च करती है, लेकिन इस कुंड के मालिकान रखवाव में कोई सहयोग नहीं करते. उद्घाटन के बाद विद्युत कनेक्शन कट जाता है, जिससे ट्यूबवेल नहीं चलता और पुष्प, पौधे सूख जाते हैं. स्थाई कर्मचारी न होने तथा अस्थाई रहते कर्मचारियों को पैसा न मिलने से वे भी ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं और फिर कुंड अपने पुरानी हालत में वापस पहुंच जाते हैं.

> हलकारा का पुरवा के निकट इस कुंड में आज भी लोग स्नान करते हैं. यह अब एक गड्ढे की शक्ल में ले रहा है और पूरे कुंड में जलकुंभी फैल चुकी है. जल भी स्वच्छ नहीं है. यहां सिर्फ़ कीचड़युक्त जल है.

अयोध्या के धार्मिक पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए आए बजट की 2007 से 2009 के बीच चार सौ अट्ठानवें करोड़ रुपये की स्वीकृति भेजी भी गई है. इस संबंध में 25 नवंबर, 2011 को लोकसभा में मंत्री सुल्तान अहमद ने बयान भी दिया था कि कुंडों के सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार पर तीन सौ अट्ठानवें करोड़ 40 लाख रुपये ख़र्च हो गए हैं. इन रुपयों के ख़र्च होने की बात करें तो जो तथ्य सामने आता है वह चौंकाने वाला है. यहां के पर्यटन विभाग में सिर्फ़ सूर्य कुंड का नाम दर्ज है, शेष कुंडों का नाम भी पर्यटन विभाग के पास नहीं है. जो विकास हुआ है, उसमें यहां के चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग शामिल हैं. इस मार्ग पर पड़ने वाले स्थलों पर ही यात्रियों के बैठने के लिए शेड, हैंडपंप तथा बैठने के स्थान बनाए गए हैं, जो देखरेख के अभाव में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं. ऐसा भी नहीं है कि इन कुंडों एवं सरोवरों को बचाने का प्रयास नहीं किया गया. यहां के समाजसेवकों एवं मीडिया द्वारा इन कुंडों- सरोवरों के अस्तित्व को बचाने के लिए समय-समय पर ख़बरें भी प्रकाशित की जाती रही हैं. चौथी दुनिया द्वारा भी अपने दो अलग-अलग अंकों 5 जुलाई, 2009 में सप्तसागर के संबंध में सप्तसागर झील को ख़त्म करने की साज़िश तथा 28 फरवरी, 2011 के अंक में ऐतिहासिक धरोहरों पर भू-माफ़ियाओं की नज़र शीर्षक देकर क्षीर सागर पर हो रहे क़ब्ज़े के बारे में विस्तृत रूप से आलेख प्रकाशित किए गए थे.

जब प्रशासन इस पर कार्यवाही करता है तो क़ब्ज़ेधारियों द्वारा उसे कोर्ट का स्टे ऑर्डर थमा दिया जाता है. इसके पीछे का कारण अधिकारी स्वयं भी जानते हैं कि इसी प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारियों द्वारा इन ऐतिहासिक स्थलों पर भूमि का पट्टा और मकान का नक्शा भी पास किया गया होता है. उदाहरण के तौर पर सप्तसागर और क्षीर सागर पर अभी तक कोई कार्यवाही इसलिए नहीं हो सकी है, क्योंकि यहां पर भी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश लागू है. बताया जाता है कि अयोध्या-फ़ैज़ाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा क्षीर सागर के जीर्णोद्धार के लिए नक्शा भी पास हुआ है, पर सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि इस पर क़ाबिज़ लोगों को यह भूमि कैसे मिली और कैसे इस ज़मीन का पट्टा और नक्शा पास हुआ यह सब शासन-प्रशासन के ही सामने है.

राकेश कुमार यादव
feedback@chauthidunya.com

विलुप्ति के कगार पर परंपरागत वाद्ययंत्र

मनुष्य और संगीत का गहरा रिश्ता रहा है. जहां वाद्य यंत्रों के नित नए आविष्कार होते रहते हैं, वहीं परंपरागत वाद्य यंत्र विलुप्त भी हो रहे हैं. ढोल का भारतीय संगीत में काफी महत्व है, इसके स्वरूप और प्रयोग में आजतक कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता. ढोल बजाने की कई विधियां हैं, कई ताल हैं. इस पर पूरा ढोल सागर लिखा गया है, ढोल सागर का मूल संकलन पंडित ब्रह्मानंद थपलियाल से आरंभ कर श्री बद्रिकेदारेश्वर प्रेस पौड़ी गढ़वाल से प्रकाशित किया था. उत्तर प्रदेश के पूर्व उच्चशिक्षा मंत्री शिवा नंद नौटियाल ने ढोल सागर के कई छंद को गढ़वाल के नृत्य-गीत पुस्तक में संपूर्ण स्थान दिया.

प्रारंभिक जानकारियों के अनुसार, ढोल की उत्पत्ति और वाद्य शैली पर शिव और पार्वती के बीच एक लंबा संवाद होता है. उत्तराखंड में किसी भी शुभ या अशुभ अवसर पर ढोल वादन होता है. ढोल सुख, दुःख और पूजा सभी कार्यों में बजता है. उतराई, चढ़ाई, स्वागत प्रस्थान, आरंभ और समापन सभी के लिए अलग-अलग ताल और सबद हैं. किसी भी वाद्य यंत्र के लिए इतना बड़ा साहित्य नहीं होगा, लेकिन आज यह लोककला विलुप्त हो रही है. ढोल काफ़ी सावधानी से बजाया जाता है. रोज़ी- रोटी की तलाश में इस परंपरागत वाद्य यंत्र से जुड़े लोग इससे विमुख होते चले गए. इस व्यवसाय से अनुसूचित जाति के लोग जुड़े हुए थे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthidunya.com

उत्तराखंड में मक्खन के पेड़ पाए जाते हैं

प्राचीन भारत की समृद्धि का बखान करने के लिए प्रसिद्ध मुहावरा है कि यहां दूध की नदियां बहती थीं. लेकिन उत्तराखंड में तो वास्तव में ऐसे वृक्ष हैं, जिनके फल का गूदा मक्खन की तरह डबलरोटी में लगाकर खाया जाता है. हालांकि इसकी जानकारी देने में अभी तक राज्य सरकार विफल रही है. हालांकि उत्तराखंड में इसे मक्खन वाला पेड़ ही कहते हैं. यह मधुमेह और ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए गुणकारी है. विदेशी इसका लुत्फ़ उठाते हैं, मगर राज्य में इसकी ख़ूबियों की जानकारी बहुत कम लोगों को है. बिना ख़ास प्रयास किए उद्यान महकमा केवल यह उम्मीद करता है कि कभी ट्रेंड बदलेगा और बटरफ्रूट लोकप्रिय होगा. एवोकैडो बटरफ्रूट नामक यह पौधा वर्ष 1950 में मैक्सिको से लाया गया था. यह पौधा सबसे पहले बागेश्वर और जौलीकोट नैनीताल में लगाया गया. देहरादून के ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक वीसी मिश्र के अनुसार, एवोकैडो तत्कालीन उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर विवटर साहनी की पहल पर लाया गया और धीरे-धीरे यह राज्य के अन्य हिस्सों में पहुंचा. अल्मोड़ा में एवोकैडो कॉटेज रेस्ट हाउस में इसके पौधे थे. इस समय बागेश्वर, वज्युला, जौलीकोट, ताकुला अल्मोड़ा, गरुड़ वैली व उत्तरकाशी में इसके पेड़ हैं. उद्यान विभाग के उपनिदेशक कुमाऊं डॉक्टर केआर जोशी के अनुसार, बटरफ्रूट एवोकैडो में पर्याप्त प्रोटीन होता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल और शुगर नहीं होता. एवोकैडो के फल का गूदा बिल्कुल मक्खन जैसा होता है, खाने में भी और दिखने में भी. यह तीन से छह हज़ार फीट की ऊंचाई पर लगता है और इसमें फल पांच-छह साल में आते हैं. सूबे में जहां यह फल मिलता है, वहां आने वाले विदेशी सैलानी और भारतीय जानकार इसे बड़े चाव से खाते हैं. डायबिटीज और रक्तचाप से पीड़ित मरीज़ों के लिए भी यह बेहद लाभदायक है, लेकिन दुर्भाग्य से कम लोग इसके बारे में जानते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthidunya.com

मुस्लिम आरक्षण पर दिग्गी का सपा पर हमला

सुर्ख़ियों में बने रहने में माहिर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने केंद्र की ओर से मुसलमानों को 18 प्रतिशत का आरक्षण दिए जाने की स्थिति में समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में समर्थन दिए जाने के सपा की प्रादेशिक इकाई के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को आश्चर्यजनक बताया है. लखनऊ में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश यादव का एक बयान पढ़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र की कांग्रेसनीत सरकार मुसलमानों को 18 प्रतिशत आरक्षण देगी तो सपा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश की जगह सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने यह बयान दिया होता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता. सिंह ने कहा कि समाजवादी नेता जानते हैं कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता. उच्चतम न्यायालय ने इस सीमा से ज़्यादा आरक्षण देने पर रोक लगा रखी है. 50 प्रतिशत से ज़्यादा आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसा करने के लिए न तो कांग्रेस के पास और न ही सपा के पास ज़रूरी बहुमत है. केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जब उनकी पार्टी की सरकार थी तो उसने अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया था, लेकिन वह मज़हबी आधार पर नहीं था.

दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब वर्ष 2004 में केंद्र की सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई तो उसने मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्तर के अध्ययन के लिए सच्चर समिति गठित की थी, जिसने आरक्षण में आरक्षण की सिफ़ारिश की थी. वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का वादा किया गया था और पार्टी ने उसे पूरा भी किया. दिग्विजय सिंह ने कहा कि जहां तक मुलायम सिंह यादव का सवाल है तो उन्होंने अपने चुनाव घोषणापत्र में कभी ऐसी बात का ज़िक्र नहीं किया और न ही इस दिशा में कोई काम किया. उन्होंने यादव पर झूठे वादे करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव का पिछला रिकॉर्ड साफ़ नहीं है. वह सत्ता की राजनीति के लिए विचारधारा को किनारे कर देते हैं.

दिग्विजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद सपा के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के भाजपा नेता वरुण गांधी के बयान के लिए उनकी निंदा भी की. उन्होंने कहा कि सपा के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का वरुण गांधी का यह बयान ख़ुद भाजपा पर व्यंग्य है. उन्होंने लोकायुक्त की जांच में दोषी पाए गए नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी की संपत्ति की प्रवर्तन निदेशालय तथा सीबीआई से जांच कराने की मांग की और कहा कि मंत्री पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुक़दमा भी दर्ज होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मायावती ने भ्रष्टाचार तथा अन्य आरोपों में अपने 21 मंत्रियों को बर्ख़ास्त कर उनके विभाग नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी को सौंप दिए थे. मायावती को यह बताना होगा कि क्या वह सिद्दीक़ी के साथ कैसा बर्ताव करेंगी.

अजय कुमार
feedback@chauthidunya.com

रोगों को दूर भगाए सेहुंड

उत्तराखंड में ऐसी वनौषधियों की कोई कमी नहीं है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के अनेक रोगों का निदान कर देती हैं. पहाड़ में जहां-तहां पाए जाने वाले और किसी काम की न समझी जाने वाली सेहुंड ऐसी ही औषधि है. आयुर्वेद में इसे अनेक व्याधियों की अचूक औषधि बताया गया है. सरू, श्योण, सुंडु आदि नामों से पुकारी जाने वाली वनौषधि आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति में प्रयुक्त होने वाली बहुमूल्य जड़ी-बूटी स्नुही या सेहुंड है. पर्वतीय क्षेत्र में इसे स्नूण भी कहा जाता है. सेहुंड की दो प्रजातियां यूफोरबिया रायलियाना एवं नेरिफोलिया राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बहुतायत में पाई जाती हैं.

सेहुंड का छोटा वृक्ष करीब छह फीट तक ऊंचा होता है, जिसके मांसल एवं कांटेदार तने एवं शाखाएं गोलाकार या पंचकोणीय होती हैं. शीतकाल में इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और वसंत में हरे-पीले फूल एवं तत्पश्चात फल लगते हैं. आयुर्वेद में वज्रक्षार, स्नुहयादि तैल, स्नुहयादि वर्ति सहित सैकड़ों औषधियों के निर्माण में सेहुंड का प्रयोग होता है. यह औषधियां पाचन, रक्तवह एवं श्वसन संस्थान के रोगों समेत अनेक चर्मरोगों में उपयोगी है. घरेलू चिकित्सा में सूजन एवं दर्दयुक्त स्थानों पर सेहुंड की पत्तियां गर्म करके बांधने पर तुरंत आराम मिलता है. कान दर्द में सेहुंड का दूध लाभकारी माना गया है. दांत दर्द में इसके दूध को रुई के फाहे के साथ रखा जाता है. इसके अलावा अनेक चर्म रोगों की घरेलू चिकित्सा में सेहुंड का दूध प्रयोग किया जाता है. बवासीर के लिए भी इसके दूध का इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने बताया कि भगंदर की चिकित्सा में क्षार सूत्र के निर्माण में भी सेहुंड के दूध का प्रयोग किया जाता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthidunya.com

मतदान से वंचित टीम अन्ना

लोकतंत्र में परिवर्तन की अलख जगाने वाले ही लोकतंत्र के महापर्व मतदान में हिस्सा नहीं ले पाए. मतदाता सूची में नाम न होने के कारण टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया वोट नहीं डाल सके. एक अन्य सदस्य कुमार विश्वास ने वसुंधरा सेक्टर चार के मीडिया पब्लिक स्कूल में वोट डाला. छठे चरण का मतदान चालू हो चुका था, लेकिन चैनल वालों की पैनी निगाहें अन्ना टीम के सदस्य अरविंद केजरीवाल पर टिकी थीं कि वह मतदान केंद्र पर आएं और उन्हें कैमरे में क़ैद करें, लेकिन इन सबसे दूर केजरीवाल अपने गोवा दौरे में जाने के लिए कार पर सवार हो चुके थे. वह एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे, लेकिन इससे पहले ही केजरीवाल को अख़बारनवीसों ने घेर लिया. चैनल पर ख़बर आई कि केजरीवाल बिना वोट डाले ही गोवा दौरे पर निकल चुके हैं. इस ख़बर के प्रसारित होते ही केजरीवाल को ख़बर लग गई. मीडिया के इस दबाव के चलते वह मतदान केंद्र पर पहुंचे, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट से नदारद था. देश के एक जागरूक प्रहरी की भूमिका निभाने वाले केजरीवाल के बारे में राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज़ हो गईं. उनकी टीम के लोगों से घेर-घेर कर मीडिया वाले सवाल करने लगे. केजरीवाल ने कहा कि वह लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, इसलिए अपनी ग़लती मानते हुए वह वोट डालने वापस आए. केजरीवाल के पहुंचने पर कुछ लोगों ने हंगामा भी किया. मनीष सिसौदिया का कहना है कि वह पहले ही मालूम कर चुके थे कि उनका नाम सूची में नहीं है. इधर, वसुंधरा सेक्टर चार में अपनी पत्नी डॉ. मंजू शर्मा के साथ वोट डालने पहुंचे कुमार विश्वास ने कहा कि प्रदेश भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो क़दम

मीडिया ने बहुत सारी खिड़कियां तक खोल दी हैं. इन खुली खिड़कियों से धूल भी आ रही है. अगर इस धूल को हटा दिया जाए तो मीडिया की सामाजिक उपादेयता पूरी तरह बरक़रार रहेगी. वही अवधेश ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर मीडिया कॉरपोरेट के हाथ में है तो उन्हीं के सरोकार को तरजीह मिलेगी. हमें ऐसे मीडिया से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जनवादी पत्रकार जनपक्षीय ख़बरों के लिए स्पेस ढूंढ ही लेते हैं. देश साफ़तौर से दो हिस्सों में बंट चुका है. एक ख़ास वर्ग और दूसरा आर्थिक रूप से कमज़ोर तबक़ा. मीडिया इसी ख़ास वर्ग के हितों का संरक्षण कर रहा है. इन परिस्थितियों में वैकल्पिक मीडिया ही सही रास्ता बचता है. संजीव माथुर ने कहा कि मीडिया की चुनौतियां समाज की चुनौतियां है. जाति-धर्म को लेकर भेदभाव किया जाना बहुत बड़ा सवाल बन चुका है. अल्पसंख्यक और महिला विरोधी जुमले सबसे ज़्यादा न्यूज़ रूम में चर्चा का विषय बनते हैं. ग़रीब आदमी को मीडिया में स्थान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. मीडिया भशाल का रूप भी धारण कर सकता है यदि इस ओर गंभीर प्रयास किए जाएं. फ़िलहाल समाज में ऐसा जज्बा देखने को नहीं मिल रहा है. इंडिया टुडे के संपादक दिलीप मंडल ने कहा कि मीडिया आपके सोचने के तरीक़े और व्यवहार को निर्णायक बनाने में सहायक होता है. जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं, उसी तरह की मानसिकता भी लोगों के मन में पैदा हो रही है. संगोष्ठी में अधिकांश वक्ताओं ने स्वीकार किया कि संपादक संस्था ख़त्म करने की साज़िश की जा रही है. संपादक प्रबंधन की कठपुतली बनता जा रहा है, जिससे अच्छे पत्रकार शीर्ष पद पर नहीं पहुंच पाते, जिससे पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है. इसके अलावा पत्रकार के उपाध्याय, डॉ. हरिमोहन शर्मा नेपाल से आए प्रकाश चंद्र, श्याम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेपाल से नीलम परियार ने भी विचार व्यक्त किए. संगोष्ठी का समापन वक्तव्य आनंद प्रधान ने दिया. अंत में धन्यवाद ज्ञापन हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. शर्मिला सक्सेना ने दिया.

अनिताभ आकाश
feedback@chauthidunya.com

पत्रकारिता का गिरता स्तर चिंताजनक

पत्रकारिता पर संगोष्ठी

बाज़ारवाद के दौर में मीडिया का भी बाज़ारीकरण हो गया है. कॉरपोरेट के प्रभाव के कारण मीडिया प्रबंधन ने संपादक संस्था को भ्रष्ट और निकम्मा बना दिया है अथवा ख़त्म कर दिया है. अब संपादक योग्य, निर्भीक पत्रकार न होकर प्रबंधक की जी हुज़ूरी करते हैं. जनवादी पत्रकारिता के लिए मीडिया में पर्याप्त स्थान नहीं है. फिर भी अच्छे और जुझारू पत्रकार जनवादी पत्रकारिता के लिए स्पेस ढूंढ ही लेते हैं. यह विचार आगरा स्थित डीईआई के हिंदी विभाग द्वारा दो दिवसीय अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी में व्यक्त किए गए. संगोष्ठी का विषय था हिंदी मीडिया की सामाजिक उपादेयता-युवा पीढ़ी और रोज़गार. वरिष्ठ पत्रकार रामशरण जोशी ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि मीडिया की छवि और विश्वसनीयता पूरी तरह कठघरे में खड़ी हो गई है. अख़बारों में विज्ञापनवाद हावी होता जा रहा है. पेड न्यूज की संस्कृति ने मीडिया की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई है. पाठक वर्ग भ्रमित हो रहा है. इस तरह के समाचार का वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है. नागरिकों को अब जागरूक होना पड़ेगा. उनके विचारों से सहमति जताते हुए मंगरेज डबराल ने कहा कि साहित्य और पत्रकारिता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. पत्रकारिता से साहित्य को अलग कर दिया गया है, जो ठीक नहीं है. पत्रकारिता, साहित्य के बग़ैर चल नहीं सकती है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मनोरंजन का साधन बन गया है. राजनीति को टीवी चैनल्स मनोरजक तरीक़े से दिखाते हैं.

संगोष्ठी में मीडिया विशेषज्ञ वर्तिका नंदा ने कहा कि मीडिया में इस बहस की ख़ास वजह है वे चैनल हैं, जो कुकरमुत्ते की तरह उग आए हैं. उनका मिशन पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है. वे सामाजिक सरोकारों से नहीं जुड़े हैं, बल्कि उनके उद्देश्य आर्थिक हैं. जो पत्रकार कमीशन पर ज़िंदा है, वे सुखी हैं. पत्रकारों का शोषण हो रहा है. उन्हें तनख़्वाह तक नहीं मिलती. उन पर विज्ञापन अथवा दलाली करने तक का दबाव डाला जाता है. पत्रकारिता का अब मज़ाक़ बन रहा है. इन परिस्थितियों में हमें स्वयं के भीतर झांकने का मौक़ा मिलता है. इसके बावजूद

शांतिनाथ जी का मंदिर इन सबमें उल्लेखनीय है. यहां मनौती के रूप में खंभों का निर्माण करवाए जाने की परंपरा रही है.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

श्रमदान से पैड़ी की सफाई

राकेश कुमार यादव

सरयू तट के समीप वर्ष 1989 में निर्मित राम की पैड़ी गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है. इसकी सफाई पर सरकार ने काफ़ी धन व्यय किया, लेकिन यह साफ नहीं हुआ. यहां के आला अधिकारियों ने श्रमदान कर इसकी सफाई की. मंडलायुक्त मधुसूदन रायजादा, डीआईजी आनंद स्वरूप, डीएम एमपी अग्रवाल, एसएसपी आरके चतुर्वेदी, अपर आयुक्त जग प्रसाद, एडीएम सिटी श्रीकांत मिश्र, प्रशिक्षु आईएएस भवानी सिंह, एसपी सिटी अनिल कुमार राय, एक्सईएन विद्युत एके वर्मा, आरएम अवधेश मिश्र आदि अधिकारियों द्वारा पैड़ी की सफाई की गई. इस दौरान अफ़सरों ने फावड़ा भी चलाया. सफाई अभियान के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि पहले हम नागरिक हैं. हमें सकारात्मक सोच के साथ अयोध्या के गौरव को स्थापित करने की पहल करनी होगी. इस सफाई अभियान में सरकारी विभागों के अफ़सर एवं कर्मचारियों ने अपनी स्वेच्छा से श्रमदान किया. सफाई अभियान में अफ़सरों एवं कर्मियों के साथ सीआरपीएफ के जवानों तथा स्थानीय नेताओं, समाजसेवियों द्वारा भी श्रमदान किया गया. इस अभियान में विभिन्न घाटों के किनारे–किनारे जमा कीचड़, गंदगी और शैवालों को हटाया गया.

अयोध्या

ग़ौरतलब है कि चौदह करोड़ रुपये की लागत से एक लंबे चौड़े क्षेत्रफल में बनाई गई इस राम की पैड़ी की तकनीक ही बेकार साबित हुई है, न तो इसमें सरयू की धारा पहुंची और न निकासी का कोई उचित रास्ता बनाया गया. इसके निर्माण के समय में जिलाधीश सीताराम शरण ने निरर्थक प्रयास बताया था और हश्र भी वैसा सामने आ गया. तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा इसके उद्घाटन के छह माह बाद ही प्रथम पुल तीन सौ फीट सीढ़ी समेत धंस गया. पैड़ी के उद्घाटन के बाद दो–चार महीने तक इसमें रंग–रोग़न दिखाई पड़ा, जल भी स्वच्छ रहा. इसके बाद धीरे–धीरे यह दुर्दशा की तरफ़ बढ़ने लगा. इसमें लगे विद्युत उपकरण ग़ायब हो गए, पुष्प और पौधे आवारा पशु खा गए, दूर–दूर तक कहीं इसके रख–रखाव के कर्मचारी नहीं दिखाई पड़े. इसके बाद एक बार फिर शासन की तरफ़ से इसे सुंदर बनाने का प्रयास शुरू किया गया, जिसमें पैड़ी के जल के बीच तीन रंग–बिरंगे फव्वारे लगाए गए. सफाई, रंगाई का दौर चला, इसके आसपास के मंदिरों को एक रंग से संवारा गया और रात्रि में मंदिर भव्य दिखे. इसके लिए फोकस युक्त लाइटें भी लगाई गईं. लोगों के आकर्षण का केंद्र बने इसके लिए पैर से चलाने वाले जल बोट की व्यवस्था की गई. एक बार फिर लोगों में आस जगी कि पैड़ी सज–संवर कर दुल्हन की तरह दिखेगी लेकिन छह माह बाद पूरी की पूरी व्यवस्था ढह गई और यह राम की पैड़ी अराजक तत्वों का अड्डा हो गया, जिससे लोगों का आना–जाना ही बंद हो गया. स्थिति यहां तक पहुंच गई कि बुर्जों से पत्थर की पट्टियों की चोरी शुरू हो गई. विद्युत उपकरण ग़ायब हुए, लोहे की रेलिंग ग़ायब हुईं, प्लेटफार्म पर लगे पत्थर तक नदारद हो गए. उद्घाटन के दिन ही यहां से एक युवक की लाश बरामद हुई थी, तब से अब तक दर्जनों लाशें बरामद होती रहीं हैं. पैड़ी को स्थानीय लोगों ने भी गंदा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, घरों का कूड़ा–कर्कट यहां डालने लगे. मरे हुए पशु भी यहीं फेंक दिए जाते हैं. मेलों में तो पैड़ी का पूरबी उत्तरी परिसर यात्रियों के शौच का स्थल बन जाता है. दिन–रात यहां आवारा पशु घूमते दिखाई देते हैं. रात में मछली पकड़ने का क्रम कई वर्षों तक चला. आज इसकी हालत गंदे नाले की तरह हो गई है, न तो इसमें पानी डाला जाता है और न निकाला जाता है. कीचड़, काई, घास से पैड़ी पट गई है. चार वर्ष पूर्व इसकी सफाई कराने का ठेका दिया गया. ठेकेदार ने पानी निकाल दिया था, जिससे सैकड़ों कुंतल मछलियां भी मर गई थीं. स्थानीय लोगों के विरोध पर कुछ मछलियों को सरयू नदी में पुन: डलवाया गया था. इसके बावजूद पैड़ी की सफाई नहीं हो पाई. कांग्रेस के शासन में इसका निर्माण कराया गया था. उस वक़्त सांसद निर्मल खत्री, मंत्री सीताराम निषाद इसका निरीक्षण भी करते रहे. इसके बावजूद कई बार सीढ़ियां धंसीं, तो कभी प्लेटफार्म धंस गए. लोगों का मानना है कि जब तक ओवर ब्रिज बनाकर या पुलिया बनाकर इसके जल की निकासी नहीं होगी और इसमें पानी डालने का तरीक़ा नहीं बदला जाएगा, तब तक इसमें शुद्ध जल नहीं रह पाएगा. पैड़ी के आसपास के नाले नालियों व सीवेज का गंदा जल पैड़ी में ही गिरता है. बरसात में तो स्वर्गद्वार, नया घाट, लक्ष्मण घाट क्षेत्र के सभी नाले नालियां उफ़न कर पैड़ी में समा जाती हैं.

कुल मिलाकर जिस मक़सद से राम की पैड़ी बनाई गई थी, वह ध्येय आज पूरा होता नहीं नज़र आ रहा है. कहने को तो यह राम के नाम से जुड़ा है, लेकिन राम के जीवन आदर्श से जुड़ा कोई दृश्य या झांकी यहां नहीं है. यदि इस पैड़ी में कुछ झांकियां ऐसी बनाई जाएं, जिससे पर्यटकों को अयोध्या के धार्मिक स्थलों की जानकारी मिल सके. साथ ही बच्चों के मनोरंजन हेतु खेल का सामान उपलब्ध हो. धार्मिक आयोजन के लिए मंच–मंडप बनाए जाएं तो निश्चित तौर पर पैड़ी की ख़ूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे. यदि संभव हो तो इसके रख–रखाव की व्यवस्था में ख़र्च होने वाली धनराशि के लिए टिकट प्रवेश के लिए कर दिया जाय तो पैड़ी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है.

feedback@chauthiduniya.com

प्राचीन धरोहर खंडहर बनी

ललितपुर में एक रमणीय स्थल है देवगढ़. पहाड़ी पर प्राचीन मंदिरों के अतिरिक्त ऊंची चट्टानों के नीचे घूमती हुई बेतवा नदी एक अनोखी छटा प्रस्तुत करती है. पहाड़ी के ऊपर की समतल भूमि पर अनेक मंदिर बने हुए हैं, जिनमें बहुत सारे ध्वस्त हो गए हैं.

एक तरफ़ कुछ भग्नावशेष पड़े हैं, जिसे वराह का मंदिर बताया जाता है. कहा जाता है कि यहां कुल 40 जैन मंदिर थे, जिनमें से आज छोटे बड़े मिलाकर कुल 31 बचे हुए हैं. शांतिनाथ जी का मंदिर इन सबमें उल्लेखनीय है. यहां मनौती के रूप में खंभों का निर्माण करवाए जाने की परंपरा रही है. ऐसे ही मनौती में शिलाखंड दिए जाने की भी प्रथा थी. लगभग 8वीं से 17वीं शताब्दी तक यह स्थल जैन मतावलंबियों (दिगंबर) का केंद्र रहा है. यहां चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफ़ा मंदिर (सिद्ध की गुफ़ा), राजघाटी, नहरघाटी आदि प्रमुख हैं. बेतवा नदी पहाड़ियों के नीचे बहती है और नीचे जाने के लिए पत्थरों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं. सीढ़ियों से नीचे उतरते समय बाईं तरफ़ चट्टानों को तराश कर छोटे–छोटे कमरे बना दिए गए हैं, जिनमें जैन मुनि एकांत में प्रकृति का आनंद लेते हुए अपनी साधना में निमग्न हुआ करते थे. चट्टानों पर लगभग 8वीं शताब्दी की ब्राह्मी लिपि में कई जगह लेख भी खुदे हैं. यह पूरा इलाक़ा जंगल और झाड़ियों से भरा पड़ा है. सही रखरखाव न होने के कारण यह दर्शनीय स्थल अब खंडहर में बदलता जा रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com